आसियान-चीन संबंध 1975-81 : हिन्द-चीन के विशेष संदर्भ में

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के
मास्टर ऑफ फिलॉसफी
उपाधि के लिए प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध

सत्यप्रकाश

दक्षिण, दक्षिण-पूर्व एवं मध्य एशियाई अध्ययन केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

1984

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

Gram : JAYENU

Telephone : 652282
652114

New Mehrauli Road,
NEW DELHI-110067.

दिनांक: 4-1-1985

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्य प्रकाश द्वारा यह शोध प्रबन्ध " आसियान-चीन संबंध 1975-1981 : हिन्द-चीन के विशेष संदर्भ में " इस विश्वविद्यालय के मास्टर आफ फिलासफी उपाधि के आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया । हमारे जानकारी में यह शोध प्रबन्ध इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में एम० फिल० की उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह शोध प्रबन्ध उनकी मौलिक कृति है ।

हम इस शोध प्रबन्ध को परीक्षण हेतु परीक्षकों के सम्मुख रखे जाने की सिफारिश करते हैं ।

अध्यक्ष

Bhagwan Dass Arora
निदेशक

पू

ज्य

की

य

माता - पिता को

सादर

समर्पित

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		(क) से (च)
प्रथम अध्याय :	पृष्ठभूमि	1 - 31
द्वितीय अध्याय :	1975 का हिन्द-चीन परिवर्तन व आसियान	32 - 65
तृतीय अध्याय :	1975 से आसियान-चीन संबंध	66 - 108
चतुर्थ अध्याय :	आसियान व चीन : कम्पूचिया के विशेष संदर्भ में	109 - 153
पंचम अध्याय :	अन्त में	154 - 169
	सन्दर्भिका	170 - 189

प्राक्कथन

दक्षिण-पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन, राजनीतिक स्थिरता व शान्ति बनाए रखने में आसियान-चीन संबंधों की महत्त्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्रस्तुत शोध प्रबंध में आसियान-चीन संबंधों, 1975-81, का हिन्द-चीन के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया गया है ।

अध्ययन अवधि (1975-81) का चयन इस आधार पर किया गया है कि वर्ष 1975 में हिन्द-चीन देशों : कम्पूचिया, दक्षिण वियतनाम तथा लाओस, में एक के बाद एक साम्यवादी सरकार की स्थापना के परिणाम स्वरूप आसियान देशों में साम्यवाद का भय व्याप्त हो गया तथा इस डर से आसियान देशों ने चीन के साथ संबंध बनाना ही उचित समझा और इस प्रकार 1975 आसियान-चीन संबंधों के विकास में एक बुनियादी वर्ष के रूप में माना जा सकता है । वियतनाम द्वारा 25 दिसम्बर, 1978 को कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उभरी कम्पूचियाई समस्या पर आसियान व चीन के विचारों में काफी समानता है तथा आसियान-चीन के बीच कम्पूचिया विवाद पर आपसी समझदारी 1981 में एक विशेष चोटी पर पहुंच गई । कम्पूचिया समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 34वें, 35वें व 36वें अधिवेशन में आसियान द्वारा रखे प्रस्तावों का चीन के समर्थन से आसियान-चीन संबंधों में स्पष्ट विकास व भविष्य का दर्शन हुआ । इसलिए आसियान-चीन संबंध के लिए 1981 एक महत्त्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है ।

वस्तुत: प्रारम्भ में आसियान के सदस्य देश - इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैण्ड थे परन्तु जनवरी, 1984 में ब्रुनेई भी इस क्षेत्रीय संगठन का छठवां सदस्य बन गया । चूंकि प्रस्तुत अध्ययन अवधि (1975-81) है इसलिए इसमें ब्रुनेई की चर्चा नहीं की गई है ।

जब दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ऑर्गेनिसेशन आफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स) की, आठ अगस्त, 1967 को बैंकाक में स्थापना हुई तब चीन ने इसे 'चीन विरोधी', 'साम्यवाद विरोधी एक नया संधि', तथा 'अमेरिका का एशियाई पिछलग्गू' कहा और अमेरिका पर आरोप लगाया कि 'क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन' के नाम पर वह आसियान देशों की सैनिक साज-सामानों की आपूर्ति कर रहा है।' परन्तु बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के प्रारंभ से चीन के आसियान के प्रति उसकी विरोधी मानसिकता में परिवर्तन का स्पष्ट दर्शन होने लगा। यह परिवर्तन हिन्द-चीन में युद्ध की समाप्ति के दौरान ही मुखर उठा जब चीन ने आसियान का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। सन् 1978 में वियतनाम के कम्पूचिया में प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप के बाद तो चीन आसियान को सर्वाधिक समर्थन देने वाले देशों में स्थापित हो गया।

आसियान-चीन संबंधों पर विचार करते समय अनेक प्रश्न सामने आते हैं -- क्या कारण है कि आसियान देशों का चीन के साथ संबंध सातवें दशक के प्रारंभ तक शत्रुता व तनावपूर्ण था जबकि सातवें दशक के मध्य से मित्रता व तनाव शैथिल्यता की शुरुआत देखने को मिलती है? क्यों चीन आसियान को एक सैनिक संगठन व संधि के रूप में इसका विरोध करता था तथा अब समर्थन? चीन आसियान देशों के स्थानीय कम्युनिस्टों की सहायता में क्यों कमी करता जा रहा है? वर्ष 1974-75 में आसियान सदस्य देश -- मलेशिया, फिलीपींस व थाईलैण्ड ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए परन्तु इंडोनेशिया व सिंगापुर ने अभी तक चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं कर सके हैं, इन दो देशों के चीन के साथ राजनयिक संबंधों का क्या भविष्य है? आसियान देश, दक्षिण-पूर्व एशिया के शान्ति व स्थिरता के लिए, किन महाशक्तियों व बड़ी शक्तियों को खतरनाक समझते हैं? आसियान सदस्य देशों का अलग-अलग सुरक्षा दृष्टिकोण क्या है? वे अपनी सुरक्षा के लिए किस दिशा से खतरे का अनुभव

करते हैं ? उनकी सुरक्षा की खतरा के लिए आंतरिक व बाह्य आयाम क्या है ? वर्तमान समय में अपनी सुरक्षा व स्थिरता के लिए आसियान देश किस प्रकार की नीति अपना रहे हैं ? चीन व हिन्द-चीन के संदर्भ में उनके लघु अवधि व दीर्घ अवधि उद्देश्य क्या हैं ? आसियान के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चीन मित्रता व कहां तक उनके लिए उपयोगी है ? सोवियत-चीन तनाव शैथिल्यता की स्थिति में आसियान-चीन संबंध पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? उपरोक्त प्रश्नों पर विचार व उत्तर प्राप्त करने के लिए विभिन्न शोध सामग्री , पुस्तकों, तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों व शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है । अध्ययन अवधि में अनेक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं में प्रस्तुत शोध-विषय से संबंधित सामग्री तो मिले पर उनमें इस विषय पर संघटित व समग्र रूप का सर्वथा अभाव रहा । इस अभाव की पूर्ति प्रस्तुत शोध अध्ययन में करने का पूरा प्रयास किया गया है पर विषय के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए इस बात का दावा भी नहीं किया जा सकता ।

प्रस्तुत अध्ययन में विषय का शोध ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक तौर पर किया गया है, जो प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रकाशित-सामग्री पर आधारित है । इस अध्ययन में आसियान देशों के विभिन्न नाम आदि का वहां के स्थानीय उच्चारण के आधार पर लिखने का प्रयास किया गया है तथा चीनी नामों को लिखने के लिए 'पिन यिन' उच्चारण प्रणाली को अपनाया गया है । मुख्य रूप से अंग्रेजी व चीनी भाषा में उपलब्ध शोध सामग्री का प्रयोग इस अध्ययन के लिए किया गया है । अन्तरराष्ट्रीय राजनीति व संबंधों के विशिष्ट शब्दावली के अनुवाद में कठिनाइयों से बचने के लिए उक्त शब्दों का भावानुवाद व कहीं-कहीं छायानुवाद का भी सहारा लेना पड़ा है ।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मुख्यत: तीन बातें प्रभावित करती हैं -- नेतृत्व जो देश में शासन कर रही होती है, आंतरिक समस्याएं या घरेलू राजनीतिक विकास अथवा परिवर्तन और देश विदेश में चल रही राजनीति प्रणाली ।

इसके अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित विभिन्न प्रकार के संबंधों के लिए प्रेरित करता है । अन्तरराष्ट्रीय राजनीति व संबंध में कोई भी देश स्थाई मित्र अथवा स्थाई शत्रु नहीं होता अपितु केवल राष्ट्रीय हित ही स्थाई होता है । अन्तरराष्ट्रीय संबंध किसी विशेष निश्चित समय या अवधि में किसी विशेष दिशा में पूरी तरह नहीं मुड़ जाते । उपरोक्त समस्त तथ्यों की प्रमाणिकता की जाँच आसियान-चीन संबंधों के संदर्भ में की जा सकती है ।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध में, आसियान-चीन संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटकों व इकाइयों का अध्ययन करना जिसमें मुख्यतः आसियान देश, चीन, हिन्द-चीन व महाशक्तियाँ — सोवियत संघ व अमेरिका के द्वितीय महायुद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ, नीतियाँ व प्रभाव आदि हैं, और हिन्द-चीन में परिवर्तन के फलस्वरूप आसियान-चीन संबंधों व आसियान की संगठनात्मक कार्य क्षमता में परिवर्तन तथा आसियान-चीन संबंधों की भविष्य व संभावनाओं आदि का अध्ययन भी शामिल है ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में पाँच अध्यायों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है ।

प्रथम अध्याय : पृष्ठभूमि -- इस अध्याय में प्राचीन समय से लेकर हिन्द-चीन में परिवर्तन (1975) तक आसियान देशों व चीन के संबंधों का अध्ययन किया गया है ।

द्वितीय अध्याय : 1975 का हिन्द-चीन में परिवर्तन व आसियान -- इसमें 1975 में हुए हिन्द-चीन में साम्यवादी परिवर्तन के परिणामस्वरूप आसियान देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा तथा आसियान देश इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के बीच अपनी आपको कैसे संतुलित कर पाए ? तथा आसियान संगठन इस घटना से कैसे उत्प्रेरित हो गया, आदि का अध्ययन किया गया है ।

तृतीय अध्याय : 1975 से आसियान-चीन संबंध -- इस अध्याय में हिन्द-चीन में परिवर्तन (1975) से वियतनाम के कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप (1978-79) तक के आसियान-चीन संबंधों के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय : आसियान व चीन : कम्पूचिया के विशेष संदर्भ में -- इसमें वियतनाम द्वारा कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप (1978-79) से लेकर 1981 तक आसियान व चीन के कम्पूचिया के विशेष संदर्भ में प्रतिक्रियाओं, परिवर्तनशील समीकरण व उससे प्रभावित उनके बीच पड़ने संबंधों का अध्ययन किया गया है।

पंचम अध्याय : अन्त में -- इसमें पूरे विषय का निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया है।

इन अध्यायों के साथ प्राथमिक प्रयोग सामग्री सूची तथा द्वितीयक प्रयोग सामग्री में ग्रन्थ सूची, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध व दैनिक पत्रों की सूची दी गई है।

आसियान सदस्य देशों में इंडोनेशिया की एक मात्र विशेष देश है जिसका साम्यवादी चीन के साथ पाचवें व छठें दशक के मध्य तक संबंध था और आज जबकि अन्य आसियान देशों की चीन के साथ संबंध काफी अच्छे हैं तो इंडोनेशिया के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है। आसियान सदस्य देशों में, हिन्द-चीन के प्रत्येक परिवर्तन चाहे वह सन् 1975 का रहा हो या 1978-79 का, इससे सर्वाधिक प्रभावित देश थाईलैण्ड रहा है। थाईलैण्ड को तो 'फ्रंट लाईन' राज्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए आसियान - चीन संबंधों के प्रस्तुत अध्ययन में इंडोनेशिया व थाईलैण्ड का चीन के साथ संबंध पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस कार्य के संपादन में मुझे विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग मिला है जिसके लिए मैं उन सबका आभारी हूं। मैं अपने प्रेरणास्रोत एवं निदेशक

डा० भगवान दास अरोड़ा का अत्यन्त आभारी हूं जिनके मार्ग दर्शन से इस शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सका हूं। दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग के प्राध्यापक प्रो० विशाल सिंह जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने मेरा समय-समय पर उत्साहवर्द्धन किया। दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व मध्य एशियाई केन्द्र के अध्यक्ष प्रो० विमल प्रसाद का तथा डा० परिमल कुमार दास, प्रो० आर० सी० शर्मा, डा० पुष्पेश पंत व डाक्यूमेंटेशन आफिसर श्री जे०एस० भट्ट का मैं अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने सदैव मुझे विभिन्न रूप से उत्साहित किया। मैं अपने इंडोनेशियाई भाषा के गुरु डा० चन्द्र दत्त पालीवाल के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधित स्थानीय समस्याओं को स्पष्ट करते हुए ज्ञानार्जन कराया। इस कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक शोध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंडियन कौंसिल फार वर्ल्ड अफेयर्स, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नयी दिल्ली व नेहरू मेमोरियल पुस्तकालयों के कर्मचारियों व अधिकारियों का अत्यन्त आभारी हूं।

मैं, अपने अग्रज श्री अशोक व श्री सत्यकाम का, विभिन्न प्रकार से उनके द्वारा दिए गए सहयोग व उत्साह के लिए हृदय से आभारी हूं तथा अपने प्रिय मित्र कु० गीता बी० नायर व श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया के सुझावादि के लिए भी आभार व्यक्त करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं।

इस शोध प्रबन्ध को स्वच्छता एवं लगन के साथ विशुद्ध टंकित करने हेतु अपने मित्र श्री परमेश्वर राम जी का हृदय से आभारी हूं।

अन्त में, प्रस्तुत शोध अध्ययन में समस्त त्रुटियों के लिए एकमात्र जिम्मेवार मैं स्वयं हूं।

सत्य प्रकाश

दिनांक: 4 जनवरी, 1985।

प्रथम अध्याय

पृष्ठभूमि

सन् 1975 में हुए हिन्द-चीन में राजनीतिक परिवर्तन के बाद सुषुप्ता अवस्था में पड़ा आसियान अचानक जाग उठा और वह सक्रिय हो उठा । इसका आसियान-चीन संबंध पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । उपरोक्त परिवर्तनों का कारण निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन तथा दक्षिण-पूर्व एशिया[1] व चीन के भौगोलिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के अतीत के पृष्ठों पर पाया जा सकता है ।

दक्षिण-पूर्व एशिया का भौगोलिक व सामाजार्थिक परिचय :

द० पू० एशिया $28^{0} 30'$ उत्तर से $11^{0} 00'$ दक्षिण तक तथा $92^{0} 20'$ पूर्व से $134^{0} 50'$ पूर्व फैला हुआ है[2]। द०पू० एशिया का भू-भाग इस पूरे क्षेत्र का केवल चौथा भाग है तथा शेष जल भाग है । इसका सम्पूर्ण भू-क्षेत्रफल 1,571,000 वर्ग मील है जिसमें प्रायद्वीप मुख्य भूमि 795,000 वर्ग मील है[3] तथा बाकी 776,000 वर्ग मील कई हजार द्वीपों में बटे हैं जिसमें मुख्य दो बड़े द्वीप समूह हैं - इंडोनेशिया व फिलीपींस । भौगोलिक रूप से द०पू० एशियाई संस्कृति को विशिष्ट रूप देने में जल की विशेष भूमिका रही है । लाओस के अतिरिक्त द०पू० एशिया के समस्त देश समुद्र के साथ भी हैं । उच्च पर्वत श्रृंखलाएं

1- एक विस्तृत क्षेत्र जो चीन के दक्षिण, भारत व बांगला देश के पूर्व तथा आस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित , भारत व चीन के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों से प्रभावित हुआ जिसे द्वितीय महायुद्ध के समय से दक्षिण-पूर्व एशिया के नाम से जाना जाता है - फिशर, ए० चार्ल्स, साउथ ईस्ट एशिया - ए सोशल, इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल जियोग्राफी, (लंदन, 1964), पृष्ठ-3 ।

2- फिशर, ए० चार्ल्स, साउथ ईस्ट एशिया - ए सोशल, इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल जियोग्राफी, (लंदन, 1964), पृष्ठ-11 ।

3- इनमें पश्चिमी न्यूगिनी को छोड़ दिया गया है अन्यथा $134^{0} 50'$ के स्थान पर $141^{0} 00'$ पूर्व हो जाएगा तथा पूरा क्षेत्रफल 1732,000 वर्ग मील जिसमें द्वीप समूह का 937,000 वर्ग मील होगा ।

द०पू० एशिया को उत्तर में चीन से तथा पश्चिम में भारत से अलग करती है।[4] द०पू० एशिया का समस्त आर्थिक आधार कृषि है। द०पू० एशिया तुलनात्मक रूप से प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दुनिया के प्राकृतिक रबड़ का लगभग 90 प्रतिशत, टिन का 50 प्रतिशत से अधिक, नारियल का 75 प्रतिशत, खजूर तेल का 55 प्रतिशत, तथा टंगस्टन का 20 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त फिलीपींस व बर्मा में कुछ सोने की खानें भी हैं। इस क्षेत्र में विशेषकर इंडोनेशिया, ब्रुनेई व दक्षिण चीन सागर में तेल का भारी मात्रा में भण्डार है।[5] इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है। यह क्षेत्र प्रशान्त महासागर व हिन्द महासागर के बीच जलमार्ग पर स्थित है।[6]

द०पू० एशियाई क्षेत्र भौगोलिक, भाषायी, धार्मिक रूप से किसी प्राकृतिक इकाई का धोतक व निर्माणकर्ता नहीं है।[7] द०पू० एशियाई समाज पंचमेल समाज है।[8] द०पू० एशिया एक महान विविधता व विषमता का क्षेत्र है। यह एक बहुराष्ट्र, बहुभाषी, बहुजाति, बहुधर्म[9], बहुराजनीतिक प्रणाली, बहु सांस्कृतिक क्षेत्र है फिर

---

4. पी० लुसियान प्यूल्ये, साउथ ईस्ट एशियन पोलिटिकल सिस्टम्स (न्यू जर्सी, 1967) पृ० 8।
5. --वही--, पृष्ठ- 9।
6. चार्ल्स ई० मोरिसन व अस्त्री सुर्के, "आसियान इन रिजनल डिफेंस एण्ड डेवलपमेंट" सुदर्शन चावला व डॉ०आर० सरदेसाई (सं०), "चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सिक्युरिटी एण्ड स्टेबिलिटी इन एशिया, प्रेगर, (न्यूयार्क, 1980) पृष्ठ- 192।
7. हैरिसन, ब्रैन, "साउथ ईस्ट एशिया, ऍ शार्ट हिस्ट्री", मैकमिलन (लंदन, 1966), पृष्ठ- 9
8. लीबी, सुर्यादिनाता, "द चाईनीज माइनॉरिटी एण्ड चाईनी - इंडोनेशियन डिप्लोमैटिक नार्मलाइजेशन" जरनल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, सिंगापुर, ग्रंथ 12, सं० 1, (मार्च 1981), पृ०-197 ।
9. इस्लाम, बुद्धवाद, कन्फ्यूशियसवाद, ईसाई धर्म, हिन्दू धर्म आदि धर्म व वाद हैं जिसमें इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामवादी राष्ट्र है।

भी यह एक ही क्षेत्र माना जाता है जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की समस्त राज्यों की भौगोलिक स्थिति में लगभग एक रूपता व समानता ही कहा जा सकता है। इस क्षेत्र के प्रत्येक दस देशों - बर्मा, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कम्पूचिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैण्ड, वियतनाम में विशिष्ट व अनेक परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा प्रत्येक देश विभिन्न अन्य विविधताओं से गुंथे हुए हैं। किसी देश में एक जैसी जनसंख्या भी नहीं है। दुनिया के किसी क्षेत्र में इस प्रकार का संपन्न व व्यवस्थित प्रमुख धर्मों का मिश्रण देखने को नहीं मिलता। मलेशिया, इंडोनेशिया व ब्रुनेई मुस्लिम देश हैं। इस क्षेत्र में एकमात्र ईसाई देश फिलीपींस है। द०पू० एशिया के बचे मुख्य भू-भाग में बुद्धमतावलम्बी समाज की बाहुल्यता है जिनमें कई विभिन्न मतावलम्बी हैं। इन धार्मिक अन्तरों के पीछे रीति-रिवाजों व ऐतिहासिक अनुभवों का अतिरिक्त भेद समझा जाता है। द०पू० एशिया में 150 से अधिक अलग-अलग भाषाएं व बोलियां हैं जिनमें से अधिकांशतः अबोधगम्य हैं। द०पू० एशिया के समस्त देशों में विविध जातीय पृष्ठभूमि से आए भारी अल्पसंख्यक जनसंख्या है। कुछ देशों में ये जातीय वितरण अपनी विशिष्टता व स्पष्टता के कारण पहचाने जाते हैं जैसे सिंगापुर व मलेशिया में मलय, चीनी व भारतीय।[10]

इस प्रकार की विभिन्न जाति व धर्म के लोगों तथा सांस्कृतिक मिश्रण से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि द०पू० एशिया युगों से एशिया के जनसंचार का मुख्यमार्ग रहा है। दो महान एशियाई संस्कृति - भारत व चीन के जलमार्ग के बीच स्थित होने के कारण द०पू० एशियाई जनता ने एशियाई इतिहास के समस्त मुख्य धारा को प्रभावित किया है। यह क्षेत्र मध्य युग से ही पश्चिमी दुनिया व अन्य देशों के व्यापारियों व वाणिज्य को आकर्षित करते रहे हैं।

द०पू० एशिया के विकास में चीन की भूमिका भारत की तुलना में काफी कम रही है। यद्यपि चीन सांस्कृतिक उपलब्धियों, भौतिक संवर्धनों, या जनसंख्या

10- पी० [illegible], इसियान हव्यू०, सं०-4, पृष्ठ- 1।

के स्तर पर भारत से निकृष्ट नहीं रहे हैं । प्राचीन समय से ही जैसा कि दक्षिणी चीन समुद्र व हिन्द महासागर के बीच व्यापारिक समुद्री मार्गों से प्रतीत होता है कि चीन अगम्य भी नहीं था ।[11] परन्तु इस विषय पर विद्वानों के विचारों में मतभेद है । के० एम० पन्निकर के विचार में, " यह सम्पूर्ण क्षेत्र, सम्भवत: बर्मा इसका अपवाद रहा हो, पहली शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक राजनीतिक रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहा ।"[12] जबकि सुनयातसेन व च्यांग काई शेक ने द०पू० एशिया की मुख्य भूमि की चीन के साथ ऐतिहासिक संबंध पर बल दिया है ।[13]

द०पू० एशिया का चीन से संबंध हजारों वर्ष पुराना है । प्राचीन समय से ही द०पू० एशियाई देशों पर चीन का सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव रहा है । पूर्वी बोर्नियो, पश्चिमी जावा तथा दक्षिणी सुमात्रा में काफी संख्या में हान वंश (207 ईसा पूर्व - 221 ई) के चीनी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो चीन व द०पू० एशिया के प्रत्यक्ष संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं । इन पुरातत्व खोजों से स्पष्ट होता है कि द०पू० एशिया व चीन के व्यापारिक संबंध पहली शताब्दी ईसा पूर्व या शायद तीन सौ ई० पू० के तांग हान काल से रहा होगा ।[14]

लगभग 1000 ई०पू० तक चीन का राज्य क्षेत्र यांग जू नदी तक ही सीमित था । इसके बाद चीनी दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारम्भ किए जिसे उस समय के राजनीतिक भाषा के अनुसार साम्राज्यवादी अथवा विस्तारवादी नहीं कह सकते । इस प्रकार चीनी या तो दक्षिण के स्थानीय लोगों को अपने अधीन कर लेते या फिर उन्हें दक्षिण की ओर नए जीवन की तलाश में जाने को विवश कर देते । ईसा की पहली शताब्दी तक चीनी 18वें या 17वें अक्षांश तक आ गए थे । उस समय चीन

11- विलियम्स, लिया ई०, साउथ ईस्ट एशिया:अ हिस्ट्री ", आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, (न्यूयार्क, 1976) पृष्ठ- 35 ।

12- पन्निकर, के० एम०, " द फ्यूचर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया," (न्यूयार्क, 1943) पृष्ठ- 1 ।

13- च्यांग काई - शेक, "चाईनाज डेस्टिनी ", (न्यूयार्क, 1947) पृष्ठ-770

14- हैरिसन, सं०-7, पृष्ठ- 10 ।

व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान व व्यापार विकास हो रहा था। इस प्रकार कुछ चीनी व्यापारियों व सिपाहियों का द०पू० एशिया में काफी दिनों से रहते हुए उनके एक समुदाय का प्राकृतिक रूप से विकास होने लगा तथा चीनी प्रवासियों की संख्या द०पू० एशियाई देशों में बढ़ने लगी। पांचवी-छठवीं शताब्दी में बौद्ध धर्मावलंबी चीनी बौद्ध भिक्षु जो चीन से द०पू० एशिया होते हुए तीर्थयात्रा व अध्ययन हेतु भारत आते थे। वे सुमात्रा आदि स्थानों पर कुछ समय के लिए आराम, संस्कृत भाषा के अध्ययन, व अपनी लम्बी यात्रा के बाद नौका की बदलने के लिए रुका करते थे। 1292 में मंगोल सम्राट कुबलाई खान चीन जीत कर जावा व सुमात्रा को भी जीतना चाहता था पर वह भौगोलिक दूरी व अन्य कारणों से असफल रहा। पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मिंग वंश के सम्राटों ने द०पू० एशिया में कई बड़े अभियान भेजे जिसका उद्देश्य चीनी शक्ति का प्रदर्शन, राजकीय शिष्टमण्डल और व्यापार था।[15]

द०पू० एशियाई देशों के लिए उत्तर में स्थित चीन हमेशा से ही खतरा ड्रैगन के रूप में दिखता रहा है। द०पू० एशियाई देशों में रह रहे लगभग दो करोड़ प्रवासी चीनी द०पू० एशियाई लोगों के लिए एक स्थाई खतरा बने हुए हैं।[16] ये प्रवासी चीनी मुख्यतः चीन के द० पूर्वी प्रान्त क्वांग तुंग, फ्यूकियन व क्वांग सी से आए। जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का अतिदाब तथा इन क्षेत्रों का द०पू० एशियाई क्षेत्रों से मिला होना था, तथा उन्नीसवीं शताब्दी में हुए चीन में ताइपिंग आंदोलन से उभरी आर्थिक पृष्ठभूमि व सामाजिक स्थिति भी कारण था। इसके अतिरिक्त चीन के अन्य आन्तरिक कारण भी चीनियों के दक्षिण की तरफ आने के मुख्य कारण थे।[17] चार्ल्स फिशर के कथनानुसार द०पू० एशिया एक उष्ण कटिबंधी

15- स्पीड, स्पा० डब्ल्यू०, "द साउथ ईस्ट एशियन पेनिनसुला टुडे" आंगुस एण्ड राबर्टसन, (लंदन, 1970) पृष्ठ- 60।

16- - वही - ,, पृष्ठ- 63।

17- परसल, विक्टर, "द चाईनीज इन साउथ ईस्ट एशिया, द्वितीय संस्करण (लंदन, 1965) पृष्ठ- 24।

क्षेत्र है, तथा भूमध्य रेखा के समीप रहने व चारों ओर से समुद्र से घिरे रहने व मानसूनी मौसम के कारण यहां का वातावरण काफी आर्द्र रहता है जिससे वहां की स्थानीय जातीय जनसंख्या सुस्त व अमेहनतकश होती है। ये विदेशी कंपनियों में स्थाई रूप से मासिक वेतन पर काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते थे इसलिए उन कंपनियों को मुख्य रूप से आप्रवासी चीनी या भारतीय मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था जिससे इनकी मांग बढ़ती गयी तथा चीनी द०पू० एशिया में मजदूर या अन्य रूप में इस क्षेत्र में आकर बसने लगे।[18]

चीनी हमेशा यह चाहते रहे हैं कि उन्हें हर तरह से सर्वोच्च, "पूरब की दुनिया में केवल एक ही सूरज चीन" को माना जाए, अन्य सभी अशिष्ट हैं। चीनी सम्राट प्रायः द०पू० एशियाई राज्यों को अपने अधीन मानते थे। जो विशेष अवसरों पर चीनी सम्राट को शिष्टमण्डल व राज्य शुल्क के रूप में कीमती उपहार भेजते थे। ये चीनी अधीन राज्य स्वतंत्र थे। उन्हें आपस में लड़ने की तब तक पूरी छूट थी जब तक उनका अन्तर्विरोध चीनी सम्राट को प्रभावित न करता हो।[19] चीन पूरे द०पू० एशिया में लगभग पिछले दो हजार वर्षों से ऐतिहासिक रूप से सक्रिय रहा है।[20] एफ० डब्ल्यू० स्पीड के मतानुसार प्रवासी चीनी अपने चीनीपना को कभी नहीं त्यागते। वे जहां भी रहते हैं अपना अलग समुदाय-समूह बनाकर रहते हैं जिससे उनका चीनीपना बना रहे। प्रवासी चीनी अपने चीन में रह रहे मूल परिवारों से किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य रखते हैं। कुछ प्रवासी चीनी तो चीन की धरती पर ही मरना चाहते हैं।[20]

18- फिशर, सं० 2, पृष्ठ- 3।

19- स्पीड, सं० 15, पृष्ठ-65।

20- क्लार्क, ग्रेगरी, "इन फीयर ऑफ चाईना", बेरी एण्ड राकलिफ्ट, द क्रिसेंट प्रेस, (लंदन, 1967) पृष्ठ-136।

21- स्पीड, सं० 15, पृष्ठ- 66।

इसी क्रम में ललिता प्रसाद सिंह चीनियों की अंधराष्ट्र भक्ति के बारे में लिखते हैं :---

"प्रवासी चीनी अपने आपको चीन के अर्ध-स्थायी भूतपूर्व देशभक्त के रूप में समझते हैं जिसका 'घर' दक्षिण चीन के किसी काल्पनिक गांव के कोने में है वैसे उनके दादा भी द०पू० एशिया में ही पैदा हुए होंगे। उनकी यह हार्दिक इच्छा होती है कि उनकी मृत्यु चीन में ही हो। जिस प्रवासी चीनी की दुर्भाग्यवश चीन में मृत्यु नहीं होती वह चाहता है कि उसकी हड्डियों को चीन की धरती में दफना दिया जाए, जिस धरती को उसने कभी देखा भी नहीं है। हांगकांग के कार्पोरेशन होटल में सैकड़ों चीनियों की शव पेटिका चीन भेजने के लिए पड़ा रहती हैं जिसे उनके उस गांव में भेजा जाता है जहां से उनका परिवार कभी आया था।"[22]

चीन के दक्षिणी प्राय:द्वीपों या द्वीपों पर पारम्परिक चीनी सभ्यता व कन्फ्यूशियस के विचारों के प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में चीनी प्रभाव रहा है। जैसा कि विदित है कि चीनी अपनी सांस्कृति का अपनी चीनी दुनिया के सीमा से बाहर निर्यात नहीं करते। उससे यह स्पष्ट होता है कि द०पू० एशिया में चीनी प्रभाव प्राकृतिक रूप से रहा है। जिससे चीनी द०पू० एशिया पर अपना विशेष अधिकार मानते हैं।[23]

यूरोपीय उपनिवेश का आगमन

आसियान क्षेत्र मुख्यत: मलय प्रभुत्व क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक श्री विजया साम्राज्य का आधिपत्य था। इसके बाद माजापाहित साम्राज्य का आसियान क्षेत्र पर सोलहवीं शताब्दी तक राज्य रहा। सोलहवीं शताब्दी में पश्चिमी उपनिवेशवादियों के आगमन के कारण व उनकी इच्छा से इस क्षेत्र में नयी क्षेत्रीय सीमाएं बनीं इसके परिणामस्वरूप लोगों का

22- सिंह, ललिता प्रसाद, 'पार्टी पॉलिटिक्स एण्ड साउथ ईस्ट एशिया', रेडिएन्ट पब्लिशर्स, (नई दिल्ली, 1979) पृष्ठ-59।

23- विलियम्स, सं० 11, पृष्ठ- 35।

पुनर्वितरण हुआ जिससे जातीय समूह अलग-अलग हो गए ।[24]

द०पू० एशिया जैसा कोई देश या क्षेत्र नहीं है जहां बड़ी शक्तियों का इतना भीषण प्रतिस्पर्धा, प्रभाव व नियंत्रण रहा हो । यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से "अल्प दाब क्षेत्र" के रूप में जाना जाता रहा है । इस क्षेत्र में विभिन्न बड़ी शक्तियों का सदैव से ही बाह्य प्रभाव रहा है । भौगोलिक रूप से निकटस्थ दो महान परम्परागत शक्तियाँ भारत व चीन का यौरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों के आगमन के पश्चात पांव द०पू० एशिया से उखड़ गए । द०पू० एशियाई क्षेत्र, थाईलैंड को छोड़कर विभिन्न यौरोपीय शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया , जैसे-पुर्तगाली , स्पेनिश (बाद में अमरिकी) , डच, ब्रिटिश, फ्रेंच ।[25]

इसके साथ-साथ चीन की संप्रभुता पर भी असर पड़ा तथा पश्चिमी उपनिवेशवादी ताकतों ने चीन के राज्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर, कई प्रकार के व्यापारिक व संस्थाओं के माध्यम से चीन का शोषण करने, चीन के साथ असामान्य संधियां करने, तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए चीन को बाध्य किया । जो चीनी नियंत्रण के बाहर था ।[26] इससे चीनी छवि बिगड़ने लगी ।[27]

उपनिवेशिक काल में इसके बावजूद कि सभी देश मजबूत व दृढ़ धार्मिक, भाषायी व अन्य प्रकार के संबंधों से जुड़े हुए थे फिर भी उन पर उन उपनिवेशक देशों की संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ा जैसे हिन्द-चीन में फ्रांस का, इंडोनेशिया पर हालैंड का, बर्मा, मलेशिया व सिंगापुर पर ब्रिटेन का तथा फिलीपींस पर स्पेन व संयुक्त

24- राउल, ई० वनिकान, "आसियान, द नेशनल कम्युनिटी", एशिया पेसिफिक कम्युनिटी" (तोक्यो) सं० 2 फाल 1978, पृष्ठ-46 ।

25- अरोड़ा, म०दास, " इन्डो-चाइना, आसियान एण्ड ग्रेट पावर्स ", मेनस्ट्रीम (नयी दिल्ली) प्रति-22 सं० 28 (मार्च 10, 1984) पृ०-24 ।

26- स्पीड, सं०- 15, पृष्ठ-67, पु० पे० क्लार्क, सं० 20, पृष्ठ-18 ।

27- क्लार्क, सं०-20, पृष्ठ-18 ।

राज्य अमेरिका का सांस्कृतिक, सामाजिक आदि, इन देशों में केवल थाईलैंड कभी किसी देश के पराधीन नहीं रहा फिर भी ऐसा समझा जाता है कि किसी न किसी तरह से वह यौरोप के प्रभाव क्षेत्र में रहा । इन चार सौ वर्षों के पराधीनता के दौरान इन देशों के बीच कुछ मतभेद भी विकसित हुए जिसे हम आज भी देख सकते हैं ।[28]

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही अमेरिकी व यौरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों के गढ़ एक के बाद एक समाप्त होने लगे तथा वे जापानी "महान पूर्वी एशिया सह-समृद्धि मण्डल" के अन्दर आकर सिमट कर रह गए । यह द०पू० एशिया के इतिहास में पहला अवसर था जब सम्पूर्ण द०पू० एशियाई क्षेत्र की जनता केवल एक शक्ति के प्रभुत्व के नीचे आ गई हो । द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति से न केवल द०पू० एशिया में एक शक्ति के प्रभुत्व की समाप्ति हुई अपितु इस क्षेत्र में एक नए युग का श्रीगणेश भी हुआ । इस राजनीतिक उथल-पुथल आदि के कारण तथा जापानी आधिपत्यान्तर्गत द०पू० एशिया के देशों को स्वतंत्र होने के लिए एक अवसर मिला ।[29]

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में एक के बाद एक स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी । 17 अगस्त, 1945 को इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली, 3 सितम्बर, 1945 को ही हो चि मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक वियतनामी गणतंत्र की घोषणा कर दी गयी । 4 जुलाई, 1946 को फिलीपींस 15 अगस्त, 1947 को भारत, 4 जनवरी, 1948 को बर्मा को स्वतंत्रता मिली । माओ त्से तुंग व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 1 अक्तूबर 1949 को चीन लोकगणराज्य की स्थापना हुई । चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना, द०पू० एशियाई देशों के लिए एक चुनौती थी । साम्यवादी चीन द०पू० एशियाई देशों की स्वतंत्रता को नकली स्वतंत्रता मानता था । चीन के लिए स्वतंत्रता का अर्थ सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में वर्ग-संघर्ष के माध्यम से साम्यवादी आंदोलन के फलस्वरूप प्राप्त पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता से था । समस्त द०पू० एशिया के देश चीनी

28- राउल, सं0 24, पृष्ठ- 46 ।

29- अरोड़ा, सं0 25, पृष्ठ-24 ।

साम्यवाद के सम्भावित विस्तार से डरे हुए थे ।[30]

द्वितीय महायुद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्ति खेमों -- सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका में बट गई । ये दोनों महाशक्तियां तीसरे विश्व युद्ध के संभावित खतरे के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी । 4 अप्रैल 1949 को अमेरिकी खेमे ने नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन (नाटो) का निर्माण किया जो वास्तव में पश्चिमी गैर साम्यवादी देशों की सोवियत साम्यवादी विस्तार के आक्रमण के विरुद्ध एक सैनिक संधि थी ।[31]

अक्तूबर 1950 में चीन की अपने पड़ोसी देश कोरिया में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति के कारण पूरे द०पू० एशियाई देशों में एक आतंक का वातावरण छा गया । हालांकि चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुए अभी केवल एक वर्ष ही हुए थे ।[32]

चीन द०पू० एशिया में साम्यवादी क्रान्ति के लिए हर संभव प्रयास करता रहा । दूसरी ओर चीनी साम्यवादी खतरे के प्रतिरोध में अमेरिका विभिन्न प्रकार के सैनिक संधि करता रहा । अमेरिका ने साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए चीन का विरोध एवं नाकाबंदी कर तथा हिन्द-चीन में युद्ध चलाकर अपने आधिपत्य को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में शीत युद्ध का सिलसिला आरंभ

30- कृ०पे० सुलह अब्दुल रहमान, "द कम्युनिस्ट थ्रेट इन मलेशिया एण्ड साउथ ईस्ट एशिया", पैसिफिक कम्युनिटी, (टोक्यो) ग्रंथ 8, अंक-4, (जुलाई 1977) पृष्ठ- 571 ।

31- पाण्डेय, बी० एन०, "साउथ एण्ड साउथ-ईस्ट एशिया, 1945-79, प्रोबलेम्स एण्ड पोलिटिक्स", (नयी दिल्ली, 1980) पृष्ठ-151

32- क्लार्क, सं०-20, पृष्ठ- [illegible]27 ।

हुआ । इसके परिणाम स्वरुप अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हावर के 'डोमिनी सिद्धान्त'[33] का प्रतिपादन हुआ । अमेरिका के विदेश सचिव जान फास्टर डुल्लस (1953-59) के नेतृत्व में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (सीटो) की स्थापना आठ सितम्बर 1954 को मनीला समझौते के अन्तर्गत हुई । इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले आठ सदस्य थे दो देश फिलीपींस व थाईलैण्ड थे जो आज आसियान के सदस्य हैं । सीटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रुप में बनाया गया था । इसका मुख्यालय बैंकाक में था जिसके मुख्य दो कार्य थे -- इसके दो सदस्यों द०पू० एशियाई देश- थाईलैंड व फिलीपींस को निश्चित आर्थिक सहायता देना तथा साम्यवाद विरोधी व प्रति-विद्रोही गतिविधियों के लिए योजनादि बनाना तथा इसके सैनिक योजना कार्यालय में जिसमें सदस्य देशों के वरिष्ठ उच्च सैनिक अधिकारी थे जिनका मुख्य कार्य हिन्द-चीन में साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध इस संधि की ओर से उनके प्रतिरोध हेतु योजनाओं का निर्माण करना था ।[34] सीटो का प्रमुख उद्देश्य कम्पूचिया, लाओस, व द० वियतनाम को साम्यवादी खतरे से बचाना तथा इसके अतिरिक्त अन्य द०पू० एशियाई देशों को साम्यवादी खतरे से रक्षा करना था ।[35] इस प्रकार साम्यवाद विरोधी अमेरिकी खेमे ने नाटो, सीटो, सेंटो[36] (सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) व अन्य संधियों के माध्यम से नार्वे से फिलीपींस तक सोवियत, चीनी व उत्तरी वियतनामी साम्यवाद की नाकाबंदी कर दी ।[37]

33- इस सिद्धान्त के अनुसार-द०पू० एशियाई देश भौगोलिक रुप से एक दूसरे से इस प्रकार से मिले हुए हैं कि अगर एक साम्यवादी क्रान्ति की चपेट में आ गया तो द०पू० एशिया के अन्य देश में भी एक के बाद एक साम्यवादी लहर फैल सकती है । पाण्डेय, सं० 31, पृष्ठ-152 ।

34- लेसजेक बुजीनस्की, "सीटो : व्हाई इट सरवाइव्ड अनटिल 1977 एण्ड व्हाई इट वाज एबालिश्ड", जरनल आफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, सिंगापुर युनिवर्सिटी प्रेस, (सितम्बर 1981) पृष्ठ-287 । प्रति 12, अंक 2 ।

35- पाण्डेय, सं०-31, पृष्ठ-152 ।

36- सेंटो- 1955 में हुए बगदाद संधि का परिणाम था जिसके सदस्य देश-ब्रिटेन, ईराक, ईरान, पाकिस्तान व तुर्की थे । परन्तु 1958 में ईराक ने सेंटो से अपनी सदस्यता वापस ले ली ।

37- पाण्डेय, सं०-31, पृ० 152 ।

इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने भी वारसॉ पैक्ट आर्गनाइजेशन की 1955 में स्थापना की, जो एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी तथा पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों की रक्षा के रूप में बनायी गयी थी।[38]

द०पू० एशिया में साम्यवादी क्रान्ति के संभावित खतरे को दूर रखने के लिए उपनिवेशवादियों ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र कर देने या उस तत्कालिक शासन व्यवस्था में ढील देने, जिससे साम्यवादी विचार को आने या उभरने से रोका जा सके, का प्रयत्न करने लगे। द०पू० एशिया के साम्यवादियों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता में रुचि लेना पश्चिमी उपनिवेशवादियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था।[39] इसके परिणाम स्वरूप 31 अगस्त, 1957 को मलेशिया को मिली स्वतंत्रता थी।

द०पू० एशिया के इस शताब्दी के पाँचवे दशक में, चीन के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे, परन्तु उत्तरी वियतनाम, बर्मा व इंडोनेशिया इसके अपवाद देश थे, इसका मुख्य कारण था चीनी साम्यवाद का द०पू० एशिया में विस्तार की संभावनाएं जिसकी शुरुआत उत्तरी वियतनाम में हो चुकी थी। द०पू० एशिया व चीन संबंध में तथा द०पू० एशिया की विदेश नीति निर्धारण में हिन्द-चीन आमतौर पर तथा वियतनाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण व प्रमुख तत्व था। साम्यवादी चीन को सामान्यत: वियतमिन्ह व उत्तरी वियतनाम पर हमलावर की दृष्टि से देखा जाता था तथा साम्यवादी चीन सरकार को प्राचीन समय से उपनिवेशवादी देश के रूप में माना जाता था और इसीलिए यह द०पू० एशियाई देशों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बना हुआ था।[40]

प्रारम्भ से ही द०पू० एशियाई देश विशेषकर थाईलैण्ड व फिलीपींस, दक्षिण वियतनाम की अमेरिकी समर्थित सरकार की सहायता व समर्थन करते रहे क्योंकि

38- वही, पृष्ठ-152।

39- काल्वर्ट रोलिंग, "साउथ ईस्ट एशिया एन इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स 1945-56", कार्नेल युनिवर्सिटी प्रेस, (लंदन 1977) पृष्ठ- 125।

40- वैने, विलकाक्स, लियो ई० रोज़, गैविन बायड, "एशिया एण्ड द इन्टरनेशनल सिस्टम", विन्थरोप पब्लिशर्स, (कैम्ब्रिज, 1972) पृ०-189।

वे यह समझते थे कि हिन्द-चीन में साम्यवादी शासन की मौजूदगी द०पू० एशिया की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख खतरा होगा ।

अप्रैल 1955 में बानडुंग में हुए प्रथम अफ्रो-एशियाई सम्मेलन से एशिया में तथा विशेषकर द०पू० एशिया में अमेरिकी विरोधी वातावरण तैयार करने में चीन को एक सुअवसर प्राप्त हुआ । साम्यवादी चीन की नीति थी कि वह सीटो के इस अफवाह को गलत सिद्ध करे कि साम्यवादी आक्रमण का खतरा द०पू० एशिया में बना हुआ है । इसलिए चीन ने " शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व " पर बल दिया जिससे द०पू० एशिया के छोटे देश विशेषकर थाईलैण्ड अमेरिका के साथ सैनिक संधियों में कटौती कर सकें ।[41]

सन् 1958 में कम्पूचिया ने साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी । 1959 को लाओस में उभरी समस्या, जो 1962 तक समाप्त न हो सकी, सीटो की प्रामाणिकता को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रही थी । द०पू० एशिया के दो सीटो सदस्य व अमेरिका ने लाओस में साम्यवाद को रोकने में काफी प्रयत्न किए पर असफल रहे । इस प्रकार सीटो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल-सा दिखाई देने लगा क्योंकि अमेरिका के लिए यह काफी कठिन था कि वह चीन व सोवियत संघ के साथ पहाड़ों से ढके वीरान जंगल में लड़े । इस प्रकार राष्ट्रपति जान केनेडी प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ती देख तटस्थ लाओस बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर बातचीत की पहल की । द०पू० एशियाई सीटो सदस्यों को इससे काफी आश्चर्य हुआ कि अमेरिका अपनी वचनबद्धता के अनुसार लाओ राजशाही को बचा न सका । इस घटना से थाईलैंड सर्वाधिक चिंतित हो गया । थाईलैंड व अमेरिका दोनों ही थाईलैंड की स्वतंत्रता, अखण्डता व साम्यवादी विद्रोह के भय से सचेत होकर सामूहिक रूप से 1962 के बाद के वर्षों में सामरिक समस्याओं पर काफी गंभीरता से जुट गए । इस अवसर का लाभ उठाते हुए अमेरिका ने थाईलैंड में उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध उपयोग में आने वाले समस्त

---

41. <u>वही</u>, पृष्ठ- 189 ।

सैनिक सुविधाओं का उपयोग किया । इसी अमेरिका ने थाईलैण्ड को अपना सैनिक अड्डा बना लिया ।[42]

क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण

द०पू० एशिया में अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा आंतरिक व बाह्य असुरक्षा से संगठन बनाने की प्रवृत्ति को बल मिलना स्वाभाविक व सहज ही था । इस मानसिकता का स्पष्ट दर्शन इस क्षेत्रीय सहयोग के नाम पर 31 जुलाई 1961 को बैंकाक में बने एसोसियेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया[43] (आसा) से कर सकते हैं । यह द०पू० एशिया का पहला क्षेत्रीय संगठन था । आसा के निर्माता सदस्य देश- मलाया[44], फिलीपींस व थाईलैण्ड थे । इन देशों के बीच फिर भी कुछ अन्तर्विरोध रहे जैसे उत्तरी बोर्नियो सबाह के प्रश्न पर फिलीपींस व मलाया के बीच[45] क्षेत्रीय सहयोग पर बल देते हुए कहा गया कि " समस्त द०पू० एशियाई देशों की अपनी शक्ति, राजनीतिक ढांचा, आर्थिक व्यवस्था, मानवीय व भौतिक साधनों की मजबूत व विकसित करना चाहिए । वे इसे व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं पर वे इसे सामूहिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ठीक तरह से कर सकते हैं ।"[46]

द०पू० एशिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व बड़े देश इंडोनेशिया ने आसा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया । आसा की सफलता इंडोनेशिया की सदस्यता पर निर्भर करती थी । मलेशियाई नेताओं के विचार में क्षेत्रीय सहयोग इंडोनेशिया की सदस्यता के बिना यथार्थवादी न था ।[47]

42- वही, पृष्ठ- 191 ।

43- फेडरेशन आफ मलाया के प्रधानमंत्री तुनकु अब्दुल रहमान जब जनवरी 1959 में फिलीपींस की यात्रा पर राष्ट्रपति कार्लोस पी० गर्सिया से मिले तो उन्होंने तीनों देशों की आपसी सहयोग पर बातचीत करने पर बल दिया जिससे उन देशों की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके तथा घनिष्ट सहयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, आसा इसी बातों का उत्पादन था ।

44- सितम्बर 1963 के पहले फेडरेशन आफ मलाया था, फिर मलेशिया

आसा को द०पू० एशिया का पहला क्षेत्रीय सहयोग संगठन होने के कारण आसियान जैसा बड़ा संगठन बनाने का रास्ता दिखाने का श्रेय प्राप्त है । आसा आसियान का आधारशिला है ।[48]

1963 में सबाह के बारे में मलेशिया व फिलीपींस के बीच हुए विवाद के कारण आसा निष्क्रिय हो गया । परन्तु जब 1966 में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार आया तो आसा पुनः सक्रिय हो गया तथा उनके विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक बैंकाक में अगस्त 1966 में हुई । आठ अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना के बाद आसा के सदस्यों ने इसे समाप्त कर दिया तथा आसियान में आसा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना जारी रखा ।[49]

द०पू० एशिया का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन अगस्त 1963 में मनीला में मफिलिन्डो[50] बना, जो एक राजनीतिक आवश्यकता थी ।[51] मफिलिन्डो के सदस्य

- बना जिसमें फेडरेशन आफ मलाया, सबाह, साराबाक व सिंगापुर राज्य थे । सिंगापुर, 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग हो गया । द्र०दे० पी० लुसियान, सं०-4, पृष्ठ-4-5 ।

45- डैने, लीयो, गेविन, सं०-40, पृष्ठ- 194 ।

46- फॉरेन अफेयर्स बुलेटिन, थाईलैण्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, (अगस्त-सितम्बर 1961) पृष्ठ- 34 ।

47- एल०जी० मैजेरिक, (सं०) , "मलेशिया-इंडोनेशिया कनफिल्कट" इन्टरनेशनल रिव्यु सर्विस (न्यूयार्क), ग्रंथ 11, सं० 86, 1965, पृ० 105 में उद्धृत ।

48- द बैंकाक क्रिलरेशन, 31 जुलाई 1961 ।

49- एस्टेला डी, सॉलिड्स, "टुवर्ड्स ए साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी," युनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस प्रेस, (क्वेजन सीटी, 1974) पृष्ठ-29 ।

50- मफिलिन्डो शब्द तीन देशों के नाम के प्रथम स्वनिमों को मिलाकर बनाया गया है - मलाया, फिलीपींस व इन्डोनेशिया ।

51- उस समय मलाया का फिलीपींस व इंडोनेशिया के साथ बोर्नियो के ऊपर

देशों- मलेशिया , फिलीपींस व इंडोनेशिया , मफिलीन्डो के उद्देश्यों में तीनों देशों को उनकी राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने, शान्तिपूर्ण विकास की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के तोड़-फोड़ चाहे वह किसी रूप में हो से बचने के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता व सुरक्षा हेतु सामूहिक रूप से प्रत्येक देश की बुनियादी रूप से जिम्मेदारी निभाने पर बल दिया गया था । मफिलीन्डो ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से तथा पूरे विश्व में सामान्य रूप से उपनिवेशवादियों तथा साम्राज्यवादियों के प्रत्येक प्रकार के स्वार्थी गतिविधियों के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष में अपनी प्रवासियों की एक जुट करने का आह्वान किया ।[52]

आसियान देशों में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है तथा इंडोनेशिया की आसियान के निर्माण व आसियान-चीन संबंध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । इन पाँचों आसियान देशों में केवल इंडोनेशिया ही एक मात्र देश था जिसने चीन के साम्यवादी सरकार को मान्यता दे रखी थी । इसलिए इंडोनेशिया व चीन के संबंधों की पृष्ठभूमि की अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

इंडोनेशिया में प्रवासी चीनियों से संबंधित विवादास्पद समस्याओं के कारण इंडोनेशिया व साम्यवादी चीन के साथ संबंधों की कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी । इंडोनेशिया काफी समय तक चीन लोकगणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने से हिचकिचाता रहा । परन्तु 1950 में इंडोनेशिया ने चीन को राजनयिक मान्यता दे दी । इसका चीन ने गलत प्रयोग किया । चीन ने इंडोनेशिया में अनाधिकारिक रूप से वाणिज्य दूतावास खोलकर इंडोनेशिया के स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी (पी०के०आई०)[53] को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की । पी०के०आई० एक सरकार विरोधी पार्टी थी । परिणामस्वरूप इंडोनेशिया व चीन के बीच राजदूतों को

विवाद काफी बढ़ चुका था इसलिए इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता पड़ी । इंडोनेशिया द्वारा चलाए गए सैनिक कनफ्रंतासी के समय तुनकु अब्दुल रहमान ने तोक्यो में राष्ट्रपति सुकार्नो से 1963 में भेंट की तथा अपनी समस्याओं को विश्वास के साथ सुलझाने पर सहमत हो गए, मफिलीन्डो इसी का परिणाम था ।

52- पैगिरो, सं० 47, पृष्ठ-105 ।

आदान प्रदान में विलम्ब हो गया । अक्तूबर 1953 में दोनों देशों के राजदूतों का आदान-प्रदान हो सका । 1954 में इंडोनेशियाई सरकार ने चीन के साथ इंडोनेशिया में पैदा हुए चीनियों को इंडोनेशियाई नागरिकता देने के जटिल प्रश्न पर बातचीत की शुरुआत की । इंडोनेशिया की सरकार केवल उन्हीं चीनियों को नागरिकता देना चाहती थी जो चीनी राष्ट्रीयता को त्यागना चाहते थे । जब चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाइ बानडुंग सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया गए हुए थे तो उन्होंने अत्यंत ही मैत्रीपूर्ण सद्भाव के साथ इंडोनेशियाई सरकार के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की तथा 22 अप्रैल 1955 को एक संधि पर हस्ताक्षर किया । इस संधि के अनुसार इंडोनेशिया में पैदा हुआ चीनी पूरी तरह इंडोनेशियाई नागरिकता या चीनी नागरिकता का चुनाव कर सकता है और अगर संधि के दिन से दो वर्ष के अन्दर वह इन दोनों में से एक की नागरिकता का चुनाव नहीं कर लेता तो ऐसे नागरिक को उसके पिता की नागरिकता मिल जायेगी ।[54] इंडोनेशिया में इस संधि के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । यह दिसम्बर 1957 में ही जाकर अनुसमर्थित हो सकी ।

1956 की पेइचिंग यात्रा में राष्ट्रपति सुकार्नो चीनी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली से अत्यन्त प्रभावित हुए । राष्ट्रपति सुकार्नो ने इंडोनेशियाई "नव शैली लोकतंत्र" के लिए चीन को एक नमूने के तौर पर देखा । उनका "गाइडेड डिमाक्रेसी" का विचार भी साम्यवादी चीनी प्रणाली से प्रेरित था । चीन से प्रभावित होकर राष्ट्रपति सुकार्नो ने पेइचिंग के साथ संबंधों को विकसित करने पर काफी बल दिया। इसका एक कारण यह भी था कि पश्चिमी इरियन के प्रश्न पर इंडोनेशिया को चीन का समर्थन भी प्राप्त करना था । पेइचिंग ने इन विकसित संबंधों का उपयोग, इंडोनेशियाई जनता को मलेशिया व पश्चिमी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण मानसिकता हेतु उत्तेजित किया ।[55] इसके बावजूद इंडोनेशियाई सरकार ने कई आर्थिक नीतियों को अपनाया । यह स्थानीय चीनी समुदाय के लाभ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी।

53- परलाई कम्युनिस इंडोनेशिया ।

54- हेराल्ड सी० हिन्टन, "कम्युनिस्ट चाइना इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स", (बोस्टन : हाउटन मिफलिन, 1966) पृष्ठ-42 ।

55- साइमन, शेल्डन डब्ल्यू० "द ब्रोकेन ट्राइंगल : पेकिंग, जाकार्ता, एण्ड द पी०के०आई०, (वाशिंगटन, 1969) पृष्ठ-37 ।

चीन ने ऐसे असमान्य मापदण्ड का विरोध किया । इंडोनेशिया में चीनी राजनयिकों ने चीनियों की आर्थिक अधिनियम का पालन करने के लिए कहा तथा इंडोनेशियाई कम्यूनिस्ट पार्टी (पी०के०आई०) की इस भूमि पर आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव डाला, पर इसका कोई परिणाम न निकल सका ।[56] इन समस्त विवादों व असहमति के बावजूद चीनी विदेश मंत्री चाउ ई के जाकार्ता यात्रा के दौरान 1961 में सांस्कृतिक संबंधों पर एक समझौता के लिए एक मैत्री-संधि पर हस्ताक्षर किया गया । दोनों देशों ने एक दूसरे के दावे व अधिकार का समर्थन किया जैसे चीन का ताइवान पर दावा व संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का अधिकार तथा पश्चिमी इरियन पर इंडोनेशिया का दावा आदि । परन्तु जब इंडोनेशिया का मलेशिया के साथ विवादों का प्रारम्भ हुआ दिसम्बर, 1964 में मलेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् का सदस्य चुन लिया गया, परिणाम स्वरूप इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली । पेकिंग ने इंडोनेशिया की इस नीति की प्रशंसा की तथा इंडोनेशिया को चीन ने 5 करोड़ अमेरिकी डालर की आर्थिक सहायता दी जिसे बाद में इंडोनेशिया को संयुक्त राष्ट्र से हटने पर अर्थदण्ड के रूप में देना पड़ा । पेकिंग ने मलेशिया के साथ हुए विवाद में इंडोनेशिया का समर्थन किया तथा पी०के०आई० को निर्देश दिया कि मलेशिया से संबंधित इंडोनेशिया की नीति के साथ अपनी नीतियों का सामंजस्य करे । चीन ने राष्ट्रपति सुकार्नो की न्यू एमर्जिंग फोर्सेज(नेफो) व गेम्स ऑफ दॅ न्यू एमर्जिंग फोर्सेज (जैनफो) आदि जैसी गतिविधियों का समर्थन किया । इसी बाद से ही चीन अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने लगा । पी०के०आई० से चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी काफी उत्साही हुई । परिणामस्वरूप चीनियों ने पी०के०आई० के किसानों व मजदूरों की हथियार देने की मांग का समर्थन किया । यद्यपि इंडोनेशियाई सेना ने इसका विरोध किया । ऐसा समझा जाता है कि पी० के० आई० के नेताओं के अनुरोध पर चीनी नेता चऊ अन लाइ ने राष्ट्रपति सुकार्नो को इंडोनेशियाई सेना के पांचवें अंग के निर्माण के बारे में राय दी । इस पांचवें सेनांग में इंडोनेशियाई

56- वही, पृष्ठ- 38 ।

युवकों, छात्रों व पी०के०आई० के अन्य शाखा[57] समर्पित लोगों की भर्ती करने की बात थी । पी०के० आई० ने राष्ट्रपति सुकार्नो को यह बताने की कोशिश की कि सेना उनकी सरकार के विरुद्ध राज्य विप्लव के षड्यंत्र में लगी हुई है ।[58]

30 सितम्बर 1965 में इंडोनेशियाई-कम्युनिस्टों द्वारा एक असफल राज्य विप्लव[59] हुआ । इस स्थिति को सेना ने सम्भाल लिया तथा हजारों कम्युनिस्टों व स्थानीय चीनियों की हत्या कर दी गयी । सेना ने पूरे इंडोनेशिया पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया । देश का प्रशासन राष्ट्रपति सुकार्नो ने जनरल सुहार्तो के हाथों सौंप दिया । जब चीन समझ गया कि राष्ट्रपति सुकार्नो अब इंडोनेशियाई सैनिकों से पी० के० आई० व स्थानीय चीनी समुदाय की रक्षा करने में असमर्थ हैं तब उसने इंडोनेशियाई सरकार का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया परिणामतः दोमित्र राष्ट्र मित्रता से शत्रुता की ओर अग्रसित होने लगे ।[60] विशेष रूप से चीन व इंडोनेशिया के बीच शत्रुता और तीव्र हुई जब वायुसेनाध्यक्ष डा० सुबाड्रियो व जनरल ओमर धानी पर मुकदमा चलाने के दौरान इस राज्य विप्लव के षड्यंत्र में चीन को शामिल किया गया था ।[61] 1966 के मध्य तक आते-आते दोनों देशों के संबंध न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए तथा दोनों देशों के राजदूत अपनी-अपनी राजधानियों में बुला लिए गए । दोनों देशों के बीच संबंध इतने खराब हो गए कि 6 अक्तूबर 1967 को इंडोनेशिया ने चीन लोक गणराज्य के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए तथा दोनों देशों ने अपने-अपने दूतावासों को बन्द कर दिया ।

57- पी० के० आई० के सहायक संगठनों में -- किसान संगठन, बी०टी० आई० (बारिसान तानी इंडोनेशिया), महिला संगठन, गेरवानी (गेराकान वानिता), युवक संगठन, पमूडा रक्यत था ।

58- वही, पृष्ठ- 108 ।

59- वास्तव में यह असफल राज्य विप्लव पहली अक्तूबर 1965 को सुबह लगभग एक बजे प्रारम्भ हुआ था पर इसे तीस सितम्बर के असफल राज्य विप्लव के नाम से जाना जाता है । यह असफल राज्य विप्लव कुछ विद्वानों के अनुसार चीनी अक्तूबर क्रांति से प्रेरित, राष्ट्रपति सुकार्नो की क्रांतिकारी रोमांसकारी मानसिकता का उत्पत्ति था जो वे पी०के०आई० के सहयोग से पहली अक्तूबर को एक परिवर्तन लाना चाहते थे ।

चीन 16 अक्तूबर 1964 को परमाणु-शक्ति वाला देश बन गया और तीन वर्षों के अन्दर ही 17 जून 1967 को हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर डाला।[62] इन परीक्षणों के साथ चीन शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया। दक्षिण-पूर्व एशिया के देश चीनी उच्च स्तरीय नवनिर्माण, उपयोगी विस्तार तथा बढ़ती जनसंख्या से डरे हुए थे कि कहीं चीन पुनः प्राचीन समय जैसा ही एशिया के लिए मुख्य खतरा न बन जाय।[63] साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जून, 1966 में सियोल में आसपेक (एशिया एण्ड पेसिफिक कौंसिल) की स्थापना की गयी। जिसके सदस्य देश- जापान, दक्षिण कोरिया, चीन गणतंत्र, दक्षिण वियतनाम आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा तीन द०पू० एशियाई देश थाईलैण्ड, मलेशिया, फिलीपींस थे। इसके संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया था : "किसी भी साम्यवादी हमले के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता व एकता की रक्षा सामूहिक प्रयत्नों द्वारा किया जाएगा।[64]

इस शताब्दी के पांचवें छठें व सातवें दशक के प्रारम्भ में चीन द०पू० एशियाई देशों में चल रहे साम्यवादी आन्दोलन का समर्थन व सहायता करता रहा। कुछ विचारकों के मतानुसार इंडोनेशिया में तीस सितम्बर 1965 को विफल राज्य विप्लव पी०के०आई० उग्रवादी कम्यूनिस्टों के चीनी समर्थन का ही परिणाम था। ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार की चीनी विदेश नीति वहां के उग्रवादी नेताओं जैसे लिनपियाओ व चीफड़ी गिरोह की देन थी। चीन के साम्यवादी विस्तार के भय व ऐतिहासिक सबक को ध्यान में रखते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया के पांच देशों--इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने आठ अगस्त, 1967 को बैंकाक में आसियान

60- साएमन, सं० 55, पृष्ठ- 132।

61- वही, पृष्ठ- 159।

62- चीन ने अपने उत्तर-पश्चिम प्रांत शिन च्यांग के लोपनोर परमाणु परीक्षण क्षेत्र में पहला परमाणु बम का परीक्षण 16 अक्तूबर 1964 को तथा हाइड्रोजन बम का परीक्षण 17 जून 1967 में किया। इन परमाणु परीक्षणों के विस्तृत सूचना हेतु देखें - युवान लीऊ (सं०), "चाईना ॲ इंड बुक", प्रेगर पब्लिकेशन, (न्यूयार्क, 1973) पृष्ठ- 884।

63- एपीड, सं० 15, पृष्ठ-70।

(एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स) की स्थापना की । इसकी विज्ञप्ति में कहा गया कि सामूहिक सहयोग से इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास किया जाएगा ।[65] दक्षिण-पूर्व एशिया में आम समस्याओं को सुलझाने और आर्थिक व सामाजिक स्थिरता लाने तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से आसियान का निर्माण किया गया था ।

अगस्त 1967 में आसियान के स्थापना के समय इसके चार सदस्य देशों फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड व सिंगापुर ने न तो चीन लोक गणराज्य को मान्यता दी थी ना ही राजनयिक संबंध बनाए थे । केवल इंडोनेशिया ने इसे मान्यता दी थी परन्तु अक्तूबर 1967 में इंडोनेशिया ने भी चीन के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए । आसियान के इन पांचों देशों का अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध बने थे जिसे चीन विरोधी शक्ति मानता था । आसियान के दो सदस्य देशों फिलीपींस व थाईलैण्ड की वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था भी थी जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में व विशेषकर हिन्द-चीन में चीनी साम्यवादी विस्तार को रोकने के अभिप्राय से अमेरिकी निर्मित व्यवस्था माना जाता था । यद्यपि अन्य तीन आसियान सदस्य देशों का अमेरिका के साथ कोई सैनिक संधि नहीं था परन्तु ऐसा समझा जाता था कि वे तीनों देश- इंडोनेशिया, मलेशिया व सिंगापुर अमेरिकी समर्थित थे तथा चीनी साम्यवादी विस्तार को रोकने के अमेरिकी लक्ष्य से पूरी सहानुभूति रखते थे ।[66]

दक्षिण-पूर्व एशिया सदैव ही चीन के रुचि का क्षेत्र रहा है । यह क्षेत्र चीन के प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों के विस्तारवादी व प्रभाव का क्षेत्र बन गया । इससे चीन को

64- रोजर इरविन, "द फारमेटिव इयर्स ऑफ आसियान": 1967-1975", एलिसन ब्रोइनोवस्की (सं0), "अंडरस्टैंडिंग आसियान, द मैकमिलन, (हांगकांग, 1982) पृष्ठ- 15 ।

65- "द आसियान डिक्लेरेशन" (बैंकाक डिक्लेरेशन), "टेन इयर्स आसियान, (जाकार्ता, 1978) पृष्ठ- 14 ।

66- ली गुवान कुन, "रीसेंट डेवलपमेंट इन चाइना-आसियान रिलेशन्स", साउथ ईस्ट एशियन अफेयर्स, (सिंगापुर, 1979) पृष्ठ- 61 ।

TH-1657

Y4-9F-N67:1941 N81 ← N75 . 13714

सदैव इस बात का डर रहा है कि एक या कई शक्तियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर चीन विरोधी नीतियों को आत्मसात या फिर चीन को ही लक्ष्य बनाकर संगठन बनाने के लिए द०पू० एशियाई देशों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। चीनी नीतियों का एक यह भी उद्देश्य रहा है कि वह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को अपनी प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों के साथ संधि न बनने देने के लिए प्रयत्नशील रहा है। ऐसी मान्यता है कि चीन अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार हेतु अपने प्रतिद्वन्द्वियों की गतिविधियों व प्रभावों को कम करने का प्रयत्न करता है।

चीन बीसवीं शताब्दी के छठें दशक व सातवें दशक के प्रारम्भ में आसियान का विरोधी था। चीन आसियान के पाँचों सदस्य देशों के नेताओं को "चीन विरोधी" "प्रतिक्रियावादी", तथा अमेरिकी पिछलग्गू कहता था।[67] चीन आसियान देशों की भर्त्सना न केवल इसलिए करता था कि वे चीन लोकगणराज्य की सरकार को एकमात्र सरकार के रूप में मान्यता[68] देने व अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने से इनकार कर रहे थे अपितु दक्षिण-पूर्व एशिया में तथा विशेष रूप से हिन्द-चीन में तथाकथित अमेरिकी नीतियों का समर्थन करते थे।[69]

सीटो के सदस्य होने तथा अमेरिकी सरकार को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति देने के परिणाम स्वरूप चीन थाईलैण्ड व फिलीपींस की भर्त्सना करता था। चीन के लिए, मलेशिया व सिंगापुर दोनों देशों के दक्षिण वियतनाम युद्ध के प्रश्न पर उनके विचार भी निन्दनीय थे। विशेष रूप से मलेशिया जो इन्डोनेशिया विवाद में सैगोन का समर्थन करता था। इन्डोनेशिया उस समय चीन का मित्र था तथा दक्षिण वियतनामी सैनिकों व पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग कर रहा था। यद्यपि इंडोनेशिया ने वियतनाम युद्ध में सबसे कम हिस्सा लिया था फिर भी चीन उसके अमेरिकी समर्थित विदेश नीति के कारण भर्त्सना करता था।

चीन आसियान को विशेष रूप से एक चीन विरोधी "सैनिक संधि" मानता था जो अमेरिकी इशारे पर दक्षिण-पूर्व एशिया के पाँच देशों के "प्रतिक्रियावादी"

---

67. [illegible] (पेइचिंग) 12 अगस्त, 1967; [illegible], 29 अगस्त, 1967।
68. इंडोनेशिया इसका अपवाद है।
69. वही, सं० 66, पृष्ठ- 62।

गुट द्वारा बनाया गया था ।[70] आसियान के स्थापना के तुरन्त बाद चीन ने आसियान को "प्रतिक्रान्तिकारी संधि", "सीटो का जुड़वा भाई", व "अमेरिकी साम्राज्यवाद का हथियार"[71] आदि कहकर इस पर कई बार अपमानजनक टिप्पणी किया । पेकिंग ने आसियान के तथाकथित आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि इस तथाकथित सहयोग के पीछे आसियान वास्तव में एक सैनिक संगठन है जिसका उपयोग चीन विरोधी नीतियों को गतिशील रखने के लिए अमेरिका द्वारा किया जाता है ।[72]

चीन ने आसियान को मुख्य रूप से "अमेरिकी साम्राज्यवाद का हथियार" कहकर उसकी आलोचना की । साथ ही साथ चीन ने उसे सोवियत "सामाजिक साम्राज्यवादी" का भी हथियार कहा । चीन के विचार में अमेरिका-सोवियत का संयुक्त रूप से चीन के घेराव करने का दोनों का सामूहिक लक्ष्य है ।[73] आसियान के स्थापना के समय केवल इसके दो सदस्य देश-इंडोनेशिया व थाईलैण्ड का मास्को के साथ औपचारिक संबंध था पर इसके कुछ ही समयोपरान्त मलेशिया व सिंगापुर ने सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए ।

आसियान देशों के विचार में चीन दक्षिण एशिया में विस्तारवादी रणनीति रखता है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में, अमेरिकी नीतियों के उनके समर्थनों के कारणों में एक विशेष व महत्वपूर्ण कारण था ।

आसियान-चीन संबंध, आसियान के गठन के बाद, कुछ वर्षों तक शत्रुतापूर्ण रहे । अपनी अपनी समस्याओं को देखते हुए इन दोनों पक्षों को लगा कि आसियान-चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध से किसी को लाभ नहीं होने वाला । चीन आसियान देशों के साम्यवादी विद्रोहियों को खुला समर्थन दे रहा था इसलिए वह राज्य-राज्य संबंध बनाने पर बल देता था । आसियान देश साम्यवादी चीन के साथ संबंध बनाना नहीं

70- कु० दे० पेकिंग रिव्यू, 18 अगस्त 1967, पृष्ठ-40

71- वही ,,

72- वही ,,

73- रेनमिनरिपाव (पेकिंग), 12 अगस्त, 1967, सिन हुवा न्यूज बुलेटिन (पेकिंग) 13 अगस्त, 1967 ।

चाहते थे क्योंकि चीन आसियान देशों के साम्यवादी विद्रोहियों की सहायता करता था इससे उन देशों की आंतरिक सुरक्षा को खतरा था ।

आसियान-चीन संबंधों में तनाव शैथिल्यता

आसियान देश व चीन की राष्ट्रीय हितों, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों तथा विशेषकर द०पू० एशिया की राजनीतिक स्थितियों ने आसियान व चीन को विवश कर दिया कि वे आपसी संबंधों की पुनर्मूल्यांकन करें । छठें दशक के अन्त तक किसी पक्ष ने यह नहीं सोचा कि संबंध बनाने से उनकी सुरक्षा प्रभावित होगी या नहीं परन्तु सातवें दशक में वे इस संबंध की आधारभूत आवश्यकता को समझ पाए तथा उन्होंने पाया कि आसियान चीन संबंध उनकी राष्ट्रीय हित में है । दोनों पक्षों के अपने अलग-अलग कारण थे जिसके कारण वे इस संबंध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे । पर उनके लिए एशिया में तथा विशेषकर द०पू० एशिया में हुए परिवर्तनों का विशेष ध्यान था । चीन के लिए सबसे बुनियादी कारण था - उसकी सुरक्षा के लिए बढ़ता हुआ सोवियत खतरा । मार्च 1969, उसूरी नदी पर तथा अगस्त 1969 को सिनकियांग सीमा पर बड़े पैमाने पर चीन - सोवियत युद्ध के परिणाम स्वरूप पेकिंग सावधान हो गया था[74] कि उसकी सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा अमेरिका से अधिक सोवियत संघ से है । इस चीन-सोवियत युद्ध के फलस्वरूप आसियान देशों को काफी संतोष मिला तथा उन्हें समाजवादी गुटों में बढ़ते तनाव से साम्यवादी विद्रोही गतिविधियों में कमी की आशा दिखी । सोवियत संघ के 1969 में चेकोस्लोवाकिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से चीन भयभीत हो उठा । चीन पूरी तरह समझ गया था कि सोवियत संघ की एशिया में प्रभुत्ववादी मानसिकता है । चीन नहीं चाहता था कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका के चले जाने के बाद सोवियत संघ इस क्षेत्र में मुख्य शक्ति के रूप में विकसित हो सके । इसके परिणामस्वरूप चीन ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त की । मार्च 1969 में हुए उसूरी विवाद के तीन माह बाद ही सोवियत संघ ने "एशियाई सुरक्षा प्रणाली"

---

74. रॉबर्ट जी० सुटर, "चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ्टर द कल्चरल रिवोल्यूशन, 1966-1977," वेस्ट व्यू प्रेस (बाल्डर, 1978) पृ० 162

प्रस्ताव की पहली बार घोषणा कर दी । चीन के विचार में यह प्रस्ताव उसे चारों तरफ से घेरने व एशिया में मुख्य शक्ति के रूप में अमेरिकी स्थान की पूर्ति करती थी ।[75] इस चीन-सोवियत विवाद के बाद चीन अपनी एशिया की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा ।

आसियान-चीन तनाव शैथिल्यता की शुरुआत की झलक छठें दशक के अंतिम वर्षों में देखी जा सकती है । ब्रिटिश लेबर पार्टी सरकार ने सन् 1968 में स्वेज के पूर्व से ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक उपस्थिति को दिसम्बर 1971 तक वापस ले लेने की घोषणा की, इससे मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों के लिए एक चिंता का विषय बन गया तथा ये देश अपने को अकेला व कमजोर समझने लगे । सन् 1968, मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के हिन्द-चीन की नीति में परिवर्तन आया । उन्होंने हिन्द-चीन में युद्ध समाप्त करने तथा उत्तरी वियतनाम से बातचीत करने की आवश्यकता पर बल दिया । और इसी प्रकार की नीति का सन् 1969, जुलाई में राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी "गुआम सिद्धान्त" में प्रतिपादित किया तथा वियतनामीकरण कार्यक्रम व फौज की वापसी की बात कही । 'गुआम सिद्धान्त' में कहा गया कि एशिया में अमेरिकी सैनिक भूमिका काफी कम कर दी जायेगी ।[76] 1969 में, अमेरिका ने चीन के साथ तनाव शैथिल्यता की इच्छा व्यक्त की, तथा राष्ट्रपति निक्सन ने एशिया में अपनी सैनिक वचनबद्धता में कमी लाने व वियतनाम में युद्ध की समाप्ति और द०पू० एशिया में शान्ति की स्थापना के प्रयत्नों की बात की ।[77] आसियान-चीन संबंध में सन् 1969 एक बुनियादी वर्ष माना जा सकता है । सन् 1969 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जिसका प्रभाव निश्चित रूप से आसियान-चीन संबंध पर पड़ा ।

75- वही, सं० 66, पृष्ठ-63 ।

76- कृ०वे०साइमन, शेल्डन डब्ल्यू, "आसियान-न्यूट्रलिज्म एण्ड यू० एस० पालिसी" (वाशिंगटन डी०सी०, 1975) पृष्ठ- 8 ।

77- झा, गंगानाथ, "फॉरेन पॉलिसी ऑफ थाईलैंड", (नयी दिल्ली, 1979) पृष्ठ- 80 ।

18 मार्च 1970 को प्रधान मंत्री लौन नोल के नेतृत्व में कम्पूचिया में हुए सैनिक राज्य-विप्लव से राजकुमार सिहानुक की कम्पूचियाई राज्यशक्ति की समाप्ति हो गई।[78] राजकुमार सिहानुक को चीन का समर्थन प्राप्त होने से आसियान देशों ने अमेरिकी समर्थित लौन नोल की गैर-साम्यवादी सरकार का समर्थन किया तथा राजकुमार सिहानुक का विरोध, जिसका आसियान-चीन संबंध पर गहरा प्रभाव पड़ा।

बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका व चीन के बीच विभिन्न आयामों के माध्यम से तनाव शैथिल्यता की शुरुआत हुई। जुलाई 1971 में अमेरिकी विदेश मंत्री किसिंजर की चीन यात्रा हुई। सितम्बर 1971 में चीनी उग्रवादी नेता लिन प्याओ[79] की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से चीन की विदेश नीति में परिवर्तनों का सिलसिला प्रारम्भ हो गया जिसे चीन के प्रधान मंत्री चाऊ अन लाए ने स्वयं स्वीकार किया था।[80] अक्तूबर 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के मिल जाने व फरवरी 1972 में अमेरिकी निक्सन द्वारा चीन की यात्रा व शंघाई विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप आसियान देश अपनी विदेश नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने लगे। इसमें सर्वप्रथम पहल करने वाला देश मलेशिया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने जन प्रतिनिधि सभा (दिवान रायत) में एक प्रश्न के उत्तर में 10 मई 1972 को कहा कि उनकी सरकार की

78- इस राज्य विप्लव के समय राजकुमार सिहानुक मास्को की यात्रा पर थे, राजकुमार सिहानुक मास्को से पेईकिंग चले गए जहां उन्होंने अपना अस्थाई कार्यालय बनाया।

79- चीनी नेता लिन प्याओ ने, 1969 में हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं कांग्रेस में, "सांस्कृतिक क्रान्ति" का पूरा सहयोग व समर्थन दिया था। कु० के० चौधरी, जी० डब्ल्यू०, "चाईना इन वर्ल्ड अफेयर्स: द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पी आर सी, सिन्स 1970" (बोल्डर, 1982), पृष्ठ-238

80- अगस्त 1973 में हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दसवीं कांग्रेस में चाऊ अन लाए ने केवल "तीसरी दुनिया के न्यायपूर्ण संघर्ष" के समर्थन की बात की थी। तथा द०पू० एशिया के तीन देशों वियतनाम, लाओस, कम्पूचिया का ही

यह नीति है कि वह चीन लोक गणराज्य से राजनीतिक संबंधों की ओर दृष्टि डाले तथा यह संबंध द०पू० एशिया में तटस्थीकरण के प्रस्ताव के संदर्भ में होना चाहिए। थाई नेता व तत्कालीन विदेश मंत्री थानात खोमान तथा विरोधी दल के नेता सेनी प्रमोज थाई विदेश नीति में परिवर्तन के पक्षधर हो गए। थानात खोमान ने अपनी सोवियत यात्रा के दौरान पेइचिंग व हनोई के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने 14 मई 1971 को बैंकाक के एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि अब दुनिया में स्थिति बदल गयी है तथा जो हमारे इर्द-गिर्द खतरे मंडरा रहे हैं उनके साथ सही ढंग से संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने थाई-चीन के बीच बातचीत की इच्छा व्यक्त की जिससे थाईलैण्ड में साम्यवादी विद्रोह को रोका जा सके। वे चीन के साथ पूरी तरह राजनयिक संबंध बनाने के पक्ष में थे। उनके विचारानुसार इस प्रकार चीनी साम्यवादी प्रचारवाद को कम किया जा सकता था तथा यह संबंध आपसी विश्वास व समानता के आधार पर बनना चाहिए।[81]

चौथे, पांचवे व छठें दशक में द०पू० एशिया से लगातार बाह्य शक्तियों के वापसी के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अल्पदाब क्षेत्र बन गया। इससे इस क्षेत्र को सोवियत संघ, चीन व अमेरिका से सदैव खतरा बना हुआ था। जिसके फलस्वरूप आसियान देशों ने अपनी सुरक्षार्थ के लिए 27 नवम्बर 1971 को क्वालालम्पुर (मलेशिया) में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में द०पू० एशिया के लिए एक नीति सूत्रपात किया जिसे "ज़ोपफान" (ज़ोन ऑफ पीस, फ्रीडम एण्ड न्यूट्रलिटी) कहा गया। इसके अनुसार द०पू० एशिया हर तरह से बाहरी शक्तियों विशेषकर अमेरिका, सोवियत संघ व चीन के हस्तक्षेप से मुक्त, शान्ति, स्वतंत्र व निरपेक्ष क्षेत्र हो। इसके लिए अमेरिका, सोवियत संघ व चीन का आश्वासन अपेक्षित था। इस ज़ोपफान घोषणा से चीन पहले तो सतर्क था पर जब सोवियत

विशेष रूप से चर्चा किया था। इसके पहले फरवरी 1972 में चऊ इन लाइ ने फिलीपींस के दूत गवर्नर रोमाल्डेज से कहा था कि फिलीपींस व अन्य द० पू० एशियाई देशों में विद्रोहात्मक गतिविधियों के लिए लिन प्याओ व उनके सहयोगी जिम्मेदार थे तथा अब इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी, कु० दे० चौधरी, सं० 79, पृष्ठ-238।

संघ एशिया में सामूहिक सुरक्षा योजना के लिए कार्यरत हुआ तब पेईचिंग जोपफान का समर्थक हो गया । 18 व 19 मई 1972 को कुवालालम्पुर रेडियो ने कहा कि चऊ अन लाए ने द०पू० एशियाई तटस्थीकरण के मलेशियाई प्रस्ताव के पक्ष में प्रतिक्रिया व्यक्त की है ।[82]

जोपफान घोषणा के बावजूद आसियान देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर काफी मतभेद है । एक तरफ मलेशिया का यह दृष्टिकोण था कि द०पू० एशिया मुख्य शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो । सिंगापुर चाहता था कि समस्त शक्तियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, व चीन, की मौजूदगी से इस क्षेत्र में संतुलन व प्रतिस्पर्धा बना रहेगा जिससे कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता ।[83] फिलीपींस का अमेरिका के साथ सैनिक संधि था । थाईलैंड की धरती का प्रयोग, अमेरिकी सैनिक अड्डों के रूप में ती किया हो जा रहा था ।

कुवालालम्पुर , 27 नवम्बर, 1971 में हुए आसियान सम्मेलन के कुवालालम्पुर घोषणा के समय चीन के साथ आसियान देशों के संबंध के विषय में बोलते हुए सिंगापुर के विदेश मंत्री ने कहा कि समस्त आसियान देशों के सदस्यों को चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने के पहले आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि चीन के साथ संबंध बनाने से द०पू० एशिया पर तथा उसके तटस्थीकरण प्रस्ताव पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा । इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया था कि चीन लोकगणराज्य के साथ राजनयिक संबंध बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रयत्न होने चाहिए पर यह संबंध द०पू० एशिया में तटस्थीकरण प्रस्ताव के संदर्भ में होना चाहिए तथा उसमें यह भी निश्चय किया गया था कि आसियान देशोंको चीन के साथ विकसित प्रत्येक प्रकार के संबंधों के बारे में सूचना देते रहना चाहिए जिससे आसियान चीन के साथ राजनयिक संबंध के संदर्भ में एक संगठन के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें ।[84]

81- बैंकाक पोस्ट, 15 मई, 1971 ।

82- चौधरी, सं०-79, पृष्ठ-236 से उद्धृत ।

83- "एशियन सेक्युरिटी", रिसर्च इन्स्टीट्यूट फॉर पीस एण्ड सिक्युरिटी तोक्यो (जापान, 1981) पृष्ठ-107 ।

84- स्ट्रेट्स टाइम्स, 28 नवम्बर, 1971 ।

मलेशिया व इंडोनेशिया का मलाका जलडमरूमध्य के प्रशासन के प्रश्न पर चीन ने 1971 के बाद समर्थन प्रारंभ कर दिया।[85] मलेशिया व इंडोनेशिया का मुख्य नव सैनिक शक्तियों के मलाका जलडमरूमध्य के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध मांग का चीन ने समर्थन किया। 1973 में चीन ने औपचारिक रूप से मलेशिया के कुआलालम्पुर प्रस्ताव का समर्थन किया।

तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री ची पंग फेई ने जनवरी-फरवरी 1973 में पेरिस में हुए वियतनामी शान्ति सम्मेलन के दौरान इंडोनेशियाई विदेशमंत्री ऐडम मलिक से मुलाकात की तथा उन्हें बताया कि "प्रवासी चीनी मामलों के आयोग" (कीटा)[86] को समाप्त कर दिया गया है। इस सूचना का अभिप्राय यह था कि चीन इस बात को व्यक्त करना चाहता था कि उनकी नीतियां परिवर्तित हो रही थीं।[87]

जुलाई 1974 में इंडोनेशिया व चीन के संबंधों में सुधार का आभास तब हुआ जब इंडोनेशियाई तत्कालीन विदेश मंत्री ऐडम मलिक के वायुयान को उलान बटोर व प्योंगयांग के बीच यात्रा के समय चीन की सीमा से होकर जाने की अनुमति दी गयी।[88] सिनार हारापान, 23 जुलाई 1974 के अनुसार मलिक ने पत्रकारों से कहा था कि पेकिंग व जाकार्ता सैद्धान्तिक रूप से संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हो गए हैं पर इस विशेष कदम के लिए एक निश्चित व उचित समय की प्रतीक्षा की जा रही है।

85- बैंकाक पोस्ट, 20 अप्रैल, 1972।

86- कीटा- कमिशन फॉर ओवरसीज चाईनीज अफेयर्स- इसका गठन चीनी सांस्कृतिक क्रान्तिकारियों के उग्रवादियों के नेतृत्व में बनाया गया था जो प्रवासी चीनियों को विद्रोही गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता था।

87- विक्टर सी० फनेंल, "चाईना एण्ड आसियान: द चेंजिंग फेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया", द वर्ल्ड टुडे (लंदन, जुलाई 1975) ग्रंथ 31, अंक-7, पृष्ठ-301, चौधरी, सं०-39, पृष्ठ-239।

88- वही, पृष्ठ-302।

परन्तु मई 1975 में पेकिंग रेडियो से एक प्रसारण में इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी (पारताई कम्युनिस इंडोनेशिया) की सशस्त्र आंदोलन के लिए प्रेरित करने के कारण इस संबंध सुधार में निष्क्रियता आ गई ।[89]

पेकिंग अपने गुप्त रेडियो स्टेशनों के प्रचार माध्यम से द०पू० एशिया के स्थानीय सरकार विरोधी कम्युनिस्ट विद्रोहियों का समर्थन करता रहा परन्तु पेकिंग अपने स्वयं के प्रचार माध्यम से द०पू० एशिया के शासन व उनके विद्रोहों के समर्थन में कमी कर दी ।[90]

28 मई 1974 को चाऊ इन लाइ ने मलेशियाई प्रधानमंत्री तुन अब्दुल रज्जाक के स्वागत में दिए एक भोज समारोह में बोलते हुए कहा था, "चीनी जनता उत्पीड़ित राष्ट्रों व जनता के उचित संघर्ष का पूरा समर्थन करती है, यह हमारा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य है । हम समझते हैं कि एक देश की सामाजिक प्रणाली उस देश के अपने लोगों द्वारा ही चुनी जानी व तय होनी चाहिए । किसी अन्य देश द्वारा थोपी जानी नहीं चाहिए । विभिन्न सामाजिक प्रणाली के देश शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के

89- फ्रैंकलिन बी० वैन्सटिन, इन्डोनेशियन फॉरेन पॉलिसी एण्ड द डाइलेमा ऑफ डिपेन्डेन्स, कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, (लंदन, 1976) पृष्ठ-124

90- चीनियों के गुप्त रेडियो स्टेशनों - द वायस ऑफ द पीपुल्स आफ थाईलैंड (वी०ओ०पी०टी०), द वायस ऑफ द पीपुल्स आफ बर्मा (वी०ओ०पी०बी०), व द वायस ऑफ द मलयन रिवोल्यूशन (वी०ओ०एम०आर०)- जो प्रतिदिन सरकार विरोधी प्रचार करते थे तथा उनके वर्तमान शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित करते थे । द्र०दे० राबर्ट जी० सुत्र, "चाईनीज फॉरेन पॉलिसी ऑफ्टर द कल्चरल रिवोल्यूशन", 1966-1977, वेस्ट व्यू प्रेस, (बोल्डर, 1978) पृष्ठ-116 ।

पांच सिद्धान्तों[91] के आधार पर अपने राज्य संबंध स्थापित कर सकते हैं।[92]

चीन के इस परिवर्तित विदेश नीति का आसियान-चीन संबंध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार आसियान देशों की, चीन के बारे में, मानसिकता में परिवर्तन आने प्रारम्भ हो गए।

---00000---

91- शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धान्त- (अ) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान,
(ब) आपसी अनाक्रमण,
(स) एक दूसरे के अन्दरुनी मामलों में हस्तक्षेप न करना,
(द) समानता और आपसी लाभ,
(त) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व।
कृ० दे० शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्तों की विजय, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, (पेकिंग 1960); पृष्ठ-1

92- रावर्ट, सं० 90, पृष्ठ- 115।

द्वितीय अध्याय

1975 का हिन्द-चीन परिवर्तन व आसियान

17 अप्रैल 1975 में नामपेन्ह (कम्पूचिया) में चीन समर्थित पोलपोट व यांगसारी के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और अमेरिकी समर्थित और चीन विरोधी लोन नोल व सिरिक मातार का तख्ता पलट गया। 30 अप्रैल को दक्षिण वियतनाम में प्रतिरोध युद्ध की अचानक समाप्ति व राष्ट्रीय मुक्ति शक्ति (नेशनल लिब्रेशन फोर्सेज) की विजय हुई। 3 दिसम्बर 1975 को लाओ लोक जनवादी गणराज्य की स्थापना के परिणामस्वरूप 1975 में पूरे हिन्द-चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना और अमेरिका की निर्णयात्मक हार ने सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के गैर साम्यवादी देशों को आश्चर्यचकित कर झकझोर दिया। हिन्द-चीन के नए परिवर्तित स्थिति के साथ आसियान देशों को अपने आपको संतुलित करना था। हिन्द-चीन में घटित इस महान घटना के बाद आसियान देशों की ज्ञानबोध व प्रतिक्रिया ही हिन्द-चीन प्रायःद्वीप व अन्य समाजवादी देशों के साथ राजनयिक व अन्य प्रकार के समस्त संबंधों की व्यापकता तथा आसियान क्षेत्र की शान्ति, स्थिरता व क्षेत्रीय सहयोग एवं संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है।[1]

नामपेन्ह में अमेरिकी समर्थित मार्शल लोन नोल की सरकार के पतन होते ही आसियान ने दूसरे दिन ही चीनी समर्थित पोल पोट की संयुक्त नयी सरकार, "कम्पूचियाई राष्ट्रीय संघ की शाही सरकार" (रायल गवर्नमेंट आफ नेशनल यूनियन आफ कम्पूचिया)(ग्रुनुक) को मान्यता दे दी। आसियान ने 18 अप्रैल, 1975 को एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा:

"कम्पूचिया में नए परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए आशा की जाती है कि

1. एस०एस० भट्टाचार्या, "द इम्पैक्ट ऑफ वियतनाम ऑन आसियान", न्यूज बुलेटिन ऑन जापान, साउथ ईस्ट एशिया एण्ड आस्ट्रेलिया, रक्षा अध्ययन एवम् विश्लेषण संस्थान, नयी दिल्ली (जून 1975), पृष्ठ-459।
2. स्ट्रेट्स टाइम्स, 19 अप्रैल, 1975, तथा रेडियो सिंगापुर, होम सर्विस, 18 अप्रैल, 1975, एस०ई० डब्लू० बी०, एफ०-ई।4883।ए-3।13, 21 अप्रैल, 1975।

नयी स्थिति से शत्रुतापूर्ण रवैये की समाप्ति व शान्ति की पुनर्स्थापना होगी । कम्पूचिया की नयी सरकार "गुट" आसियान देशों के साथ सौहार्दपूर्ण, मित्रता व समझदारी से शान्ति व स्थिरता के उद्देश्यों के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में आसियान के उद्देश्यों व नीतियों के साथ होगी । कम्पूचिया की "गुट" सरकार को आसियान स्कूप व संवैधानिक सरकार मानती है। आसियान देश कम्पूचिया से संबंधित अपने पिछले कार्यक्रमों को जारी करने के लिए तैयार होंगे जिसके अनुसार कम्पूचिया के पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण के लिए भरपूर सहायता, आपसी सहयोग के आधार पर देने के लिए तैयार हैं जिससे कम्पूचियाएँ राष्ट्र व जनता की समृद्धि व उन्नति को लाने में प्रयत्न किया जा सके ।[3]

एलिसन ग्रोस्नीस्की के अनुसार हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन के पहले आसियान गुमनाम, अकेला, व ठहराव की स्थिति में था ।[4] यह पूर्णतया स्वीकार्य है कि हिन्द-चीन के 1975 में हुए सम्पूर्ण साम्यवादी नियंत्रण की शुरुआत आसियान देशों के बीच विस्तृत व अधिक ठोस रूप से सहयोग को गतिशील व क्रियान्वित करने में उत्प्रेरक के रूप में सिद्ध हुआ ।[5]

आसियान देशों के विचार में हिन्द-चीन के देशों विशेषकर वियतनाम के बारे में अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हो गई थीं- क्या वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया में सर्वशक्तिमान सैनिक शक्ति बनने के लिए, जिससे "डोमिनो सिद्धान्त" की प्रमाणिकता सिद्ध हो, प्रयत्न करेगा ? क्या वियतनाम आसियान देशों में

3- वही ।

4- एलिसन, ग्रोस्नीस्की (सं०), "अंडरस्टैंडिंग आसियान" डेविड इरविन, "मेकिंग हेस्ट लेस स्लोली : आसियान फ्रॉम 1975", (हांगकांग 1982), पृष्ठ- 37 ।

5- आर्नफिन जार्गेनसेन डाहल, "आसियान 1967-76, डेवलपमेंट आर स्टैगनेशन", पैसिफिक क्वार्टरली, प्रति-7, अं०-4 (जुलाई 1976) पृष्ठ- 534 ।

विद्रोही शक्तियों को प्रश्रय व सहायता देने में चीन कैसी भूमिका अदा करेगा जिसके विषय में अब चीन स्वयं कम चिंतित है ? क्या वियतनाम अमेरिका से हथियाए गए हथियारों का आसियान देशों के साम्यवादी विद्रोहियों को देने के लिए शीघ्र ही प्रयास करेगा ? अथवा वियतनाम अपने देश के सुदृढ़ीकरण व पुनर्निर्माण के कार्य की ओर ध्यान देगा ?

इस प्रकार उपरोक्त संदिग्ध राजनीतिक वातावरण में आसियान नेताओं ने वियतनाम, लाओस व कम्पूचिया की तरफ मित्रता व आपसी सहयोग के लिए अपने प्रस्ताव रखे । वैसे भी आसियान की मौलिक नीति हिन्द-चीन को अपने अन्दर शामिल करना अपेक्षित था ।[6]

30 अप्रैल 1975, किंग्स्टन में आयोजित राष्ट्र संघ के राष्ट्राध्यक्षों के एक सम्मेलन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने हिन्द-चीन के साथ संबंध बनाने के बारे में कहते हुए प्राचीन चीनी सैन्य रणनीतिज्ञ "सुन जू" का उल्लेख किया कि "सुन जू" आज से लगभग 2000 वर्ष पहले तथा पाश्चात्य सैन्य रणनीतिज्ञ क्लाउज विट्ज ने कहा है -- "स्वयं को जानो, अपने दुश्मन को समझो, सौ युद्धों में सौ विजय प्राप्त करो" इस प्रकार साम्यवादी दुश्मनों से दोस्ती करके उन्हें समझा जा सकता है जिससे साम्यवाद के विस्तार को रोकने में सहायता मिलेगी ।[7]

आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की कुआलालम्पुर में 13 से 15 मई, 1975 के बीच हुई बैठक में हिन्द-चीन के युद्ध की समाप्ति का स्वागत किया गया तथा कम्पूचिया व दक्षिण-वियतनाम में शान्ति की पुनः स्थापना व हिन्द-चीन देशों के साथ

6- एशियन, क्रॉनिकल, सं०-4, पृष्ठ- 39 ।

7- स्ट्रेट्स टाइम्स (सिंगापुर) 2 मई 1975 ।

आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग की इच्छा व्यक्त की गई ।[8]

हिन्द-चीन के परिवर्तन को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मारकोस व थाईलैण्ड के प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने चीन की यात्रा की तथा चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयत्न किए । सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुवान यू ने अपने आसियान देशों के सदस्य सहयोगियों को राय दी कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे चीन अप्रसन्न हो । चीन को ली कुवान यू ° साम्यवादी शक्तियों में अधिक पढ़ ° मानते हैं ।[9]

हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आसियान देशों के विचारों में परिवर्तन तो अवश्य आए परन्तु उनके विचारों में स्पष्टता के साथ-साथ अनेक बातों में अन्तर्विरोध भी थे । कुछ आसियान देश इस घटना से काफी भयभीत थे और कुछ ऐसे दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए शान्ति व स्थिरता के लिए अच्छा मानते थे ।

मलेशिया :

कम्बूचिया व दक्षिण वियतनाम में साम्यवादी परिवर्तन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मलेशिया के प्रधान मंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने उन देशों के साथ सहयोग पर बल देते हुए 2 मई, 1975 को कुआलालम्पुर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहते हुए कहा :

°आसियान हिन्द-चीन में बने नए सरकारों से सहयोग तथा उन देशों के पुनर्निर्माण हेतु सहायता करने के लिए तैयार है ... खमेर गणतंत्र व वियतनाम गणतंत्र के गिरने के बाद, आसियान सदस्य देशों के लिए कोई विकल्प नहीं बच रहा पर हिन्द-चीन के पड़ोसी होने के कारण उन्हें हिन्द-चीन व चीन की स्थितियों

8- एस०एस० मट्टाचार्या, हिन्द-चीन व आसियान °न्यूज बुलेटिन ऑन जापान साउथ ईस्ट एशिया एण्ड आस्ट्रेलिया, एशिया अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नयी दिल्ली ।

9- वही ।

के साथ सामंजस्य स्थापित तो करना ही चाहिए ।[10]

वे इस परिवर्तन से आसियान देशों के लिए कोई खतरा नहीं मानते थे उन्होंने डोमिनो सिद्धान्त को गलत बतलाते हुए 3 मई, 1975 को कहा :

"हम 'डोमिनो सिद्धान्त' में विश्वास नहीं रखते कि अगर एक राज्य साम्यवादी बन गया तो उसका प्रभाव पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा ।[11]

एस० एस० भट्टाचार्या ने रक्षा अध्ययन स्वयं विश्लेषण संस्थान, नयी दिल्ली के बुलेटिन में प्रकाशित एक निबंध में मलेशियाई प्रधान मंत्री तुन अब्दुल रज्जाक की हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन के पक्ष में उद्धृत करते हुए लिखा कि तुन अब्दुल रज्जाक, इसके पक्ष में जनता के बीच बोलते हुए कहा था कि हिन्द-चीन में साम्यवादी विजय से मलेशिया के साम्यवादी छापामारों की गतिविधियों से मलेशिया को तत्काल कोई खतरा नहीं है । उन्होंने मलेशिया के प्रति रक्षा रणनीति की पुनरावलोकन करने का आदेश दिया । उन्होंने "डोमिनो सिद्धान्त" को गलत बतलाते हुए कहा कि मलेशिया व वियतनाम के साम्यवादियों में काफी अन्तर है । वियतनाम की जनता ने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया जबकि मलेशिया के साम्यवादी तो डाकू हैं जो हिंसा के माध्यम से मलेशिया की जनप्रिय निर्वाचित सरकार को गिराना चाहते हैं ।[12]

सैगोन के पतन होने के दो सप्ताह बाद मलेशिया के प्रधान मंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने घोषणा की कि आसियान हिन्द-चीन के नए सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है तथा इसके समर्थन में कहा :

10- सभी ऑफ वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट, एफ ई।4896।ए-3।9, 6 मई 1975, एस० डब्ल्यू० बी०, एफ ई।4904।ए-3।9 , 15 मई 1975 ।

11- बैंकाक पोस्ट, 4 मई 1975 ।

12- भट्टाचार्या, सं०-1 के पृष्ठ-459 में उद्धृत रुपया सभी ऑफ वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट, एफ ई।4896।ए-3।9, 6 मई 1975 भी देखें ।

"इस क्षेत्र के इतिहास में, दक्षिण-पूर्व एशिया के नए क्षेत्र के निर्माण व स्थापना हेतु जो विदेशी अधिकारों व प्रभावों से मुक्त व शान्त हो- एक ऐसी दुनिया जिसमें एक क्षेत्र के देश आपसी लाभ व अच्छाई के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, के लिए पहले कभी ऐसा अवसर नहीं मिला।[13]

13 मई 1975 को आसियान के आठवें मंत्री स्तर बैठक में हिन्द-चीन के नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए मलेशिया के विदेश मंत्री गजाली शफी ने कहा :

"हमारे भविष्य की सुरक्षा व स्थिरता की कुंजी-शीत युद्ध के पुराने व निरर्थक घटकों में नहीं है अपितु आज के नए वास्तविकताओं की कल्पनाओं तथा निर्माणकारी उत्तरदायित्व में है। हिन्द-चीन के युद्धान्त में आधारभूत नया जन्मा वातावरण एक वास्तविक अवसर है।"[14]

हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन की मलेशिया के राजा यांग डी परतुआन अगोंग ने 4 जून 1975 को रेडियो व दूरदर्शन प्रसारण में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उचित बताते हुए कहा :

"आसियान आशा करता है कि जब उचित समय आएगा तब हिन्द-चीन के देश आसियान में शामिल हो जाएंगे। हिन्द-चीन के हाल के परिवर्तन से दक्षिण-पूर्व एशिया को शान्ति, स्वतंत्र व तटस्थ क्षेत्र के निर्माण के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है।"[15]

13- "टेन इयर्स आसियान", (जकार्ता, 1978), पृष्ठ-281।

14- फॉरेन अफेयर्स बॉफ मलेशिया, " मिनिस्ट्री बॉफ फॉरेन अफेयर्स, मलेशिया, ग्रंथ सं० 8, प्रति-2।

15- वही, एफ ई 14922/ए-314, 6 जून, 1975।

मलेशियाई प्रधान मंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में शान्ति व सहयोग का मजबूत ढाँचा तैयार करने के अभिप्राय: से हिन्द-चीन के देशों को आसियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया परन्तु आसियान के ये समस्त प्रयत्न कोई महत्वपूर्ण परिणाम दे सकने में असमर्थ रहे। 12 जून, 1975 को तुन अब्दुल रज्जाक ने कहा :

"हिन्द-चीन को भी आसियान प्रस्ताव के "ज़ोपफान" का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। ज़ोपफान नीति केवल आसियान देशों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में केवल आसियान देशों को ही नहीं मानना चाहिए अपितु इसमें हिन्द-चीन को भी शामिल करना चाहिए। इससे इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त की जा सकती है। पर जो भी हो यह हिन्द-चीन के परिवर्तन पर बहुत कुछ निर्भर करता है।"[16]

इंडोनेशिया :

हिन्द-चीन में संभावित परिवर्तन पर विचार करते हुए इंडोनेशियाई विदेश मंत्री ऐडम मलिक ने 15 अप्रैल 1975 को कहा, "अगर साम्यवादी सम्पूर्ण हिन्द-चीन पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उनसे आशा की जाती है कि वे आसियान के साथ सहयोग करेंगे तथा ऐसा करना काफी उचित होगा। इससे बड़ी शक्तियों के दक्षिण-पूर्व एशिया में हस्तक्षेप को रोकने में सहायता मिलेगी।" उन्होंने विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि उत्तरी वियतनाम अपना प्रभाव हिन्द-चीन से बाहर नहीं बढ़ायेगा।"[17]

---

16. स्ट्रेट्स टाइम्स, 13 जून, 1975।

17. बैंकाक पोस्ट, 16 अप्रैल, 1975।

इंडोनेशिया, हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन से आसियान देशों के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं मानता। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ऐडम मलिक ने "डोमिनो सिद्धान्त" पर चल रहे बहस की आलोचना करते हुए उसका इन शब्दों में खण्डन किया :

"डोमिनो सिद्धान्त" की विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा काफी जोर शोर से व्याख्याएं दी जा रही हैं। पश्चिमी नेताओं का यह भ्रमपूर्ण विचार है कि समस्त हिन्द-चीन साम्यवादियों के हाथ में आ जाने के बाद इन साम्यवादियों की, पड़ोसी देशों पर, आक्रमणकारी गतिविधियां प्रारंभ हो जायेंगी।"[18]

ऐडम मलिक ने "डोमिनो सिद्धान्त" को पुराना बताया। उन्होंने कहा कि इस सिद्धान्त को बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किया जा रहा है जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया की जनता डर जाए व अपने आपको अमेरिका पर निर्भर रखे। उन्होंने कहा कि वियतनाम की साम्यवादी सेनाएं साम्राज्यवादी सेनाओं में परिवर्तित नहीं हो सकतीं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि साम्यवादी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि साम्यवादी विचारधारा उन्हें साम्राज्यवादी होने के लिए नहीं कहेगी। वे यह उम्मीद करते हैं कि हिन्द-चीन में साम्यवाद जिसकी स्वयं की अपनी विशेष पहचान है आसियान देशों-थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जो इस क्षेत्र (दक्षिण-पूर्व एशिया) में एक बल का विकास कर चुके हैं, के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहेगा। इस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अपने क्षेत्र में किसी बड़े शक्ति के प्रभाव का सामना कर सकने में सक्षम हो सकेंगे।[19] ऐडम मलिक ने पत्रकारों के साथ एक बातचीत में कम्पूचिया की आसियान की सदस्यता के बारे में कहा :

"अच्छा होता अगर कम्पूचिया आसियान का सदस्य बन जाए।"[20]

इंडोनेशिया के अनुसार हिन्द-चीन के परिवर्तन से आसियान की 'ज़ोपफान' नीति को लागू करने में सरलता होगी। इसके समर्थन में बोलते हुए विदेश मंत्री ऐडम मलिक ने कहा :

---

18. एस० डब्ल्यू० बी०, पं०-10, एफ-ई/4880/ए-3/1, 17 अप्रैल, 1975।
19. वही।
20. एस० डब्ल्यू० बी०, एफ ई/4889/ए-3/8, 28 अप्रैल, 1975।

"हिन्द-चीन में नया विकास दक्षिण-पूर्व एशिया की शान्ति, स्वतंत्र, तथा तटस्थ क्षेत्र में परिवर्तित करने की घोषणा के कार्यान्वित करने के लिए एक प्रगतिशील प्रयास होगा। हिन्द-चीन के वर्तमान विकास से पहले दक्षिण-पूर्व एशिया की "ज़ोपफान" घोषणा जिसे नवम्बर 1971 में आसियान ने पारित किया था, को कार्यान्वित करना सम्भव न था।"[21]

हिन्द-चीन देशों के साथ सहयोग पर इंडोनेशियाई सरकार ने स्वीकारात्मक विचार अपनाए। इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय के अधिकारी व विदेश मंत्री एडम मलिक के सहायक जनरल एच० आर० डारसोनो के अनुसार :

"दक्षिण-पूर्व एशिया में महाशक्तियों द्वारा संभावित खतरे से बचने के लिए आसियान देशों को हिन्द-चीन के साम्यवादी राज्यों से आपसी सहयोग की आवश्यकता है तथा इस प्रकार के सहयोग से इस क्षेत्र में वर्तमान स्थिरता की रक्षा की जा सकती है।"[22]

हिन्द-चीन के नए परिवर्तित स्थिति के संदर्भ में, 13 मई, 1975 को कुआलालम्पुर में हुए आसियान के विदेशमंत्रियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशियाई विदेश मंत्री एडम मलिक ने कहा :

"हिन्द-चीन में शान्ति, समस्त दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की वास्तविक शान्ति व उन्नति के शुरूआत की प्रतीक है। शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धान्त---- इस क्षेत्र में संबंध स्थापित करने के मूलभूत आधार होंगे।"[23]

इंडोनेशिया भी हिन्द-चीन को आसियान में शामिल करने के पक्ष में था। 11 फरवरी 1976 को कुआलालम्पुर में इंडोनेशियाई विदेश मंत्री एडम मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा :

21- एस० डब्ल्यू० बी०, सं० 10, एफ ई/4898/ए-3/16, 8 मई 1975।

22- स्ट्रेट्स टाइम्स, 12 मई 1975।

23- एस० डब्ल्यू० बी०, सं०-10, एफ ई/4904/ए-3/9, 15 मई 1975।

"वैचारिक व सामाजिक प्रणालियों में अन्तर होने से हिन्द-चीन के देशों को आसियान में शामिल होने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आसियान की सदस्यता हेतु अभी भी हिन्द-चीन देशों का स्वागत है।"[24]

एडम मलिक ने विस्तारपूर्वक कहा :

"अभी तक हिन्द-चीन के देशों की तरफ से आसियान में शामिल होने की पहल नहीं दिख रही है। संभवतः इसका कारण उनके अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त रहना है। परन्तु हिन्द-चीन देशों ने आसियान द्वारा प्रस्तावित मित्रता की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया है जिसकी झलक हमें मिल रही है।"[25]

इंडोनेशिया ने हिन्द-चीन को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जिससे उसकी क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता हो और वह दो महासाम्यवादी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो सके। इस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया से साम्यवादी शक्तियों को दूर रख आसियान देशों की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। इसके समर्थन में एडम मलिक ने कहा :

"आसियान उत्तरी वियतनाम की सहायता करना चाहता है जिससे वह दोनों साम्यवादी शक्तियों सोवियत संघ व चीन के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो सके। हम आसियान देश उन्हें इसके लिए प्रेरित करेंगे।"[26]

सिंगापुर :

अप्रैल, 1975 में आसियान देशों ने दोनों वियतनाम को आसियान की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया था जिसका मुख्य उद्देश्य महाशक्तियों से दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिरता को कायम रखना था।[27] परन्तु सिंगापुर की हिन्द-चीन के

24- वही, एफ ई|5133|ए-3|6, 13 फरवरी 1976। 25- वही।

26- स्ट्रेट्स टाइम्स, 13 मई, 1976।

27- द आस्ट्रेलियन, (कैनबरा), 3 मई, 1975।

प्रति नीतियाँ अन्य आसियान सदस्यों जैसी नरम न थी । 13 मई 1975 में हुए आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में सिंगापुर के विदेश मंत्री राजारत्नम् ने कहा :

"आसियान देश हिन्द-चीन से मजबूत हैं । हम लोगों को उन्हें सदस्य बनाने के लिए उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए अपितु वे हम लोगों के पीछे पड़ें --- मुख्य खतरा बाहरी आक्रमण का नहीं है बल्कि आंतरिक विद्रोह से है ।"[28]

सिंगापुर के विदेश मंत्री की उपरोक्त बात से पता चलता है कि आसियान देशों का हिन्द-चीन से संबंध बनाने अथवा उनसे सहयोग व सदस्य बनाने का अभिप्राय बाहरी खतरे से बचना है और वह तथाकथित बाह्य खतरा हिन्द-चीन के साम्यवादी देश हैं इस प्रकार के कई अन्य आसियान के प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा अन्तर्विरोध पूर्ण वक्तव्य दिए जाते रहे हैं ।

अनतारा के महानिदेशक मुहम्मद नाहार को सिंगापुर के प्रधान मंत्री ली कुवान यू द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में ली ने आसियान व हिन्द-चीन के सामाजार्थिक व राजनीतिक संबंधों के अन्तर्विरोधों को स्पष्ट करते हुए कहा :

"हिन्द-चीन अपनी राजनीतिक प्रणाली में अब साम्यवादी हो चुका है । आसियान देश व्यक्तिगत उद्यम में विश्वास रखते हैं, इन दोनों प्रणालियों में अन्तर्विरोध है परन्तु इसका अभिप्राय: कदापि यह न होगा कि हमारे द्विपक्षीय लाभ के लिए आर्थिक सहयोग का कोई रास्ता ही नहीं है । वास्तव में हम इस प्रकार के सहयोग का स्वागत करते हैं पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों पक्षों की राजनीतिक व आर्थिक प्रणालियों में मतभेद हैं --- ।"[29]

फिलीपींस :

हिन्द-चीन में अप्रैल, 1975 में हो रहे परिवर्तन से फिलीपींस को काफी चिन्ता व अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों पर संदेह होने लगा । इस परिवर्तन पर चिन्ता

---

28. स्टेट्समैन (नयी दिल्ली) 15 मई, 1975 ।
29. एस0 डब्ल्यू0 बी0, सं0 10, एफ-ई।5070।ए-317, 27 नवम्बर, 1975 ।

व्यक्त करते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति मारकोस ने 17 अप्रैल 1975 को आसियान देशों की शीघ्र उच्च शिखर सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा जिसमें हिन्द-चीन में परिवर्तन के संदर्भ में दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया जाए। हिन्द-चीन में परिवर्तन, जिसमें कम्बोडिया की सरकार का पतन व खमेर रूज का शासन में आना व विश्लेषण होना चाहिए कि दक्षिण-पूर्व एशिया पर इस हिन्द-चीन परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा?"[30]

हिन्द-चीन के परिवर्तन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 20 अप्रैल, 1975 को फिलीपींस के राष्ट्रपति मारकोस ने अमेरिका पर द०पू० एशिया की सुरक्षा के विषय पर संदेह प्रकट किया। इसलिए उसने अमेरिका के साथ अपनी तत्कालिक संधियों तथा फिलीपींस में स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डों की भी शीघ्रता से समीक्षा करने का आदेश दिया।[31]

राष्ट्रपति मारकोस के अनुसार कम्बोडिया व दक्षिण-वियतनाम के पतन से फिलीपींस व दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों को कोई बाह्य खतरा नहीं हो सकता। एक प्रश्न--"क्या कम्बोडिया व दक्षिण वियतनाम का पतन दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आर्थिक व सैनिक असुरक्षा को बढ़ावा देगा?" के उत्तर में मारकोस ने 28 अप्रैल, 1975 को कहा :

"वर्तमान समय में मैं, दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी प्रकार के बाह्य खतरे को नहीं देख रहा हूं। मैं उस दक्षिण-पूर्व एशिया की बात कर रहा हूं जो मुख्य धरती (चीन) से अलग है। जब आप चीन की मुख्य धरती (चीन लोक गणराज्य) की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से सदैव खतरा रहता है परन्तु फिलीपींस समुद्र के कारण ऊपरी तौर पर इस खतरे से मुक्त है। हमारे पश्चिम व उत्तर दिशा से इस अशान्ति से पृथक्करण हेतु देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम

---

30. बैंकाक पोस्ट, 18 अप्रैल, 1975, समरी ऑफ वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट, एफ ई/4886/ए-3/13, 24 अप्रैल, 1975, एफ ई/4888/ए-3/14, 26 अप्रैल, 1975।

31. हिन्दुस्तान टाइम्स, 21 अप्रैल, 1975।

उठाए जाने चाहिए।"[32]

राष्ट्रपति मारकोस ने 12 मई, 1975 को अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि राष्ट्रीय हित में अगर आवश्यकता पड़ी तो फिलीपींस से अमेरिकी सैनिक अड्डों की समाप्ति कर दी जायेगी तथा अमेरिका के साथ आपसी प्रतिरक्षा संधि को भी रद्द कर दिया जायेगा।[33] मारकोस ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बल दिया तथा "अमेरिकियों की वापसी" की नीति को स्पष्ट किया।[34]

फिलीपींस के अमेरिका के साथ संबंध-नीति में लगातार बढ़ते अन्तर्विरोधों के कारण, मारकोस ने उत्तरी वियतनाम के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे हनोई से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया जा सके।[35]

थाईलैंड :

हिन्द-चीन में साम्यवादी विजय ने आसियान देशों में थाईलैण्ड को विशेष रूप से अत्यन्त विपत्ति काल जिसमें तथाकथित "डोमिनो सिद्धान्त" की सत्यता की जाँच की स्थिति में लाकर रख दिया था।[36] थाईलैण्ड की लम्बी सीमा उत्तर व उत्तर-पूर्व में लाओस व पूर्व में कम्बोडिया के साथ है जहाँ पर साम्यवादी सरकार का पदार्पण हो चुका था। और हिन्द-चीन युद्ध में थाईलैण्ड साम्यवादी शक्तियों के विरोधियों का पुराना मित्र व सहयोगी रह चुका था।[37] परन्तु हिन्द-चीन में संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए थाई प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने इसे खतरनाक नहीं मानते हुए 21 मार्च 1975 को कहा :

32- हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 अप्रैल, 1975।

33- बैंकाक पोस्ट, 13 मई, 1975।

34- वही।

35- हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 अप्रैल, 1975।

36- भट्टाचार्या, सं0-1, पृष्ठ- 460।

37- वही।

"थाईलैण्ड शीघ्र ही कम्पूचियाई सैनिकों को प्रशिक्षण देना बन्द कर देगा क्योंकि हम कम्पूचिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते दीखना नहीं चाहते। खमेर रूज का कम्पूचियाई राजधानी नामपेन्ह की तरफ बढ़ने से थाई आंतरिक सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है। अगर नामपेन्ह में साम्यवादी सरकार भी बन जाती है तब भी यह युद्ध थाईलैण्ड की ओर नहीं बढ़ सकेगा।"[38]

थाई विदेश सचिवालय के अनुसार अगर लोन नोल हार जाते हैं तथा कम्पूचिया में राजकुमार सिंहानुक की सरकार बनेगी तो थाईलैण्ड कम्पूचिया में सिंहानुक की नयी सरकार को मान्यता देगा। 30 मार्च, विदेश मंत्री चातिचाए चुन्हावान ने कहा :

"कम्पूचिया में नयी सरकार चाहे सिंहानुक बनायें या कोई अन्य यह कम्पूचिया का अपना आंतरिक मामला है हम उसे मान्यता देंगे।"[39]

थाईलैण्ड ने भी नामपेन्ह सरकार के पतन होने तथा 17 अप्रैल, 1975 को खमेर रूज के सरकार की स्थापना के तुरन्त बाद आसियान देशों के राजदूतों की एक बैठक बुलाकर सामूहिक रूप से खमेर रूज को मान्यता देने के लिए बातचीत की थी।[40] 21 अप्रैल, 1975 को थाई विदेश मंत्री मेजर जनरल चाटिचाए चुन्हावान ने थाई-कम्पूचिया संबंध पर बोलते हुए कहा :

"थाई-कम्पूचिया संबंध में कोई परेशानी नहीं है। थाईलैण्ड कम्पूचिया से केवल यही चाहता है कि वह तटस्थ बना रहे।"[41]

हिन्द-चीन में हो रहे परिवर्तन के परिणामस्वरूप थाईलैण्ड ने अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करते हुए प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने संवाददाताओं से 22 अप्रैल, 1975 को कहा :

38- <u>एशियन टाइम्स</u>, 22 मार्च, 1975।

39- <u>बैंकाक पोस्ट</u>, 31 मार्च, 1975।

40- भट्टाचार्या, सं०-1, पृष्ठ-461।

41- <u>एस० डब्ल्यू० बी०</u>, एफ ई। 9886। ए-3। 11, 24 अप्रैल, 1975।

"थाईलैण्ड अमेरिका से सहायता लेने की नहीं सोच रहा । थाई आत्मनिर्भर बने तथा राजनीतिक व वैचारिक मतभेदों के होते हुए भी वह सभी देशों के साथ संबंध बनाए ।"[42] कम्पूचिया में साम्यवादी सरकार की स्थापना से उत्पन्न भय की विरोध में अपने विचार प्रकट करते हुए थाई उप प्रधान मंत्री व प्रतिरक्षा मंत्री जनरल परामान आदिरेकसान ने कहा :

"कम्पूचिया की जनसंख्या थाई से काफी कम है तथा नामपेन्ह की नयी नेतृत्व से थाईलैण्ड को कोई खतरा नहीं हो सकता ।"[43] इसी साथ-साथ विदेश मंत्री चातिचाए चुन्हावान ने 1 मई, 1975 को कहा कि थाईलैण्ड दक्षिण वियतनाम की नयी सरकार, "अंतरिम क्रान्तिकारी सरकार" (दे प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट) को मान्यता देगी ।[44]

आसियान देशों का हिन्द-चीन के साथ संबंध बनाने का कारण भय नहीं था, इसी समर्थन में थाई प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने 9 जून, 1975 की अपनी तीन दिवसीय कुवालालम्पुर यात्रा के दौरान कहा : "थाईलैण्ड का हिन्द चीन के साथ संबंध बनाने का कारण डर अथवा हमारी कमजोरी नहीं है । कुछ लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि हिन्द-चीन में घटित हाल की घटनाओं के कारण हम संबंध बढ़ाना चाहते हैं ।[45]

हिन्द-चीन को आसियान में शामिल करने की आसियान देशों की प्राय: एक-सी राय व विचार थी तथा इसी विचार के समर्थन में थाई प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने 13 जून, 1975 को कहा :

"आसियान सदस्य देशों ने हिन्द-चीन के देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने की इच्छा व्यक्त की है तथा आशा करते हैं कि एक न एक दिन वे आसियान में शामिल होंगे । अगर वे ऐसा करते हैं तो आसियान उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करेगा ।"[46]

42- वही ।

43- वही ।

44- फ्रंटियर पोस्ट, 2 मई, 1975 ।

45- न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स, (कुवालालम्पुर) 10 जून, 1975 ।

हिन्द-चीन के परिवर्तन के समय आसियान के घनिष्ट संबंधों की आवश्यकता पर, सिंगापुर विदेशी प्रतिनिधि कक्ष में बोलते हुए क्लारित प्रमोज ने थाई विदेश नीति के बारे में कहा :

"हमारे पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है पर हमें एक दूसरे के साथ सहिष्णुता की भावना तथा आपसी आत्मविश्वास व आस्था के साथ रहना, तालमेल करना सीखना है --- हमारी विदेश नीति की बुनियादी आवश्यकता पुरानी वैमनस्यता को दफनाना, पुराने भय पर विजय पाना, नए रास्तों की शुरुआत, बिगड़े संबंधों पर ध्यान तथा वर्तमान मित्रता को मजबूत करना है।"[47]

क्लारित प्रमोज ने हिन्द-चीन के साम्यवादी शक्तियों के संभावित खतरे तथा उनके थाईलैण्ड में विस्तार को रोकने के बारे में कहा :

"हम थाई आश्वस्थ हैं कि हमारा देश उन कुछ दक्षिण-पूर्व एशिया (हिन्द-चीन) की तरह साम्यवादी चपेट में नहीं आ सकता। इसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थाई बहुसंख्यकों में एकता है तथा वे राजा के प्रति निष्ठावान हैं जो सारे नागरिकों के लिए चिंतित रहते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं। तथापि लाओस, वियतनाम, व कम्पूचिया में सरकारों के गिरने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिससे हम संभावित खतरों से अपने देश को बचा सकें। थाईलैण्ड कई खतरों का सामना कर रहा है परन्तु हम केवल साम्यवादी खतरे की बात करते हैं जिसका भय कई देशों में बना हुआ है। साम्यवादी हमारे देश के लिए सर्वाधिक खतरनाक है। साम्यवादी साम्राज्यवाद का विस्तार हिन्द-चीन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। वे आंतरिक व बाह्य दोनों तरह से लोकप्रिय सरकार को गिराने के लिए प्रयत्नशील हैं जिसका उद्देश्य उनकी राष्ट्रीय सत्ता, स्वतंत्रता व अस्तित्व को बरबाद करना है। साम्यवादी साम्राज्यवाद सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया को अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में लाना चाहता है तथा वह लाओस वियतनाम व कम्पूचिया में ऐसा करने में सफल भी हुआ है। थाईलैण्ड उनके लिए

46- एस0 डब्ल्यू0 बी0, एफ-ई।4929।ए-3।5, 14 जून, 1975।

47- बर्नार्ड वाइडमान, "अ फेयरवेल टू सीटो", फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू, (हांगकांग), 8 अगस्त, 1975, पृष्ठ-20।

एक बड़ा उपहार बना हुआ है जिसे साम्यवादी साम्राज्यवादी लेना चाहते हैं। वे इसके लिए गुप्त व प्रत्यक्ष रूप से समस्त प्रयास कर रहे हैं तथा इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे।[48]

हिन्द-चीन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आसियान देशों का अमेरिका के प्रति मोह भंग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। एशियन ग्रोपनिस्की के अनुसार आसियान देशों में दक्षिण-पूर्व एशिया की सुरक्षा मानसिकता पर अन्तर्विरोध भी मौजूद है। दक्षिण-पूर्व एशिया में हिन्द-चीन की घटना के बाद शक्ति संतुलन निश्चित रूप से पलट गया था।[49] 1975 में हुए परिवर्तन के बाद आसियान देशों की सुरक्षा समस्या की दिशा ही बदलने लगी जिससे नयी सुरक्षा मानसिकता का जन्म हुआ जो वियतनामी व सोवियत सैनिक खतरे से परिपूर्ण माना जाता था तथा आसियान देशों को इस बात की चिंता थी कि अगर सोवियत समर्थित वियतनाम या हिन्द-चीन से किसी प्रकार का साम्यवादी आक्रमण होता है तो थाईलैण्ड को किस प्रकार की सैनिक सहायता व सहयोग दी जानी चाहिए -- यह बात आसियान के लिए महत्वपूर्ण विषय-वस्तु था।[50] इसके अतिरिक्त द०पू० एशिया में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी व आसियान देशों की सुरक्षा के प्रश्न पर आसियान देशों के बीच मतभेद थे। इंडोनेशिया ने समस्त प्रकार की विदेशी शक्तियों को दक्षिण-पूर्व एशिया से बाहर चलेजाने पर बल दिया। इसका मुख्य कारण हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तनाव था तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से बाह्य शक्तियों के चले जाने से इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया के गैर साम्यवादी देशों में सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिक देश बन जाता जो दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में इंडोनेशिया के पक्ष में होता। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री एडम मलिक ने दक्षिण-पूर्व एशिया में तटस्थीकरण व विदेशी सैनिक अड्डों के बारे में अपने विचार रखते हुए कहा :

48- स्स० डब्ल्यू० बी०, एफ-ई।5234।ए-315, 15 जून, 1976।

49- एशियन, सं०-4, पृष्ठ- 39।

50- एशियन सेक्युरिटी 1981, रिसर्च इन्स्टीच्यूट फॉर पीस एण्ड सेक्युरिटी, (तोक्यो, 1981) पृष्ठ- 110।

"..... हिन्द-चीन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब यह काफी आसान हो गया है कि तटस्थीकरण की ज़ीपकान नीति को प्रयोग व व्यवहार में लाया जाए। अब समय आ गया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया से विदेशी सैनिक अड्डों को समाप्त कर हटा दिया जाए।.... दक्षिण-पूर्व एशिया की शक्ति किसी बाह्य बड़ी शक्तियों के साथ सैनिक संधि के परिणाम स्वरूप नहीं होनी चाहिए अपितु प्रत्येक देश की शक्ति राष्ट्रीय समुत्थान पर आधारित होनी चाहिए जो बाद में क्षेत्रीय संगठित शक्ति के रूप में विकसित हो जाए..... अगर इस क्षेत्र से बड़ी शक्तियों के सैनिक आधारक्षेत्रों को बाहर कर दिया जाए तो यह समस्त दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के हित व पक्ष में होगा।"[51]

दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र से बाह्य शक्तियों के चले जाने से संभावित रिक्त क्षेत्र बनने के विचार का खण्डन करते हुए इंडोनेशिया के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल मारादीन पांगाबीन ने भी विचार प्रकट किया कि वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों के चले जाने से इस क्षेत्र में रिक्तता नहीं बन सकेगी। परन्तु वे स्थानीय साम्यवादियों के बारे में काफी चिंतित थे और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया भूमिगत साम्यवादियों के विरुद्ध कार्रवाई तीव्र करेगा क्योंकि हिन्द-चीन में साम्यवादी विजय का प्रभाव पड़ने की आशंका है।[52]

हिन्द-चीन में परिवर्तन के बाद सिंगापुर के प्रधान मंत्री ली कुआन यू ने एशिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का कड़ा विरोध किया तथा कहा कि इससे रूसियों को दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा। अगर अमेरिका जल्दीबाजी में इस क्षेत्र से वापस चला गया तो सोवियत संघ को इस क्षेत्र में अन्दर घुसने का अवसर मिल जाएगा। इस स्थिति से थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस व इंडोनेशिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने राय दी कि इस क्षेत्र के

51- भट्टाचार्या, सं०-1, प्रकाशित निबंध में उद्धृत।

52- वही।

देशों को चीन का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सबसे अधिक हितैषी साम्यवादी शक्ति हैं जिसकी कोई विस्तारवादी इच्छा नहीं है। ली ने कहा कि केवल चीन व वियतनाम अपने आपको हस्तक्षेप से रोकें तो इससे थाईलैण्ड अमेरिका की तरफ झुकाव पर सावधानी से ध्यान देगा तथा चीन को रूस आवश्यकता के रूप में स्वीकार करेगा। परन्तु अगर थाईलैण्ड ने चीन के विरुद्ध संतुलन के लिए रूस का प्रयोग किया तो इसका काफी खतरनाक परिणाम हो सकता है। इससे उन्हें बचना चाहिए। ली ने दक्षिण वियतनाम में साम्यवादी विजय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हिन्द-चीन के पड़ोसी देश विशेषकर थाईलैण्ड व मलेशिया सोवियत समर्थित नीति अपनाएंगे तो चीन निश्चित रूप से उन देशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र कर सकता है। ली ने आसियान देशों के लिए मुख्य समस्या आर्थिक उत्थान को बतलाते हुए बलपूर्वक कहा कि बेरोजगारी व मंदी के कारण जनता में असंतुष्टी बढ़ती है और बढ़ती हुई विरक्ति व असंतोष लघु स्तर के विद्रोह को उच्च स्तरीय क्रान्ति में परिवर्तित कर डालेगी।[53] उन्होंने आसियान के पांचों देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ाने पर बल दिया। ली ने अपनी सुरक्षा व स्थिरता के हित में अमेरिका से अनुरोध किया कि वह पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखे। उन्होंने कहा कि हिन्द-चीन के बाद अमेरिका को अब कोई घाटा नहीं होगा अगर वह यह स्पष्ट रूप से तय कर ले कि आगे आने वाली गतिविधियों का अमेरिका अपनी पूरी सामर्थ्य व शक्ति, जो उसके पास है, के साथ उनका विरोध करेगा।[58]

ली कुआन यू ने दक्षिण वियतनाम द्वारा प्राप्त किए अमेरिकी हथियारों को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए खतरनाक बताते हुए कहा :

"चिन्ता इस बात की है कि बहुत अधिक मात्रा में हथियार जिनमें काफी नए प्रकार के अमेरिकी हथियार हैं जो अब वियतनामी सरकारों- हनोई व सैगोन के पास

53- टेन इयर्स ऑफ आसियान, (जकार्ता, 1978), पृष्ठ- 99।

54- वही, स्ट्रेट्स टाइम्स, 6 मई, 1975, कृ० भट्टाचार्या, खं० 1, निबंध भी देखें।

रह गए हैं । अगर ये हथियार एशिया या किसी अन्य स्थान के विद्रोहियों के हाथ पड़ जाएं तो इससे भय का होना स्वाभाविक ही है ।"[55] ली का विचार था कि ऐतिहासिक अनुभवों व कारणों से थाईलैण्ड अन्ततोगत्वा पेंडुलम की उपस्थिति को ही उपयोगी समझेगा जिससे वियतनामी खतरे का प्रभाव कम हो सकेगा ।[56]

सिंगापुर के विदेश मंत्री एस० राजारत्नम् ने 15मई 1975 को कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है पर उनकी मौजूदगी एक विशेष संतुलन में होनी चाहिए ।[57]

फिलीपींस के विदेश मंत्री रोमुलो ने बाह्य खतरे की अपेक्षा आंतरिक खतरे पर बल देते हुए कहा :

"आज दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सर्वाधिक खतरा बाहरी आक्रमण का नहीं है अपितु घरेलू विद्रोह व घुसपैठ के जटिल रूपों से है ।"[58]

इसी विचार को विस्तृत रूप से इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुहार्तो ने जाकार्ता में 9 जुलाई, 1975 को कहा :

"वास्तविक साम्यवादी शक्ति हथियारों में नहीं छुपा करती बल्कि उनके वैचारिक धर्मान्धता में होती है तथा इसकी आधुनिक हथियारों से समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु इसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वैचारिक धर्मान्धता को देनी होगी ।"[59]

55- एस०डब्ल्यू० बी०, एफ-बी०।4896।ए-3।8, 6 मई, 1975 ।

56- वही ।

57- स्ट्रेट्स टाइम्स, 16 मई, 1975 ।

58- एस०डब्ल्यू० बी०, एफ-बी०।4904।ए-3।9, 15 मई, 1975 ।

59- वही, एफ-बी०।4952।ए-3।1, 11 जुलाई, 1975 ।

इसी क्रम में राष्ट्रपति सुहार्तो ने आसियान देशों को चेतावनी देते हुए कहा :

"..... दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवादी विस्तार या प्रभाव को रोकने के लिए इस क्षेत्र के देशों में राष्ट्रीय उत्थान की आवश्यकता है और हम इंडोनेशिया में राष्ट्रीय उत्थान पर ध्यान दे रहे हैं।"[60]

मनीला पैलेस में आसियान सदस्य देशों से आए युवकों के स्वागत में राष्ट्रपति सुहार्तो ने सितम्बर, 1975 में कहा :

"आसियान देशों को खतरा उनके आंतरिक साम्यवादी तत्वों से है जिससे गैर साम्यवादी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडोनेशियाई अनुभवों ने यह दिखा दिया है कि साम्यवादी खतरे का मुकाबला राष्ट्रीय उत्थान द्वारा किया जा सकता है न कि सैन्य शक्ति से।... प्रतिरक्षा, सैनिक व राजनीतिक संधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समस्त देश अपनी राष्ट्रीय उत्थान को मजबूत बनाएं तथा उसके बाद क्षेत्रीय उत्थान को मजबूत बनाएं जिससे शांति की स्थापना न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में अपितु सम्पूर्ण विश्व में की जा सके।"[61]

ऐतिहासिक रूप से थाईलैण्ड ने नए परिवर्तनों के साथ निपटने के लिए जिससे उनकी स्वतंत्रता व सुरक्षा बनी रहे सदैव अपनी महान व विशिष्ट नीतियों को दिखलाया है। हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन के बाद भी उसकी इस नीति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है यद्यपि थाईलैण्ड, हिन्द-चीन युद्ध में, अमेरिका के साथ था व अमेरिकी सैनिक अड्डों को थाईलैण्ड में अनुमति दी थी। परन्तु हिन्द-चीन में साम्यवादियों की सफलतापूर्वक विजय व अमेरिका की पराजय के परिणामस्वरूप थाईलैण्ड, अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए, सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो गया कि समस्त अमेरिकी सैनिक साज-समान व व्यक्ति जून 1975 तक उबोन रातचाथानी के उत्तर-पूर्व

60- वही।

61- वही, एफ-बी।50111।ई-3।3, 11 सितम्बर, 1975।

वायु सैनिक अड्डे से हटा लिए जाएंगे । थाई सरकार पहले भी अमेरिकी सरकार से बातचीत कर चुकी थी जिसके अनुसार थाईलैण्ड से 7500 अमेरिकी सैनिकों तथा अज्ञात संख्या में जहाजों की वापसी की बात थी ।[62] थाई शाही सरकार के अनुसार मार्च 1976 तक सम्पूर्ण रूप से अमेरिकी सैनिक अड्डों की समाप्ति कर दी जाएगी ।[63] कुछ विद्वानों के मतानुसार थाईलैण्ड ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेरिकी सैनिक अड्डों को 1976 में बन्द करने का आदेश दिया ।[64]

थाई प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने आर्थिक व सामाजिक विकास के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्थिरता व प्रगति मुख्यत: आर्थिक व सामाजिक विकास पर आधारित होती है ।[65]

आसियान देश 11 फरवरी 1976 को पटाया में हुए बैठक में तीन हिन्द-चीन देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व पर तैयार हो गए ।"[66]

राष्ट्रपति मारकोस ने अपने भाषण में कहा :

"आसियान न तो सैनिक ना ही राजनीतिक संगठन समूह है । आसियान किसी देश या राष्ट्र के पक्ष अथवा विपक्ष में, या किसी विचार, आर्थिक या राजनीतिक प्रणाली के पक्ष या विपक्ष में नहीं है । चार बड़ी शक्तियां- अमेरिका, सोवियत संघ, चीन व जापान एशिया में अपनी रुचि को उचित ठहराते हैं ।"[67]

दक्षिण-पूर्व एशिया की सुरक्षा के प्रश्न पर बोलते हुए मारकोस ने कहा :

"यह स्पष्ट है कि आसियान अगले कुछ वर्षों में शायद अगले दस वर्षों में किसी वाह्य आक्रमण के खतरे का अनुमान नहीं लगा रहा है । मुख्य खतरा व भय

62- अमेरिका थाईलैण्ड के अनुरोध पर सहमत हो गया जिसके अनुसार थाईलैण्ड से एक वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी । कृ0 देखें, भट्टाचार्या, सं0 1 ।

63- स्ट्रेट्स टाइम्स, 19 मई, 1975 ।

64- एशियन सैक्युरिटी-1981, (तोक्यो, 1981), पृष्ठ- 107 ।

65- 10 इयर्स ऑफ आसियान, (जाकार्ता, 1978), पृष्ठ- 104

66- मैनिची डेली - न्यूज (तोक्यो) 12 फरवरी, 1976 ।

67- एस0 डब्ल्यू0बी0, एफ-ई।5145।ए-3।2, 27 फरवरी, 1976 ।

प्रत्येक राष्ट्रों को उनके विरुद्ध विद्रोह व आर्थिक समस्याओं का है। इन विद्रोहों को रोकने का हथियार समस्याओं को समाप्त करना है - विशेषकर आर्थिक समस्याओं को। तथा सामाजिक व आर्थिक विकास कर इन खतरों का सामना कर सकते हैं। अत: हमें अपनी आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देना होगा। यह तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि विद्रोहों व क्रान्तिकारी गतिविधियों के विरुद्ध सर्वाधिक प्रभावशाली हथियार सदैव ही आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय रहा है।[68]

24 जून, 1976 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया को भविष्य में बड़ी शक्तियों के प्रति स्पर्धा से बचाने के लिए 'ज़ोपफान' को शीघ्र क्रियान्वित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि हिन्द-चीन में युद्ध समाप्त हो चुका है फिर भी इस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इसका कारण इस क्षेत्र में चीन-सोवियत प्रतिस्पर्धा के बढ़ने तथा वियतनाम के नए सैनिक शक्ति के रूप में उभरना है।[69] इस आसियान सम्मेलन में ऐडम मलिक ने कहा कि आसियान इस क्षेत्र में संभावित वास्तविकताओं से निपटने के लिए तैयार है। 25 करोड़ आसियान जनता की शान्ति, स्वतंत्रता व प्रगति निरन्तर गतिशील रहेगी।[70] फिलीपींस के विदेश मंत्री कारलोस रोमुलो ने आसियान के सामने खड़े चार मुख्य सुरक्षा संबंधित प्रश्न सामने रखे -- क्या सोवियत संघ व चीन लोक गणराज्य के बीच तनाव समाप्त होगा जो मुख्य रूप से युद्ध का द्वार या प्रारंभीकरण है? क्या अमेरिका के एशिया से हटने से दूसरी शक्तियों के इशारे पर आन्दोलनों को प्रश्रय मिलेगा?, क्या वियतनाम एक सैनिक शक्तिशाली देश होने के कारण हिन्द-चीन पर अपना प्रभुत्ववाद के लिए प्रयत्न करेगा और अगर वह ऐसा करता है तो उसका तत्काल प्रभाव आसियान देशों पर क्या पड़ेगा? तथा इस प्रकार की जटिल समस्याओं को देखते हुए क्या जापान भी अपनी उच्च शक्ति स्थान की क्षमता का परिचय देने का प्रयत्न करेगा?[71]

68- वही, कु0 देखें - 10 इयर्स ऑफ आसियान, (जाकार्ता, 1978), पृ0-98।

69- स्ट्रेट्स टाइम्स, 25 जून, 1976।

70- वही।

71- वही।

28 जून, 1976 को दक्षिण-पूर्व एशिया में बहु-शक्ति उपस्थिति के पक्ष में बोलते हुए सिंगापुर के विदेश मंत्री राजारत्नम् ने कहा :

"दक्षिण-पूर्व एशिया में बहुशक्ति उपस्थिति होनी चाहिए । इससे क्षेत्र के देशों के लिए अच्छा होगा क्योंकि इससे इस क्षेत्र में किसी विशेष शक्ति का प्रभुत्व नहीं बन सकता ।"[72]

फिलीपींस ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैनिक की उपस्थिति का समर्थन करते हुए 16 नवम्बर, 1976 को मारकोस ने कहा :

"इस क्षेत्र में शान्ति अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत महासागर में रहने से ही हो सकती है । इस क्षेत्र के सभी नेता इस बात से सहमत हैं कि सैनिक संतुलन हेतु अमेरिकी उपस्थिति अति आवश्यक है । हम अमेरिका का न केवल स्वागत करते हैं अपितु हम उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह इस क्षेत्र में रहे ।"[73]

आसियान नेताओं की कूटनीतिक गतिविधियों में उस समय हलचल - सी आ गयी जब थाई आंतरिक मंत्री समाक सुन्दरावेज ने दावा किया कि वियतनाम उनके देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है तथा उन्होंने जाकार्ता को सूचना दी, "इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि हमारे देश में साम्यवादी प्रणाली का जीवन हो -- अगर समय की मांगहुई तो हम सब अंतिम समय तक एक जुट होकर लड़ते रहेंगे ।" इससे अनुमान लगाया गया था कि आसियान के पांचों देश सैनिक संधि कर और अग्रसित होंगे ।[74]

सिंगापुर में थाई प्रधानमंत्री थानिन क्रैविचियन ने कहा :

"साम्यवादियों के विरुद्ध प्रत्येक प्रकार के युद्ध छेड़ने के लिए तैयार होना चाहिए ।"[75]

72- बैंकाक पोस्ट, 13 जुलाई, 1976 ।

73- बैंकाक पोस्ट, 17 नवम्बर, 1976 ।

74- नायन चींगम, "आर्मी काल्स दॅ ट्यून", फॉर ईस्टर्न एकॉनोमिक रिव्यू, 24 दिसम्बर, पृष्ठ- 8 ।

75- वही ।

उन्होंने कहा, "चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक साम्यवादी भय का खतरा बना हुआ है --- हमें अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए।"[76]

डेविड जेनकिंस के अनुसार आसियान निश्चित रूप से सैनिक संधि के पक्ष में नहीं है। आसियान के नेताओं ने इसे पूरी तरह रद्द कर - कर दिया। वे समझते हैं कि इस प्रकार की संधि से वियतनाम को अकारण प्रेरित होने का अवसर मिलेगा।[77]

आसियान देशों के राजनीतिक विचारों में साम्यवादी हिन्द-चीन व चीन के विषय मुख्य प्रभावशाली पहलू हैं जिसमें वियतनाम के रवैए के बारे में मतभेद मौजूद है -- 1975 में मलेशिया का मत था कि वियतनाम आसियान क्षेत्र के शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए स्वीकारात्मक कारण बन सकता है तथा आसियान को कुछ भी नहीं करना चाहिए नहीं तो हो सकता है कि वियतनाम आसियान देशों का विरोधी बन जाए।"[78]

मलेशिया के लिए तो समस्या का समाधान "ज़ोपफान" है। उनके विचार में संभवतः हिन्द-चीन के देश भी "ज़ोपफान" को अन्ततोगत्वा स्वीकार कर लें। कई प्रभावशाली इंडोनेशियाएँ चीन को क्षेत्रीय शान्ति व स्थिरता के लिए अभी भी मुख्य खतरा मानते हैं परन्तु जब तक वियतनाम, आसियान देशों की तरफ वास्तविक मित्रतापूर्ण रवैए का सबूत नहीं दे पाता, तब तक इंडोनेशियाई नेतृत्व वियतनाम से भी सावधान रहने की आवश्यकता पर ध्यान देता है। हिन्द-चीन के साम्यवादी क्रान्तिकारी वचनबद्धता के खतरे से अधिक प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए कुछ इंडोनेशियाई लोगों ने आसियान देशों के बीच घनिष्ठ सैनिक सहयोग के

76- वही।

77- डेविड जेनकिंस, "द नान- एलायंस पैक्ट", फॉर ईस्टर्न एकोनोमिक रिव्यू, अंक 18 मार्च, 1977, पृष्ठ- 13

78- माइकेल रिचर्डसन, द एज (कैनबरा), 10 अक्तूबर, 1975।

विचार भी उठाए थे।[79] जैसे आसियान के कुछ देशों के बीच विद्रोहों के विरुद्ध द्वीपक्षीय सैनिक सहयोग के अभ्यास की स्थापना की गयी थी, जैसे मलेशिया व थाईलैण्ड के बीच इंडोनेशिया व फिलीपींस के बीच, मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच। पर ये सैनिक संधि के विरुद्ध थे।

जनवरी, 1976 में सैनिक संधि के विरोध में, इंडोनेशियाई प्रतिरक्षा मंत्री, जनरल पांगबीन ने घोषणा की :

"किसी प्रकार की सैनिक संधि चाहे वह किसी रूप में ही हो स्वीकार न होगा... इस प्रकार की सैनिक संधि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेगा... जैसे ही ऐसे संधि स्थापित किए जाएंगे, एक सैनिक संधि शीघ्र ही उन देशों द्वारा इसके विरुद्ध स्थापित कर दी जाएगी जो इसके विरुद्ध हैं... परन्तु इसका अभिप्राय: यह कदापि नहीं है कि आसियान देशों के बीच सैनिक व प्रतिरक्षा समस्याओं पर घनिष्ठ सहयोग न हो। इस प्रकार के सहयोग निश्चित रूप से चलते रहेंगे, उदाहरण के लिए मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया व फिलीपींस के बीच और मलेशिया व थाईलैण्ड के बीच। ये सभी अपने उभय सीमा क्षेत्रों में साम्यवादी विद्रोहियों से निपटते हैं।[80]

फरवरी के प्रारंभ में आसियान विदेश मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि फरवरी, 1976 में होने वाले शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में सैनिक या सुरक्षा सहयोग का नाम तक नहीं होगा।

79- वही। वास्तव में इंडोनेशियाई सैनिक समूह ने क्षेत्रीय प्रतिरक्षा संधि के लिए सुझाव नहीं दिए थे बल्कि एक लघु स्तर पर सैनिक सहयोग की बात की गयी थी जिसके अनुसार सामूहिक जल, थल व वायु सैनिक अभ्यासों को शामिल किया गया था जिसमें हथियारों का मानकीकरण, मंत्रों व नीतियों के तौर तरीकों और आसियान सैनिक अध्ययन विद्यालय की स्थापना की बात की गयी थी। इनकी दृष्टि देश के अन्दर विद्रोहों पर थी न कि बाह्य अन्य देशों के आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा संधि के लिए। तु० देखें रिचार्डसन, द एज (कैनबरा), 10 अक्तूबर, 1975।

80- अंतारा न्यूज एजेंसी बुलेटिन (जाकार्ता), 12 जनवरी, 1976।

1976 से ही आसियान सम्मेलनों में सैनिक सहयोग पर समय-समय पर चर्चा होती रहती थी पर इस नीति को कभी प्रश्रय नहीं मिला। यह केवल द्विपक्षीय सदस्य देशों के बीच होता रहा। आसियान इसके बावजूद एक आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बना रहा। बल्कि बाली शिखर सम्मेलन ने इसे औपचारिक रूप से राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित कर दिया।[81]

वियतनाम के बारे में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के संदेह ने आसियान के सामूहिक विचारों को जन्म दिया। आसियान देश वियतनाम से कमसे कम प्रत्यक्ष सैनिक प्रतिद्वन्द्वता की आशा नहीं भी करते फिर भी राजनीतिक व आर्थिक प्रतिद्वन्द्वता की उम्मीद तो करते ही थे। आसियान के सभी सदस्य देशों ने आसियान को सैनिक संधि में विकसित न होने देने के लिए प्रयत्न किया।[82] आसियान देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय समस्या का हल क्षेत्र के अन्दर खोजने पर बल दिया न कि बाह्य सहायता पर निर्भर रहने पर, जो कभी बिना पराधीनता के नहीं होता।

मलेशिया, आसियान क्षेत्र की स्थिरता के खतरे को समाप्त करने के लिए, अपनी "ज़ोपफानें" (ज़ोन आफ पीस, फ्रीडम एण्ड न्यूट्रालिटी) धारणा को प्रमुख नीति मानता रहा और 1975 के अंतिम माहों में "ज़ोपफान" के बारे में कई सरकारी स्तर पर बातचीत की गयी। दक्षिण-पूर्व एशिया में परिवर्तित शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए आसियान के कुछ सदस्यों ने सैनिक-सहयोग के वृद्धि पर भी बल दिया परन्तु जाकार्ता ने "राष्ट्रीय समुत्थान", अपनी इंडोनेशियाई धारणा, जिसका वास्तविक अभिप्राय: "क्षेत्रीय समुत्थान" था, के लिए आह्वान किया।[83]

उपरोक्त धारणाएं आसियान की विशिष्ट शब्दावली बन चुकी हैं तथा आसियान के बुनियादी उद्देश्यों को समझने के लिए मूल मंत्र बन चुकी हैं। राष्ट्रपति सुहार्तो के शब्दों में "राष्ट्रीय समुत्थान" का अभिप्राय: एक देश की प्रगति के लिए

81- एशियन, सं0-4, पृष्ठ-46।

82- वही।

83- वही।

आवश्यक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के निर्माण की क्षमता तथा देश की आवश्यक राष्ट्रीय एकात्मता व पहचान को बनाए रखने के समय समस्त बाह्य खतरों को सामना करने के लिए है ।[84]

दाऊद युसुफ, (तत्कालीन जाकार्ता स्थिति सामरिक व अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र), अन्तर्मुखी धारणा के प्रवर्तक थे । इनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सैनिक संधि अथवा किसी महाशक्ति-सैनिक छत्रछाया के अन्तर्गत संभव नहीं है अपितु आत्मनिर्भरता व घरेलू समस्याओं को दूर कर, आर्थिक व सामाजिक विकास कर, राजनीतिक स्थिरता व राष्ट्रवादी मानसिकता से संभव हो सकती है ।[85] यह इंडोनेशियाई विचार आसियान के बीच सामान्यतः स्वीकार्य है । इस विचार के अनुसार अगर प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय समुत्थान का विकास करता है तो इस प्रकार धीरे-धीरे क्षेत्रीय समुत्थान का विकास होगा जिससे इस क्षेत्र के प्रत्येक देश सामूहिक रूप से अपनी एक जैसी समस्याओं व भविष्य को सही दिशा प्रदान कर सुलझा सकते हैं ।[86]

इंडोनेशिया ने अपनी राय दी कि आसियान को 1975 के हिन्द-चीन में परिवर्तन के बदले में आर्थिक विकास के कदम को दोनों स्तरों -- प्रत्येक देश की राज्य स्तर पर प्रयास व क्षेत्रीय राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर सहयोग में वृद्धि के माध्यम से तीव्र कर देनी चाहिए । विदेशी संचालित घुसपैठ व विद्रोह के विरुद्ध सर्वोत्तम प्रतिरक्षा के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए ।[87]

इसके समर्थन में इंडोनेशियाई विदेश मंत्री ऐडम मलिक ने 14 अप्रैल 1975 को चेतावनी देते हुए जाकार्ता में दूरदर्शन पर एक विशेष बातचीत के दौरान घोषणा की :

84- "रिजनलिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया" (क्षेत्रीय मामलों के आसियान देश के छात्रों के प्रथम सम्मेलन में प्रस्तुत लघु शोधप्रबंधों का संकलन, जाकार्ता, 22 से 25 अक्तूबर, 1970), (जाकार्ता, 1975) पृष्ठ-8 ।

85- वही, पृष्ठ- 80 ।

86- वही, पृष्ठ- 8 ।

87- एशियन, सं0-4, पृष्ठ-41 ।

"डोमिनो सिद्धान्त पर आधारित दक्षिण - पूर्व एशिया में साम्यवादी प्रभाव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त जीवनोपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करायी जाएं। बुनियादी आवश्यकता यह है कि जनता को पर्याप्त सामग्री, कपड़े व शिक्षा उपलब्ध करायी जाए जिससे वे अपनी आपको " वाद " की अच्छाइयों व उसकी बुराइयों से दूर रख सकें। अगर इन जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया तो विभिन्न प्रकार के "वादों", का विकास होगा जो अतिवामपंथी या वामपंथी हो सकता है।"[88]

हिन्द-चीन में नए परिवर्तन के संदर्भ में परसातुआन दल के संसद सदस्य हाजी मुहम्मद सानुसी, जो स्क इस्लाम मुहम्मदिया आन्दोलन के नेता थे, ने इंडोनेशियाई जनता का आह्वान किया कि वे "पांचाशीला" के सिद्धान्त कि रक्षा की भावना से साम्यवादी घुसपैठियों व विद्रोहियों से लड़ें। उन्होंने कहा कि यह अत्यावश्यक है कि सरकार जनता की जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा विकास की गति को तेज करने का प्रयास करे। राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय उत्थान को मजबूत बनाने के लिए देश में धार्मिक सामंजस्य बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए।[89]

सुहार्तो ने आसियान नीति को जनता के बीच ले जाकर उसका सामाजीकरण करने की बात कहते हुए कहा :

"आसियान देशों के बीच सहयोग राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है, तथा इस राजनीतिक इच्छा को न केवल सरकारी स्तर पर अपितु सामाजिक स्तर पर और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में आसियान को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। आसियान का उद्देश्य समस्त देशों में शान्ति व स्थिरता बनाए रखना तथा इन्हें घुसपैठियों व विद्रोह से मुक्त रखना है। सभी सदस्य देशों के उत्थान को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए हमें क्षेत्रीय उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।"[90]

88- एस०डब्ल्यू०बी०, एफ-ई।4880।ए-3।1, 17 अप्रैल, 1975।

89- वही, एफ-ई।4899।ए-3।8, 9 मई, 1975।

90- वही, एफ-ई।5145।ए-3।2, 27 फरवरी, 1976।

थाई प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने क्षेत्रीय सहयोग पर बल देते हुए कहा :

"थाईलैण्ड सदैव इस बात का पक्षधर रहा है कि आसियान सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग हेतु व्यावहारिक व अर्थपूर्ण तथा मजबूत व घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की आवश्यकता है। यह आसियान के प्रगतिशील व सुरक्षा की ओर एक दृढ़ आधार की तरह संगठन की उद्देश्यों के लिए उपयोगी होगा.... आसियान की उपलब्धियां.... उल्लेखनीय व प्रशंसनीय हैं।"[91] उन्होंने आर्थिक सहयोग पर सर्वाधिक बल दिया।

मलेशियाई प्रधानमंत्री दतुक हुसैन ओन ने कहा, " बड़ी समस्याएं जैसे- गरीबी, जनसंख्या में वृद्धि, असुरक्षा, आर्थिक शोषण, प्रदूषण, आदि की समस्याओं का हल केवल सामूहिक क्षेत्रीय सहयोग से कर सकते हैं।" इस प्रकार क्षेत्रवादिता को मलेशिया की विदेश नीति में प्राथमिकता दी गई है उनकी इच्छा है कि विश्व स्तरीय सहयोग जो पहले कभी भी न हुआ हो। इन समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक गुट निरपेक्ष नीतियों का पालन सर्वाधिक उचित होगा। हिन्द-चीन युद्ध के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया को तटस्थ क्षेत्र बनाने का प्रयास अब और अधिक प्रासंगिक होगा जबकि यह क्षेत्र एक क्षेत्रीय स्वीकरण के दौर में प्रवेश कर रहा है। आसियान सुरक्षा संगठन नहीं है इसे होना भी नहीं चाहिए। अन्ततोगत्वा हमारे द्वारा जनता को दिए गए अच्छे जीवन, एक समाज जिसमें सबको न्याय मिले आदि पर हमारी सुरक्षा निर्भर करती है। आसियान अपने बुनियादी उद्देश्यों -- दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग को विकसित करने के बुनियादी उद्देश्यों से प्रयत्नशील नहीं होगा। मलेशिया का यह विचार है कि विवादपूर्ण राजनीति से कोई लाभ नहीं होता। आसियान किसी विचार विशेष से जुड़ा नहीं है, आसियान असैनिक संगठन है, आसियान विरोधी संगठन नहीं है। इसे पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया के हितों के लिए काम करना चाहिए। सहयोग हमारा सिद्धान्त है, विवाद इसका काम नहीं।"[92]

91- वही।

92- वही।

आसियान देशों में वियतनाम के बारे में आम धारणा थी कि इससे पहले कि इन्हें अपना ध्यान दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों की ओर ले जाए इन्हें के अपने आंतरिक दृढ़ीकरण व पुनर्निर्माण तथा दक्षिणी वियतनाम के शान्ति स्थापन में अभी कम से कम पांच-सात वर्ष लग जायेंगे और यह समय आसियान देशों के लिए अच्छा दम लेने का अवसर प्रदान करता था जिसमें आसियान देश अपने आंतरिक मामलों को ठीक-ठाक कर लें तथा अन्तर आसियान-सहयोग के माध्यम से विशेषकर आर्थिक क्षेत्र को विस्तृत करके क्षेत्रीय समुत्थान का विकास कर सकें। हिन्द-चीन व आसियान अपने विशिष्ट वैचारिक परिवेश में आर्थिक व सामाजिक विकास के परीक्षण-काल के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में थे। आसियान को अपने ही प्रयासों से साम्यवादी खतरे से बचने के लिए आगे बढ़ना था। आसियान वियतनाम के साथ मुकाबला करने वाली नीति नहीं अपना सकता था अपितु समझौता वाली नीति का चुनाव करना चाहता था।[93]

1975 के पहले सात वर्षों में आसियान देशों के नेताओं ने अच्छी तरह समझ लिया था कि उन एक समान सरकार व्यवस्था वाले पांचों देशों के सामने सामूहिक सहयोग प्रयास ही एक मात्र सर्वनिष्ठ आर्थिक व राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकल्प था और सैगान सरकार के गिरने के बाद समय आ गया था जब आसियान देशों की शब्दों को कार्य रूप देने की आवश्यकता थी। आसियान को अपने प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के दावे को सिद्ध करने के लिए ठोस उपलब्धियों की आवश्यकता थी। आसियान देशों ने आसियान के परामर्श व निर्णय बनाने वाले विभागों की आपात आर्थिक सहयोग की आवश्यकताओं का पुनरावलोकन की महत्ता को समझा। इस प्रकार की आपात व उद्देश्यपूर्ण मानसिकता आसियान देशों में 1975 के पहले कभी नहीं देखी गयी थी तथा यह नयी मानसिकता 1975 के हिन्द-चीन में परिवर्तन के बाद तीव्र होती गयी।[94]

93- अली मोरतोपो, "फ्यूचर ऑफ इंडोनेशियन- यू एस रिलेशन्स: ए व्यू फ्रॉम जाकार्ता", पैसिफिक कम्यूनिटी (तोक्यो), सं० (4 जुलाई, 1976), पृष्ठ- 582।

94- एलिसन, सं0-4, पृष्ठ- 41।

एशियन क्रोनिकल के अनुसार आसियान देशों ने क्षेत्रीय समुत्थान के लिए आर्थिक विकास व सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जिससे हिन्द-चीन में हुए साम्यवादी परिवर्तन के संभावित खतरों से निपटा जा सके । आर्थिक समस्याओं पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक सम्मेलन, 26-27 नवम्बर, 1975 को जाकार्ता में आसियान देशों के आर्थिक मंत्रियों द्वारा हुआ, जिसमें कई विस्तृत प्रस्ताव रखे गये जो मुख्यत: आसियान आर्थिक सहयोग, बुनियादी आवश्यक वस्तुओं में सहयोग के लिए, औद्योगिक परियोजनाओं, व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से लिए गए थे । प्रत्येक सहकारी प्रयासों, जो राष्ट्रीय व उसके साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें, पर बल दिया गया था । आवश्यक वस्तुओं के सहयोग हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान खाना व ईंधन को दिया गया जिसमें आसियान देश ऐसी वस्तुओं की भयानक कमी के समय उत्पादन में एक दूसरे का सहयोग कर सकें । इस सम्मेलन में आसियान देश बड़े पैमाने पर अपनी आवश्यक उत्पादनों की क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत पर सहमत हो गए ।[95]

बाली में हुए 23 से 24 फरवरी 1976, ऐतिहासिक आसियान शिखर सम्मेलन से आसियान के नए युग का औपचारिक रूप से श्रीगणेश हुआ जो 1975 के हिन्द-चीन में हुए गुणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप आसियान देशों में चल रहे परिमाणात्मक परिवर्तन का परिणाम था । इस हलचल पूर्ण सम्मेलन के लिए आठ माह से तैयारियां चल रही थीं । इसका उद्देश्य आसियान क्षेत्रवाद था । आसियान देशों के नेता राष्ट्रीय चिन्ता के कारण इस बार वे इस संगठन के कार्य को अत्याधिक गम्भीरता से ले रहे थे । आसियान के इस प्रथम शिखर सम्मेलन से आसियान देशों को पर्याप्त राहत मिली ।[96]

95- एशियन, सं0-4, पृष्ठ- 43 ।

96- रेजिरो सोवा," साउथ ईस्ट एशिया टरमुॅयल एण्ड जापान," एशिया पैसिफिक कम्युनिटी, (टोक्यो) फाल 1979, पृष्ठ- 94

बाली सम्मेलन में आसियान सामंजस्य और मित्रता संधि व दक्षिण-पूर्व एशिया में सहयोग की घोषणा की गयी ।[97] आसियान पुनः एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में संयुक्त रूप से उभरने लगा, तथा इससे आसियान विचारों को नया मोड़ मिला ।[98] आसियान सामंजस्य घोषणा एक विज्ञप्ति थी जिसमें आसियान के 10 वर्षों की रणनीति की बात थी । इन सबका उद्देश्य इस क्षेत्र में राजनीतिक व आर्थिक उत्पाद को तीव्र व शक्तिशाली करना था जिससे आसियान, हिन्द-चीन का, राजनीतिक व आर्थिक रूप से सामना कर सके यहाँ तक कि उससे भी आगे निकल जाए ।[99]

हिन्द-चीन में 1975 की साम्यवादी विजय के बाद आसियान व्यावहारिक रूप से सक्रिय हो गया । आसियान ने जाकार्ता में अपना केन्द्रीय सचिवालय खोला जिसके प्रथम महासचिव इंडोनेशिया के जनरल धारसोनो बने । बाली सम्मेलन में और भी संस्थागत उपलब्धियाँ हुई जैसे "आर्थिक मंत्री परिषद्" जिससे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को गतिशील बनाया जा सके ।[100]

बाली सम्मेलन के बाद आसियान एक धुरी बन गया जिससे पाँचों दक्षिण-पूर्व एशियाई देश हिन्द-चीन में परिवर्तन के बाद अपनी राजनीतियों को ठीक-ठाक करने के बारे में बातचीत करते थे ।[101]

97- बाली सम्मेलन में तीन मुख्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जिससे आसियान भविष्य में और अधिक गतिशील हो सके --- मित्रता व सहयोग संधि, आसियान मैत्री की घोषणा और संयुक्त विज्ञप्ति ।

98- एशियन, सं0-4, पृष्ठ- 42 ।

99- रेजिरी, सं0 96, पृष्ठ- 95 ।

100- ललिता प्रसाद सिंह, "पावर्स पॉलिटिक्स एण्ड साउथ ईस्ट एशिया" (नयी दिल्ली, 1979), पृष्ठ- 152 ।

101- वही, पृष्ठ- 160 ।

दिसम्बर, 1977 में कम्पूचिया के पोलपोट शासन का वियतनाम के साथ संबंध खराब हो जाने तथा कम्पूचिया व वियतनाम के बीच शत्रुतापूर्ण रवैए से आसियान देश प्रसन्न हुए कि कम्पूचिया अब वियतनाम के विस्तारवाद पर नियंत्रण रखेगा तथा वियतनाम के दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रभुत्ववाद में कमी आएगी पर दिसम्बर, 1978 में वियतनाम के कम्पूचिया में हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आसियान देशों में "डोमिनो सिद्धान्त" का भय पुनः छा गया।[102]

---00000---

102- रेजिरो, सं०-96, पृष्ठ- 95।

तृतीय अध्याय

1975 से आसियान - चीन संबंध

आसियान-चीन संबंध के इतिहास में सन् 1975 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। सन् 1975 में हिन्द-चीन में साम्यवादी परिवर्तन व विजय तथा अमेरिका की हार के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका की राजनयिक व सैनिक छवि धूमिल हुई। इससे आसियान देशों की अपनी सुरक्षा हेतु अमेरिका पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। आसियान देश हिन्द-चीन की घटना के बाद केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। आसियान देश साम्यवादी शक्ति को हिन्द-चीन में अधिक नजदीक से उभरते हुए देख रहे थे तथा यह खतरा उनकी ओर न बढ़ सके इसलिए उन्होंने चीन से संबंध बनाना ही उचित समझा। इसके साथ-साथ सोवियत संघ व चीन में बढ़ती तनाव तथा अमेरिका-चीन तनाव शैथिल्यता को आसियान देश भांप गए थे।

आसियान की "ज़ोपफान" नीति का चीन ने 19 जून 1975 को समर्थन देने का वायदा किया।[1] हिन्द-चीन में युद्ध की समाप्ति ने चीन को बिना किसी बाधा के आसियान देशों से संबंध के लिए प्रेरित किया।[2] 26 अगस्त 1975 को चीन की औपचारिक सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने कहा कि आसियान देशों ने पिछले वर्षों में अमेरिका व सोवियत साम्राज्यवादियों द्वारा लूट व शोषण के विरुद्ध काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। शिनहुआ ने इसके द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक अधिकारों व लाभों की प्राप्ति के अन्य आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा :

"आपसी लाभ के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की एकतात्मक व सम्मिलित गतिविधियों की भावना गति प्राप्त कर रही है।... दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तीसरी दुनिया के देशों के साथ घनिष्ट आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को बनाए हुए हैं ......।"[3]

1- मैनिची डैली न्यूज (तोक्यो), 20 जून, 1975।

2- रॉपर्ट ओ' नेल (सं0) "सैक्युरिटी इन ईस्ट एशिया," एडल्फी लाइब्रेरी 9, द इन्टरनैशनल इन्स्टीच्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (ग्रेट ब्रिटेन, 1984) पृ0103

3- बैंकाक पोस्ट, 27 अगस्त, 1975।

चीन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थानप्राप्त करने के लिए एक अभिभावक के रूप में आसियान नीतियों की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया जिससे उसकी श्रेष्ठता व नेतृत्वकारी छवि का दक्षिण-पूर्व एशिया व विशेषकर आसियान देशों में विकसित हो सके। 27 दिसम्बर 1975 को शिनहुआ ने अपने एक लेख में आसियान देशों की राष्ट्रीय अधिकार व हितों की सुरक्षा व आर्थिक सहयोग की प्रशंसा करते हुए लिखा :

"आसियान देश विश्व मंदी के कारण घाटे से परेशान है तथा ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। आसियान के देश व जनता ने महाशक्तियों व अन्य साम्राज्यवादियों के स्वार्थवादिता को ठुकरा दिया है तथा वर्तमान बिगड़ती स्थिति में सुधार लाने के लिए नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की है।"[4]

24 फरवरी, 1976 को चीन ने पुन: शिनहुआ के माध्यम से बाली में हुए आसियान देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन को मान्यता दिया तथा मलेशियाई प्रधानमंत्री दत्तकहुसैन ओन के "दक्षिण-पूर्व एशिया को शान्ति, स्वतंत्र व तटस्थ क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव के समर्थन पर बलदिया।"[5]

चीन ने आसियान देशों के साथ पूरी सहानुभूति का प्रदर्शन किया। आसियान के पुराने आर्थिक संबंधों के माध्यम से लूट के विरुद्ध आसियान देशों के क्षेत्रीय सहयोग की मजबूती की प्रशंसा करते हुए 16 मई 1976 को शिनहुआ समाचार एजेंसी के माध्यम से कहा गया :

"साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी अमेरिका व सोवियत संघ, पुराने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर आसियान देशों के आर्थिक व औद्योगिक क्षमता का

4- डान, (कराची) 28 दिसम्बर, 1975।

5- दं ट्रिब्यून, (चंडीगढ़) 25 फरवरी, 1976।

शोषण कर रहे हैं। सोवियत संघ व अमेरिका आसियान देशों की सम्पत्ति का लूट तथा सहायता के नाम पर मालों का दोहन करते हुए असमान्य मूल्यों के व्यापार के माध्यम से उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व अर्थव्यवस्था में घाटा लाते जा रहे हैं।[6]

चीन के आसियान के समर्थन के इसी क्रम में कई वक्तव्य लगातार आते रहे जिससे आसियान देशों में चीन के प्रति मानसिकता पर प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था।

28 दिसम्बर 1977 को चीनी समाचार सूत्र शिनहुवा ने कहा : चीन वर्ष 1977 के दौरान आसियान देशों के दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग व एकता के लिए कार्यरत रहने तथा इस क्षेत्र की शान्ति क्षेत्र व तटस्थीकरण और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु उनके जोरदार प्रयासों की सराहना करता है।... चीन आसियान के सामूहिक आंचलिक परियोजनाओं, अधिमान्य व्यापार समझौतों व अन्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के मामलों का भी समर्थन करता है।[7]

आसियान-चीन संबंधों का अध्ययन, आसियान एक संगठन के रूप में चीन के साथ, करना संभव नहीं हो सकता।[8] इसलिए आसियान सदस्य देशों का चीन के साथ संबंधों का अध्ययन विभिन्न आयामों में किया जाएगा।

मलेशिया - चीन-संबंध :

मलेशिया व चीन के बीच सिलाड़े दलों के आदान-प्रदान तथा क्रमशः बढ़ते व्यापार के परिणामस्वरूप मलेशिया ने चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने का निश्चय किया और प्रधान मंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने 14 मई 1974 को चीन की

6- स्ट्रेट्स टाइम्स, (सिंगापुर), 17 मई, 1976।

7- बैंकाक पोस्ट, 29 दिसम्बर, 1977।

8- आसियान सदस्य देशों -- मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस व थाईलैण्ड का चीन के साथ एक समान संबंध नहीं है। इनमें से केवल तीन देशों-मलेशिया, फिलीपींस व थाईलैण्ड का चीन के साथ राजनयिक संबंध है। इंडोनेशिया के साथ चीन का राजनयिक संबंध अक्तूबर, 1967 में टूट गए थे, सिंगापुर का चीन के साथ अभी तक राजनयिक संबंध नहीं है।

यात्रा की तथा चीनी प्रधान मंत्री चऊ अनलाइ के साथ 31 मई 1974 को एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किया । इस विज्ञप्ति में "विद्रोह" शब्द का प्रयोग किया गया था जो चीनी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का दृष्टांत था । इस विज्ञप्ति में कहा गया :

"दोनों सरकारें हर तरह के विदेशी आक्रमण, हस्तक्षेप, नियंत्रण व विद्रोहों की अनुज्ञेय मानती हैं..."[9]

यह विज्ञप्ति न केवल मलेशिया के लिए महत्वपूर्ण था बल्कि आसियान देशों में साम्यवादी विद्रोह की समस्या के संदर्भ में पूरे आसियान देशों के लिए भी महत्वपूर्ण था ।

चीनी राजदूत वांग यूपिंग ने 29 जनवरी, 1975 को मलेशिया के राजा को अपना प्रत्यय-पत्र (CREDENTIALS) दिया तथा दोनों देशों व जनता के बीच शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर मैत्री को बढ़ाने पर बल दिया..... मलेशिया के राजा ने चीनी राजदूत वांग से कहा :

"यद्यपि दोनों देशों में अलग-अलग समाज व्यवस्था है फिर भी एक दूसरे की संप्रभुता , क्षेत्रीय अखण्डता का आदर करने, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा समान प्रतिष्ठा व शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर हमारी मित्रता बढ़ती जायगी..... ।"[10]

मलेशिया के नीतियों के समर्थन में 21 दिसम्बर, 1977 को चीनी राजदूत थेङ्ग चांग ने मलेशिया में कहा :

"चीन मलेशियाई सरकार के दक्षिण-पूर्व एशिया के तटस्थीकरण करने व बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के विरोध करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है । चीनी

9- आर० के० जैन, "चाईना एण्ड मलेशिया", 1949-1983", रेडियन्ट पब्लिशर्स, (दिल्ली-1984), पृष्ठ- 222 में फारेन अफेयर्स ऑफ मलेशिया , कुवालालम्पुर, अप्रैल-दत्त, 1974 के पृष्ठ- 47-48 से उद्धृत ।

10- स्ट्रेट्स पोस्ट, 25 जनवरी, 1975, स्ट्रेट्स टाएम्स, 30 जनवरी, 1975 ।

सरकार मलेशियाई जनता के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के कार्य का भी समर्थन करती है।... हम आशा करते हैं कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त पर संबंध मजबूत व विकसित होंगे।"[11]

29 अप्रैल 1975 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मलेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी की 45 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बधाई तार भेजा जिससे मलेशियाई सरकार को काफी आश्चर्य हुआ तथा उसने कुआलालम्पुर स्थित चीनी दूतावास के माध्यम से इसका कड़ा विरोध किया तथा इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप व पारस्परिक वायदों को तोड़ने के प्रतिक्रिया में उस तार की भर्त्सना की।"[12]

18 सितम्बर, 1978 को मलेशियाई विदेश मंत्री तंग्कू अहमद रिथाऊद्दीन चीन की यात्रा पर पेकिंग पहुंचे। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शान्ति व स्थिरता के लिए प्रयत्न रहने पर बल दिया।[13]

इंडोनेशिया-चीन संबंध :

विश्व के अन्य अधिकांश देशों की तरह इंडोनेशिया की विदेश नीति का भी आंतरिक राजनीति से घनिष्ट संबंध है, तथा यह तथ्य तो इंडोनेशिया व चीन संबंधों के संदर्भ में अक्षरशः सत्य है।[14] यद्यपि पिछले लगभग पन्द्रह वर्षों से इंडोनेशिया व चीन के नेताओं आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनौपचारिक रूप से संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए बातचीत चलती आ रही है, जिसमें पेकिंग की इच्छा रही है कि वह जाकार्ता से पुनर्संबंध स्थापित करे। चीन इंडोनेशिया को आसियान का प्रमुख सदस्य देश मानता है क्योंकि इंडोनेशिया का क्षेत्र व जनसंख्या तथा आर्थिक क्षमता आसियान के अन्य सदस्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है। इंडोनेशिया नागरिकों का चीन के साथ संबंध

11- बैंकाक पोस्ट, 22 दिसम्बर, 1977।

12- स्ट्रेट्स टाइम्स, 1 मई, 1975।

13- इंडोनेशिया टाइम्स, (जाकार्ता), 25 सितम्बर, 1978।

14- लियो सुर्यादिनाता, "इंडोनेशिया, ए इयर ऑफ कन्टिन्यूइंग चैलेंज" साउथ ईस्ट एशियन अफेयर्स- 1979, (सिंगापुर, 1979), पृष्ठ-115।

के विषय में स्वीकारात्मक रवैया है।[15] पर इंडोनेशियाई सरकार ने साम्यवादी पृष्ठभूमि के भय से कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, तथा वहां के सैनिक अधिकारियों के विचार भी इसके विपरीत हैं। ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया के सैनिक अधिकारी देश के वास्तविक शक्तिशाली उच्चवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वर्ग 1965 की असफल राज्य-विप्लव के बारे में अभी भी सोचता रहता है।[16] ऐसा समझा जाता है कि इंडोनेशियाई प्रतिरक्षा व सुरक्षा विभाग के जनरलों का एक समूह चीन के साथ संबंध बनाने के विरुद्ध है। इसी प्रकार के विचार इस्लामी दल के भी हैं।[17] कन्सर्वेटिव इस्लामिक पार्टी के नेता हाजी इमरान रोजादी चीन-इंडोनेशियाई संबंध पर अपने विरोधी विचार प्रकट करते आए हैं। जून, 1977 में जब वे संसद में विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया को चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं करने चाहिए। इसके स्थान पर उसे हिन्द-चीन के देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने चाहिए। उनके इस तर्क का मुख्य कारण यह था कि हिन्द-चीन, चीन के प्रभाव पर नियंत्रण रख सकेगा।[18]

वर्तमान शताब्दी के सातवें दशक में इंडोनेशिया-चीन के संबंधों में मुख्य बाधा चीन का पी०के० आई० को दिया गया समर्थन था। . . . .

26 मई, 1975 को इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ऐडम मलिक ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पी० के० आई० के समर्थन में दिए गए वक्तव्य की भर्त्सना की तथा कहा : " यह चीन द्वारा 1972 में दिए गए वायदों कि वह इंडोनेशिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, का उल्लंघन है। इंडोनेशियाई सैनिक स्रोतों द्वारा पता चला है कि चीन पी०के० आई० को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे 1965 के असफल राज्य-विप्लव के समय बर्बाद कर दिया गया था जिसके एक लाख

15- चौधरी, जी० डब्ल्यू०, "चाइना इन वर्ल्ड अफेयर्स: द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पी आर सी सिन्स 1970" (कोलोराडो, 1982) पृष्ठ-243।

16- वही।

17- लियो, सं० 14, पृष्ठ- 115।

18- वही, टीम कोमपास, "प्रीडान कोन्तरा मेंगनाए नोरमलीसासी हुबुंगान डेंगान पी आर सी", कोमपास, 2 जून, 1977 से उद्धृत।

सैनिक मार दिए गए... चीन ने पी०के० आई० के 55वीं वर्षगांठ पर 23मई, 1975 को दिए एक संदेश में कहा कि इंडोनेशियाई क्रान्ति कुछ कमियों के कारण असफल हुई थी... पर अपनी कठिन दौर से गुजरती हुई अपनी मजबूती को प्राप्त कर आगे लड़ाई जारी रखेगी... ।"[19]

20 जून, 1975 को ऐडम मलिक ने अपने सिंगापुर यात्रा के दौरान कहा था कि इंडोनेशिया चीन के साथ संबंधों व नीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है । उन्होंने कहा कि जब सिंगापुर चीन को मान्यता दे देगा तब इंडोनेशिया चीन के साथ संबंध बनाएगा तथा उन्होंने आसियान द्वारा पारित दो वर्ष पूर्व के निर्णय आसियान चीन को मान्यता देगा, की भी चर्चा की ।"[20]

इंडोनेशिया ने बार-बार कहा है कि चीन के साथ संबंधों का पुनरागमन तभी संभव होगा जब चीन पी०के०आई० को अपना समर्थन देना पूरी तरह बन्द कर देगा और इंडोनेशिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा करेगा । अगस्त, 1975 में राष्ट्रीय दिवस के भाषण में राष्ट्रपति सुहार्तो ने कहा :

"--- देश की भूतपूर्व पी० के० आई० नेताओं को अभी भी शरण दिए हुए हैं या खुले रूप से इस देश में पी० के० आई० की पुनरागमन के लिए प्रयत्नशील है.... हम इस प्रकार की गतिविधियों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा इसे अमैत्रीपूर्ण रवैया मानते हैं । हम इसे चीन लोग गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध की पुनरागमन में वर्तमान बाधा मानते हैं ।"[21]

चीन का दिसम्बर 1975 के बाद, पूर्वी तिमोर के प्रश्न पर इंडोनेशियाई नीति की लगातार भर्त्सना तथा पी०के०आई० की गतिविधियों को चीन का खुला समर्थन मिलने के कारण तथा 1976 के नव वर्ष पर चीन व पी०के०आई० के आपसी बधाई संदेशों के आदान-प्रदान से[22] दोनों देशों के संबंधों में और अधिक

19- इन्डोनेशिया टाइम्स, 27 मई, 1975 ।

20- वही, 21 जून, 1975 ।

21- डेविड जेनकिंस, " इंडोनेशिया-चाईना ", फॉर ईस्टर्न इकॉनोमिक रिव्यू (हांगकांग) 7 अक्तूबर, 1977 , पृष्ठ-82 में उद्धृत ।

22- वही ।

जटिलता उत्पन्न हुई ।[23]

इंडोनेशियाई विदेश मंत्री ऐल मल्लिक ने 9 अप्रैल, 1976 को कहा कि इंडोनेशिया चीन के साथ संबंध बनाने की दिशा में जल्दबाजी में नहीं है ।[24] 20 मई, 1976 को इंडोनेशिया व चीन के संबंधों की सामान्यीकरण के बारे में बोलते हुए ऐल मल्लिक ने कहा :

"इंडोनेशिया की चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने के लिए अभी और समय चाहिए । आमतौर पर दोनों देशों के बीच कोई विशेष अन्तर्विरोध नहीं है जिससे संबंध की पुनर्निर्माण में कोई परेशानी हो । हमलोगों का संबंध तो 1948 से है । हमारी परेशानी स्थिति अभी उचित नहीं है कि चीन से संबंध को सामान्य किया जा सके... ।"[25]

ऐल मल्लिक ने संबंध सामान्य करने की सही तिथि बताने से इन्कार किया तथा कहा कि तिथि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध तो एक दिन में बन जाएगा ।[26]

राष्ट्रपति सुहार्तो ने इंडोनेशिया की 31वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 16 अगस्त, 1976 के अपनी भाषण में पी० के० आई० के संदर्भ में चीन की चर्चा नहीं की । उन्होंने इंडोनेशिया-चीन संबंध की चर्चा करते हुए कहा कि इंडोनेशिया चीन के साथ संबंध बना सकता है अगर चीन उनकी सरकार को मान्यता दे, इंडोनेशिया की क्षेत्रीय अखण्डता का आदर करते हुए उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे । इंडोनेशिया-चीन संबंध में ठण्डापन का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी देश के बड़े या शक्तिशाली होने से संचालित नहीं होना चाहते ।[27] और इस वक्तव्य के 23 दिन बाद 9 सितम्बर, 1976 को, अध्यक्ष माओ जेदुंग की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति सुहार्तो ने संयुक्त राष्ट्र के स्थाई चीनी प्रतिनिधि के माध्यम से चीनी

23- रॉबर्ट, सं०-2, पृष्ठ- 107 ।

24- रुटर्स टाइम्स, 10 अप्रैल, 1976 ।

25- इंडोनेशिया टाइम्स, (जाकार्ता), 21 मई-1976 ।

26- वही ।

27- रुटर्स टाइम्स, 17 अगस्त, 1976 ।

प्रधानमंत्री हुवाक्वीफंग को शोक-संदेश भेजकर चीनी नेता की मृत्यु पर गहरी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि दुनिया, ऐतिहासिक महत्व के राजनेता तथा एक पुरुष जिसने अपनी जनता व देश के लिए सेवक के रूप में काम किया, माओ को याद करेगी। सुहार्तो ने माओ के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना भेजी।[28]

28 अक्तूबर, 1976 को ऐडम मलिक ने कहा कि चीन में हुए नए परिवर्तन से जाकार्ता व चीन के बीच संबंधों में सुधार होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने पर बल देते हुए कहा कि संबंध में सुधार इंडोनेशिया के आंतरिक मामलों पर भी निर्भर करता है। मलिक कई बार कह चुके हैं कि 40 लाख चीनियों को पहले यह समझ लेना चाहिए कि वे इंडोनेशियाई हैं उन्होंने कहा कि चीन ने अन्य शर्तें तो पूरी कर ली हैं जिसमें दोहरी राष्ट्रीयता को समाप्त कर दिया गया है, चीन ने इंडोनेशिया विरोधी प्रचार समाप्त कर दिया है तथा विद्रोहियों के समर्थन की समाप्ति कर दी है।[29]

पहली नवम्बर, 1976 को राज्य गुप्तचर विभाग के उपाध्यक्ष जनरल अली मूरतोपो ने कहा कि 1977 के आम चुनाव के बाद ही चीन के साथ संबंध सुधार के बारे में निश्चय किया जाएगा।[30]

इंडोनेशिया-चीन संबंधों के बारे में जनवरी 1977 में तब पुनः एक चर्चा की शुरुआत हुई जब पपुआ न्यूगिनिया के प्रधानमंत्री माइकेल सोमारे ने जो उसके पूर्व पेईचिंग की यात्रा से लौटे थे, अपनी इंडोनेशियाई यात्रा के दौरान कहा कि उन्होंने चीनी उपप्रधान मंत्री ली शियेन नियेन के साथ बातचीत के दौरान इंडोनेशिया-चीन संबंधों के बारे में चर्चा की जिसमें चीनी नेता ली शियेन नियेन ने उनसे कहा कि चीन इंडोनेशिया के साथ राजनयिक संबंध की "पुनरागमन" के लिए तैयार है अगर इंडोनेशिया

---

28. डेविड, सं०-21, पृष्ठ- 82।

29. हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 अक्तूबर, 1976।

30. हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 नवम्बर, 1976।

की भी ऐसी ही इच्छा होती...।[31] सोमारे ने कहा कि राष्ट्रपति सुहार्तो ने भी चीन के साथ संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की है।[32]

2 अक्तूबर 1977 को मलिक ने चीन के साथ संबंध बनाने पर हुवांग हुआ से, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में बातचीत की।[33] 7 नवम्बर, 1977 को मलिक ने कहा कि मार्च या अप्रैल 1978 तक चीन व इंडोनेशिया के बीच संबंध सामान्य हो सकेंगे। इंडोनेशिया टाइम्स के अनुसार यह वक्तव्य उन्होंने भूतपूर्व विदेश मंत्री की हैसियत से व्यक्तिगत रूप से दी। इसके पहले वे कह चुके हैं कि परंतु सुरक्षा समस्याओं के हल होने पर ही यह संबंध निर्भर करता है। यद्यपि अब तो सुरक्षा की समस्या नहीं है।[34] परन्तु इसी दौरान चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हुवा क्वो फंग ने पेकिंग में 18 मई, 1977 को पी०के०आई० केन्द्रीय समिति के प्रतिनिधिमण्डल के नेता व सचिव युसुफ आजितोरोप से मुलाकात की[35] जिसका इंडोनेशिया - चीन के संभावित संबंध पर पुनः बुरा प्रभाव पड़ा।

इंडोनेशियाई सरकार में साम्यवादी विरोधी मानसिकता चीन के साथ संबंध बनाने में मुख्य रूप से बाधक माना जाता है। इसके साथ-साथ वहां का उच्चवर्ग भी बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि इंडोनेशिया-चीन संबंध से सर्वाधिक हानि इसी वर्ग की हो सकती है। परन्तु इन समस्त विरोधों के अतिरिक्त विरोध करने वाला वहां का चीनी समुदाय भी है।[36]

31- डेविड, सं०-21, पृष्ठ-82।

32- इंडोनेशिया टाइम्स, 14 जनवरी, 1977।

33- हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) 3 अक्तूबर, 1977।

34- इंडोनेशिया टाइम्स, 8 नवम्बर, 1977।

35- रॉबर्ट, सं० 2, पृष्ठ-107 तथा डेविड, सं०-21, पृष्ठ- 82

36- लियी, सं०- 14, पृ० 115। काफी चीनी व्यापारी जो इंडोनेशियाई उच्चवर्ग के साथ सहयोग करते हैं, थाइवान के साथ संबंध बनाए रखने में उनके व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति होती है क्योंकि जाकार्ता-थाइवान प्रत्यक्ष व्यापार की मात्रा जाकार्ता-पेकिंग अप्रत्यक्ष व्यापार की मात्रा से अधिक है तथा चीन जनवादी गणराज्य के साथ संबंध उनके इस व्यापारिक लाभ को प्रभावित कर सकता है।

इंडोनेशियाई सरकार में विरोधी दल के नेता राजनीतिक मुद्दे के रूप में सुहार्तो सरकार से सदैव चीन से पुनर्संबंध की माँग करते हैं। एडम मलिक व अली मुरतोपो के नेतृत्व के अन्य दल भी चीन के साथ संबंधों की पुनर्स्थापना के पक्ष में हैं।

राष्ट्रपति सुहार्तो ने 1978 के राष्ट्रपति-चुनाव के पूर्व संध्या पर वल देते हुए कहा कि वे शीघ्र ही चीन के साथ राजनयिक संबंधों की पुनर्वापसी करेंगे।[37] 11 मार्च 1978 को राष्ट्रपति सुहार्तो ने कहा कि इंडोनेशिया चीन के साथ राजनयिक पुनर्संबंध के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने जन सलाहकार समिति की एक बैठक में कहा कि इंडोनेशिया, राजनयिक संबंधों को, "आपसी सम्मान व एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के "बुनियादी सिद्धान्तों पर चीन के साथ संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनके चीन के साथ संबंध अभी भी शीतल हैं, तथा उन्हें आज भी अतीत के कड़वे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समस्त संभावनाओं को देखना है।"[38] इंडोनेशिया के सूचना मंत्री अली मुरतोपो ने मई 1978 में कहा कि इंडोनेशिया दोनों देशों (इंडोनेशिया व चीन) के बीच सामान्य संबंधों की वापसी हेतु नयी नीतियों के गठन में लगा हुआ है।"[39]

इंडोनेशियाई विदेश मंत्री मुख्तार कुसुमातमाजा ने 8 जून, 1978 को कहा : "जाकार्ता चीन के साथ निश्चित रूपेण संबंधों की पुनर्स्थापना करेगा। कुछ समस्याओं के समाप्त होने के बाद इस योजना को निश्चित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा पर वैसे निश्चित दिनांक बतलाना संभव न होगा।[40]

1978 में चीन के आर्थिक व्यावहारिक-नीतियों ने इंडोनेशियाई सरकार को एक बार फिर चीन के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था परन्तु चीनी

37- वही।

38- बैंकाक पोस्ट, 12 मार्च, 1978।

39- लाऊ गुवात जून, "रीसेंट डेवलपमेंट इन चाईना- आसियान रिलेशंस" साउथ ईस्ट एशियन अफेयर्स, 1979, सिंगापुर। पृष्ठ- 66।

40- बैंकाक पोस्ट, 9 जून, 1978।

उपप्रधानमंत्री तंग शियावो फिंग का, नवम्बर 78 में दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा के दौरान, कथन " चाहे चीनी सरकार कुछ भी करे पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस क्षेत्र के क्रान्तिकारी पार्टी की समर्थन देना बन्द नहीं करेगी ।" इस चीनी नीति से इंडोनेशिया - चीन संबंध पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा ।[41] तंग के इस वक्तव्य की प्रतिक्रिया में विदेश मंत्री मूल्तार कुसुमात्मजा ने इस बात पर दुःख प्रकट करते हुए 13 नवम्बर 1978 को कहा :

"चीन के दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रतिबंधित साम्यवादी क्रांतिकारियों के समर्थन देने की नीति.... इस प्रकार के वक्तव्य निश्चित रूप से इंडोनेशिया के लिए चेतावनी जनक हैं जबकि आज हम चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं ।... इंडोनेशिया ने चीन के साथ संबंध बनाने के लिए गम्भीरता पूर्वक कार्य किया है पर अब इसे शीघ्र पूरा करने में कठिनाई होगी ।"[42]

इसी प्रकार के विचार इंडोनेशियाई राजनीतिक व सुरक्षा मामलों के सहयोगी मंत्री जनरल सु० पांगाबीन ने 14 नवम्बर, 1978 को देते हुए कहा :

"अगर चीन इंडोनेशिया में विद्रोही साम्यवादी आंदोलनों को समर्थन देता रहेगा तो इंडोनेशिया चीन के साथ राजनयिक संबंध नहीं बना सकेगा ।... अगर हम इस देश के किसी सशस्त्र विद्रोहियों को किसी प्रकार के चीनी समर्थन का सबूत पाते तो संबंधों के विकास की आशा नहीं करनी चाहिए ।... हम संबंधों के सामान्यीकरण हेतु समस्त प्रयासों का स्वागत करते हैं परन्तु अगर सामान्यीकरण ही बर्बाद करेगा तो हम संबंध नहीं बनाएंगे -- इंडोनेशिया साम्यवादी आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयत्न जारी रखेगा ।"[43]

41- रॉबर्ट, सं० 2, पृष्ठ- 107 ।

42- इंडोनेशिया टाइम्स, 14 नवम्बर, 1978 ।

43- इंडोनेशिया टाइम्स, 15 नवम्बर, 1978 ।
इंडोनेशिया टाइम्स के एक समाचार के अनुसार 1978 में उत्तरी कालीमानतान सीमा पर हुए साम्यवादी विद्रोहों में चीनियों के शामिल होने के प्रमाण प्राप्त हुए थे । पू० दे० 15 नवम्बर 78 का पत्र ।

27 जनवरी, 81 को गोल्कर (गोलोन्गान कार्या) राजनीतिक मामलों के उपाध्यक्ष सुकार्डी ने कहा कि चीन का दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलनों का समर्थन बन्द नहीं करना यह सिद्ध करता है कि इंडोनेशिया की चीन के साथ संबंधों की पुनर्स्थापित न करने की नीति उचित है। वे चीनी प्रधान मंत्री चाओ जु यांग के 27 जनवरी 81 को वर्मा में दिए गए एक वक्तव्य के प्रतिक्रिया में बोल रहे थे। चाओ ने कहा था कि चीन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के कम्युनिस्ट आंदोलनों का समर्थन करना बन्द नहीं करेगा। सुकार्डी ने कहा कि इंडोनेशिया चीन के साथ संबंध को पुनर्स्थापित करना चाहता है पर उन्हें इंडोनेशिया के लिए सदैव साम्यवाद का गुप्त खतरा लगा रहता है। उन्होंने कहा कि चीनी प्रधानमंत्री चाओ के इस वक्तव्य से इंडोनेशिया को चीन के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बार पुनः महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करना होगा।[44]

राजनीतिक सुरक्षा मामलों के संचालक मंत्री जनरल एम० पांगाबीन ने कहा कि इंडोनेशिया चीन लोक गणराज्य के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने में तेजी नहीं करेगा क्योंकि अभी भी कई समस्याएं बाधक हैं। उन्होंने 1981 में संबंधों की पुनर्वापसी को नकारते हुए कहा :

"हमें राजनीतिक, आर्थिक व वैचारिक संबंधों को सामान्य करने से पहले कुछ पहलुओं पर विचार करना होगा... अभी भी इंडोनेशिया में रह रहे काफी चीनी इंडोनेशियाई नागरिक नहीं हैं।... साम्यवाद अभी भी इंडोनेशिया के लिए गुप्त खतरा बना हुआ है।.... हमें पड़ोसी देशों, जो चीन के साथ संबंध बनाए हुए हैं, के अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए।... एक तरफ तो चीन सरकार सहयोग करने पर तैयार होती है तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन करती है... इस प्रकार के सहयोग को हम पसन्द नहीं करते।[45]

चाओ के पार्टी-पार्टी संबंधों को मान्यता देने के विचार की प्रतिक्रिया में 14 सितम्बर 81 को विदेश मंत्री मुख्तार कुसुमातमाजा ने कहा कि इंडोनेशिया चीन

44- इंडोनेशिया टाइम्स, 28 जनवरी, 1981।

45- इंडोनेशिया टाइम्स, 11 मार्च, 1981।

केसाथ राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए और अधिक सावधान है ।[46]

12 दिसम्बर 1981 को शिनहुआ ने इंडोनेशियाई नेताओं की जाकार्ता में थाइवान के राष्ट्रवादी चीनी सरकार के प्रधानमंत्री सुन युन सुवान के साथ बातचीत करने पर आलोचना की । पश्चिमी समाचार पत्रों के अनुसार सुन की इस जाकार्ता यात्रा से चीन व इंडोनेशिया के राजनयिक संबंधों के शीघ्र पुनर्स्थापना के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।[47] यद्यपि इंडोनेशिया का थाइवान के साथ औपचारिक संबंध नहीं है, शिनहुआ ने कहा कि इंडोनेशियाई अधिकारी निश्चित रूप से चीन के साथ संबंध बनाने में दोहरी नीति अपना रहे हैं ।[48]

परन्तु चीन के इस विचार को गलत बताते हुए विदेश मंत्री कुसुमात्माजा ने 14 दिसम्बर 81 को कहा कि राष्ट्रवादी चीनी प्रधान मंत्री सुन युन सुवान के हाल ही में जाकार्ता यात्रा के बावजूद इंडोनेशिया अभी भी "एक चीन नीति" का प्रतिपादक है ।[49]

सिंगापुर - चीन संबंध

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थाई सदस्यता मिलने व मलेशिया के चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के परिणामस्वरूप सिंगापुर का चीन के प्रति व्यवहार में नरमी का आविर्भाव हुआ । मार्च 1975 में सिंगापुर के विदेश मंत्री एस० राजारत्नम् जब पेकिंग की यात्रा पर गए तब उन्होंने बलपूर्वक कहा कि आसियान देशों में सिंगापुर अंतिम देश होगा जो साम्यवादी चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाएगा । उन्होंने चीनी विदेश मंत्री चियाव कुवान हुवा को आश्वासन दिया कि सिंगापुर सोवियत समर्थित रवैया नहीं अपनाएगा और सिंगापुर अन्य क्षेत्रों जैसे व्यापार व सांस्कृतिक क्षेत्र में चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में प्रयत्न करेगा । चीन ने सिंगापुर के साथ

46- इंडोनेशिया टाइम्स, 15 दिसम्बर, 1981 ।

47- बैंकाक पोस्ट, 14 दिसम्बर, 1981, इंडोनेशिया व थाइवान के इस बातचीत में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया ।

48- वही ।

49- द एज, (जकारता) 14 दिसम्बर, 1981 ।

व्यापार की इच्छा व्यक्त की जिसमें सामान्य वस्तुओं के अतिरिक्त औद्योगिक उपकरणों के व्यापार पर अधिक बल दिया गया ।[50]

7 जुलाई, 1975 को सिंगापुर में राजारत्नम् ने कहा कि इसके पहले कि सिंगापुर चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाकर सिंगापुर में चीनी दूतावास खोलने की अनुमति दे, सिंगापुर की 80 प्रतिशत चीनी जनसंख्या की पहचान की जानी चाहिए कि वे सिंगापुर के निवासी व नागरिक हैं न कि चीन लोक गणराज्य के नागरिक । अगर कभी सिंगापुर व चीन के बीच कोई विवाद होता है तो स्थानीय चीनियों को सिंगापुर का ही समर्थन करना चाहिए ।[51] नवम्बर, 1975 में अनतारा के महानिदेशक मुहम्मद नाहर को दिए गए एक साक्षात्कार में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुवान यू ने कहा :

"सिंगापुर ने आम घोषणा की है कि सिंगापुर आसियान देशों में अंतिम देश होगा जो चीन के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करेगा । हमारी यही नीति है । तथापि हम चीन के साथ वाणिज्य व सांस्कृतिक संबंधों को बनाए हुए हैं । चीन लोक गणराज्य की दो बैंक व तीन बीमा कम्पनियाँ सिंगापुर में हैं । हम चीन के साथ व्यापार को कभी नहीं बन्द करेंगे । जब हम मलेशिया के साथ मिले हुए थे तो उस समय भी हम चीनी बैंक को बन्द करने के पक्ष में नहीं थे । हम यह विश्वास करते हैं कि बैंकों के कारण इन दोनों देशों (सिंगापुर व चीन) के व्यापार में सहायता मिलती है । इस स्तर के संबंध चीन में चल रहे सांस्कृतिक क्रांति के दौरान भी थे । चीन के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है, पर विश्व व्यापार के अनुपात के अनुसार सिंगापुर-चीन के बीच व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है.... ।"[52]

सिंगापुर को डर है कि उसे कहीं "तीसरा चीन" के नाम से न पुकारा जाए या उसे दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का "घोड़ा-गाड़ी" कहा जाए ।

50- एशियन रिकार्डर (नई दिल्ली), 1975, पृष्ठ- 12622 ।

51- वही, पृ0-12766 ।

52- एस0 डब्ल्यू0 बी0, एफ-ई।5070।ए-317,

इसी डर से सिंगापुर की विदेश नीति काफी संतुलित है।[53]

चीनी उपप्रधानमंत्री तंग शियावो फिंग के 12 नवम्बर 78 को सिंगापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत नहीं किया गया।[54] इससे सिंगापुर ने यह प्रदर्शित करना चाहा था कि उसके चीन के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है ना ही बनाने में रुचि रखता है।

13 नवम्बर, 1978 को सिंगापुर के एक सरकारी वक्ता ने स्पष्ट किया कि सिंगापुर के चीनी (बहुसंख्यक) स्वयं को प्रवासी चीनी नहीं मानते तथा वे बहुसांस्कृतवादी ही रहने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। यह वक्तव्य सिंगापुर में ली कुवान यू व तंग शियाओ फिंग के बीच बैठक में दी गयी। ली ने कहा :

"सिंगापुर का भविष्य, दक्षिण-पूर्व एशिया के भविष्य पर निर्भर करता है न कि चीन के भविष्य पर।... चीनी व सिंगापुर के निवासी अपने अलग-अलग ऐतिहासिक अनुभवों से पुर्ण हैं।... इसकी संभावना है कि समस्त आसियान देश सामूहिक रुप से तंग के इस यात्रा पर दृष्टि डालें।"[55] सिंगापुर के एक सरकारी वक्ता ने 13 नवम्बर 78 को कहा कि सिंगापुर की इच्छा दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र के अन्तर्गत एक अलग देश के रुप में रहने की है तथा इसका प्रयत्न रहा है कि यह एक बहुजातीय समाज[56] हो जिसकी अपनी सिंगापुरी पहचान हो।"[57]

स्थानीय चीनी समुदाय के अनिश्चित व्यवहार व मानसिकता के भय और उनको चीन से प्राप्त होने वाली संभावित सहायता के कारण ऐसे विचारों का सिंगापुर सरकार के मन में आना स्वाभाविक ही है जैसा कि उन्हें इंडोनेशिया से ऐतिहासिक

53- पीटर्स ० जे० एन (सं०) "सिंगापुर डेवलपमेंट पॉलिसीज एण्ड ट्रेंड्स", (आक्सफोर्ड, 1983), पृष्ठ- 345।

54- स्ट्रेट्स टाइम्स, 13 नवम्बर, 1978।

55- स्ट्रेट्स टाइम्स, 14 नवम्बर, 1978।

56- सिंगापुर में 76.2 प्रतिशत चीनी, 15 प्रतिशत मलय, 7 प्रतिशत भारतीय व 1.8 प्रतिशत अन्य जातियां हैं। पीटर्स, सं० 53, पृ०-345।

57- स्ट्रेट्स टाइम्स, 14 नवम्बर, 1978।

अनुभव प्राप्त हो चुका है।[58] यह एक मुख्य कारण है जिससे सिंगापुर सरकार अभी तक चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं कर सकी है। वह अभी प्रतीक्षा करना अधिक उचित समझती है।

फिलीपींस-चीन संबंध :

पेइचिंग-वाशिंगटन तनाव शैथिल्यता, साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थाई सदस्यता के प्राप्त होने, मलेशिया व चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना और हिन्द-चीन की राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन, सोवियत चीन के बीच बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप फिलीपींस सरकार के चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार में परिवर्तन आया। इसके पश्चात फिलीपींस ने अपनी चीन नीति का पुनर्मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दिया।

मार्च 1972 में सैनेटर सलवाडोर लारेल के नेतृत्व में एक फिलीपींस शिष्टमण्डल पेइचिंग की यात्रा पर गया। इस शिष्टमण्डल ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना पर बातचीत की शुरुआत की। 27 सितम्बर, 1974 को फिलीपींस सरकारी प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्षा के रूप में फिलीपींस के राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती इमेल्डा मारकोस पेइचिंग की यात्रा पर गयीं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य चीन लोकगणराज्य के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बारे में बातचीत करनी थी। 4 अक्तूबर 74 को फिलीपींस के एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि फिलीपींस सरकार चीन लोक गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध बनाने को तैयार है।[59]

नवम्बर 1974 में फिलीपींस के उद्योग मंत्री व निवेश बोर्ड के अध्यक्ष हिलेरी पेटर्नो के नेतृत्व में एक व्यापार शिष्टमण्डल चीन की यात्रा पर गया। इस यात्रा के दौरान फिलीपींस ने चीन के साथ एक व्यापार समझौता किया। इस

58- यहां पर इंडोनेशिया से ऐतिहासिक अनुभव का संकेत इंडोनेशिया में घटित 30 सितम्बर, 65 के चीनी समर्थित असफल राज्य-विप्लव से है।

59- कीसिंग्स कन्टेम्परेरी आरकाइव्ज़ (यू०के०) 1975, पृष्ठ-26986।

समझौते के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के विषय पर भी बातचीत हुई।[60]

पहली मार्च, 1975 को फिलीपींस के राष्ट्रपति मारकोस ने चीन जाने के विषय में अपने विचार रखते हुए कहा कि फिलीपींस व चीन के बीच राजनयिक संबंध इस वर्ष के अन्दर ही बन जायेंगे तथा वे स्वयं इसी वर्ष (1975) चीन की यात्रा पर जायेंगे।[61] 7 जून 1975 को मारकोस चीन की यात्रा पर गए। उन्होंने पेईचिंग में एक सरकारी भोज में बोलते हुए चीन को 'तीसरी दुनिया का तटस्थ नेता' बताया।[62] मारकोस के इस चीन यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री चऊ अन लाए ने मारकोस को आश्वासन दिया कि चीन फिलीपींस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।[63]

शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर फिलीपींस व चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के सन्दर्भ में 9 जून 75 को राष्ट्रपति मारकोस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। इससे फिलीपींस में संभावित विद्रोह में कम्यूनिस्टों की सहायता न करने की चीन की बचनबद्धता बनी रही। इस समझौते के अनुसार दोनों सरकारें प्रत्येक प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए सेना आदि का प्रयोग नहीं करेंगी।[64] फिलीपींस थास्वान में अपनी दूतावास को एक माह यानी 9 जुलाई 1975 तक बन्द करने पर सहमत हो गया। फिलीपींस इस बात पर भी सहमत हो

60- इस व्यापार समझौते में, फिलीपींस चीन को बांस, नारियल का तेल, तांबा व चीनी का निर्यात करना था। कृ० दे० मैनिला डेली न्यूज, 20 नवम्बर, 1974।

61- बैंकाक पोस्ट, 2 मार्च, 1975 तथा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी (पेईचिंग), 3 मार्च, 1975।

62- न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, 8 जून, 75 तथा बैंकाक पोस्ट, 9 जून, 1975।

63- मैनिला डेली न्यूज, 9 जून, 1975।

64- यह अनुमान फिलीपींस के समुद्रीतटों के क्षेत्रीय जल के चीनी दावे के प्रश्न पर विवाद के संदर्भ में कहा गया था।

गया कि अगर प्रवासी चीनी तटस्थता के आधार पर फिलीपींस की नागरिकता को स्वीकारते हैं तो उन्हें चीनी नागरिकता के दावे को रद्द करना होगा।[65] राष्ट्रपति मारकोस ने अपनी इस चीन यात्रा से चीनी उपलब्धियों से अत्याधिक प्रभावित होकर कहा :

"इस पाँच दिवसीय चीन यात्रा से चीन के बारे में समस्त संदेह दूर हो गए। हमने समाजवादी देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं पर हमारे अन्य संबंध व संधियाँ बिना किसी प्रभाव अथवा पूर्वाग्रह के बनी रहेंगी।"[66]

27 नवम्बर, 75 को चीनी विदेश मंत्री चियाव कुनाव हुवा को फिलीपींस के प्रतिनिधि चार्ज डी अफेयर्स रैफेल गोंजलस ने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किया, तथा फिलीपींस ने चीन के साथ संबंध बनाने में सर्वाधिक बल दिया। पेईचिंग होटल में फिलीपींस का दूतावास बना।[67]

जून, 1975 में फिलीपींस व चीन के बीच एक व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे की निकटता में वृद्धि की शुरुआत हो गयी।

मारकोस ने 20 दिसम्बर 1978 को अपने एक वक्तव्य में अमेरिका-चीन संबंध का स्वागत किया था तथा उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि चीन-अमेरिका बीच के संबंध से एशियाई सुरक्षा समस्या में बेहतर आयेगा।[68]

थाई-चीन संबंध :

सातवें दशक के मध्य में हिन्द-चीन में अमेरिका की संभावित हार के परिणामस्वरूप थाईलैण्ड अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर ही निर्भर न रहकर अन्य देश की तलाश करने लगा था और चीन के परिवर्तनशील राजनीतिक मानसिकता

65- एशियन रिकार्डर, 1975, पृ० 12692 तथा न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स, (क्वालालम्पुर), दि आस्ट्रेलियन, 10 जून, 1975।

66- द टाइम्स (लंदन) 11 जून व 12 जून, 1975।

67- स्ट्रेट्स टाइम्स, 28 नवम्बर, 1975।

68- हांगकांग स्टैंडर्ड (हांगकांग) 21 दिसम्बर, 1978।

उसकी पता मैं थी जब जनवरी, 1975 में, चीन ने थाईलैण्ड से कहा था कि थाईलैंड से पूरी तरह अमेरिकी अड्डों का समापन या वापसी की आवश्यकता नहीं है। यह बात थाई उप विदेश मंत्री मेजर जनरल चातीचाय चुन्हावान की चीन यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री चऊ अन लाए ने यह भी कहा था कि चीन चाहता है कि अगर सोवियत संघ हिन्द महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाता है तो अमेरिकी सेना थाईलैण्ड में मौजूद रहे। 14 जनवरी 1975 को चऊ ने यह भी कहा कि थाईलैण्ड से अमेरिकी सेना की वापसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा इस प्रकार की बातें चऊ ने अनेक अवसरों पर बार-बार कही थी।[69]

चीन के इस मानसिकता से थाईलैण्ड ने चीन को अपने मित्र देश के रूप में देखना प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त सोवियत-चीन तनाव व अमेरिका-चीन तनाव शैथिल्यता तथा चीन की संयुक्तराष्ट्र संघ की स्थाई सदस्यता ने थाई-चीन संबंध पर गहरा धनात्मक प्रभाव डाला। इस प्रकार थाई-चीन मित्रता के लिए दोनों देशों द्वारा प्रयत्न किए जाने लगे।

1 जनवरी, 75 को थाई शिष्टमण्डल के नेता उप वाणिज्य मंत्री प्रसोंग सुखुम ने चीन यात्रा से वापस आने के बाद बताया कि चीनी उप प्रधानमंत्री ली शियेन नियेन ने उनसे कहा था कि थाई-चीन संबंध में सुधार तभी हो सकता है जब बैंकाक अपने ताइवान स्थित दूतावास को बन्द कर दे। थाईलैण्ड का ताइवान को राजनयिक मान्यता देना थाई-चीन के विकास में एक बड़ी बाधा है।[70]

जनवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह में चीनी सरकार ने शाही थाई राजकुमार व राजकुमारी को चीन आने का निमंत्रण दिया।[71] चीनी प्रधान मंत्री चऊ के अनुसार इस निमंत्रण का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मैत्री को बढ़ाना था।[72] 1975 में थाई-अमेरिकी संबंध की गति धीमी होने का प्रभाव थाई-चीन संबंध पर पड़ा।

69- इन्डिपेन्डेन्ट टाइम्स, 20 जनवरी, 1975।

70- बैंकाक पोस्ट, 3 जनवरी, 1975।

71- बैंकाक पोस्ट, 15 जनवरी, 1975।

72- वही, 16 जनवरी, 1975।

15 मार्च 1975 को थाई प्रधानमंत्री कुकरित प्रमोज ने अपनी एक घोषणा में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ मित्रता चाहता है पर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उस पर पूरी तरह आश्रित नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा, " किसी देश के साथ मित्रता का यह अर्थ नहीं कि सुरक्षा समस्याओं के लिए उस पर निर्भर रहा जाए।" उन्होंने अपनी विदेश नीति के बारे में कहा कि वे चीन के साथ भविष्य में राजनयिक संबंधों की स्थापना करना चाहते हैं तथा थाईलैण्ड से अमेरिकी सैनिकों की वापसी....।[73] 20 मार्च, 1975 को थाई विदेश मंत्री चातीचाए चुन्हावान ने चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने तथा 1975 में उसके साथ राजनयिक संबंध बना लेने की घोषणा कर दी।[74] 22 जून, 1975 को चीनी प्रधान मंत्री चाऊ का थाई प्रधानमंत्री कुकरित को चीन जाने का निमंत्रण मिला। इस निमंत्रण का उद्देश्य चीन-थाई के बीच राजनयिक संबंधों का औपचारिक रूप से स्थापना करना था।[75] 29 जून, 1975 को कुकरित प्रमोज ने चीन जाते समय हांगकांग में पत्रकारों को बताया कि समझौते के अनुसार चीन थाईलैण्ड के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।[76] 30 जून, 1975 को कुकरित पेकिंग गए तथा पेकिंग में पहली जुलाई 1975 को थाईलैण्ड व चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हो गयी।[77] इस समझौते के अनुसार थाइवान में थाई दूतावास को बन्द कर दिया गया व थाई सरकार ने चीन लोकगणराज्य को वास्तविक चीन के रूप में मान्यता दे दी। समस्त चीनी जो थाईलैण्ड में रहते हैं तथा जिसने थाई राष्ट्रीयता नहीं ली है वे चीनी नागरिक बन सकते हैं। परन्तु दोनों देशों की नागरिकता उन्हें नहीं मिल सकती।[78]

30 जून, 75 के रैनमिनरिपाव (जन दैनिक) ने बलपूर्वक लिखा कि चीन थाईलैण्ड के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिसका अभिप्राय निश्चित रूपेण थाईलैण्ड में साम्यवादी विद्रोह से था।[79]

73- वही, 16मार्च, 1975।

74- वही, 21 मार्च, 1975।

75- वही, 23 जून, 1975।

76- हिन्दुस्तान टाइम्स (नयी दिल्ली) 30 जून, 1975।

77- स्ट्रेट्स टाइम्स, 1 जुलाई, 1975 व बैंकाक पोस्ट, 2 जुलाई, 1975।

78- द्रष्टव्य सम्पूर्ण थाई-चीन संयुक्त विज्ञप्ति, पेकिंग रिव्यू, 4 जुलाई, 1975, पृ० 8-9

थाई-चीन संबंध में प्रमुख समस्या थाई कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को चीन का समर्थन मिलना था। परन्तु पहली जुलाई, 1975 को अध्यक्ष माओ ने प्रधानमंत्री कुकरित से कहा था कि थाई कम्युनिस्ट पार्टी के काफी छोटी होने से थाईलैण्ड की सरकार के लिए कोई चिंता की बात नहीं है।[80]

✓अध्यक्ष माओ ने कुकरित से अपने क्रांतिकारी अनुभवों के बारे में बताया कि विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए "तीन कार्य न करो कि रणनीतियां" आवश्यक हैं -- पहला, कम्युनिस्टों के विरुद्ध प्रचार अभियान न छेड़ो, दूसरा उनसे युद्ध न करो - क्योंकि जब तुम सिपाही भेजोगे तो वे भाग जायेंगे तथा जब सिपाही वापस आयेंगे तो वे पुनः वापस चले आयेंगे, तीसरा, उनकी हत्या न करो, क्योंकि इस तरह तुम उन्हें अमर बना दोगे। माओ ने कहा कि इन विद्रोही कम्युनिस्टों को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। माओ ने कुकरित को आश्वासन दिया कि वे थाई कम्युनिस्टों से बिना डरते हुए अपने देश की प्रगति को तेज करें।[81] ✓

प्रधान मंत्री कुकरित प्रमोज ने अपने पेईचिंग निवास के दौरान अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि थाईलैण्ड व चीन के बीच पिछले चौथाई शताब्दी से चले आ रहे मनमुटाव व तनाव की समाप्ति हो गयी। उन्होंने चीन के आसियान व उसके जोनऑफ़ शान्ति प्रस्ताव को समर्थन देने से संतोष व्यक्त की।[82]

थाईलैण्ड के आर्थिक सहायतार्थ चीन ने थाईलैण्ड से दो लाख टन चावल खरीदने का निश्चय किया।[83] यह चीनी सरकार का थाईलैण्ड के प्रति व्यावहारिक मित्रता का सबूत था। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के अंतिम चौथाई के प्रारंभिक वर्ष 1975 में थाई-चीन संबंधों में एक नया व खुशहाल अध्याय का श्रीगणेश हुआ।

79- एशियन रिकार्डर, 1975, पृष्ठ-12715

80- बैंकाक पोस्ट, 3 जुलाई, 1975।

81- बैंकाक पोस्ट, 9 जुलाई, 1975।

82- पेकिंग रिव्यू, 4 जुलाई, 1975, पृ०-11-12।

इन संबंधों के संदर्भ में यह उम्मीद की गयी कि चीन थाईलैण्ड के स्थानीय साम्यवादी विद्रोही गतिविधियों को समर्थन देना बन्द कर देगा क्योंकि थाई-चीन संबंधों की विज्ञप्ति में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात की गई थी पर व्यावहारिक रुप से इसके समाप्त न होने पर थाई सरकार काफी चिंतित हो गयी । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 17 अक्तूबर 1975 को थाई आंतरिक सुरक्षा नियंत्रण कमांड के विशेष सलाहकार जनरल क्रिस सिवारा ने कहा :

"जबसे थाई-चीन संबंध बना है तबसे थाईलैण्ड में विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई है । संबंध बनने से जो उम्मीद थी कि विद्रोह नहीं होगा, पर बात तो विपरीत दिशा में दिखायी दे रही है । स्थानीय कम्युनिस्टों को बाहर (चीन) से समर्थन मिल रहा है ।[84]

चीन का पहला राजनयिक शिष्टमण्डल चीनी चार्ज डी अफेयर लु [illegible] पी के नेतृत्व में थाईलैण्ड गया ।[85] 25 दिसम्बर 1975 को पहला थाई दूतावास स्थायी तौर पर पेईकिंग होटल में हुआ जिसके चार्ज डी अफेयर उत्थार युंग फाक्ती थे ।[86] 24 मार्च, 1976 को चीनी राजदूत चिया यु मिन ने थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री को अपना प्रत्यय-पत्र प्रेषित किया ।[87] चीन ने थाई - कम्पूचिया सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने पर बल दिया ।[88] थाईलैण्ड व चीन के बीच सैनिक-दूत का आदान प्रदान हुआ ।[89]

83- यह चीन द्वारा थाईलैण्ड केलिए सहायतार्थ इसलिए था क्योंकि थाई बाजार में, अमेरिकी चावल बहुल्यता से, चावल की कीमत गिर रही थी । एशियन रिकार्डर, 1975, पृष्ठ-12767 ।

84- बैंकाक पोस्ट, 18 सितम्बर, 1975 ।

85- वही, 22 अक्तूबर, 1975 ।

86- वही, 20 दिसम्बर, 1975 ।

87- वही, 25 मार्च, 1976 ।

88- वही, 21 अक्तूबर, 1977 ।

89- वही, 29 अप्रैल, 1978 ।

5 नवम्बर, 1978 को चीनी उपप्रधान मंत्री तंग शियाव फिंग पांच दिन की सरकारी यात्रा पर बैंकाक पहुंचे। तंग ने बैंकाक में कहा,

"चीन व थाई पड़ोसी देश हैं। प्राचीन समय से ही हमारी दोनों जनता शान्ति व समन्वय के साथ एक दूसरे से मित्रतापूर्ण संबंध रखती है, तथा दोनों ने चीन-थाई संबंधों के महान ग्रंथ में भावनापूर्ण अध्यायों का श्रीगणेश किया है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों जनता के पारम्परिक मित्रता को मजबूत व विकसित करना है तथा दोनों सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से थाई जनता के उनके राष्ट्र निर्माण के अनुभवों से सीखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों देशों के नेताओं के परस्पर यात्रा से चीन व थाईलैण्ड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध व सहयोग और अधिक मजबूत व विकसित होंगे।"[90]

चीनी उप प्रधान मंत्री तंग ने 7 नवम्बर, 1978 को थाई प्रधान मंत्री जनरल क्रियांगसाक व थाई विदेशमंत्री उपादित पचारियांगकुल से बातचीत के दौरान सोवियत-वियतनाम के बीच हुई मैत्री व सहयोग संधि[91] पर विचार विमर्श किया तथा हिन्द-चीन के प्रश्न पर विशेषकर कम्पूचिया-वियतनाम सीमा युद्ध पर बातचीत की और इसके साथ-साथ वियतनाम व चीन के बीच पैदा जातीय चीनियों की समस्या के विषय में हुई विवाद पर बातचीत की।[92]

चीनी नेता तंग के इस थाई यात्रा के दौरान थाईलैण्ड के नेताओं ने विशेष रूप से तंग को अपना सैनिक केन्द्र तथा उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया जो एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था।[93]

चीनी नेता तंग ने बैंकाक में 8 नवम्बर, 78 को एक पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए वियतनाम को "पूर्व का क्यूबा," तथा दक्षिण-पूर्व एशिया का "गुण्डा"

90- बैंकाक पोस्ट, 6 नवम्बर, 1978।

91- सोवियत संघ व वियतनाम के बीच 3 नवम्बर, 1978 को मास्को में मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए।

92- द हिन्दू (मद्रास) 8 नवम्बर, 1978।

93- बैंकाक पोस्ट, 9 नवम्बर, 1978।

कहा । उन्होंने कहा कि चीन वियतनाम के रवैए को ध्यान से देख रहा है कि वह काम्पूचिया के विरुद्ध आक्रमणकारी रवैया अपना रहा है । उन्होंने चीन की द्वितरीय मित्रता को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे "सरकार-सरकार" व "पार्टी-पार्टी" संबंध की नीति में विश्वास रखते हैं । तंग ने वियतनामी प्रधानमंत्री फाम वान डोंग की आलोचना की और उन्हें "झूठा" कहा । उन्होंने सोवियत-वियतनाम संबंध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हनोई-मास्को संधि एक सैनिक संधि है । हनोई-मास्को संधि के संभावित खतरे पर बोलते हुए तंग ने कहा :

"... आप सब लोगों को जानना चाहिए कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले न केवल इस क्षेत्र (दक्षिण-पूर्व एशिया) पर अधिकार जमाना चाहते हैं अपितु पूरी दुनिया पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं । एशिया व दक्षिण-पूर्व एशिया में उनके इस प्रकार के प्रभुत्ववादी इच्छाओं के लिए प्रयत्न जारी हैं । एक महाशक्ति सोवियत संघ छोटे शक्ति वियतनाम के साथ सहयोग कर रहा है । वियतनाम-सोवियत संधि में प्रभुत्ववाद की मानसिकता को त्यागा नहीं गया है बल्कि वह पूरी तरह इस संधि में समाहित है । इससे प्रभुत्ववाद का "गुन्डागर्दी" साफ स्पष्ट होता है । आप जानते हैं कि क्यूबा कैसा है । अब पूर्व का क्यूबा भी उभर रहा है । हमारा उद्देश्य केवल चीन की सुरक्षा नहीं है । इसका प्रभाव पूरी एशिया पर पड़ सकता है । यह संधि एशिया व प्रशांत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है । .... पार्टी-पार्टी संबंध, सरकार-सरकार संबंध को प्रभावित नहीं करेगी... थाईलैण्ड के साथ सरकार-सरकार संबंध काफी संतोषप्रद है ।... हमें एक दूसरे को समझना चाहिए तथा हमलोगों को एक दूसरे से सहानुभूति होनी चाहिए । अगर हम अच्छे मित्र होना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से काफी दायित्व पूर्ण बात करनी चाहिए । अगर हम झूठ बोलें या अपनी आत्मा ही बेच दें तो मित्रता करना काफी कठिन हो जाएगा । इस बात में, मैं फाम वान डोंग से सीख नहीं ले सकता ।"[94]

94- बैंकाक पोस्ट, 9 नवम्बर, 1978, तथा पेकिंग रिव्यू, 17 नवम्बर 78, पृष्ठ- 25-26 ।

आसियान-चीन आर्थिक संबंध :

आसियान देशों व चीन के बीच आर्थिक संबंध, उनके भौगोलिक निकटता की विशेषताओं तथा आसियान देशों में रह रहे प्रवासी चीनियों के आर्थिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण काफी पुराने व गहरे रहे हैं। तथापि अतीत में, आसियान व चीन के बीच आर्थिक संबंध, वस्तुत: राज्यों की नीतियों के नेतृत्व के बिना मुख्यत: छोटे निजी क्षेत्र तक सीमित थे। चीन के नए आर्थिक प्रणाली के कारण, चीन के आर्थिक मामलों के संचालन में राज्य का प्रभाव व शक्ति अत्याधिक है, तथा इन आर्थिक संबंधों की प्रकृति में काफी भिन्नता आयी है। परिणाम-स्वरूप, आसियान देशों में निजी क्षेत्र के व्यापारियों के संचालन के लिए राज्य-राज्य संबंध एक भूमिका व ढांचा के रूप में विकसित हुए हैं। चूंकि आसियान एक समूह के रूप में है इसलिए इसका चीन के साथ आर्थिक व राजनीतिक गणनाओं के लिए काफी महत्ता है। आसियान के प्रत्येक घटक देशों व चीन के आर्थिक संबंधों में भिन्नता मौजूद है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि चीन के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रत्येक आसियान देशों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है तथा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन प्रत्येक देशों के राजनीतिक संबंध चीन के साथ किस प्रकार के हैं।

कुछ विद्वानों के मतानुसार तीन आसियान देशों - मलेशिया, फिलीपींस, व थाईलैंड की तुलना में इंडोनेशिया व सिंगापुर चीन के आधुनिकीकरण गतिविधियों में न्यूनतम रूप से रुचि रखते हैं, और 1985 तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। वास्तव में इंडोनेशिया व सिंगापुर में अन्य तीन आसियान मित्र देशों की तुलना में चीन के साथ आर्थिक संबंधों में उनके लाभ की उम्मीद कम तथा हानि की आशा अधिक है। इसका कारण जितना ही राजनीतिक है उतना ही आर्थिक भी समझा जाता है। इंडोनेशिया चीन के साथ संबंध बनाने में काफी सावधान है इसी लिए इन देशों के बीच आर्थिक संबंध सीमित व गैर सरकारी रूप से है। इन दोनों देशों के बीच व्यापार हांगकांग तथा कुछ सिंगापुर के माध्यम से अप्रत्यक्ष

रूप से होता है ।[95]

मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैण्ड के चीन के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के परिणामस्वरूप उनके चीन के साथ व्यापारिक व पूंजी निवेश दोनों में आर्थिक संबंध तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं ।

बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के प्रारंभ में आसियान देशों के साथ चीन के सम्पूर्ण व्यापार का मात्र 5 से 6 प्रतिशत था जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम था । इसमें भी दो-तिहाई आसियान-चीन से आयात करता था तथा एक तिहाई आसियान चीन को निर्यात । आसियान के पांचों देशों में सिंगापुर-चीन व्यापार पूरे आसियान-चीन व्यापार का एक तिहाई था जबकि इंडोनेशिया का चीन के साथ कम व्यापार होता था, जो पूरे व्यापार का 15 प्रतिशत ही था, तथा यह भी मुख्यत: चीन से इंडोनेशिया का एक पक्षीय व्यापार था जिसमें चीन इंडोनेशिया को मुख्य रूप से चावल, चीनी तथा अन्य खाद्य सामग्री अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात करता था।

आसियान चीन से मुख्य रूप से कच्चा तेल, हल्के तैयार माल (उत्पादन) एवम् प्रवासी चीनियों के लिए तैयार खाद्य सामग्री, आदि आयात करता है । आसियान इसके बदले में चीन को खाद्य सामग्री, कच्चा माल जैसे-- अबाका फाइबर, प्राकृतिक रबड़, तांबा, टिन, जिंक, समुद्रतेल, क्रोमियम बाक्साइट, निकिल व टंगस्टन ।[96] आसियान व चीन के बीच का सम्पूर्ण व्यापार 1978 में लगभग 2 अरब अमेरिकी डालर पहुंच गया था ।[97] सन् 1980 में चीन ने इंडोनेशिया को 16.1 करोड़ डालर की वस्तुएं अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की । अन्य चार आसियान देशों के साथ चीन का

95- सुरा सानितानोंत, "चाइनाज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एण्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन आसियान," एशिया पैसिफिक कम्यूनिटी (टोक्यो) सं06, फाल 1979, पृष्ठ- 63 ।

96- वही, पृष्ठ- 64 ।

97- एशिया वीक (हांगकांग) 18 अप्रैल, 1980, पृष्ठ- 42 ।

तालिका सं0-1

आसियान- चीन व्यापार 98

(अमेरिकी डालर) (करोड़ में)

वर्ष	व्यापार	थाईलैण्ड	फिलीपीन्स	मलेशिया	सिंगापुर	इंडोनेशिया	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1974	आयात	0.45	2.70	19.54	26.46	11.39	62.64
	निर्यात	0.02	1.34	8.71	5.13	---	19.79
	सम्पूर्ण	0.47	4.04	28.25	31.59	11.39	82.43
1975	आयात	1.69	5.08	14.89	28.62	20.35	72.23
	निर्यात	1.92	2.30	5.24	4.07	---	13.62
	सम्पूर्ण	3.61	7.38	20.13	32.69	20.35	85.85
1976	आयात	5.67	5.66	13.44	26.67	13.18	66.22
	निर्यात	6.68	3.83	4.48	3.87	---	18.95
	सम्पूर्ण	12.35	9.49	17.92	30.54	13.18	85.17
1977	आयात	6.70	8.30	14.10	29.50	15.40	75.50
	निर्यात	6.68	3.83	4.48	3.87	---	18.95
	सम्पूर्ण	16.90	19.20	26.10	35.40	15.40	114.60
1978	आयात	7.99	11.39	21.06	32.58	10.69	83.10
	निर्यात	7.07	4.87	11.03	5.79	अप्राप्त	अनुपलब्ध
	सम्पूर्ण	15.06	16.26	32.09	38.37	अनुपलब्ध	''

98- रिपोर्ट, सं0-2, पृष्ठ- 113, जैन, सं0-9, सन् 1979 से 1981 तक, पृष्ठ- 349 में यूरोपा पब्लिकेशन्स, द फॉर ईस्ट एण्ड आस्ट्रेलिया, 1982-83(लंदन 1982), 750 से, तथा एयरबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सिंगापुर : डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1979	आयात	24,189	अनुपलब्ध	22,259	89,41 (÷)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	निर्यात	7,698	,,	18,174	13,07	,,	,,
	सम्पूर्ण	31,887	,,	40,433	90,62	,,	,,
1980	आयात	अनुपलब्ध	,,	55,13 (-)	अनुपलब्ध	,,	,,
	निर्यात	,,	,,	47,13	,,	,,	,,
	सम्पूर्ण	,,	,,	102,26	,,	,,	,,
1981	आयात	39,127 (÷)	,,	63,16 (-)	,,	,,	,,
	निर्यात	26,164	,,	20,31	,,	,,	,,
	सम्पूर्ण	65,291	,,	83,47	,,	,,	,,

(-) मलेशियाई डालर या रिंगिट्स में। (÷) सिंगापुरी डालर में। (÷) चीनी मुद्रा रेन मिनपी में।

1979।80, पृष्ठ- 126 से पी टर्स, सं0-53, पृष्ठ- 346 में उद्धृत तथा थाईलैण्ड - चीन , 1979-81 का आकड़ा यू0एन0 इयर बुक ऑफ इन्टरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में थाईलैण्ड, डिपार्टमेंट आफ कस्टम, एन्युअल स्टेटमेन्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ थाईलैण्ड से उद्धृत।

तालिका सं० -8

आसियान - चीन व्यापार[99]

(अमेरिकी डालर, करोड़ में)

आसियान देश	वर्ष सन् 1971-75	सन् 1976-78	सन् 1978-85
इंडोनेशिया (अप्रत्यक्ष)	30.00	45.00	200.00
मलेशिया	45.00	67.30	260.00
फिलीपींस	32.00	46.70	220.00
सिंगापुर	69.00	102.60	400.00
थाईलैण्ड	34.00	50.40	250.00
सम्पूर्ण आसियान	210.00	312.00	1130.00
औसत	42.20	104.00	119.00
चीन के सम्पूर्ण व्यापार का प्रतिशत	5.1 प्रति०	6.5 प्रति०	5.2 प्रतिशत

99- सूरा, सं०- 95, पृष्ठ-68 में जापान एक्सटरनल ट्रेड आर्गनाइजेशन से उद्धृत ।

व्यापार 1970-80 में काफी मात्रा में बढ़ता गया । मलेशिया व चीन के बीच सन् 1978 में 32.9 करोड़डालर से 1980 में 53.3 करोड़ डालर हो गया । इसी अवधि में फिलीपींस व चीन के बीच व्यापार 16 करोड़ डालर से 27.7 करोड़ डालर, सिंगापुर व चीन के साथ 23.4 करोड़ डालर से 86.2 करोड़ डालर तथा थाईलैण्ड का चीन के साथ 15.7 करोड़ डालर से 59.8 करोड़ डालर हो गया था ।

आसियान-चीन के बीच सामूहिक आर्थिक सहयोग का भी असाधारण विकास हुआ है । आसियान देशों में चीन के साथ सामूहिक सहयोग के क्षेत्र में फिलीपींस पहला विकासशील देश था जिसने चीन के साथ एक समझौते के अनुसार ट्रिंटीम व पेईचिंग में 500 कमरे का होटल निर्माण के लिए जुलाई 1979 में हस्ताक्षर किया । इसी प्रकार के होटल परियोजना के लिए चीन थाईलैण्ड के साथ भी सामूहिक सहयोग पर सहमत हो गया था, तथा मलेशिया भी अत्याधिक क्षमता वाले टावर के निर्माण हेतु चीन के साथ सामूहिक सहयोग का अध्ययन कर रहा है । चीन अपने औद्योगिक विकास के लिए काफी बड़े पैमाने पर आसियान देशों के आर्थिक प्रगति व व्यवस्था का की आंदोलित करने में रूचि रखता है ।[100] थाई व्यापार आर्थिक विभाग के निदेशक आनंद पाचा उम ने 26 मार्च 78 को थाई-चीन व्यापार संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि थाईलैण्ड का चीन के साथ व्यापार काफी बढ़ गया है, यद्यपि राजनयिक संबंध मात्र तीन वर्ष पूर्व बने थे ।[101] 1977 में थाई-चीन व्यापार, समस्त समाजवादी देशों के साथ हुए व्यापार का 73 प्रतिशत था। थाई - चीन के बीच व्यापार 1974 से 1977 के दौरान 9.44 करोड़ बात से 333.8 करोड़ बात हो गया जो 35 गुना अधिक था । थाई से चीन निर्यात 1974 में 9.19 करोड़ बात से बढ़कर 1977 में 197.23 करोड़ बात हो गया जो 21 गुना था । थाई ने चीन से आयात 25 लाख बात से 136.57 करोड़ बात जो 546 गुना अधिक था ।[102]

100- रिपोर्ट, सं० 2, पृष्ठ-114 ।

101- बैंकाक पोस्ट, 27 मार्च, 1978 ।

102- वही ।

इंडोनेशिया-चीन आर्थिक संबंध :

इंडोनेशियाई विशेषज्ञों का विचार था कि चीन से मुख्य खतरा सैनिक न होकर आर्थिक है। इंडोनेशियाई गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल योगा सुगामा ने इंडोनेशियाई अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए कहा था कि चीन प्रत्येक वर्ष करोड़ों डालर मूल्य की वस्तुएं तस्करी द्वारा इंडोनेशिया भेज रहा है।[103] एक राज्य स्तरीय मंत्री ने कहा कि इंडोनेशियाई घरेलू उद्योगों को बर्बाद व समाप्त करने के लिए इंडोनेशियाई बाजारों में मालों का हेराफेरी करना चीन की आर्थिक नीति है।

1965 में इंडोनेशिया-चीन संबंधों के समाप्त होने के बावजूद हांगकांग व सिंगापुर के माध्यम से इंडोनेशियाई बाजार में चीनी वस्तुओं का ढेर लगा रहता है। इंडोनेशियाई नेताओं के अनुसार चीन का उद्देश्य चीनी वस्तुओं के निर्यात व इंडोनेशिया में प्रभावशाली आर्थिक चीनी आबादी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रबल अधिकार कायम करना है। राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक प्रभाव का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है जैसा कि इतिहास साक्षी है।[104]

अक्तूबर 1967 में इंडोनेशिया व चीन के राजनयिक संबंध स्थगित होने के बाद पहली बार इंडोनेशियाई राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स व उद्योग का पांच सदस्यों का सरकारी प्रतिनिधि मण्डल, इंडोनेशियाई वाणिज्य चैम्बर व उद्योग के अध्यक्ष नूर अमिन के नेतृत्व में नवम्बर, 1977 में चीन की यात्रा पर गया। इस व्यापार व उद्योग प्रतिनिधि मण्डल का उद्देश्य कैन्टोन में आयोजित व्यापार मेले का निरीक्षण करना तथा दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार संबंधों की संभावना पर भी विचार करना था। इसमें राजनयिक संबंधों के बिना व्यापार संबंधों को विकसित करने पर बातचीत की गई। जिसका उदाहरण सिंगापुर-चीन आर्थिक संबंध था।[105]

103- इन्डोनेशिया टाइम्स, 26 नवम्बर, 1975।

104- वही।

105- इंडोनेशिया टाइम्स, 22 नवम्बर, 1977।

मई 1978 में भी इसी प्रकार का एक प्रतिनिधि-मण्डल चीन की यात्रा पर गया था । यह प्रतिनिधि मण्डल अपने चीन यात्रा के दौरान प्रत्यक्ष व्यापार की समस्या पर बातचीत करने पेकिंग भी गया । इस प्रतिनिधिमण्डल ने प्रत्यक्ष व्यापार के बारे में अपना विचार प्रकट किया कि सीधे व्यापार से आशातीत कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला विशेषकर राजनीतिक रूप से ।[106]

व्यापार व सहकारिता मंत्री राडियस प्राविरो ने 23 मई 78 को प्रत्यक्ष व्यापार को टालते हुए कहा :

"राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यापार व्यवस्था अधिक फलोत्पादक है ।"[107] चीन समर्थित व्यापार दल ने सीधे व्यापार के पक्ष में तर्क पेश करते हुए कहा कि हांगकांग व सिंगापुर के माध्यम से अप्रत्यक्ष व्यापार की तुलना में प्रत्यक्ष व्यापार से इंडोनेशिया को 10 से 20 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ हो सकता है ।[108]

18 फरवरी, 80 को इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ऐडम मलिक ने कहा कि इंडोनेशिया चीन को प्रत्यक्ष रूप से रबड़ व बांस का निर्यात करेगा जो दोनों देशों के राजनयिक व व्यापारिक संबंधों की पुनर्वापसी का पहला कदम था । मलिक ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना में अब कोई मुख्य बाधा नहीं है । उन्होंने कहा कि अब व्यापार में किसी अन्य देश जैसे हांगकांग या सिंगापुर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इंडोनेशिया राजनीतिक वातावरण में "प्रगतिशील संबंधों" का पक्षपाती है ।[109]

परन्तु 25 मार्च 80 को विदेशी व्यापार मामलों के निदेशक सुहादी मंगकुसुबन्दो ने कहा कि इंडोनेशिया व चीन के बीच प्रत्यक्ष सीमित व्यापार तभी हो सकेगा जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की वापसी हो जाए ।[110]

106- बैंकाक पोस्ट, 8 मई, 1978 ।

107- बैंकाक पोस्ट व इंडोनेशिया टाइम्स, 24 मई, 1978 तथा स्ट्रेट्स टाइम्स, 3 जून, 78 ।

108- किंग्स, स०-14, पृष्ठ-116 ।

109- बैंकाक पोस्ट, 20 फरवरी, 1980

110- इंडोनेशिया टाइम्स, 26 मार्च, 1980 ।

सिंगापुर-चीन आर्थिक संबंध :

औपचारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति से सिंगापुर -चीन के बीच व्यापार व आर्थिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । सिंगापुर ने चीन को चीनी बैंक तथा एक अर्ध-कार्यालयी पेकिंग प्रतिनिधि की अनुमति दे रखी है । जिससे सिंगापुर में चीन अपना व्यापार करता रहे । चीनी बैंक सिंगापुर-चीन व्यापार का माध्यम है ।[111]

1968 से 78 तक सिंगापुर-चीन के बीच व्यापार लगभग दूना हो गया । जबकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं है । 1968 में सिंगापुर व चीन के बीच सम्पूर्ण व्यापार 24.6 करोड़ अमेरिकी डालर था तथा 1978 में बढ़कर 41.2 करोड़ अमेरिकी डालर हो गया । राजनयिक संबंध के बिना भी सिंगापुर चीन के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण हैं ।[112]

आसियान - चीन संबंध व प्रवासी चीनी :

आसियान व चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व नाजुक समस्या प्रवासी चीनियों की है । थाईलैण्ड में 10.5 प्रतिशत, मलेशिया में 33.8 प्रतिशत, सिंगापुर में 75 प्रतिशत, फिलीपींस में 1.2 प्रतिशत तथा इंडोनेशिया में 2.7 प्रतिशत जातीय चीनी हैं ।[113]

111- पीटर्स, सं० 53 , पृष्ठ- 346 ।

112- बैंकाक पोस्ट, 20 मार्च, 1979 ।

113- कु० पे० तालिका सं०-3

तालिका सं०-3

आसियान देशों में प्रवासी चीनी

देश	पूरी जनसंख्या (करोड़ में)	प्रवासी चीनी (लाख में)	चीनी राष्ट्रीयता प्राप्त	प्रवासी चीनी समूची जनसंख्या का भाग (प्रतिशत में)
थाईलैण्ड	4.750	50.00	3.00	10.5
मलेशिया	1.300	44.00	कुछ	33.8
सिंगापुर	0.240	18.00	कुछ	75.0
फिलीपींस	4.630	5.50	1.20	1.2
इंडोनेशिया	13.700	38.00	9.70	2.7

स्रोत : प्रस्तुत आंकड़ा एशिया ईयर बुक 1979, फॉर ईस्टर्न एकॉनॉमिक रिव्यू, (हांगकांग) से लिया गया है।

इस प्रकार आसियान देशों में कुल मिलाकर लगभग दो करोड़ प्रवासी चीनी रहते हैं। आसियान-चीन संबंध में यह एक अनूठा, जटिल व रोचक आयाम है। ऐसा समझा जाता है कि आसियान सरकारों के लिए, चीनी अल्पसंख्यकों में वृद्धि, उनके साम्यवादी चीन के साथ संबंध, सरदर्द बना हुआ है। इस सरदर्द का मुख्य कारण यह है कि चीनी आसियान समाज के अपच्य समूह हैं तथा सर्वत्र राज्य संस्था के रूप में जीवन यापन करते हैं। इन चीनियों ने आसियान देशों में अपना घर पर ही बना लिया है तथा "चीनी-बाजार" व "चीनी-नगर" का निर्माण कर रखा है।[114]

114. सिंह, ललिता प्रसाद, "पावर पॉलिटिक्स एण्ड साउथ ईस्ट एशिया", रेडियंट पब्लिशर्स (नयी दिल्ली, 1979), पृष्ठ- 59।

यद्यपि प्रवासी चीनियों की, आसियान देशों में, जनसंख्या पूरी जनसंख्या के मात्र 5 प्रतिशत है पर आसियान देशों के आर्थिक क्षेत्र में उनकी स्थिति काफी मजबूत है। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रवासी चीनी , जिस देश में रहते हैं, एक विशेष रूप से अपने आपको संगठित करके स्थानीय समाज से अलग-थलग रहते हैं।[115] प्रवासी चीनी आसियान देशों के प्रमुख आर्थिक , तकनीकी, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। आसियान देशों में चीनियों के पास आर्थिक शक्ति से आसियान देशों की अधिक परेशानी होती है। परन्तु इससे भी अधिक आतंकित करने वाली बात प्रवासी चीनियों की चीन के प्रति निष्ठा से है ऐसा समझा जाता है कि चीन इन्हीं प्रवासियों के माध्यम से इन आसियान देशों से अपनी राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है।

चीन अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के बारे में वास्तविक रूप से सचेत होने के कारण, आसियान देश के प्रवासी चीनी सदैव चीन की ओर सांस्कृतिक प्रेम के रूप में देखते रहते हैं तथा वे जिस देश में रहते हैं उसके बारे में कुछ चिंता नहीं करते। जब चीन कमजोर था तब भी वह प्रवासी चीनियों की निष्ठा व समर्थन को प्राप्त करता रहता था, अब तो वह एक मजबूत व विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश बन चुका है। इस स्थिति में तो प्रवासी चीनियों के दिल में चीन के प्रति काफी आदर व निष्ठा का होना स्वाभाविक ही है। कुछ विचारकों के अनुसार यही कारण था कि अमेरिका ताइवान की एक पूर्ण चीन की तरह समर्थन देता रहा ताकि प्रवासी चीनियों की इस अंतराष्ट्रीयकृत मानसिकता को संतुष्ट किया जा सके और वह अपना संबंध गैरसाम्यवादी सरकार जो चीन गणराज्य से बनाए रखे जो चीन लोकगणराज्य के विकल्प के रूप में होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रवासी चीनियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साम्यवाद से नफरत करते हैं तथा वे ताइवान शासन के प्रति निष्ठावान हैं, पर उनकी संख्या कम है।[116] सी०पी० फिट्जेराल्ड के अनुसार चीनी कभी पराजित शक्तियों के समर्थक नहीं रहे हैं, परम्परावादी चीनी दृष्टिकोण

115- रिपोर्ट, सं० 2, पृष्ठ- 108।

116- सिंह, सं०-114, पृष्ठ- 60।

के अनुसार - समाप्त हो रहा शासन जो "स्वर्ग का शासनादेश" खो चुका हो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए ।[117] इस तर्क के अनुसार चीन की साम्यवादी सरकार स्वर्ग का नया शासनादेश है । प्रवासी चीनी इस बात को समझते हैं कि पेकिंग की सरकार ने एक बार फिर उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है ।

कुछ विद्वानों के अनुसार प्रवासी चीनी आसियान-चीन संबंध के बीच एक "सेतु" का कार्य कर रहे हैं । इसलिए चीन, आसियान देशों में रहने वाले प्रवासी चीनियों के साथ संबंध बनाने में काफी सक्रिय है । प्रवासी चीनियों का आसियान देशों में पूंजी निवेश लगभग दस अरब डालर से 15 अरब डालर के बीच है ।[118] ऐसा माना जाता है कि प्रवासी चीनी अपने लाभांश को चीन भेजते हैं तथा चीन के आर्थिक व सैनिक बजट में अपना आर्थिक सहयोग देते हैं । प्रवासी चीनी अपने आपको आसियान देशों में कभी-कभी असुरक्षित महसूस करते हैं । इसीलिए प्रवासी चीनी पूंजीवाद व पश्चिम देशों के समर्थक होते हुए भी वे चीन के साथ अपना पूरा निकट संबंध रखना चाहते हैं ताकि संकटकालीन अवस्था में वे चीन से सहयोग प्राप्त कर सकें ।

कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रवासी चीनी चाहे किसी भी विचार से संबंधित हो, किसी समाज व्यवस्था में विश्वास रखता हो, किसी देश में रहता हो या उसका नागरिक हो, वह सदैव चीन की तरफ देखता रहता है तथा उसे ही अपना सब कुछ मानता है । चीन भी प्रवासी चीनियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करता है । चीन हमेशा से ही आसियान क्षेत्र को अपने आंगन की तरह देखता आ रहा है । ऐतिहासिक तौर पर चीन की इस क्षेत्र पर अपना विशेष अधिकार व आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति रही है । वह इन देशों के साथ संबंध बनाने में अपनी राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र को सीमित समझने लगता है । ऐसा समझा जाता है कि चीन आसियान देशों में राजनीतिक, व्यापारिक व आर्थिक खेल खेल रहे प्रवासी

---

117. फिट्जेराल्ड, सी०पी० "द थर्ड चाइना : द चाइनीज कम्युनिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया" (ग्रेट ब्रिटेन, 1965), पृष्ठ 63

118. वही, सं०-114, पृष्ठ 62 ।

चीनियों को हर तरह का आरक्षण देना व उनसे अपना कार्य करवाना परम कर्तव्य समझता है ।

प्रवासी चीनियों की समस्या पर इंडोनेशिया के जनरल अली मुरतोपो व जनरल सुमारसो का दृष्टिकोण है कि अगर समस्त आप्रवासी चीनियों को आसियान देशों द्वारा नागरिकता दे दी जाती है तो ये चीनी तदोपरान्त उस देश के नागरिक बन जायेंगे तथा उनसे संबंधित पैदा हुई समस्यायें उस देश की आंतरिक समस्या होगी जिससे सरकार जैसे चाहे वैसे निपटे । उस स्थिति में चीन किसी प्रकार इन प्रवासी चीनियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पायेगा । इस दृष्टिकोण यह भी है कि चीनी समस्यायें राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों में है । इस विचार के अनुसार चीनी अल्पसंख्यक सर्वप्रथम राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से उस देश के वास्तविक नागरिक बनें । इसके अतिरिक्त आसियान देशों में चीनी अल्पसंख्यकों के आर्थिक प्रभाव समाप्त होने चाहिए या कम-से-कम मध्यवर्गीय लोगों को उनके प्रतिद्वन्द्वी के रूप में विकसित करना चाहिए ।[119]

आसियान के प्रति चीन का समर्थन पूर्ण रवैए का दर्शन विशेष तौर पर अगस्त 1977 में कुवालालम्पुर में हुए द्वितीय आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ । चीन ने आसियान की समस्त गतिविधियों का पूर्ण समर्थन किया । यहाँ तक कि चीन ने उसके विकसित देशों-जापान, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तथा यौरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों के साथ संबंधों का भी समर्थन किया । चीन के इस नए प्रकार की विदेश नीति का एक कारण यह भी था कि वह अपनी नए नेतृत्व के अन्तर्गत सन् 1976 से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक स्वीकारात्मक नीति का प्रतिपादक रहा था । आसियान देशों की गतिविधियों को, चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में, सोवियत प्रभाव तथा महाशक्तियों के इच्छा के विरुद्ध समझने लगा । इस आसियान नीति के संदर्भ में चीन का स्वीकारात्मक रवैया बढ़ता ही गया ।[120]

119- जियी, सं0-14, पृष्ठ- 183 ।

120- रॉयटर, सं0-2, पृष्ठ- 103 ।

26 फरवरी, 1978 को चीनी प्रधानमंत्री हुवा क्वो फ्रांग ने राष्ट्रीय जन सभा (नेशनल पीपुल्स कांग्रेस) के पांचवें बैठक में संदेश दिया कि चीन इंडोनेशिया के साथ राजनयिक संबंध पुनः बनाने के लिए तैयार है तथा सिंगापुर के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करना चाहता है। इस रिपोर्ट में उन्होंने चीन व दक्षिण-पूर्व एशिया के पुराने घनिष्ट संबंधों पर टिप्पणी करते हुए मलेशिया, फिलीपींस व थाईलैण्ड के साथ राजनयिक संबंधों की चर्चा की, तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के समस्त देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।[121]

चीन उन आसियान देशों, जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध हैं, के साथ अपने संबंधों को अत्याधिक मजबूत बनाने का प्रयत्न करता रहा है। चीन ने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं को आसियान देशों की यात्रा हेतु भेजा था जैसे मार्च में ली शिएन निएन ने फिलीपींस की यात्रा की, नवम्बर, 78 में तंग शियाओ पिंग ने थाईलैण्ड मलेशिया व सिंगापुर की यात्रा की। इसके साथ-साथ आसियान नेता जैसे थाई प्रधानमंत्री व मलेशिया के विदेश मंत्री तुंकु अहमद रिथाउद्दीन ने मार्च, 1978 व सितम्बर 1978 में चीन की यात्राएं की।[122]

चीन के तत्कालीन उपप्रधानमंत्री ली शिएन निएन ने मार्च, 1978 की अपनी फिलीपींस यात्रा के दौरान कई बार आसियान को चीन के पूर्ण समर्थन की चर्चा की।

13 मार्च, 78 को ली शिएन निएन ने राष्ट्रपति मारकोस द्वारा दिए गए भोज समारोह में कहा कि चीन आसियान की संप्रभुता की रक्षा करने व महाशक्तियों के हस्तक्षेप के विरोध करने के आसियान के उचित संघर्ष की प्रशंसा करता है। उन्होंने कहा कि चीन दक्षिण-पूर्व एशिया के तटस्थता के आसियान के प्रस्ताव व उनके आर्थिक अधिकारों व प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों का समर्थन करता है। राष्ट्रपति मारकोस ने चीन के विश्व शान्ति के लिए योगदान, तथा

---

121. <u>इंडोनेशिया टाइम्स</u>, 8 मार्च, 1978, तथा लाउ, पूर्व 39, पृष्ठ- 65 में उद्धृत।

122. लाउ, पूर्व-39, पृष्ठ- 66।

फिलीपींस जैसे विकासशील देशों के हित के लिए उसकी "गम्भीर व गहरी" रुचि की सराहना की । दोनों देशों ने स्पार्टली द्वीप के प्रश्न पर नम्रतापूर्वक बातचीत की जिसका फिलीपींस-चीन संबंध पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उन्होंने यह तय किया कि द्वीपों के बारे में प्रत्येक प्रकार के विवादों का शान्तिपूर्ण राजनयिक प्रयासों से हल किया जायगा । चीनी नेता ने कहा कि आसियान, एकता की मजबूती व आर्थिक सहयोग के माध्यम से, प्रभुत्ववादी विस्तार को रोक सकता है, तथा आसियान सोवियत प्रभाव को दक्षिण-पूर्व एशिया में रोकने में सहायता कर सकता है ।[123]

1978 तक चीन ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय संबंधों की बात की थी क्योंकि आसियान एक संगठन के साथ उसके संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था । परन्तु इस नीति में परिवर्तन तब हुआ जब थाई प्रधानमंत्री क्रियांग साक चामानंद ने मार्च 1978 में चीन की यात्रा की । इस यात्रा के समय तंग शियाओ पिंग ने क्रियांगसाक चामानंद के सम्मान में दिए गए भोज में बोलते हुए घोषणा की कि आसियान ने क्षेत्रीय संगठन के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में अपनी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है । तंग ने चामानंद के स्वागत में कहा :

"हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग व हमारी दोनों जनताओं के बीच मैत्री तथा मित्रतापूर्ण संबंध के विकास की नयी शृंखला में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान होगा.... चीन आसियान के उद्देश्यों व इसके दक्षिण-पूर्व एशिया में "शान्तिक्षेत्र" के प्रस्ताव की सराहना व समर्थन करता है । चीन नए अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थापना हेतु समान संघर्षों में भी आसियान देशों का समर्थन करता है ।... यह कुशाग्र मानसिकता उनकी प्रभुत्ववादी विस्तार व घुसपैठ को रोकने की मजबूत क्षमता को दर्शाती है तथा यह प्रभुत्ववाद के विरुद्ध एकता एशियाई जनता के लिए अच्छी

123- बैंकाक पोस्ट, 14 मार्च, 1978 तथा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, 13 मार्च, 1978 ।

होगी - इन समस्त प्रयत्नों का चीनी सरकार समर्थन करती है।"[124]

चीनी नेता तंग ने थाई नेता बापानंद से चीन व आसियान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में कहा कि चीन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने विदेशी संबंधों को विकसित व मजबूत करने के लिए सदैव कार्यरत रहने के लिए तैयार है।[125]

थाई प्रधानमंत्री क्रियांगसाक ने पहली अप्रैल, 1978 को कहा कि चीन आसियान के प्रत्येक देश के साथ सद्भावपूर्ण समझदारी के साथ संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन की यह नीति निश्चित रूप से इस क्षेत्र में स्थिरता व सुरक्षा की बढ़ाने में सकारात्मक योगदान कर सकती है। उन्होंने कहा :

"मैं आशा करता हूं कि आसियान व चीन के संबंध और अधिक विकसित होंगे। अभी तो केवल तीन देशों - मलेशिया, फिलीपींस व थाईलैण्ड का ही चीन के साथ संबंध हैं। ... चीन ने आसियान के प्रति काफी सद्भावपूर्ण मानसिकता व समर्थन का परिचय दिया है।"[126]

थाई नेता बापानंद ने कहा कि वे चीन के अन्तरराष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने की भावना की प्रशंसा करते हैं तथा उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि चीन तीन गणराज्य आसियान के अच्छे उद्देश्यों की समझता व समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि आसियान व चीन के बीच उपयोग सहयोग के लिए काफी विस्तृत आयाम व क्षेत्र हैं।[127]

जुलाई, 1978 में मनीला में हुए आसियान व्यापार मेले के समय चीन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इस मेले से प्रतीत होता है कि संगठन

120- न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स (कुआलालम्पुर) 31 मार्च, 1978, हिंदुस्तान पोस्ट, 30 मार्च, 78।

125- वही।

126- द पैट्रियट (नयी दिल्ली) 2 अप्रैल, 1978।

127- हिंदुस्तान पोस्ट, 30 मार्च, 1978।

(आसियान), अपनी बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका में अन्तरराष्ट्रीय मामलों व एशिया में एक उभरती शक्ति है।[128]

1978 के हिन्द-चीन में हुए परिवर्तन जिसमें सोवियत-वियतनाम संधि, सोवियत समर्थित वियतनाम का 25 दिसम्बर, 1978 को जनवादी कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप तथा सोवियत-वियतनाम के संयुक्त रूप से बढ़ती रोमांचकारी गतिविधियों का आसियान-चीन संबंध पर धनात्मक प्रभाव पड़ा।

---00000---

128- रॉबर्ट, सं०-2, पृष्ठ- 103।

चतुर्थ अध्याय

आसियान व चीन : कम्पूचिया के विशेष संदर्भ में

वर्ष 1978 से आसियान राजनीति में बुनियादी परिवर्तन हुए। जिस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के हिन्द-चीन में 1975 के परिवर्तन के परिणामस्वरूप आसियान उत्प्रेरित हुआ था उसी प्रकार 1978 के परिवर्तन के बाद वह पुनः उत्प्रेरित हुआ।

वर्ष 1978, आसियान-चीन संबंधों में एक विशेष वर्ष कहा जा सकता है। आसियान देश सोवियत-वियतनाम के बीच बढ़ते संबंधों से काफी चिंतित थे पर वे इन साम्यवादियों के हिन्द-चीन या दक्षिण-पूर्व एशिया के विवादों में किसी विशेष देश के पक्षधर नहीं थे चाहे वह चीन हो या वियतनाम।[1]

आसियान देश वियतनाम के सोवियत संघ के साथ बढ़ते संबंधों को काफी ध्यान से देख रहे थे। 1978 के अंतिम मासों में वियतनाम की दक्षिण-पूर्व एशिया में तटस्थ होने की छवि का ह्रास तब होना प्रारंभ हो गया जब उसके मास्को के साथ बढ़ते समझौते सामने आए। हनोई इन समझौतों के बाद सोवियत खेमे में जा पहुँचा। वियतनाम 29 जून, 1978 को सोवियत संघ के कॉमकॉन[2], परस्पर आर्थिक सहयोग परिषद् (कौंसिल ऑफ म्युचुअल एकोनॉमिक कोऑपरेशन) का दसवां पूर्ण सदस्य बन गया। हनोई ने 3 नवम्बर 1978 को मास्को के साथ मैत्री व सहयोग संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिया। इस संधि के बाद आसियान की स्थिति में एक नया मोड़ आया तथा इन देशों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के प्रति अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाना चाहा। आसियान देशों की हनोई-मास्को संधि के परिणामस्वरूप,

---

1. डान ओबरडोर्फर, "रेड्स वर्सेज रेड्स इन इंडो-चाइना : ए न्यू, कम्प्लीकेटिंग कार्इन्ड ऑफ वार", वाशिंगटन पोस्ट, 1 अप्रैल, 1979।
2. कॉमकॉन मास्को के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप का साम्यवादी आर्थिक समूह है।

ज्वाईं के दक्षिण-पूर्व एशिया में तटस्थ रहने के विचारों पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि आसियान देशों के विचार में अब यह दक्षिण-पूर्व एशिया में सोवियत प्रतिनिधि बन चुका था । इन समझौतों के बाद आसियान देश वियतनाम को एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह मानने पर तैयार न थे ।[3]

चीन आसियान देशों को सावधान करता आ रहा था कि वियतनाम लगभग एक सोवियत हथियार है तथा वह दक्षिण-पूर्व एशिया में क्यूबाई पद्धति से पहल कर रहा है ।[4] तथा वियतनाम के कामरान्ह खाड़ी में सोवियत सैनिक अड्डों की तथाकथित स्थिति गैर-साम्यवादी आसियान देशों के लिए एक चेतावनी है । चीनी उपप्रधान मंत्री तंग शियाओफिंग ने अपने आसियान के चार देशों की यात्रा के दौरान कहा कि सोवियत संघ दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने सामरिक अड्डे के लिए स्थान की तलाश कर रहा है तथा वह इसके लिए वियतनाम का प्रयोग कर रहा है ।[5] चीनी वरिष्ठ नेता तंग के चार आसियान देशों- थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर व फिलीपींस की नवम्बर, 1978 में यात्रा का उद्देश्य चीन के आसियान देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास हेतु नया कूटनीतिक प्रयास था । कम्पूचिया -वियतनाम तनाव व वियतनाम-चीन तनाव के बीच तंग के इस यात्रा का उद्देश्य वियतनामी प्रधानमंत्री फामवान दोंग के सितम्बर-अक्टूबर 1978 में आसियान देशों की यात्रा को प्रभावहीन करना था । चीनी नेता तंग के इस यात्रा में मुख्य तीन बातों --सोवियत संघ व वियतनाम के "विस्तारवाद" का बढ़ता खतरा, आसियान देशों में साम्यवादी छापामारों के गतिविधियों का चीनी समर्थन तथा आसियान देशों में प्रवासी चीनियों की स्थिति, पर विचार हुए ।[6] पर चीन के इस चेतावनी का आसियान देशों पर कोई विशेष प्रभाव न

3- चौधरी, जी० डब्ल्यू०, चाईना इन वर्ल्ड अफेयर्स : द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पी आर सी सिंस 1970, (कोलोराडो 1982),पृ०-246 ।

4- नंदा, नयन, "ड बीयर हग फ्राम मास्को", फॉर ईस्टर्न इकॉनॉमिक रिव्यू (हांगकांग) 17 नवम्बर, 1978, पृष्ठ- 17

5- एशिया वीक, (हांगकांग), 3 नवम्बर, 1978, पृष्ठ-32 ।

6- मैनिची डेली न्यूज (तोक्यो), 16 नवम्बर, 1978 ।

पड़ा । कम्पूचिया पर, 25 दिसम्बर, 1978 को वियतनामी आक्रमण के बाद आसियान देशों को चीन के विचारों में सत्यता की झलक मिली जिसमें इस क्षेत्र (दक्षिण-पूर्व एशिया) में मास्को व हनोई की विस्तारवादी रणनीति की बात की गयी थी ।[7] 25 दिसम्बर, 1978 को 1,20,000 वियतनामी सैनिकों ने कम्पूचिया में प्रवेश किया । 7 जनवरी, 1979 को वे नामपेन्ह पहुंच गए और तीन दिन बाद जन क्रान्ति परिषद् (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी कौंसिल) ने कम्पूचियाई लोक गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कम्पूचिया) की स्थापना की घोषणा की । कम्पूचियाई राष्ट्रीय मुक्ति के लिए राष्ट्रीय एकता मंच के नेता हेंग सामरिन, कम्पूचिया लोकगणराज्य के राष्ट्रपति बने । यह राष्ट्रीय एकता मंच" (कम्पूचियन नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नेशनल साल्वेशन), 2 दिसम्बर, 1978 को स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य जनवादी कम्पूचिया के पोलपोट की नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकना और जनता की प्रजातांत्रिक सरकार को स्थापित करना था जिससे कम्पूचिया समाजवाद की ओर अग्रसर एक शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र, तटस्थ व गुटनिरपेक्ष देश का रूप ग्रहण कर सके । इसके साथ-साथ यह पोलपोट सरकार की ज्यादतियों, जैसे सामूहिक श्रम, सामूहिक उपभोग आदि को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखता था ।[8]

पोलपोट सरकार ने अपने ही देश वासियों पर अकथनीय अत्याचार किए जिसने सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया । इस सरकार ने कम्पूचिया को सिर्फ अपने दम पर उन्नत व आत्मनिर्भर बनाने का ढोंग रचना प्रारंभ किया और इसीलिए विदेशी सहायता को आंतरिक मामलों में दखल व देश की स्वतंत्रता व संप्रभुता का अपमान मानकर अस्वीकार कर दिया । अमेरिका से चावल का आयात बन्द हो जाने से अकाल की स्थिति पैदा हो गयी । लोग भूखों मरने लगे । अप्रैल

7- <u>कम्पूचिया इन द सैवेन्टीज</u> : रिपोर्ट ऑफ द फिनिश इन्क्वायरी कमीशन (हेलसिंकी, 1982), पृष्ठ-24 ।

8- विस्तृत विवरण के लिए देखिए - <u>कम्पूचिया इन द सैवेन्टीज</u> : सं०7, पृ०24

जनता को जबरदस्ती गांवों की ओर स्थानांतरित किया गया । वहां लोगों को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया । लोग बिना विश्राम के घण्टों अस्वास्थ्यकर दशाओं में भी काम करने को बाध्य थे । उन्हें खाने के लिए बहुत कम और घटिया भोजन दिया जाता था, जो लोगों को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए अपर्याप्त था । इससे भी भयंकर बात यह थी कि इस सरकार ने न सिर्फ लोन नोल सरकार के पदाधिकारियों, सेनाधिकारियों को ही खत्म किया, बल्कि इसने बुद्धिजीवियों तक को ढूंढकर गोलियों से उड़ा दिया और कम्पूचिया की भूमि को लाशों के ढेर से पाट दिया । लोग इन सब घटनाओं से घबरा कर पड़ोसी देशों की ओर भागने लगे लेकिन कुछ को छोड़कर अन्य सभी को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के पहले ही इस संसार से दूर भेज दिया गया । कम्पूचिया की सीमाओं पर बने शरणार्थी शिविरों तक जो लोग पहुंच पाए वे भी मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष से अधिक दूर नहीं पहुंच सके । इस प्रकार लगभग तीन वर्षों के दौरान कम्पूचिया में दस लाख से भी अधिक लोग मारे गए ।[8]

वियतनाम के कम्पूचिया सैनिक हस्तक्षेप के कारण आसियान देशों में वियतनाम के प्रधानमंत्री फामवान दोंग के आसियान देशों के समय आर यात्रा पर किए वायदों के प्रति संदेह व्याप्त हो गया । वियतनामी प्रधानमंत्री फामवान दोंग ने सितम्बर-अक्टूबर, 1978 में आसियान देशों की यात्रा[9] के दौरान आसियान

8- विस्तृत विवरण के लिए देखिए - कम्पूचिया इन द सेवेन्टीज : रिपोर्ट आफ फिनिश स्वतन्त्र जांच कमीशन, (हेलसिंकी, 1982), बेनकीनान, "सोशल कंडीशन इन रिवोल्यूशनरी कम्पूचिया", आस्ट्रेलियन आउटलुक (कैनबरा) प्रति 30, सं0 3 (दिसम्बर, 1976), चीन ने 5 सितम्बर, 1981 को स्वीकार किया कि खमेर रूज का अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा खराब होने का मुख्य कारण इसकी उग्रवादी नीतियां थी जब उसकी 1975-79 में कम्पूचिया में सरकार थी । वर्किंग पीपुल्स डेली, (रंगून) 7 सितम्बर, 1981 ।

9- वियतनामी प्रधानमंत्री फामवान दोंग ने आसियान देशों की सितम्बर-अक्टूबर, 1978 में यात्रा की थी । उन्होंने 6-16 सितम्बर, 1978 को

देशों से वायदा किया था कि वियतनाम थाईलैण्ड व फिलीपींस के किसी विद्रोही आन्दोलन का समर्थन नहीं करेगा तथा क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के शांतिपूर्ण रास्तों से हल करने का पक्षधर होगा।[10] चीनी पत्रिका पेकिंग रिव्यू के अनुसार, वियतनामी नेता फाम वान दोंग ने आसियान देशों की अपनी यात्रा के दौरान वायदा किया था कि वियतनाम थाईलैण्ड पर आक्रमण नहीं करेगा ना ही आधिपत्य जमाएगा।[11] वियतनाम के कम्पूचिया पर आक्रमण के परिणामस्वरूप आसियान देशों में चीन के प्रति मानसिकता में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था।

हिन्द-चीन व विशेष रूप से कम्पूचिया समस्या आसियान-चीन संबंधों के लिए उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण है।

1978 में हिन्द-चीन की घटनाओं ने विशेषकर वियतनाम द्वारा कम्पूचिया में सैनिक कार्यवाही ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सोवियत-चीन-वियतनाम के मध्य त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा को नया आयाम दिया। ऐसा समझा जाता है कि आसियान सदस्य देश थाईलैण्ड चीन को वियतनाम के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध अवरोधक के रूप में प्रयोग करना चाहता है। थाईलैण्ड बड़ी शक्तियों के मध्य एवं बीच में एक नया संतुलन चाहता है क्योंकि कम्पूचियाई समस्या से आसियान सदस्य देशों में सर्वाधिक खतरा थाईलैण्ड को है। क्योंकि थाईलैण्ड की सीमाएं उत्तर व पूर्व से लाओस तथा दक्षिण-पूर्व में कम्पूचिया से लगी हुई हैं। थाईलैण्ड को "फ्रंट लाईन" राज्य के रूप में जाना जाता है।

कम्पूचिया में वियतनामी सैनिकों की मौजूदगी के कारण आसियान व वियतनाम के बीच मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) का लोप हो गया, जिससे

बैंकाक, 16-20 सितम्बर, 1978 को मनीला, 20-23 सितम्बर, 1978 को जकार्ता तथा 12-16 अक्तूबर 1978 को क्वालालम्पुर व 16-18 अक्तूबर 1978 को सिंगापुर की यात्रा की।

10. एशियन सेक्युरिटी, 1979 रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पीस एण्ड सेक्युरिटी टोक्यो, (जापान, 1980), पृष्ठ-97।

सोवियत समर्थित वियतनाम से आसियान के क्षेत्रीय स्थिरता को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया।

चीनी समर्थित जनवादी कम्पूचिया की पोलपोट सरकार के पतन हो जाने तथा चीन विरोधी वियतनाम व सोवियत समर्थित कम्पूचिया लोक गणराज्य के हेंग सामरिन के शासन स्थापित हो जाने से चीन आसियान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आसियान की नीतियों आदि का जोरदार समर्थन करने लगा। 11 जनवरी, 1979 को थाई उपप्रधान मंत्री सुनथोर्न होंगलाडारोम को दिए एक भोज समारोह में चीनी उपप्रधान मंत्री कू मू ने कहा :

"कम्पूचिया के विरुद्ध आक्रमण करने की वियतनामी अधिकारियों की प्रभुत्ववादी गतिविधि से एशियाई-प्रशांत क्षेत्र व विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया की शान्ति व स्थिरता के लिए गम्भीर खतरा बना हुआ है --- वियतनामी सरकार का कम्पूचिया के विरुद्ध आक्रमणकारी मानसिकता के पीछे न केवल उसका क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद है बल्कि इससे महाशक्ति सोवियत प्रभुत्ववाद की विश्वव्यापी रणनीति की पूर्ति होती है --- चीनी सरकार व जनता, कम्पूचियाई सरकार व उसके आक्रमण के विरुद्ध उचित संघर्ष का समर्थन करती है। चीनी सरकार व जनता दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सरकार व जनता का नए वातावरण में उनके दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति, स्थिरता व वैभव को बनाए रखने के नए प्रयासों का सक्रियता के साथ समर्थन करती है। हम उनके उचित प्रस्ताव "जोपफान" का सक्रियता के साथ समर्थन करते हैं।"[12]

कम्पूचिया समस्या पर आसियान देशों को काफी चिन्ता होने लगी। आसियान स्थायी समिति के अध्यक्ष इंडोनेशियाई विदेश मंत्री मुख्तार कुसुमातमाजा ने जाकार्ता में 9 जनवरी, 1979 को एक वक्तव्य जारी किया :

11- पेकिंग रिव्यू, 9 फरवरी, 1979, पृष्ठ- 28

12- एस० डब्ल्यू०बी०, एफ-ई।6016, 15 जनवरी, 1979, ए-3।4।

"आसियान सदस्य देशों ने हिन्द-चीन की समस्या तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की शान्ति, सुरक्षा व स्थिरता पर इन हिन्द-चीन के परिवर्तनों के कारण परिणामों व प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आसियान देशों का मानना है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों की राष्ट्रीय विकास के लिए शान्ति व स्थिरता आवश्यक शर्त है।"[13]

7 जनवरी, 1979 को नामपेन्ह के, वियतनामी फौजों द्वारा आक्रमण के परिणाम स्वरूप, पतन के एक सप्ताह के अन्दर ही बैंकाक में आसियान विदेश मंत्रियों की एक तदर्थ बैठक हुई जिसमें सार्वजनिक रूप से कम्पूचिया की स्वतंत्रता संप्रभुता व क्षेत्रीय अखण्डता के विरुद्ध सैनिक घुसपैठ की भर्त्सना की गई, आसियान विदेश मंत्रियों ने कम्पूचियाई जनता के अपने भविष्य को बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वयं निश्चय करने के अधिकार का समर्थन किया। इस विवाद को समाप्त करने की दिशा में आसियान विदेश मंत्रियों ने कम्पूचियाएँ क्षेत्र से विदेशी शक्तियों की शीघ्र व सम्पूर्ण वापसी की मांग की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के अविलम्ब हिन्द-चीन की स्थिति पर विचार करने के निर्णय का स्वागत किया तथा उसने परिषद् से जोरदार ढंग से मांग की कि इस क्षेत्र में शान्ति, सुरक्षा, व स्थिरता को कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए।[14]

कम्पूचिया पर वियतनामी आक्रमण से आसियान देशों की तथा विशेषकर थाईलैण्ड की चिंता और अधिक बढ़ गई जब कम्पूचियाई शरणार्थी उनके देशों में काफी संख्या में आने लगे। इनकी संख्या 1981 तक केवल थाईलैण्ड में डेढ़ लाख तक पहुंच गयी थी।[15] हिन्द-चीनी शरणार्थियों के बारे में आसियान विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक, 13 जनवरी, 79 को बैंकाक में हुई। आसियान विदेश मंत्रियों ने हिन्द-चीनी शरणार्थियों के आसियान देशों में लगातार आने की समस्या

13- इंडोनेशिया टाइम्स, (जाकार्ता) 10 जनवरी, 1979।

14- वर्किंग पीपुल्स डेली (रंगून) 14 जनवरी, 1979।

15- कम्पूचिया एन्ड द सैवेन्टीज़ सं07, पृष्ठ- 45।

पर बल दिया तथा इन शरणार्थियों को आसियान देशों में परेशानी व समस्या पैदा होने का कारण, व इसके साथ-साथ इस क्षेत्र की स्थिरता पर गम्भीर प्रभाव पड़ने की संभावना पर बात की ।[16] इन शरणार्थियों से आसियान देशों पर काफी बोझ बढ़ता गया जिससे उन देशों में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूपों आदि में समस्याएं पैदा होने लगीं जो उनके राष्ट्रीय हित व स्थिरता को प्रभावित कर रही हैं । इन कम्पूचियाई शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए थाईलैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयुक्त की स्वैच्छिक स्वदेशागमन की नीति को लागू किया ।[17] परन्तु हेंग सामरिन सरकार ने स्वैच्छिक स्वदेशागमन की इस नीति को चीन और अमेरिका का इसके विरोधी शक्तियों को शक्तिशाली बनाने का एक षड्यंत्र माना ।[18]

चीन - कम्पूचिया समस्या को हल करने के लिए आसियान देशों से बराबर सहयोग की मांग करता आ रहा है । इस संदर्भ में कम्पूचिया समस्या से आसियान के प्रभावित होने की संभावना पर चीनी नेताओं ने वक्तव्य दिए हैं । रेडियो पेईचिंग ने 13 जनवरी, 1979 को कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष व प्रधानमंत्री हुआ कुओ फेंग ने थाईलैण्ड से अनुरोध किया है कि वह कम्पूचिया में वियतनामी आक्रमण के प्रश्न पर चीन के साथ सहयोग करें । उन्होंने थाई उपप्रधान मंत्री सुनथोर्न होंगलाडारोम से कहा कि चीन-थाई सहयोग इस क्षेत्र में शान्ति व स्थिरता कायम रखने में सहायक हो सकती हैं ।[19] इसी नीति के पक्ष में 13 जनवरी, 79 को चीनी उपप्रधान मंत्री तंग ने कहा कि थाईलैण्ड व चीन के बीच घनिष्ठ सहयोग वर्तमान हिन्द-चीन की स्थिति में काफी आवश्यक हो गया है तथा इस सहयोग से न केवल चीन व थाईलैण्ड अपितु एशियाई राष्ट्र व प्रशांत क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकेंगे । चीन व थाईलैण्ड को एक दूसरे की सहायता

16- बैंकाक पोस्ट, 14 जनवरी, 1979 ।

17- कम्पूचिया इन द सैवेन्टीज़, सं0 7, पृष्ठ- 46 ।

18- एशियन सैक्युरिटी 1980, सं0 10, पृष्ठ- 155 ।

19- बैंकाकपोस्ट, 14 जनवरी, 1979 ।

तथा समर्थन करनी चाहिए । उन्होंने सोवियत संघ की वियतनाम के कम्पूचिया पर आक्रमण में सहायता करने के लिए भर्त्सना की, तथा कहा कि इससे बड़ी शक्तियों के प्रभुत्ववाद व क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद का पता चलता है ।[20]

आसियान देश व चीन ने कम्पूचिया प्रश्न पर अपनी रणनीतियों को तय करने के लिए अपना काफी समय व शक्ति लगाया । आसियान व चीन के कम्पूचियाई समस्या के संदर्भ में उनकी नीतियों में कोई बुनियादी मतभेद नहीं है । पर इस विषय पर अन्य आसियान देशों की तुलना में थाईलैण्ड व चीन की नीतियां एक देखी जाती हैं । आसियान देशों में कम्पूचियाई समस्या से सबसे अधिक खतरा थाईलैण्ड को है क्योंकि वह हिन्द-चीन से सर्वाधिक समीप है । आसियान की नीति कम्पूचिया समस्या के समाधान हेतु राजनीतिक हल ढूंढने के प्रयास में उनका मुख्य ध्यान है, जबकि वे कम्पूचिया से वियतनामी सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करते रहे हैं । वैसे आसियान इस प्रकार के प्रयास में सफल रहा पर व्यावहारिक रूप से परिणामरहित ही रहा ।[21]

आसियान, कम्पूचिया प्रश्न पर, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में :

आसियान देशों व वियतनाम के मध्य कम्पूचियाई समस्या के राजनीतिक हल ढूंढने के लिए एक बड़ी बाधा यह है कि जहां आसियान देश इस समस्या पर बातचीत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर जोर देते हैं वहीं वियतनाम इसे सिर्फ क्षेत्रीय सम्मेलन तक ही सीमित रखना चाहता है ।[22] इसके साथ-साथ इन सम्मेलनों

20- वही ।

21- सिथि पी राबित, "थाई-कम्पूचियन रिलेशन्स : प्रॉब्लम्स एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स" एशियन सर्वे, (बर्कले, कैलिफोर्निया) ग्रंथ 22, सं०-6 (जून 1982) पृष्ठ- 572 ।

22- 13 से 17 जुलाई 1981 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कम्पूचिया पर बुलाए गए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक "इन्टर सेशनल कमेटी" गठित की जो क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की दो विपरीत परिस्थितियों के बीच

में कम्पूचिया का प्रतिनिधित्व कौन करे ? इस प्रश्न पर भी मतभेद है, क्योंकि वियतनाम के प्रतिकूल, आसियान किसी भी सम्मेलन में हेंग सामरिन को कम्पूचिया के प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेने का समर्थन नहीं करता । उनके विचार में ऐसा करना हेंग सामरिन की कम्पूचिया सरकार व इस प्रकार किसी भी देश में बाहरी हस्तक्षेप को मान्यता देना होगा ।

आसियान ने कम्पूचिया समस्या के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विभिन्न मंचों के दरवाजे को खटखटाया । सात गुटनिरपेक्ष देशों, जिसमें आसियान देशों के गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य भी थे , ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् में 15 जनवरी, 1979 को प्रस्ताव रखा जिसमें कम्पूचिया में वियतनामी आक्रमण की भर्त्सना की गयी थी । इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 मत पड़े और विपक्ष में दो । इन दो मतों में सोवियत संघ का विशेषाधिकार होने के कारण उक्त प्रस्ताव पारित न हो सका ।[23] इसी प्रकार का एक प्रस्ताव 16 मार्च, 1979 को आसियान देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् में रखा जिसमें दोनों देशों वियतनाम के कम्पूचिया में घुसपैठ व चीन का वियतनाम को "सबक सीखाने" वाली सैनिक गतिविधियों की भर्त्सना की गयी थी । परन्तु उनका यह प्रस्ताव सोवियत संघ के विशेष मताधिकार द्वारा पारित न हो सका । परन्तु आसियान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 34 वें, 35वें व 36वें महा सभा में जहां विशेष मताधिकार संभव नहीं होता, साबित कर दिया कि उसकी कूटनीति संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी प्रभावशाली है । आसियान द्वारा प्रत्यय-पत्र व कम्पूचिया से विदेशी सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव 1979, 1980 व 1981 के महा सभा द्वारा भारी बहुमत से पारित हुआ ।

यह प्रस्ताव पोलपोट के नेतृत्व में जनवादी कम्पूचियाई सरकार की संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बने रहने के पक्ष में था । 21 सितम्बर, 1979 को

कोई हल निकालने का प्रयास करेगी । कृपया देखें रशियन सैक्यूरिटी 1982, सं० 10, पृष्ठ- 112 ।

23- द ट्रिब्यून, (चंडीगढ़) 18 मार्च, 1979 ।

प्रत्यय-पत्र समिति में पोलपोट की जनवादी कम्पूचिया केप्रतिनिधित्व तथा हेंग सामरिन सरकार केप्रतिनिधित्व न मिलने के पक्ष में 71, विरोध में 35 तथा 34 तटस्थ थे ।[24]

14 नवम्बर, 1979 को महासभा में कम्पूचिया से शीघ्र विदेशी सैनिकों की वापसी के पक्ष में 91 मत, विरोध में 21 तथा 29 तटस्थ थे । इस सत्र में महासचिव से कम्पूचिया समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी मांग की गई थी । इस प्रस्ताव का आसियान सहित तीस सदस्य देशों ने अनुमोदन किया था ।[25] 13 अक्तूबर, 1980 को उक्त प्रस्ताव सुधार के साथ रखा गया जिसमें पोलपोट सरकार को अस्वीकार किया गया था । इस प्रस्ताव के पक्ष में 35 मत, विपक्ष में 75, तथा 32 तटस्थ थे ।[26]

22 अक्तूबर, 1980 को एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में आसियान देशों द्वारा रखा गया तथा 30 सदस्य देशों ने उसका अनुमोदन किया था । इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से 1981 के प्रारंभ में, कम्पूचिया समस्या पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया गया था, जिसमें समस्त दलों के लोग, तथा विशेष रूप से वे लोग जो इस समस्या से संबंधित हैं, भाग लें । इस सम्मेलन का उद्देश्य इस समस्या का राजनीतिक हल ढूंढना था । तथा एक निश्चित अवधि के अन्दर कम्पूचिया से संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण में समस्त विदेशी शक्तियों की पूर्ण वापसी तथा विश्व समिति द्वारा कम्पूचिया में स्वतंत्र चुनाव[27] करवाया जाए... इस प्रस्ताव के पक्ष में 97 मत, विरोध में 23 मत तथा 22 तटस्थ देश थे ।[28]

24- रसेल, एच० फिफील्ड, "आसियान, कम्पूचिया एण्ड द यूनाइटेड नेशन्स", एशिया पैसिफिक कम्युनिटी (तोक्यो) अंक 2, (समर 1982) पृष्ठ- 78 ।

25- वही ।

26- वही ।

27- समाजवादी वियतनाम गणराज्य ने कम्पूचिया पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन से पहले ही कम्पूचिया लोकगणराज्य के हेंग सामरिन सरकार को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए, कम्पूचिया में 1 मई, 1981 को राष्ट्रीय

इस आसियान देशों द्वारा रखे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन " के पारित प्रस्ताव में छः मुद्दों पर बातचीत करने का प्रस्ताव था - (क) संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में कम्पूचिया से समस्त विदेशी सैनिकों की वापसी । (ख) सैनिकों की वापसी के समय संयुक्त राष्ट्र संघ कम्पूचिया में कानून- व्यवस्था व मानवीय अधिकारों को बनाए रखेगी । (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की देख रेख में कम्पूचिया में स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना । (घ) कम्पूचिया में किसी प्रकार की विदेशी सैनिकों की पुनर्पैठ पर प्रतिबंध । (ड) स्वतंत्र व संप्रभुता सम्पन्न कम्पूचिया अपने किसी पड़ोसी देश के लिए खतरा नहीं होगा का आश्वासन (च) कम्पूचिया के संप्रभुता, स्वतंत्रता क्षेत्रीय अखण्डता व तटस्थता के आदर करने का आश्वासन ।

आसियान ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में वायदा किया कि दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति की वापसी के बाद आसियान कम्पूचिया, लाओस व वियतनाम के पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास कार्यक्रमों का पूरी क्रियाशीलता से सहयोग करेगा ।[29]

फरवरी, 1981 , नयी दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्रियों ने कम्पूचिया व अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बारे में आह्वान व आसियान स्थिति का समर्थन किया ।[30] आसियान व चीन ने हवाना के गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में कम्पूचिया का स्थान रिक्त छोड़े जाने को वियतनाम के विरुद्ध छेड़े गए राजनीतिक युद्ध में एक सकारात्मक कदम माना । 18 सितम्बर, 1981 को 21 सितम्बर 1979 जैसा ही प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा गया जिसमें 37 मत पक्ष में, 77 मत विपक्ष में तथा 31 तटस्थ देश थे ।[31]

संसद का चुनाव करवाया । चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा - राष्ट्रपति हेंगसामरिन के पक्ष में 99.75 प्रतिशत तथा कम्पूचिया के तत्कालीन उप-राष्ट्रपति व प्रतिरक्षा मंत्री पेन सोवान के पक्ष में 99.63 प्रतिशत मतदान हुआ । रखैल, सं0-24, पृष्ठ-83 ।

28- वही, पृष्ठ- 78-79 ।

29- जास्टस, एम0 ,फानडर क्रोफ, 'आसियान , लार्ड, एण्ड द कम्पूचियन कनफ्लिक्ट: बिटवीन कुवानतान एण्ड अ "थर्ड अल्टरनेटिव"', एशियन

इसके अतिरिक्त आसियान कई अन्य विश्व मंच पर कम्पूचियाई समस्या को ले गया जैसे 5 नवम्बर, 1979 को न्यूयार्क में हुए शरणार्थियों के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष सम्मेलन, 26-27 जून, 1980 को कम्पूचियाई शरणार्थियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलन, 13-17 जुलाई, 1981, न्यूयार्क में कम्पूचिया के बारे में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि। उपरोक्त समस्त सम्मेलनों का वियतनाम द्वारा विरोध व चीन द्वारा समर्थन किया गया।[32]

चीनी प्रधान मंत्री हुवा क्वोफेंग ने मलेशियाई नेता हुसैन ओन को 4 मई, 1979 की एक मुलाकात में कहा : " इस क्षेत्र में आक्रमण व विस्तारवादी प्रभुत्ववादियों को रोकना आसियान व चीन दोनों के हित में है। हिन्द-चीन समस्या को सुलझाने के लिए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में आसियान देशों के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता है।... इस क्षेत्र में आक्रमणकारी व विस्तारवादी प्रभुत्ववादी योजनाओं को नाकाम करने के लिए हमें एक जुट होना चाहिए। वर्तमान समय में दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति व स्थिरता की संभावना कम्पूचिया समस्या पर निर्भर करती है..."[33]

मई, 1979 में, थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री प्रेम तिनसुलानन्द ने चीनी प्रधानमंत्री चाओ के सम्मान में दिए गए एक भोज समारोह में कहा : " चीन ने आसियान की संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 35/6 में रचनात्मक मानसिकता का परिचय

सर्वे ", ग्रंथ 21, सं0 6, (मई, 1981), पृष्ठ-527।

30- लाऊ तिथिक सुन, " आसियान एण्ड द कम्पूचियन प्राबलेम, " एशियन सर्वे, " ग्रंथ 22, सं0-6, (जून, 1982), पृष्ठ-550-51।

31- रसेल, सं.25, पृष्ठ- 78।

32- सिंह, सं0 21, पृष्ठ- 572।

33- फॉरेन ब्राडकास्टिंग इन फॉरमेशन सर्विस, डेली रिपोर्ट, (चीन लोक गणराज्य) 8 मई, 1979, ए-3।

दिया है। यह कम्पूचियाई समस्या के सफलतापूर्वक समाधान में अच्छा अवसर प्रदान करता है। मुझे काफी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में आसियान के प्रयासों का चीनी सरकार अपना समर्थन जारी रखेगी।" प्रेम ने चीनी सरकार की आसियान के सहयोग व विकास के पक्ष में रचनात्मक सहयोग की प्रशंसा की, "थाई सरकार व जनता आशा करती है कि चीनी सरकार आसियान के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अच्छी समझदारी, आपसी विश्वास व रचनात्मक सहयोग को आगे विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, तथा कम्पूचियाई समस्या के समाधान के बाद, जो इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, थाई सरकार पूरी तरह विश्वास करती है कि दक्षिण-पूर्व एशिया को एक शान्त, स्वतंत्र व तटस्थ क्षेत्र बनाने में चीन, इस क्षेत्र के प्रत्येक देश को शान्ति व घनिष्ठ सहयोग के साथ रहने हेतु सहायता करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण व रचनात्मक भूमिका अदा करता रहेगा।"[34] थाई विदेश मंत्री सिद्धि सावेतसिला ने बैंकाक में एक पत्रकार सम्मेलन में 14 नवम्बर 1980 को आसियान-चीन सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा : "हम समझते हैं कि चीन एक महत्वपूर्ण देश है जो कम्पूचिया पर जोर दे, आसियान द्वारा प्रायोजित, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। थाई व चीन ने कम्पूचियाई समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समान नीति को अपनाया है।"[35]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती रही -- संयुक्त राष्ट्र संघ में जनवादी कम्पूचिया के स्थान व कम्पूचिया से विदेशी सैनिकों की वापसी।

3-9 सितम्बर, 1979 को हवाना (क्यूबा) में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आसियान के नेतृत्वकारी व विशेष प्रतिनिधित्वकारी भूमिका में सिंगापुर ने कम्पूचिया विवाद को उठाया। इस सम्मेलन में सिंगापुर ने वियतनाम की

34- एस० डब्ल्यू० बी० एफ-ई/6633, 2 फरवरी, 1981, ए-3/15-16।

35- एफ०बी०आई०एस०, (सं० 33), 17 नवम्बर, 1980, ई-4,
एस०डब्ल्यू०बी०, एफ-ई/6578, 10 नवम्बर, 1980, ए-3/2।

उसके कम्पूचिया पर आक्रमण के लिए भर्त्सना की तथा पोलपोट का समर्थन किया । इसके परिणामस्वरूप उसके पक्ष में 95 में से 27 राष्ट्रों व संगठनों का मत पोलपोट के पक्ष में पड़ा 21 मत हेंगसामरिन के लिए तथा 11 तटस्थ और 36 राष्ट्रों ने मतदान में भाग नहीं लिया । इसलिए इस सम्मेलन में कम्पूचिया के स्थान को रिक्त छोड़ने का निर्णय ले लिया गया ।[36]

आसियान का विचार था कि कम्पूचिया पर वियतनामी सैनिक मौजूदगी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी लगातार चर्चा करते रहने से इस समस्या पर विश्व जनमत भी तैयार हो सकता है । वियतनाम पर विशेष रूप से तीसरी दुनिया से नैतिक दबाव पड़ सके जो एक महत्वपूर्ण नीति व उपलब्धि हो सकती है । इन सम्मेलनों से आसियान के लिए राजनीतिक विजय प्राप्त हुई ।[37]

सोवियत समर्थित वियतनाम के कम्पूचिया पर सैनिक कार्यवाही के विरुद्ध चीन व आसियान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक साथ मत दिया । 1979-80 में हिन्द-चीन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आसियान देशों व चीन के बीच संधि न होते हुए भी घनिष्ठ सहयोग में विकास हुआ । उन्होंने विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मंच पर कम्पूचिया में वियतनामी सैनिकों की घुसपैठ की सामूहिक रूप से भर्त्सना की । आसियान के हिन्द-चीन के प्रश्न पर नए प्रतिक्रिया से उत्पन्न नियम व नीतियों से चीन निश्चित रूप से प्रसन्न था ।

17 फरवरी, 1979 को चीन ने वियतनाम पर सीमा नियमों के अतिक्रमण के आरोप में वियतनाम पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया जिसे वरिष्ठ चीनी नेता तंग ने "सबक सीखाने" वाले युद्ध का नाम दिया । कुछ विद्वानों के मतानुसार फरवरी-मार्च, 1979 में वियतनाम पर चीनी आक्रमण से आसियान देशों को कुछ राहत मिली । आसियान देश इन समाजवादी देशों के बीच खुले

36- एशियन सेक्यूरिटी - 1980, (सं0 10), पृष्ठ- 152 ।

37- वही, सं0 24, पृष्ठ-85 ।

मुठभेड़ से दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवादी शक्ति के खतरे की तस्वीर व स्पष्ट रूप से विघटित होते देख रहे थे और इसके साथ स्पष्ट रूप से यह समझ गये थे कि चाहे दो दो साम्यवादी देशों चीन व वियतनाम में गम्भीर विवादों के साथ अन्तर्विरोध मौजूद है वे इस युद्ध की समाप्ति पर बल देते रहे और विभिन्न मंचों व अवसरों पर चीन के वियतनाम पर आक्रमण की भर्त्सना करते रहे। आसियान देशों को चीन से सदैव खतरा रहा है तथा कम्पूचिया पर वियतनाम के आक्रमण व वियतनाम को सोवियत समर्थन प्राप्त होने तथा सोवियत सैनिक बेड़ों की कामरान्ह खाड़ी में मौजूदगी से आसियान देशों को सोवियत समर्थित वियतनाम से खतरा उत्पन्न हो गया है। आसियान देश इन दोनों शक्तियों के बीच तटस्थ होकर अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पर आसियान देशों के तटस्थ रहने की मानसिकता में मतभेद है। तटस्थ रहने के प्रतिपादी आसियान देशों में मलेशिया व इंडोनेशिया हैं तथा वियतनामी खतरे से भयभीत थाईलैण्ड सिंगापुर व फिलीपींस हैं जो दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़ी शक्तियों की मौजूदगी के साथ चीन की विशेष भूमिका को महत्वपूर्ण समझते हैं। क्वालालम्पुर में 9 सितम्बर, 1979 को मलेशियाई विदेश मंत्री तेंगकू अहमद रियाऊद्दीन ने कहा कि मलेशिया हिन्द-चीन में वियतनाम-चीन विवाद में तटस्थ रहेगा।[38] रियाऊद्दीन ने चीन-वियतनाम विवाद पर टीका टिप्पणी में बोलते हुए कहा :

"हम हिन्द-चीन विवाद में किसी के पक्षधर नहीं हो सकते परन्तु हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र में सदैव स्थायी शान्ति व स्थिरता बनी रहे... हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं... आसियान देशों में मलेशिया व इंडोनेशिया हिन्द-चीन में शान्ति हेतु प्रयत्नशील हैं पर इंडोनेशिया हिन्द-चीन विवाद की समाप्ति के लिए वियतनाम से बात करेगा तथा मलेशिया भी इस विषय पर चीन से बातचीत करेगा...।"[39]

38- पेट्रियट पीपुल्स डेली, 11 अप्रैल, 1979 ।

39- फॉरेन अफेयर्स ऑफ मलेशिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मलेशिया मार्च, 1979, पृष्ठ- 76 ।

चीन के वियतनाम पर आक्रमण से सिंगापुर के विदेश मंत्री एस० राजारत्नम् ने हिन्द-चीन विवाद के लिए चीन व वियतनाम दोनों को दोषी ठहराते हुए 20 फरवरी, 1979 को कहा कि जब तक कम्पूचिया में वियतनामी सैनिक मौजूद रहेंगे विवाद चलता रहेगा।[40] इंडोनेशिया ने चीन के इस आक्रमण की भर्त्सना की। इंडोनेशियाई उपराष्ट्रपति हेडम मलिक ने 24 फरवरी, 1979 को कहा कि चीन इलाई पर अधिकार नहीं कर सकता तथा चीन को यह अच्छी तरह पता होगा कि वियतनाम को कौन समर्थन दे रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान किसी देश में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है तथा वह चीन व वियतनाम के बीच शान्ति स्थापना के लिए मध्यस्थता कर सकता है।[41] इस चीनी आक्रमण का इंडोनेशिया-चीन के बीच संभावित संबंधों पर थोड़ा असर पड़ा फिर भी इंडोनेशिया ने चीन के साथ संबंधों की पुनर्वापसी पर बल दिया। 23 फरवरी, 1979 को तोक्यो में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री मुख्तार कुसुमातमाजा ने कहा कि इंडोनेशिया चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने में काफी सावधानी बरतेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताह की घटनाओं (चीन का वियतनाम पर आक्रमण) ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया है पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम चीन से संबंध बनाने की बात समाप्त कर दिये, हमें कोई विशेष कारण नहीं दिखता जिससे हम चीन से राजनयिक संबंध बनाने की ओर न बढ़ें। उन्होंने कहा कि चीन का दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवासी चीनियों के प्रति रवैया इंडोनेशिया-चीन संबंध में एक मुख्य बाधा है।[42] मलेशिया ने वियतनाम पर चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया में चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए खतरनाक बताया। जून 1979 में मलेशियाई उप प्रधान मंत्री डा० महाथिर ने एक सम्मेलन में कहा कि उभरते सैनिक सक्षम देश चीन से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को खतरा है जिसका

40- वर्किंग पीपुल्स डेली, (रंगून), 22 फरवरी, 1979।

41- द ट्रिब्यून (चंडीगढ़) 25 फरवरी, 1979।

42- इंडोनेशिया टाइम्स, (जाकार्ता) 24 फरवरी, 1979।

परिचय चीन वियतनाम में अपनी सैन्य पुष्ठपैठ द्वारा दे चुका है । उन्होंने कहा कि आसियान को इस क्षेत्र के लिए चीन को बड़ी शक्ति क्षमता वाले देश के रूप में खतरनाक मानना चाहिए ।[43]

कम्पुचियाई समस्या पर प्रारंभ में थाईलैण्ड ने तटस्थता बरतनी चाही थी । एक पत्रकार सम्मेलन में थाई प्रधान मंत्री क्रियांगसाक ने खमेर रूज के लिए चीनी हथियारों आदि के वाहक की भूमिका को निभाने में स्पष्ट रूप से नकारते हुए अनिच्छा व्यक्त की और कहा कि उनकी सरकार इस सिद्धान्त पर दृढ़ है कि वे किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।[44] परन्तु थाई सीमाओं पर वियतनामी सेनाओं के भारी जमाव को देखते हुए इसने अपनी नीति बदली और अप्रैल, 1979 में कई हजार खमेर रूज सैनिकों को वियतनामी फौजों से बचने के लिए थाई सीमा पार कर थाईलैण्ड में प्रवेश करने और पुन: कम्पुचिया में जाने की अनुमति दे दी । थाई सेनाओं का तर्क था कि उसके पास यही एक मात्र रास्ता था क्योंकि यदि वे उन्हें सीमा पार नहीं करने देते तो वे शक्ति के बल पर जबरदस्ती ठिकाने बना लेते ।[45]

कम्पुचिया प्रश्न व आसियान की सुरक्षा दृष्टि :

18 फरवरी, 1979 को वियतनामी प्रधान मंत्री फाम वान दोंग की नामपेन्ह यात्रा के दौरान एक मित्रता व सहयोग संधि की गयी । यह एक प्रकार की सैनिक संधि थी जिसमें एक देश की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखण्डता को खतरा होने की दशा में दूसरा देश हर संभव सहायता करेगा ।[46] इस समझौते से

43- एल्डिन ब्रोइनोव्स्की, *अन्डरस्टैंडिंग आसियान*, (हांगकांग, 1982), पृष्ठ- 139-40 में उद्धृत ।

44- "द क्वेश्चन ऑफ सप्लाईज़", "एशिया वीक", (हांगकांग) प्रति-5, सं०- 8, (2 मार्च, 1979), पृष्ठ- 24 ।

45- अन्सिल राम्जे, "थाईलैण्ड 1979 : द गवर्नमेंट इन ट्रबल", "एशियन सर्वे" (बर्कले) प्रति 20, सं०- (फरवरी, 1980), पृ०-119-20 ।

46- *कम्पुचिया इन द सैवेन्टीज़*, सं० 7, पृष्ठ- 24-25 ।

आसियान देश और अधिक चिंतित हो गए तथा इनमें सबसे अधिक चिंता थाईलैण्ड को थी क्योंकि वह 'फ्रंट लाईन' राज्य बना हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप आसियान का राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बजट वर्ष 1979 व 1980 के बीच काफी बढ़ा। 1980 में पूरे आसियान का प्रतिरक्षा बजट 5.45 अरब अमेरिकी डालर हो गया जो 1979 की तुलना में 46.5 प्रतिशत अधिक था और 1975 की तुलना में लगभग दुगुना था। मलेशिया में प्रतिरक्षा बजट 1979 व 1980 में 140 प्रतिशत व इंडोनेशिया में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ये दोनों देश वियतनाम से मित्रतापूर्ण बातचीत करने की कूटनीति के प्रतिपादक हैं। 1980 में सिंगापुर व थाईलैण्ड की प्रतिरक्षा बजट में वृद्धि क्रमशः 27.2 प्रतिशत व 17.2 प्रतिशत रहा जबकि फिलीपींस में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आसियान की अमेरिकी हथियारों पर आसियान देशों की निर्भरता बढ़ी। 1970 व 1977 के बीच अमेरिकी हथियार आसियान देशों में 1 अरब 12 करोड़ अमेरिकी डालर का आया था जबकि केवल तीन वर्षों 1978-80 में यह बढ़कर 2.48 अमेरिकी डालर हो गया।[47]

थाईलैण्ड 'फ्रंट लाईन राज्य' होने के कारण, अपनी सैनिक कमजोरी के प्रति विशेष रूप से सचेत हो कई तरीकों से अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। इससे थाईलैण्ड का कुल सुरक्षा बजट 1978 में सोलह अरब बात[48] से 1981 में 28 अरब बात तक पहुंच गया। जहां 1978 में थाईलैण्ड ने दो करोड़ पिच्यान्वे लाख अमेरिकी डालर के क्रय किए वहीं यह संख्या 1981 में आठ करोड़ अमेरिकी डालर तक पहुंच गई। इसने थाईलैण्ड के आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।[49]

थाईलैण्ड की सुरक्षा के लिए चीन ने सदैव वायदा किया तथा कहा कि अगर वियतनाम थाईलैण्ड पर आक्रमण करता है तो चीन थाईलैण्ड का पक्ष लेगा तथा

47- रशियन सैक्यूरिटी 1981, सं0-10, पृष्ठ-116-17

48- 'बात' थाईलैण्ड की मुद्रा का नाम है। इसकी कीमत रूपए की तुलना में लगभग आधी होती है।

49- सिपैन, सं0 21, पृष्ठ- 571

उसकी सहायता होगा । इस प्रकार की चीनी नीति का कम्पूचिया समस्या के कारण, यहाँ पहली बार हुआ ।[50] इसी तथ्य को चीनी वरिष्ठ नेता तंग ने 28 अक्तूबर, 1979 को थाई प्रतिनिधि मण्डल से कहा कि अगर वियतनाम आसियान देशों पर आक्रमण करता है तो चीन आसियान का पक्ष लेगा ।[51] इसके अतिरिक्त चीन ने वियतनाम आक्रमण के प्रतिरोध में हथियार देने की बात करते हुए चीनी उप-रक्षामंत्री का चिए ने एक थाई पत्रकार से कहा कि चीन थाईलैण्ड को वियतनाम आक्रमण के विरुद्ध हथियार दे सकता है जिससे थाईलैण्ड अपनी रक्षा कर सके । वैसे चीन तो हथियारों का व्यापारी नहीं है पर अगर थाईलैण्ड चाहेगा तो चीन उचित मूल्य पर चीनी हथियार दे सकता है क्योंकि थाईलैण्ड का यह संघर्ष उचित है ।[52] 3 अप्रैल, 1979 को चीनी उपप्रधान मंत्री कु मु ने आसियान को वियतनाम व सोवियत संघ के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग करने तथा वियतनाम को कम्पूचिया से बाहर निकालने के लिए आह्वान किया । उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति व सुरक्षा हेतु आसियान को न्यायिक रूप से सक्रिय भूमिका अदा कर योगदान करना चाहिए ।[53] इस प्रकार चीन ने कम्पूचिया समस्या के कारण आसियान का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया और आसियान को शक्तिशाली व मजबूत बनाने के लिए चीन ने उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जिससे आसियान, कम्पूचिया समस्या पर, दृढ़ता से सोवियत समर्थित व चीन विरोधी वियतनाम का मुकाबला कर सके । 3 मई, 1979 को चीनी नेता तंग ने आसियान को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि सोवियत-वियतनामी विस्तारवाद के विरुद्ध अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आसियान देश आपसी सहयोग करें तथा एशिया में व दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं ।[54] चीन ने आसियान देशों को उनकी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने पर बल दिया ताकि वह सोवियत व वियतनाम के बढ़ते खतरे का मुकाबला कर सकें ।[55]

---

50. मैनिचि डेली न्यूज (तोक्यो), 3 अप्रैल, 1979 ।
51. द हिन्दू, 30 अक्तूबर, 1979 ।
52. बैंकाक पोस्ट, 30 अक्तूबर, 1979 ।
53. पेकिंग डेली न्यूज, 5 अप्रैल, 1979 ।
54. बैंकाक पोस्ट, 5 मई, 1979, इंडोनेशिया टाइम्स, 4 मई, 1979 ।

हिन्द-चीन की समस्या से बढ़ते खतरे के प्रति आसियान देशों ने अपनी विभिन्न राजनीतिक सतहों से चीन, वियतनाम व कम्पूचिया के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उनकी सुरक्षा चिंता समाहित थी । परन्तु उनके अपने ही वक्तव्यों में अन्तर्विरोध भी मौजूद था । इंडोनेशिया के वरिष्ठ नेता ऐडम मलिक ने 1 मार्च 1979 को आसियान देशों को सावधान करते हुए कहा कि अगर हिन्द-चीन विवाद को रोका नहीं गया तो उसकी लपटें काफी खतरनाक हो सकती हैं । यह आग आसियान देशों व अन्य तीसरी दुनिया के देशों में भी फैल सकता है जिसपर नियंत्रण पाना कठिन हो जाएगा ।[56] ऐडम मलिक के इस वक्तव्य के एक वर्ष बाद ही इंडोनेशियाई प्रतिरक्षा व राजनीतिक मामलों के मंत्री सचिव मेजर जनरल पुरनोमो ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संगोष्ठी पर बोलते हुए 4 मार्च, 1980 को कहा :

".... आसियान देशों को वियतनाम से कोई गम्भीर खतरा नहीं है ।... वियतनामी सैनिक शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी हम समझते हैं । यद्यपि उनके पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए आधुनिक हथियार हैं पर उनके पास प्रयोग करने की दक्षता की कमी है... आसियान चाहता है कि वियतनाम चीन व आसियान के बीच एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में बना रहे जो दक्षिण की ओर चीन के आक्रमण में बाधक होगी । कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे आसियान वियतनाम के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें । हम लोगों को उस देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए ।[57]

थाईलैण्ड कम्पूचिया को वियतनामी विस्तार के विरुद्ध एक मध्यवर्ती राज्य मानता है न कि चीन को । कम्पूचियाई प्रश्न पर आसियान के दो देशों में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए यह एक वास्तविक मतभेद है । थाई उप-

---

55- बंगलादेश ऑबजरवर (ढाका), 22 अप्रैल, 1979 ।

56- टाइम्स ऑफ इंडिया, (नई दिल्ली), 3 मार्च, 1979 ।

57- डॉन पोस्ट, 5 मार्च, 1980 ।

प्रधान मंत्री थानात सोमान ने 5 अक्तूबर, 1981 को नेशन रिव्यू (बैंकाक) को दिए एक इंटरव्यू में कहा :

" आसियान के दो सदस्य देशों के अनुसार चीन व वियतनाम दोनों से एक समान खतरा है परन्तु थाई नेताओं के विचार में सोवियत समर्थित वियतनाम से इस क्षेत्र को तुरन्त खतरा है । चीन जंगल में घूमता एक शेर हो सकता है जबकि वियतनाम तो हमारे दरवाजे पर बैठा शेर है जो हमें खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, मैं मानता हूँ कि चीन से खतरा है पर अभी नहीं ।"[58]

सिंगापुर आसियान देशों के लिए चीन को अधिक खतरनाक नहीं मानता । 3 जुलाई, 1980 को सिंगापुर के प्रधान मंत्री ली कुवान यू ने कहा कि आसियान को चीन से खतरा कम है । आसियान को मुख्य खतरा सोवियत संघ से है । उन्होंने कहा कि चीन सोवियत संघ व अमेरिका से लगभग 20 वर्ष पीछे है -- सिंगापुर अमेरिका से नहीं डरता पर सोवियत संघ से डरता है । सोवियत संघ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, इसके पास दुनिया के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थान हैं ।[59] इस तथ्य को, ली के, इंडोनेशियाई पत्रिका "टेम्पो" में प्रकाशित, एक इंटरव्यू से और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । इस रिपोर्ट में ली ने कहा :

"दक्षिण-पूर्व एशिया को वास्तविक खतरा चीन से नहीं अपितु सोवियत संघ व इसके संबंधित राष्ट्र वियतनाम से है । सिंगापुर को "सोवियत विस्तार" का खतरा बना हुआ है ।..... चूंकि सोवियत संघ तीसरी दुनिया के बाजारों को विदेश, तकनीकी आदि से अमेरिका की तुलना में प्रभावित नहीं कर सकता इसलिए वह सैनिक शक्ति के प्रयोग से दक्षिण-पूर्व एशिया में मास्को के पक्ष में विचार विकसित करना चाहता है ।"[60] ली कुवान यू की दृष्टि में सोवियत

58- एस-डब्ल्यू०बी० एफ-ई।6847, 7 अक्तूबर, 1981, ए-3।3-4 ।

59- बैंकाक पोस्ट, 5 जुलाई, 1980 ।

60- मार्निंग न्यूज (कराची) 2 सितम्बर, 1980 ।

साम्यवाद का खतरा दुनिया में सबसे बड़ा डर बना हुआ है । वे चाहते कि उनके हिन्द-चीन पड़ोसी देशों का चीन से अच्छे संबंध हो जाएं जिससे वे सोवियत संघ के भय से मुक्त हो सकें ।[61]

फिलीपींस के विचार थाईलैण्ड व सिंगापुर से मिलते हैं वह सोवियत संघ व वियतनाम से आसियान देशों को मुख्य खतरा मानता है । 10 फरवरी 1979 को फिलीपींस के राष्ट्रपति मारकोस ने आसियान देशों को चीन व अमेरिका के साथ संबंध बनाने पर बल देते हुए कहा कि इससे एशिया में शक्ति संतुलन बना रहेगा ।[62]

मलेशिया ने आसियान देशों के लिए सोवियत संघ व चीन दोनों को समान रूप से खतरनाक बताया । जून, 1981 में एक संगोष्ठी में बोलते हुए मलेशियाई विदेश मंत्री रिथाउद्दीन ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में सोवियत संघ व चीन समान रूप से असुरक्षा के स्रोत हैं ।[63] इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मलेशिया के प्रधान मंत्री मुहम्मद महाथिर ने 13 अगस्त, 1981 को कहा कि आसियान देशों पर वियतनाम हमला नहीं कर सकता क्योंकि वह अपने राष्ट्र निर्माण में ही काफी व्यस्त है । हमें मुख्य खतरा अमेरिका, चीन व सोवियत संघ से है ।[64]

हिन्द-चीन में सोवियत समर्थित वियतनाम का प्रभुत्व हो जाने के परिणामस्वरूप सोवियत सैनिक गतिविधियां आसियान क्षेत्रों में बढ़ गयीं । कुछ खबरों के अनुसार सोवियत संघ ने थाईलैण्ड खाड़ी में अपना सैनिक बेड़ा डाल दिया जिससे आसियान देशों में सुरक्षा व स्थिरता के प्रश्न पर हलचल-सी मच गई । पर इस दृष्टिकोण में उनमें मतभेद भी है । सबसे अधिक चिंता हिन्द-चीन

61. वही ।
62. बर्लिन पीपुल्स डेली, 11 फरवरी, 1979 ।
63. मलेशिया डेली (क्वालालम्पुर), 30 जून, 1981, पृष्ठ 2 ।
64. इंडोनेशिया टाइम्स, (जकार्ता), 14 अगस्त, 1981, बैंकाक पोस्ट, 15 अगस्त, 1981 ।

के निकट देशों -- थाईलैण्ड, फिलीपींस व सिंगापुर भी हैं इसलिए वे अधिक सतर्क व सैनिक संधि के पक्ष में हैं । फिलीपींस के राष्ट्रपति मारकोस आसियान के सैनिक संधि के पक्ष में बताये जाते हैं ।[65] सिंगापुर के विदेश मंत्री सुप्पिया धनाबालन ने 12 जनवरी, 1980 को दक्षिण-पूर्व एशिया में उत्पन्न प्रभावित सोवियत खतरे पर टिप्पणी करते हुए कहा :

"... अगर सिंगापुर की सुरक्षा को खतरा होगा तो वह निर्गुट नीति त्याग कर बड़ी शक्तियों से सहायता चाहेगा । हम नहीं चाहते कि सिंगापुर राष्ट्रीय नीति के विरोध में जाए तथा उसे बड़ी शक्तियों की शरण पहुंचे... सिंगापुर सोवियतों के हिन्द-चीन में राजनीतिक गतिविधियों की अनदेखा नहीं कर सकता जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिरता को खतरा है ।"[66] परन्तु प्रधानमंत्री ली कुआन यू इस सोवियत के बढ़ते खतरे के बावजूद आसियान के सैनिक संधि पर तटस्थ थे ।[67] सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश नीति प्रतिनिधि एस० राजारत्नम् ने मार्च, 1981 में अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट किया :

" हम एक स्वतंत्र वियतनाम चाहते हैं, यह हमारे पक्ष में होगा... अगर वियतनाम चीनी प्रभाव क्षेत्र में चला जाता है तो हमारी दृष्टि में इससे सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा और इस प्रकार से पूरा हिन्द-चीन चीनियों के मुट्ठी में आ जाएगा और हम ऐसी स्थिति के पक्ष में नहीं हैं... मैंने वियतनामियों से कह दिया है कि हम एक सम्पन्न वियतनाम चाहते हैं जो हमारे लिए कोई समस्या पैदा न करे... तथा हम वियतनाम को कम्पूचिया से चले जाने के लिए कहते हैं ।[68]

65- बर्लिन पीपुल्स डेली, 10 जुलाई, 1980 ।

66- बैंकाक पोस्ट, 14 जनवरी, 1980 ।

67- बर्लिन पीपुल्स डेली, 5 जुलाई, 1980 ।

68- एन्टस, एस० कानडाप्रीपा, "कम्पूचिया : द डिप्लोमेटिक डिमेन्शन", एशियन सर्वे, खंड 22, सं०-29 (अक्तूबर, 1982) पृ०-1022 में ले फिगारो (पेरिस), 12 मार्च, 1981 से उद्धृत ।

मलेशिया के उपविदेश मंत्री मुख्तार हाशिम ने फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस के विचारों, की आसियान की ओर अधिक आपसी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए जिससे हिन्द-चीन के संभावित खतरे का सामना किया जा सके, का सम्मान करते हुए कहा कि मलेशिया आसियान देशों के बीच हुए किसी प्रकार के प्रतिरक्षा संधि का विरोध करता है। मुख्तार ने कहा कि आसियान की कोशिश तो दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति क्षेत्र, स्वतंत्रता व तटस्थीकरण की नीति को कार्यान्वित करना है तथा इस क्षेत्र से बड़ी शक्तियों के प्रतिस्पर्धाओं को बाहर रखना है। आसियान प्रतिरक्षा संधि से तटस्थीकरण की प्राप्ति में बाधा पहुँचेगी।[69]

हिन्द-चीन व कम्पूचिया-थाई विवाद के कारण आसियान ने थाईलैण्ड की सैनिक सहायता का इंडोनेशियाई अधिकारियों ने विरोध किया तथा इसे गलत व घातक बताते हुए कहा कि इससे हिन्द-चीन व आसियान देशों के बीच गलत-फहमी पैदा हो सकती है, आसियान हिन्द-चीन के प्रति तटस्थ रहा है तथा ऐसे तटस्थ रहना भी चाहिए, आसियान का यही सिद्धान्त है।[70] परन्तु 12 जून, 1979 को आसियान देशों ने निश्चय किया कि अगर वियतनाम या अन्य हिन्द-चीन देशों ने थाईलैण्ड पर आक्रमण किया तो वे सामूहिक रूप से थाईलैण्ड की सैनिक या अन्य सहायता देंगे। वैसे आसियान देश इस प्रकार की सैनिक संधि-आदि नहीं करना चाहते थे।[71]

आसियान सरकारें थाईलैण्ड की सुरक्षा पर अत्याधिक ध्यान देती हैं पर उनके बीच कम्पूचिया प्रश्न पर अन्तरविरोध मौजूद है। मलेशिया व इंडोनेशिया चीन की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हैं तथा इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि आसियान को वियतनाम से अलग न होने के लिए सावधान रहना

69- स्ट्रेट्स टाइम्स, 21 फरवरी, 1980।

70- बैंकॉक पोस्ट डेली, 6 मई, 1979।

71- इंडोनेशिया टाइम्स, 13 जून, 1979।

चाहिए तथा इन्हीं के साथ मिलकर इस चीन की समस्या के समाधान हेतु शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए ।[72] "कुआनतान सिद्धांत" में[73] आसियान देशों के बीच हिन्द-चीन विवाद पर भिन्नता उभर उठी थी जब मलेशिया व इंडोनेशिया ने हिन्द-चीन समस्या समाधान हेतु आवश्यकता पर सहमति प्रकट की जिसमें वियतनाम द्वारा कम्पूचिया से पूरी सेना की जगह कुछ सेना को हटाए जाने तथा वियतनाम की सोवियत संघ व चीन पर निर्भरता या प्रभाव आदि से अधिक से अधिक मुक्त करने व हेंग सामरिन सरकार की मान्यता देने के साथ ही उभेर रूज को दिए जाने वाले आसियान सहयोग समाप्त करने पर तैयार हो गए । इस बातचीत में यह भी तय किया गया कि कम्पूचिया में शक्ति समस्या के लिए सैनिक समाधान की अपेक्षा राजनीतिक हल होना चाहिए ।[74]

इस "कुआनतान सिद्धान्त" के प्रतिक्रिया में थाई प्रधानमंत्री प्रेम तिनसुलानंद ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और अप्रैल, 1980 को जाकार्ता की यात्रा पर गए तथा 'कुआनतान घोषणा' पर अपना रोष प्रकट किया । थाईलैण्ड के इस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने "कुआनतान घोषणा" को रद्द करने का निर्णय लिया क्योंकि इससे आसियान की एकता को खतरा था ।

23 जून, 1980 को वियतनामी सैनिकों का थाईलैण्ड सीमा में घुसपैठ व आक्रमण के परिणामस्वरूप इंडोनेशिया व मलेशिया को वियतनाम के पड़ोसी देशों

72- ऐशियन, सं0- 43, पृष्ठ- 66-67

73- कुआनतान, मलेशिया के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है जहाँ 26-28 मार्च, 1980 को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुहार्तो व मलेशियाई प्रधानमंत्री दातो हुसैन ओन के बीच बात चीत के दौरान "कुआनतान सिद्धान्त" सामने आया ।

74- फारनहर ईस्टर्न ... , सं0 29, पृष्ठ- 516, ली, ए निरउच, "थाईलैण्ड इन आएन्शीन स्टूटी : कन्फ्रान्टेशन विथ वियतनाम एण्ड फाल ऑफ क्रियांगसाक", "एशियन सर्वे", प्रति 21, सं0-6, (फरवरी, 1981), पृष्ठ- 224-5 ।

के साथ तथाकथित शान्तिपूर्ण मानसिकता का पता चल गया।[75] इस वियतनामी आक्रमण से स्थिति चीन के पक्ष में परिवर्तित हो गयी। इस घटना के बाद आसियान देशों का हनोई के साथ किसी प्रकार के समझौते का अवसर नहीं बचा। इस वियतनाम - थाई सीमा विवाद के परिणाम से चीन काफी प्रसन्न हुआ। थाई विदेश मंत्री सिद्धी सावेतसिला ने जुलाई, 1980 की अपनी बेजिंग यात्रा के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में हनोई-मास्को सम्मिलित कु-प्रयासों की भर्त्सना की, जो निश्चित रूपेण चीनियों के लिए काफी प्रसन्नदायक था। चीन ने थाईलैण्ड को आश्वासन दिया :

"अगर वियतनाम थाई-कम्पूचिया सीमा पर ऐसी गतिविधियां करता रहा तथा थाईलैण्ड को छेड़ता रहा तो चीन इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा... तथा वियतनामी समझते हैं कि हमारे कहने का क्या अभिप्राय हो सकता है..."[76]

इस प्रकार इन संभावनाओं से थाई-कम्पूचिया सीमा पर वियतनाम विरोधी गतिविधियों में संलग्न खमेर फौजों को समर्थन देने के लिए थाई-चीन के मध्य सहयोग बढ़ गया। चीन द्वारा प्रदान की जाने वाली सामरिक व औद्योगिक सहायता थाईलैण्ड के माध्यम से खमेर फौजों तक पहुंचायी जाती है।[77]

78- 23 जून, 1980 को वियतनामी बटालियन जिसमें टी-54 टैंकों ने अचानक थाई-कम्पूचिया सीमा पार कर अरान्याप्राथेट शहर को काफी बर्बाद किया तथा 150000 शरणार्थी शिविरों को बर्बाद करते हुए थाई सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध तीन दिन तक चला तथा थाई सैनिकों ने इसे पीछे हटाने में सफलता प्राप्त कर ली। वियतनामी सैनिकों का उद्देश्य स्वदेशागमनकारियों को रोकना था जिसे वे "सशस्त्र शरणार्थी" कहते थे। एशियन सैक्यूरिटी 1980, सं०-10, पृष्ठ-155।

79- चौधरी, सं०-3, पृ०-228-9 में "फार ईस्टर्न इकॉनॉमिक रिव्यू" (हांगकांग) 1 अगस्त, 1980, पृष्ठ-21-22 से उद्धृत।

77- 9 फरवरी, 1979 को राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक ने न्यूयार्क टाइम्स को दिए एक भेंट के दौरान इसकी पुष्टि की हालांकि थाईलैण्ड ने इसे इंकार किया। एशियन रिकार्डर, (नई दिल्ली), प्रति-25, सं०-10

तीन प्रमुख, आसियान मंत्री स्तर की बैठकें, बाली में जून, 1979, कुआलालम्पुर में जून, 1980 तथा मनीला में जून, 1981 में हुईं। इसके अतिरिक्त आसियान के राजनयिकों की बातचीत अनौपचारिक रूप से होती रही। इन समस्त सम्मेलनों व बातचीत में मुख्य रूप से वियतनाम - कम्पूचिया पर चर्चा हुई।

28-30 जून, 1979 को आसियान देशों के विदेशी मंत्रियों की बाली में हुए सम्मेलन का चीन ने समर्थन किया। <u>पेकिंग रिव्यू</u> ने इस सम्मेलन के समर्थन में तथा इसमें हुए बातचीत को 13 जुलाई, 1979 को प्रकाशित किया, "इस सम्मेलन में एक संयुक्त विज्ञप्ति दी गयी जिसमें कहा गया, "कम्पूचिया में चलते युद्ध या थाईलैण्ड में किसी विदेशी फौजों की घुसपैठ, आसियान सदस्य देशों की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी तथा इससे पूरे क्षेत्र की शान्ति व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।" इसको ध्यान में रखते हुए आसियान के विदेश मंत्रियों ने वियतनाम से अनुरोध किया कि वह शीघ्र थाई-कम्पूचिया सीमा से अपनी सेनाओं की वापसी करे तथा कम्पूचियाएँ क्षेत्र से पूर्णरूप से वापस चला जाए तथा कम्पूचियाई जनता को बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने दे। इसमें यह भी कहा गया था कि वियतनाम शरणार्थियों का निर्यात करना बन्द करे। इससे वियतनामी आक्रमणकारी व विस्तारवादी नीतियों के विरोध में दक्षिण-पूर्व एशियाई लोगों के उचित मांग का पता चलता है। इस सम्मेलन की सफलता से पता चलता है कि आसियान देश इलाके के क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद के प्रति सचेत हैं तथा उसकी मीठी-मीठी बातों से धोखा खाने वाले नहीं हैं। इससे यह भी पता चलता है कि वियतनामी आक्रमण के खतरों के सामने दक्षिण-पूर्व एशियाई देश व जनता अपनी किसी कमजोरी आदि का परिचय नहीं देंगे बल्कि वे एक होकर अपने दुश्मन का सामना करेंगे।"[78]

17 व 18 जून, 1981, मनीला में आसियान के विदेश मंत्रियों द्वारा हिन्द-चीन की समस्या समाधान के लिए छः सूत्री प्रस्ताव रखे गए ---

---

78. <u>पेकिंग रिव्यू</u>, 13 जुलाई, 1979, पृष्ठ 29;

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की देख-रेख में कम्पूचिया से समस्त विदेशी सैनिकों की वापसी ।

(ख) शान्ति, कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा योजना ।

(ग) समस्त विदेशी सैनिकों की वापसी के तुरन्त बाद खमेर दलों को निरुशस्त्र करना ।

(घ) जब तक कम्पूचिया में हुए स्वतंत्र चुनाव के परिणाम स्वरूप सरकार नहीं बन जाती तब तक कम्पूचियाई अन्तरिम सरकार का गठन करना ।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में स्वतंत्र व गुप्त मतदान के माध्यम से कम्पूचियाई राष्ट्रीय संसद का चुनाव कराना जिसमें समस्त कम्पूचियाई राजनीतिक दल भाग ले सकें ।

(च) कम्पूचिया भविष्य में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विवाद में अपने पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण राजनीति का अनुसरण नहीं करेगा इस बात का आश्वासन प्राप्त हो ।[79]

इसके विपरीत थाई-कम्पूचिया सीमा पर तनाव में कमी लाने के लिए हिन्द-चीन देशों द्वारा 18 जुलाई, 1980 को एक चार सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । यह तीनों देशों द्वारा वियेन तियेन (वियेन-चान) की बैठक में निश्चित किए गए --

(य) थाई-कम्पूचिया सीमा पर सैनिक विहीन क्षेत्र का निर्माण ।

(र) शरणार्थी समस्या हल करने और थाईलैण्ड पर उसका भार कम करने के लिए , थाईलैण्ड, कम्पूचिया व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संगठनों के मध्य सहयोग किया जाए ।

79- दर्मा फ्रून, " द इंडोचाईना कन्फिलक्ट एण्ड द पोजिशन्स ऑफ द कन्ट्रीज इनवाल्व्ड ", कन्टेम्प्रेरी साउथ ईस्ट एशिया, इंस्टीच्यूट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज (सिंगापुर) ग्रंथ-5, सं0-1, (जून, 1983), पृष्ठ- 112 ।

(ल) शरणार्थियों को दी जाने वाली सहायता का वितरण कम्पूचिया द्वारा हो।

(व) हेंकाग व नामपेन्ह के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वार्ता हो।[80]

इस हिन्द-चीन के शान्ति प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया स्वरूप हेंकाग ने इसे "राजनीतिक व्यवसाय" का नाम देते हुए नामंजूर कर दिया और इसे थाईलैण्ड को युद्ध में घसीटने का षड्यंत्र बताया। हेंकाग की यात्रा पर आए फरवरी, 1981 को चीनी प्रधानमंत्री चाओ झ्यांग ने वियतनाम के नए फार्मूला को "अत्यन्त भ्रामक" बताया।[81]

आसियान देशों के विचार में जनवादी कम्पूचियाई सरकार की समस्या को हल करने के लिए चीनी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आसियान देश आमतौर पर तथा थाईलैण्ड व सिंगापुर ने विशेष रूप से जनवादी कम्पूचियाई सरकार की समस्या के हल के लिए चीनी सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया। नवम्बर व दिसम्बर 1980 में थाईलैण्ड व सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों ने पेकिंग की यात्रा की तथा चीनी प्रधान मंत्री से इस समस्या पर बातचीत की। इन दोनों प्रधान मंत्रियों ने खमेर रूज को सरकार से हट जाने की बात की और अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो जनवादी कम्पूचियाई सरकार का पुनर्निर्माण करने की राय देते हुए वियतनाम विरोधी अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार की स्थापना करने पर बल दिया। चीन खमेर रूज की अपनी सहायता बन्द करने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि चीन के विचार में यही एक मात्र प्रभावशाली वियतनाम विरोधी छापामार शक्ति हो सकता था तथा इसके साथ-साथ हिन्द-चीन क्षेत्र में यह चीन का मुख्य मित्र है। परन्तु इस बातचीत के बाद चीन ने जनवादी कम्पूचियाई सरकार गठन की वास्तविक स्थिति पर सोचना प्रारंभ कर दिया।[82]

---

80. "वियतनाम नेट एण्ड हुक", "एशिया वीक" (हांगकांग), खंड 6, सं० (1 अगस्त, 1980)।

81. फानईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू, सं०- 29, पृष्ठ- 533।

82. वही, सं०-30, पृष्ठ- 550।

संभवत: इन नेताओं के चीन यात्राओं के परिणाम स्वरूप, कम्पूचियाई उलझन के विषय पर चीन के दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन आया। 13 दिसम्बर, 1980 को चीनी उप विदेश मंत्री हान निस लुंग ने घोषणा की कि उनकी सरकार अब कम्पूचिया से पूरी तरह वियतनामी सैनिकों की वापसी की बात नहीं करती।[83] हान निस लुंग के इस वक्तव्य के पूर्व पेईचिंग ने आसियान द्वारा प्रस्तावित कम्पूचियाई समस्या के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जोरदार ढंग से अस्वीकार किया था। परन्तु कम्पूचियाई प्रश्न पर अन्य महत्वपूर्ण आयामों में आसियान व चीन की स्थितियां पहले से ही समनुरूप हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुवान यू, जो थाई प्रधान मंत्री प्रेम तिनसुलानंद की पेईचिंग यात्रा के दो सप्ताह बाद पेईचिंग की यात्रा पर गए थे, ने सूचना दी कि चीन अब वियतनामी सैनिकों की वापसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में हुए गैर साम्यवादी कम्पूचियाई सरकार के मुक्त रूप से चुनाव कराने के बारे में तैयार हो चुका है।[84]

कम्पूचिया में हेंगसामरिन और पोलपोट के अलावा 1979 में तीसरी फोर्स का विचार भी उभरने लगा था। ये घटक अपनी सैन्य शक्ति और समर्थकों के आधार पर कम्पूचिया के असली शासक व प्रतिनिधित्व के रूप में अपने दावे पेश करने लगे। मार्च, 1979 में कम्पूचिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सोन सान द्वारा गठित साम्यवाद विरोधी, व लोननोल समर्थक "खमेर राष्ट्रीय जन मुक्ति मंच" (खमेर पीपुल्स नेशनल लिबरेशन फ्रंट) ऐसा ही एक गुट था जिसे थाईलैण्ड के दक्षिण-पंथी उग्रवादियों का समर्थन प्राप्त था इसका प्रतिद्वंद्वी साम्यवाद विरोधी समूह "कम्पूचियाई राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन," (मूवमेंट फॉर द नेशनल लिबरेशन ऑफ कम्पूचिया) है जो अक्तूबर, 1978 में गठित किया गया था। इनके अलावा "कम्पूचियाई राष्ट्रीय संघ" (कम्पूचियन नेशनल लीग) भी है जो सिंहानुक की अध्यक्षता में गठित है, तथा इसे कई निष्कासित समूहों का समर्थन प्राप्त है। खमेर

83- एशियन रिकार्डर, (नई दिल्ली) दिसम्बर, 1980, पृष्ठ- 1।

84- वही।

सेरी भी इसे समर्थन देता है । ये सभी दल कम्पूचिया पर अपना प्रभाव जमाकर उसे स्वीकृत करना चाहते हैं ।[85]

इन अलग-अलग समूहों के अलग-अलग दावे ने कम्पूचियाई समस्या को और पेचीदा कर दिया । वियतनाम विरोधी इन कम्पूचियाई गुटों को एक जुट कर उसका सामना करने के भी प्रयास शुरु हुए, जिससे इनका पक्ष मजबूत हो सके । सिंहानुक इनके संभाव्य नेता हो सकते थे, किन्तु प्रारंभ में सिंहानुक का किसी भी प्रस्तावित सरकार का अध्यक्ष होना या कम्पूचियाई समस्या के समाधान में नेतृत्व करना थाईलैंड को बिल्कुल स्वीकार नहीं था । उनका कहना था कि सिंहानुक की निष्कासित सरकार वियतनाम की कम्पूचिया में उपस्थिति को जायज बनाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती । सिंहानुक को उनके देश का समर्थन मिल सकता है, किन्तु समर्थन और मान्यता दो अलग चीजें हैं । पोलपोट की सरकार का संयुक्त राष्ट्र में स्थान ही वियतनाम की कम्पूचियाई स्थिति को मजबूत करने में मुख्य रुप से बाधक है । सिंहानुक इस स्थिति में पलटकर वियतनाम के हाथों में एक खिलौना बन जायेंगे । इस प्रकार रिचार्ड नेशन्स के मतानुसार थाईलैण्ड के कम्युनिस्टों की दृष्टि में कम्पूचिया में वियतनाम के विरुद्ध सिर्फ पोलपोट ही एक सशक्त व प्रभावी कार्य कर सकता है । सोन सान द्वारा अपने दल खमेर सेरी को भी सम्मिलित करके एक स्वीकृत मोर्चा बनाने और सिंहानुक को प्रस्तावित सरकार में कम्पूचिया का नाम धारी प्रमुख बनाने का विचार रखा गया । थाईलैण्ड की मदद इन योजनाओं के लिए आवश्यक थी, परन्तु थाईलैण्ड का कहना था कि यदि सोन सान सिंहानुक को नामपेन्ह में सत्तासीन करना चाहेगा तो थाईलैण्ड की तरफ से उन्हें कोई मदद संभव नहीं होगी । उन्हें सिंहानुक व थाईलैण्ड में से एक को चुनना होगा । 86

85- "कम्पूचिया इंटेन्डिंग डोमिस्टिक फोर्सिज", एशियन सिक्युरिटी 1980, सं०- 10, पृष्ठ- 147-48 ।

86- रिचर्ड नेशन्स, "सिंहानुक, द अनवान्टेड सेव्यर", फार ईस्टर्न एकॉनॉमिक रिव्यू (हांगकांग), प्रति 105, सं०- (7 सितम्बर, 1979) पृष्ठ- 9 ।

काफी समस्याओं के बावजूद इस दिशा में जुलाई, 1980 में सिंहानुक के नेतृत्व में खमेर रूज, सिंहानुक के समर्थक समूहों व अन्य तटस्थ दलों की मिली-जुली सरकार बनाने की ओर प्रगति हुई । हालांकि इस पर थाईलैण्ड की उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं हुई लेकिन आसियान की स्थायी आयोग की बैठक में यह घोषणा की गई कि वह राष्ट्रवादी घटकों द्वारा कम्पूचियाई सरकार के गठन का समर्थन करेगी । आसियान यह नहीं चाहता था कि पोलपोट भी इस प्रस्तावित सरकार में शामिल हो, क्योंकि इसके द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण प्रस्तावित सरकार का पक्ष भी कमजोर हो सकता है । लेकिन इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा चीन द्वारा पोलपोट को समर्थन दिया जाना था ।

आसियान ने कम्पूचियाई समस्या के बारे में चीनी मानसिकता के परिवर्तन के लिए उस पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता रहा । थाईलैण्ड व सिंगापुर के प्रधान मंत्रियों ने चीन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन व कम्पूचियाई शक्ति घटकों को संयुक्त करने के आसियान प्रस्ताव पर सहमति करवा ली थी । चीन की इच्छा सम्मिलित सरकार के पक्ष में नहीं थी । थाई नेताओं ने स्पष्ट रूप से चीन को खमेर रूज की सहायता समाप्त करने के लिए आग्रह किया तथा कहा कि अगर यह सम्भव नहीं हो तो चीन खमेर रूज नेताओं की सहायता में नरमी कर दे । और नए नेतृत्व को ढूंढने का प्रयत्न करे । चीन ने इसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया , परन्तु जनवादी कम्पूचिया के चोटी के नेतृत्व में थोड़ी-सी फेर बदल से अधिक कुछ भी करने से इन्कार किया ।[87]

जब जनवरी, 1981 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ जु यांग थाईलैण्ड की यात्रा पर गए तो उन्होंने वियतनाम विरोधी संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रस्ताव पर काफी नरम व स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया । उन्होंने कहा कि वियतनाम के विरुद्ध चीन संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करेगा । यह चीन की तरफ से पहला गम्भीर कदम था जिसमें संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन की बात थी । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व सम्मिलित सरकार के आसियान ,

87. बैंकाक पोस्ट, 27 अक्तूबर, 1980 ।

विशेषकर थाईलैण्ड व सिंगापुर, स्थिति से चीनी स्थिति काफी निकट आ गयी ।[88]

3-4 सितम्बर, 81 को सिंगापुर में वियतनाम विरोधी गुटों की बैठक एक ठोस कदम साबित हुई । इसमें सिंहानुक, 'खमेर राष्ट्रीय जन मुक्ति मंच' के सनसान व जनवादी कम्पूचिया के प्रधानमंत्री खियु सैंफान ने भाग लिया और वियतनाम विरोधी मोर्चे के रूप में एक मिली-जुली सरकार के गठन का आह्वान किया गया । यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि अब तक ये तीनों घटक वियतनाम विरोधी एक जैसे उद्देश्यों के बावजूद वैचारिक भिन्नता के कारण सहयोग करने में असफल रहे थे ।[89] किन्तु इस सम्मेलन में कम्पूचिया से वियतनामियों को कैसे हटाया जाए, इस प्रश्न पर वे सहमत नहीं हो पाए । परस्पर अविश्वास के कारण इस बैठक का कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मिली-जुली सरकार के गठन और इस ओर प्रयास के लिए एक विशिष्ट समिति के गठन पर सहमति हुई । सन सान समूह द्वारा, वियतनामियों को बाहर किए जाने के बाद, कम्पूचिया से जनवादी कम्पूचिया के नेताओं के निष्कासन और खमेर राष्ट्रीय जन मुक्ति मंच के बहुमत वाले मंत्रिमण्डल का गठन किए जाने की पूर्व शर्त रखी गई ।[90]

ऐसा समझा जाता है कि इस सम्मेलन के बाद तीनों गुट सहयोग से अधिक अपने स्वार्थों में रुचि दर्शाने लगे । खमेर रूज और सनसान के मध्य नेतृत्व को लेकर खींचातानी चलती रही । जिससे वियतनाम विरोधी प्रतिरोध युद्ध में गतिहीनता आई ।

---

88. लाज, सं० 30, पृष्ठ 558 ।

89. 'टेकिंग अ ईज़ी फर्स्ट स्टेप', एशिया वीक, प्रति 7, सं० 44 (18 सितम्बर, 1981), पृष्ठ 13

90. एशियन सिक्युरिटी 1982, सं०-10, पृष्ठ 111 ।

आसियान देशों में साम्यवादी विद्रोह व चीन :

कम्पूचिया में वियतनामी आक्रमण के परिणाम स्वरूप कम्पूचियाई समस्या पर आसियान देशों का चीन समर्थित जनवादी कम्पूचिया के पक्ष में समर्थन पाने के लिए चीन ने आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की दिशा में विशेष रूप में बढ़ना शुरू किया । इस आसियान चीन संबंधों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी -- आसियान देशों में साम्यवादी आन्दोलनों को चीन का समर्थन मिलना । पेकिंग के वियतनामी विस्तारवाद के आसियान प्रतिरोध को सक्रिय व मजबूत बनाने के लिए 1979 के मध्य में थाई कम्युनिस्ट पार्टी के लिए युनान में बने रेडियो स्टेशन से थाई सरकार विरोधी प्रसारण को बन्द कर चीन ने कम्युनिस्टों की सहायता में कमी का स्पष्ट परिचय दिया तथा चीन ने बैंकाक को आश्वासन दिया कि वह थाई सरकार विरोधी गतिविधियों को कम करने हेतु थाई कम्युनिस्टों से सिफारिश करेगा ।[91]

ईस्ट तिमोर में चीन ने फ्रीटिलिन को समर्थन देना बन्द कर दिया तथा चीन के पूरक के रूप में वियतनाम ने फ्रीटिलिन को सहायता देना प्रारंभ कर दिया है । 'रायटर' के अनुसार फ्रीटिलिन के प्रतिरक्षा मंत्री रोगेरियो लोबातो ने लिसबन डेली को यह सूचना दी कि अब चीन के स्थान पर समस्त सहायता वियतनाम कर रहा है ।[92] यदि यह सच हो तो इस प्रकार के परिवर्तन से स्पष्ट हो जाता है कि इंडोनेशिया के चीन पर दबाव का कितना प्रभाव पड़ता है तथा यह परिवर्तन कम्पूचियाई समस्या के संदर्भ में ही है । चीन आसियान देशों के साथ संबंध बनाने के लिए अपने छोटे-छोटे लाभों को त्याग कर वह सोवियत संघ व वियतनाम के विरुद्ध दक्षिण-पूर्व एशियाई राजनीतिक भूमि को अपने विभिन्न प्रकार के संबंधों के माध्यम से तैयार कर रहा है । समाचार पत्र-पत्रिकाओं के अनुसार यहाँ तक कि चीनी उपप्रधान मंत्री ची पांग फेई ने 19 अक्तूबर, 1979 को थाई कम्युनिस्ट पार्टी को

91. एशियन सिक्युरिटी 1980, सं०-10, पृष्ठ- 153 ।

92. स्ट्रेट्स टाइम्स (सिंगापुर), 14 जनवरी, 1980 ।

वियतनामी प्रभुत्ववाद के विरुद्ध थाईलैण्ड के क्रियाशील सरकार का समर्थन करने के लिए कहा ।[93]

आसियान देशों में साम्यवादी आंदोलनों को समर्थन देना चीन मात्र ऐतिहासिक व नैतिक कारण बताता है तथा कई महत्वपूर्ण अवसरों पर उन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा करता रहा है जिससे कम्पूचियाई प्रश्न पर वह आसियान देशों की सहानुभूति व समर्थन प्राप्त कर सके । चीनी नेता हुवांग हुवा ने 17 मार्च, 1980 को कहा कि पेईचिंग का आसियान देशों के भूमिगत साम्यवादी आंदोलनकारियों का समर्थन एक ऐतिहासिक व नाजुक मामला है तथा इस विषय पर बातचीत आपलोगों के बीच नहीं हो सकती ।[94] इसका अर्थ यह हुआ कि वे आसियान के महत्वपूर्ण नेताओं से स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि आसियान के साम्यवादी आंदोलनों का चीनी समर्थन केवल एक औपचारिकता है । जिसे वे आम लोगों के बीच बताने में डरते थे । चीन के विचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए चीनी प्रधानमंत्री चाओ जू यांग ने अपनी सिंगापुर प्रवास के दौरान एक पत्रकार सम्मेलन में 1 फरवरी 1981 को बोलते हुए कहा : " मैं नहीं समझता कि हम लोग किसी साम्यवादी क्रांति का निर्यात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध तो राजनीतिक व वैचारिक है ।... हम इस बात का वायदा करते हैं कि यह संबंध किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।" हमारे आसियान देशों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, तथा हम इन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध व सहयोग को विकसित करना जारी रखेंगे । हम इन देशों में एकता, स्थिरता व संपन्नता के लिए पूरी तरह से आशान्वित हैं । हमने "क्रांति के निर्यात" सिद्धान्त दर्शन को रद्द कर दिया है... यह केवल स्वयं जनता तय करेगी कि उनके देश के लिए कौन-सी आर्थिक व राजनीतिक प्रणाली उचित होगी ।"[95] 13 अगस्त, 1981 को चीनी प्रधान मंत्री चाओ ने अपने उपरोक्त विचार को स्पष्ट करते हुए कहा :

93- बैंकाक पोस्ट, 21 अक्तूबर, 1979 ।

94- बैंकाक पोस्ट, 18 मार्च, 1980, 19 मार्च, 1980 ।

95- एशियानिया टाइम्स, 2 फरवरी, 1981 ।

"चीन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के स्थानीय कम्युनिस्टों की सहायता करना बन्द कर दिया है। चीन केवल उनका राजनीतिक व नैतिक स्तर पर समर्थन करता है। चीन ने अपनी सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त स्थानीय कम्युनिस्ट रेडियो स्टेशनों को बन्द कर दिया है जैसे "वॉयस ऑफ मलेशियन रिवोल्यूशन", अतीत में चीन का दक्षिण-पूर्व एशियाई कम्युनिस्टों के समर्थन का प्रभाव आज के संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए।"[96] चाओ ने अपने उपरोक्त वक्तव्य के तीन दिन बाद ही यहाँ तक कह दिया कि आसियान देश अपने स्थानीय कम्युनिस्ट विद्रोहियों के साथ जैसा उचित समझें वैसा व्यवहार करें... उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट छापामार आसियान देशों के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के उत्पादन हैं। चीन किसी प्रकार के क्रांति के निर्यात में विश्वास नहीं रखता।"[97]

वास्तव में चीन आसियान देशों के कम्युनिस्टों को अपनी सहायता व समर्थन देना समाप्त करना चाहता है पर चीन ऐसा करने में डरता है कि अगर वह चीन समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन देना बन्द कर दिया तो यह विद्रोही दल सहायतादि के लिए सोवियत समर्थित हो जायेंगे जिसके अति भयानक परिणाम हो सकते हैं।[98] परन्तु मलेशिया के विदेश मंत्री गजाली बीन शफी ने 15 अगस्त, 1931 को चीन के इस तर्क को अनुचित ठहराते हुए कहा कि सोवियत-वियतनामी समर्थित कम्युनिस्ट इस क्षेत्र में नहीं उभर सकते क्योंकि मलेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी में 80 प्रतिशत चीनी हैं। वे चीन समर्थित तो हो सकते हैं पर सोवियत या वियतनाम समर्थित नहीं।[99] उन्होंने कहा कि सोवियत खतरे से अधिक चीन समर्थित स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी खतरनाक है, जैसे मलेशिया में कम्युनिस्ट पार्टी के चीनी समर्थित होने के कारण हो सकता है कि सोवियत संघ कोई दूसरी सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करे।[100]

---

96. बैंकाक पोस्ट, "इंडोनेशिया टाइम्स, 14 अगस्त, 1931।

97. फ्रांसीस डेविड, "चाइना रिसेस सबजेक्ट टु रशियन सस्पीशन", बैंकाक पोस्ट, 17 अगस्त, 1981।

98. बैंकाक पोस्ट, 10 अगस्त, 1981।

99. वही, 17 अगस्त, 1981।

कम्पूचियाई प्रश्न पर चीनी नीति व हिन्द-चीन :

हिन्द-चीन देश, आसियान-हिन्द-चीन संबंधों को खराब करने के, चीनी साजिश से भयभीत हैं । कम्पूचियाई समस्या पर वियतनाम का मानना है कि इस समस्या के समाधान में चीन बाधक है । वह चीन को कम्पूचियाई समस्या के लिए दोषी ठहराता है । कम्पूचिया लोक गणराज्य, लाओस व वियतनाम के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में 5 जनवरी, 1980 को एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया :

"चीन का कहना कि 'हिन्द-चीन देशों से आक्रमण का खतरा है', यह केवल आसियान देशों को वियतनाम, कम्पूचिया व लाओस के प्रति भड़काना व उत्तेजित करना है ।" इस विज्ञप्ति में कहा गया कि थाई-कम्पूचिया सीमा पर अस्थिरता के लिए चीन दोषी है, जो खमेर प्रतिक्रियावादियों को समर्थन दे रहा है... दुश्मन हिन्द-चीनी जनता के विरुद्ध कुछ आसियान देशों के सैनिक शक्ति व क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं । अभी भी समय है आसियान देशों को इस बात को समझ लेने में कि चीनी विस्तारवाद व प्रभुत्ववाद उनका प्रयोग कर रहा है ।[101] इसी क्रम में वियतनामी विदेश मंत्री गुयन को थाक ने 6 नवम्बर, 1980 को न्यूयार्क विदेशी संबंधों के परिषद् में कहा :

"चीन, हिन्द-चीन देशों व आसियान देशों के बीच बातचीत में बाधक है । चीन कम्पूचिया-थाई सीमा पर तनाव रखने के लिए पोल पॉट दल का प्रयोग कर रहा है । चीन की राजनीतिक रुचि, दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने विस्तार को बढ़ाने में सहायक इस क्षेत्र में शान्ति व स्थिरता को बिगाड़े रखना है । यह राजनीति उसकी प्रतिक्रियावादी विश्वव्यापी रणनीति, जिसके अनुसार 'तृतीय विश्व युद्ध अवश्यम्भावी है', का एक भाग है, जिससे अन्य देश एक जैसे

100- इंडोनेशिया टाइम्स, 10 अगस्त, 1981 ।

101- वियतनाम इनफॉरमेशन बुलेटिन, नयी दिल्ली स्थित वियतनाम दूतावास से प्रकाशित, 23 जनवरी, 1930, पृष्ठ-5 ।

विवादों में पड़कर कमजोर हों जिससे चीन की लाभ हो सके।... कम्पूचिया में स्थिति स्थिर व सामान्य है। जो कम्पूचिया में अस्थिर है वह कम्पूचिया-थाई सीमा जहाँ थाईलैण्ड पोलपोट की कम्पूचियाई जनता का विरोध करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है।[102]

जहाँ तक चीन का प्रश्न है, चीन कम्पूचियाई समस्या के समाधान हेतु आसियान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है तथा उसे अपना विश्वासपात्र मित्र के रूप में अपने विभिन्न प्रयत्नों से प्रभावित करना चाहता है। इसका परिणाम आसियान - चीन आर्थिक संबंध से पा सकते हैं। आसियान का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार, 1979 के पहले छः माह में 1978 की तुलना में 59 प्रतिशत बढ़ गया। आसियान ने चीन को निर्यात अधिक किया तथा चीन से आयात कम। यह व्यापार आसियान देशों के पक्ष में रहा।[103]

आसियान-चीन संबंध के पक्ष में समस्त आसियान देश हैं परन्तु ऐसा समझा जाता है कि उन्हें डर है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से वे कम्पूचिया प्रश्न पर पूरी तरह चीन का साथ देंगे तो सोवियत संघ पूरी तैयारी के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में वियतनाम के साथ सैनिक सहयोग को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा देगा। 13 अक्टूबर, 1979 को इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ऐडम मलिक ने चीन के साथ संबंध बनाने के पक्ष में कहा, "दक्षिण-पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन व स्थिरता के लिए आसियान को चीन के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए। इस नीति से आसियान और मजबूत होगा तथा यह संदेह भी समाप्त हो जाएगा कि आसियान देश चीन को पसन्द नहीं करते हैं।" उन्होंने कहा कि यह संबंध दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्राध्यक्षों की आपसी यात्रा के माध्यम से ही हो सकते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया व चीन के संबंधों पर कहा, "संबंधों के सामान्य होने में कोई परेशानी नहीं है। हम केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर

---

102. वियतनाम कूरियर "पीस एण्ड स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया", (हनोई, 1981), पृष्ठ- 59-।

103. चाईना न्यूज लेटर, अ पब्लिकेशन ऑफ जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन, मार्च, 1980।

रहे हैं । ऐडम मलिक ने कहा कि आसियान - चीन संबंध उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना आसियान व सोवियत संघ वियतनाम व कम्पूचिया ।[104] अक्तूबर, 1979 में इंडोनेशियाई संसद में इस्लामिक समूह के अध्यक्ष अमिल एस्कन्दर ने चीन के साथ संबंध का विरोध करते हुए कहा, " हम पहले से ही भालू के साथ जूझ रहे हैं, ड्रैगन को आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता है ?"[105] अक्तूबर, 1979 में इंडोनेशियाई पत्रिका "टेम्पो" में प्रकाशित एक निबंध में युसुफ वानान्दी ने चीन के साथ संबंध पर अपने विचार प्रकट किए :

"इस समय आसियान के लिए वियतनाम को स्वतंत्र रूप से सोवियत संघ से हटकर विचार करना कठिन हो गया है । वियतनाम अब मुख्य शक्तिशाली खतरा बन चुका है । सोवियत संघ, वियतनाम के साथ मित्रता संधि के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए हुए है । चीन व रूस के बीच रक्तात्मक विवाद के संदर्भ में इस प्रकार की घटना दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए हानिकारक व खतरनाक हो सकती है । यह स्पष्ट है कि वियतनाम की तुलना में चीन लोक गणराज्य से दूरगामी बड़ा खतरा है । पर वर्तमान समय में वियतनाम चीन से बड़ा खतरा है । इस विशिष्ट स्थिति के संदर्भ में आसियान के लिए सर्वाधिक उचित यही होगा कि वह सभी विकल्पों को अपनाए । दूसरे शब्दों में, आसियान को अपनी कूटनीतिक गतिविधियों में काफी लचीलापन रखना चाहिए । वास्तव चीन के पास सीमित सैनिक क्षमता है तथा वह अपने चार आधुनिकीकरण कार्यक्रम में व्यस्त है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि चीन घरेलू मामलों में उलझा हुआ है । अगर ऐसा है तो इंडोनेशिया को निकट भविष्य में चीन के प्रति नीतियों को तय करना होगा । केवल इंडोनेशिया-चीन सामान्य राजनीतिक संबंध के परिणाम स्वरूप आसियान अधिक-से-अधिक अपना कूटनीतिक प्रयोग कर सकता है ।[106]

104- <u>इंडोनेशिया टाइम्स</u>, 15 अक्तूबर, 1979 ।

105- लिनी सुर्यादिनाता, " द आईनिक माइनारिटी एण्ड साईनो-इंडोनेशियन डिप्लोमैटिक नार्मलाइजेशन", <u>जर्नल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज</u>" (सिंगापुर) प्रति 12, सं०-1 (मार्च, 1981), पृ०-201 में टेम्पो, 27 अक्तूबर, 1979, पृष्ठ-10 से उद्धृत अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

फॉर ईस्टर्न एकॉनॉमिक रिव्यू के चीनी प्रतिनिधि संवाददाता डेविड बैनाविया से एक भेंट में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुवान यू ने आसियान व चीन के हिन्द-चीन में घटित कम्पूचिया में वियतनामी सैनिक पृष्ठपीठ के प्रश्न पर आपसी दृष्टिकोण में मतभेद की ओर संकेत करते हुए नवम्बर, 1980 में कहा :

"दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह वियतनाम के किसी विशेष स्थिति की तस्वीर बनाये जिसे चीन, समीर रूप के माध्यम से, अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता है। इसके बावजूद कि आसियान देशों व चीन ने कम्पूचिया में वियतनामी सैनिकों द्वारा आधिपत्य का संयुक्त रूप से विरोध किया है तथा वहाँ से वियतनामी सैनिकों की वापसी की माँग की है व संयुक्त राष्ट्र संघ में पोलपोट के स्थान के बारे में अपना सामूहिक समर्थन दिया है। फिर भी आसियान व चीन के बीच हिन्द-चीन की समस्या को हल करने के विषय पर भिन्न राय है। हम लोग एक ही दुनिया को विभिन्न चश्मों से देख रहे हैं। चीन के लिए हमारा चश्मा विस्तृत दृष्टिकोण वाला दूरगामी है जबकि सिंगापुर के लिए समीपस्थ सूक्ष्म चश्मा से देखते हैं। चीन का हिन्द-चीन के प्रति दृष्टिकोण काफी गम्भीर है क्योंकि वह सोवियत संघ के विश्वव्यापी नीति से भयभीत है तथा उसके विरोध में अपनी नीतियों का निर्धारण कर रहा है जबकि आसियान देशों की रुचि व हित तो क्षेत्रीय शान्ति व स्थिरता बनाए रखने के हित में है।"[107]

चीन आसियान देशों को कम्पूचियाई समस्या से उत्पन्न, सोवियत समर्थित वियतनामी खतरे से डराता रहता है। चीनी उपप्रधान मंत्री तंग ने 13 जनवरी, 1979 को पेकिंग में थाई उप प्रधान मंत्री सुनथोर्न होंगलाडारोम से कहा :

"चाहे जो भी हो... हमें साफ-साफ वास्तविकता को सामने रख देना

106- वही, पृष्ठ- 199 में युसुफ वानादी, "फारजागान कमाह वाणी आसियान", "टेम्पो", 13 अक्तूबर, 1979 से उद्धृत, अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

107 डेविड बोनाविया, "इन्टरव्यू : ली कुवान यू", फॉर ईस्टर्न एकॉनॉमिक रिव्यू, 21 नवम्बर, 1980, पृष्ठ- 20।

चाहिए... कम्पूचिया व चीन के बीच संबंध या कम्पूचिया व दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच का संबंध एक दूसरे पर निर्भर करता है तथा एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर एक का पतन होता है तो दूसरा खतरे में होता है। इसलिए थाईलैण्ड के लिए तटस्थ रहना उचित न होगा। हमें विश्वास है कि थाईलैण्ड इन तीन बातों को समझ लेगा ---

(क) इस समय थाईलैण्ड को मुख्य खतरा कम्पूचिया से नहीं है अपितु वियतनाम से है।

(ख) थाईलैण्ड को इस बात को समझ लेना चाहिए कि वियतनाम का अगला निशाना थाईलैण्ड होगा। अगर थाई सरकार बुद्धिमान होगी तो वह जनवादी कम्पूचिया के छापामार युद्धों का अच्छी तरह सहायता करेगी। एसी थाईलैण्ड के जरिए चीन से सामग्री सहायता भेजवाने के अतिरिक्त थाईलैण्ड को अन्य आसियान देशों को आमंत्रित करना चाहिए, यहां तक कि उसे अमेरिका व जापान तक को कम्पूचिया की सहायता के लिए बुलाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कम्पूचिया का प्रतिरोध युद्ध मजबूत होगा और इससे वियतनाम के थाई क्षेत्र में विस्तार में रुकावट पैदा होगी। क्या यह थाईलैण्ड के लिए अच्छी बात न होगी कि वह दुश्मनों को अपने दरवाजे से दूर रखे।

(ग) जितनी देर तक कम्पूचिया में प्रतिरोध युद्ध चलता रहेगा उतना ही वियतनाम के "हिन्द-चीन संघ", -- जो दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है, बनाने की योजना में विलम्ब होगी। और जितना विलम्ब होगा उतना ही वियतनाम के राष्ट्रीय शक्ति का ह्रास होगा।"[108]

चीन ने आसियान देशों में, कम्पूचिया समस्या के संदर्भ में, अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजता रहा ताकि वे हिन्द-चीन विवाद पर वियतनाम व

108- ईशूज एण्ड स्टडीज़ (ताए पेई), जनवरी, 1981, पृष्ठ-88-92, ।

सोवियत विरोधी तथा चीन समर्थित हो सकें। इसी क्रम में चीनी प्रधान मंत्री चाओ जु यांग ने अगस्त, 1981 में तीन आसियान सदस्य देशों की यात्रा की। चीनी प्रधान मंत्री चाओ ने 8 अगस्त, 1981 को मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति मारकोस से कहा कि पेइचिंग दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी प्रकार का अपने प्रभाव बनाने के या प्रभुत्व के पक्ष में नहीं है अपितु वह चाहता है कि आसियान अधिक मजबूत व मिलजुल कर शान्ति व स्थिरता के लिए कार्यरत रहे।[109] चाओ ने 9 अगस्त, 1981 को मनीला से मलेशिया जाते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया को सोवियत व वियतनामी विस्तारवाद से सावधान किया तथा कहा कि सोवियत समर्थित वियतनाम का अगला कदम कोई दूसरा दक्षिण - पूर्व एशियाई देश होगा। उन्होंने कहा, "वियतनाम का कम्पूचिया पर आक्रमण यह केवल कोई क्षेत्रीय मामला नहीं है ना ही चीन-सोवियत प्रतिस्पर्धा का रूप है, अपितु यह चीन, आसियान, जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड द्वारा सोवियत आक्रमण व विस्तारवाद के विरुद्ध छेड़ा गया प्रश्न है।" चाओ ने कहा कि चीन एक शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण चाहता है तथा सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का इच्छुक है।[110]

चीन आसियान की सफलताओं व उपलब्धियों की जोरदार ढंग से प्रशंसा करता है। चीनी वरिष्ठ नेता चाओ ने कुआलालम्पुर में, 9 अगस्त, 1981 को एक भोज समारोह में कहा :

"हमें, क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान को देखकर काफी प्रसन्नता होती है जिसने आर्थिक विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की है। आसियान अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कम्पूचिया के प्रश्न पर आसियान देशों ने न्याय को बनाए रखने, आक्रमण का विरोध करने, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों की सुरक्षा तथा

109- बैंकाक पोस्ट, 9 अगस्त, 1981।

110- बंगलादेश ऑब्जर्वर, 11 अगस्त, 1981।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिमानों को बनाए रखने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया है।"

"आसियान देशों के योगदान से "कम्पूचिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" हो सका। चीनी सरकार आसियान देशों की, दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति व स्थिरता के लिए उनके प्रयत्नों की प्रशंसा करती है। हम आसियान के "ज़ोपफान" प्रस्ताव का तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता व राज्य की प्रभुता की रक्षा में उनकी उचित भावनाओं का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।"

"चीनी जनता शान्ति प्रेमी है तथा वह लम्बी अवधि की शान्तिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण चाहती है जिसमें वे अपनी चार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकें।.... चीन राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों के साथ दृढ़ता से वचनबद्ध है। हम सदैव इस बात के पक्षधर रहे हैं कि किसी देश की सामाजिक व राजनीतिक प्रणाली का चुनाव उस देश विशेष की जनता द्वारा होनी चाहिए तथा उसमें किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चीन के दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं तथा वह इन देशों में एकता, स्थिरता व संपन्नता के लिए गम्भीर रूप से इच्छुक है।[111]

कम्पूचिया समस्या के समाधान के विषय में चीन की इच्छा यह नहीं है कि वहाँ पोलपोट की सरकार की वापसी हो। वह चाहता है कि कम्पूचिया में वियतनाम समर्थित सरकार न हो। इसके पक्ष में चीनी प्रधान मंत्री चाओ ने अपनी दक्षिणएशियाई यात्रा के दौरान आसियान को आश्वासन देते हुए कहा कि चीन कम्पूचिया को अपना पिछलग्गू बनाने का कोई इरादा नहीं रखता जिससे दक्षिण - पूर्व एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा हो। उन्होंने कहा कि चीन अपना वायदा पूरा करता है तथा इसकी ईमानदारी को समय की अन्तराल में देखा जा सकता है.... चाओ ने कहा कि चीन इसके बारे में चिंतित नहीं है कि कम्पूचिया से वियतनाम के हटने के बाद वहाँ कौन शासन करेगा।[112] चीनी

---

111. एस० डब्ल्यू० बी०, एफ-ई।6993, 11 अगस्त, 1981, ए-3।5 ।

112. वही, एफ-ई।6799, 12 अगस्त, 1981, ए-3।1 ।

प्रधान मंत्री चाओ ने अपने इसी विचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए 13 अगस्त, 1981 को कहा कि यद्यपि कम्पूचिया समस्या के हल के लिए चीन व आसियान के विचारों में अन्तर हो सकता है पर दोनों का उद्देश्य एक ही है -- 'कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं की पूर्ण रूपेण वापसी'। उन्होंने थाई विदेश मंत्री एस0सी0एस0 सिद्धि से कहा कि चीन के विचारों के बारे में यह दुविधा है कि वह पौलपोट व यांगसारी को कम्पूचिया के शासन में पुनः लाना चाहता है, ऐसा नहीं है। चीन चाहता है कि कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में हुए चुनाव के बाद एक स्वतंत्र व तटस्थ सरकार की स्थापना हो, चीन को वियतनाम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में प्रसन्नता होगी अगर वियतनाम शीघ्र अपनी समस्त सैनिकों को वापस बुला ले।[113]

मलेशिया के प्रधान मंत्री दत्तो श्री डा0 महाथिर कम्पूचिया समस्या के समाधान में चीन की नीतियों से काफी हद तक सहमत हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आसियान की नीतियों से चीन का काफी कम अन्तर है बस कुछ तरीकों में मतभेद को छोड़कर। महाथिर ने चीन से कहा कि वह कम्पूचिया प्रश्न पर आसियान का सहयोग व समर्थन करे।[114] हिन्द-चीन में वियतनाम का सैनिक व राजनीतिक प्रभुत्व बनाने का निर्णय व इसके सोवियत संघ के साथ नए समझौतों ने चीन-वियतनाम प्रतिस्पर्धा को क्षेत्रीय अधिपत्यवाद के लिए एक दूसरे आयाम की शुरुआत किया जिसका उत्पादन था आसियान व चीन के बीच घनिष्ठ संबंध।

---00000---

113- बैंकाक पोस्ट, 14 अगस्त, 1981।

114- एस0 डब्ल्यू0 बी0 एफ0ई0/6799, 12 अगस्त, 1981, ए-3/1।

पंचम अध्याय

अन्त में

दक्षिण-पूर्व एशिया का चीन से संबंध हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन समय से ही दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों पर चीन का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। इन देशों के बीच के संबंध कभी मित्रतापूर्ण तो कभी शत्रुतापूर्ण रहे हैं। प्राचीन काल से ही दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अपनी खनिज संपदा, कृषि उत्पादन, आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक दृष्टि से विदेशियों के आकर्षण के केन्द्र रहे हैं। चीन की रुचि इन देशों में अपेक्षाकृत अधिक रही है।

प्रशांत महासागर व हिन्द महासागर के मध्य स्थित होने के कारण दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र का महत्व प्राचीन समय से ही चीन की अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोपरि रहा है। चीन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश होने के कारण प्रारंभ से ही दक्षिण-पूर्व एशिया को अपने आधीन समझता रहा है, तथा वह अपनी श्रेष्ठता के सामने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को तुच्छ समझता रहा।

दक्षिण-पूर्व एशिया में आसियान-चीन संबंधों की अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में विशेष योगदान हो सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वहाँ विश्व शान्ति के लिए स्थिरता का होना अति आवश्यक है। क्षेत्रीय तनाव, हथियारों का जमाव, विदेशी शक्तियों की घुसपैठ, आदि को तभी रोका जा सकता है जब आसियान देशों के चीन के साथ संबंध सामान्य हों।

सोवियत-चीन, चीन - अमेरिका, चीन-वियतनाम और आसियान-चीन ऐसे समीकरण हैं जो एक दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करते रहते हैं।

आसियान-चीन के बीच पहले संबंध सोवियत-चीन व चीन-वियतनाम के संबंधों में तनाव तथा चीन-अमेरिका के बीच तनाव शिथिलता का एक परिणाम है। इस शताब्दी के सातवें दशक में आसियान-चीन संबंधों में काफी परिवर्तन आए। आसियान देशों में चीन का प्रभाव काफी फैलता जा रहा है जबकि वे पहले चीन की विद्रोही समर्थित मानसिकता से काफी भयभीत थे।

आसियान-चीन संबंधों का आसियान देशों के आर्थिक विकास, सुरक्षा व स्थिरता तथा चीन के आधुनिकीकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

आसियान-चीन संबंधों के इतिहास में मूलतः दो विशेष समस्याएं रही हैं -- चीन का आसियान देशों में स्थानीय कम्युनिस्ट आंदोलनों के साथ संबंध और तथाकथित प्रवासी चीनियों की जातीय समस्याएं। आसियान-चीन संबंध में सबसे बड़ा व्यवधान चीन का आसियान देशों में साम्यवादी विद्रोही आंदोलनों के समर्थन करने की खुलेआम नीति रही है। और इंडोनेशिया-चीन के राजनयिक संबंध में यह सबसे बड़ी बाधा है। चीन के समस्त कूटनीतिक प्रयत्नों के बावजूद, जिससे वह आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बना सके, चीन आसियान के साथ संबंध निर्माण में अधिक सफल नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण चीन की द्विपक्षीय संबंध मानसिकता रही है -- एक तरफ चीन आसियान की प्रशंसा करता है तथा दूसरी तरफ आसियान देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन भी करता है। परन्तु वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन की नीति आसियान देशों में कम्युनिस्ट आंदोलनों की सहायता करना नहीं है। चीनी नेता आसियान देशों की साम्यवादी संगठनों के साथ चीन के संबंध को एक राजनीतिक व नैतिक रूप में मानते हैं। वे किसी प्रकार की क्रांति के नियति में विश्वास से इन्कार करते हैं। उनके विचार में पार्टी-पार्टी संबंध राज्य-राज्य संबंध को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा। चीन की दृष्टि में अगर चीन आसियान देशों के चीन समर्थित स्थानीय साम्यवादियों के साथ संबंध समाप्त कर दे तो वे निश्चित रूप से सोवियत संघ व वियतनाम की ओर

भड़क सकती हैं । यह स्थिति आसियान देशों व चीन के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है तथा इस खतरे को आसियान देश व चीन कभी आमंत्रित करना नहीं चाहेंगे ।

वर्तमान समय में चीन का आसियान देशों के साम्यवादियों का समर्थन केवल एक नाटक मात्र है । चीन अब अपने वैचारिक व क्रांतिकारी दुनिया से काफी पीछे आकर अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय हित व एकता पर अधिक बल देता है तथा अपने देश के चार आधुनिकीकरण की तरफ तेजी से बढ़ना चाहता है चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े । चीन की तीव्रगति से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में उसे मार्क्सवाद , लेनिनवाद का दार्शनिक व वैचारिक कवच भारी पड़ रहा है । चीन अब राष्ट्रवादी मानसिकता की और विशेष रूप से अग्रसित है, और चीन जैसी बड़ी आबादी व क्षेत्रफल तथा पिछले पैंतीस वर्षों से अनुशासित व संगठित देश के लिए राष्ट्रवादी होना विश्व शान्ति व सुरक्षा के लिए अत्याधिक खतरनाक हो सकता है । साम्यवादी देशों से दूसरी व तीसरी दुनिया के देशों को तब तक कोई खतरा नहीं हो सकता जब तक वह अन्तर्राष्ट्रवाद में विश्वास करता है ।

चीन ने आसियान देशों की "राष्ट्रीय स्वतंत्रता" के लिए लोकयुद्ध की सहायता करना लगभग समाप्त कर दिया है । आसियान देशों में जिनके साथ चीन के राजनयिक संबंध पहले से हैं, के साथ राज्य स्तर पर संबंध को और विकसित करना चाहता है । चीन अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में अपनी जिम्मेदारी को रचनात्मक रूप से तीव्रतर करता जा रहा है, फिर भी आसियान देश, पेईचिंग के आसियान देशों की सरकार के विरुद्ध साम्यवादी विद्रोही गतिविधियों के समर्थन से, चिंतित हैं । आसियान देशों की साम्यवादी पार्टियां सोवियत की अपेक्षा पेईचिंग समर्थित हैं । परन्तु चीन की विश्वक्रांति व अन्तर्राष्ट्रवादी साम्यवादी मानसिकता के साम्यवादी नीतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आसियान के साम्यवादी क्रांतिकारी केवल चीन का मुंह नहीं देखते रहेंगे बल्कि

वे निश्चित रुप से चीनी समर्थन के अभाव में अपनी नीतियों में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। इससे वहां की स्थानीय साम्यवादी पार्टियों में अलगाव की स्थिति की संभावना बढ़ सकती है तथा इसमें से एक पार्टी सोवियत समर्थित हो सकती है।

कम्पूचिया में वियतनामी सैनिक मौजूदगी के कारण वहां हेंगसामरिन की वियतनाम व सोवियत समर्थित सरकार बनने से आसियान देशों को चीन के साथ पूरी तरह, आसियान देशों में साम्यवादियों को चीनी सहायता न देने के बारे में, सौदा करने का अवसर मिल गया अन्यथा पिछले पांच वर्षों में आसियान देशों में साम्यवादी आन्दोलन काफी आगे बढ़ सकता था।

अगर हिन्द-चीन देशों में चीन समर्थित साम्यवादी सरकारें होतीं तो शायद आसियान-चीन संबंधों का रुख और ही रुख होता। इस स्थिति में चीन आसियान देशों में चल रहे साम्यवादी गतिविधियों में किसी प्रकार से नरमी नहीं करता अपितु उसे और अधिक जोरदार समर्थन देता तथा चीन अपनी सीमा क्षेत्र में उन समस्त आसियान देशों के विरुद्ध रेडियो स्टेशनों को बनाए रखता और संभवतः आसियान को किसी दूसरे रुप में मान्यता देता। परन्तु सोवियत-चीन तनाव के कारण चीन अपने आपको सोवियत संघ से चारों ओर से घिरा पाता है और चीन सोवियत संघ के बढ़ते संभावित खतरे से भयभीत है और इसका परिणाम अमेरिका-चीन व चीन-जापान तनाव शिथिलता है। वर्तमान स्थिति में चीन आसियान देशों व अन्य तीसरी दुनिया तथा सोवियत विरोधी देशों के साथ मिलकर सोवियत विरोधी मोर्चा बनाना चाहता है।

आसियान-चीन संबंधों के बीच जटिल समस्या, आसियान देशों में प्रवासी चीनियों की है। आसियान देशों में रह रहे प्रवासी चीनी आसियान देशों के लिए कांटे की भांति के समान हैं। आसियान देशों के प्रतिबंधित साम्यवादी आन्दोलन मौलिक सहायता व वैचारिक प्रोत्साहन के लिए काफी

समय से ही चीन की तरफ विमुख रहे हैं। इसके कुछ तो वैचारिक व राजनीतिक कारण रहे हैं पर प्रमुख कारण उनमें आसीय चीनी सदस्यों की बाहुल्यता है। आसियान देशों में तथा विशेषकर इंडोनेशिया में चीन के प्रति मुख्य रोष का कारण प्रवासी चीनियों का स्थानीय जनता के साथ बुरा व्यवहार है जिसमें उनके आर्थिक शोषण मुख्य रूप से शामिल है। इंडोनेशिया व चीन के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के संबंध में इंडोनेशियाई सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, चीन के साम्यवादी विद्रोह की सहायता समाप्ति आदि बहानों के माध्यम से विलम्ब किया जा रहा है यद्यपि इंडोनेशिया के लगभग समस्त आरोपों व मांगों को चीन ने ठीक कर लिया है फिर भी संबंधों की पुनर्स्थापना नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण इंडोनेशिया की आर्थिक नीति की चीन से संभावित खतरा तथा द०पू० एशिया में शक्ति संतुलन को सोवियत-चीन-वियतनाम के संदर्भ में बनाए रखना है।

आसियान देशों को उनकी स्थिरता व सुरक्षा को मुख्य खतरा बाहरी न होकर आंतरिक ही प्रतीत होती है। प्रत्येक प्रकार के विद्रोह का कारण विभिन्न प्रकार के मौजूद सामाजिक व आर्थिक अन्तर्विरोध ही हैं तथा उनको राष्ट्रीय उत्थान के विभिन्न प्रणाली से समाप्त किया जा सकता है।

आसियान देशों में बढ़ रही आर्थिक असंतुष्टता, गरीब व अमीर के बीच मौजूद असीमित खाईं, नेताओं की अयोग्यता एवं अनियोजित व्यवस्था के कारण इन देशों की सुरक्षा को विदेशी शक्तियों की अपेक्षा स्थानीय सामाजिक अन्तर्विरोधों से अधिक खतरा है। अगर वहां की स्थानीय जनता प्रसन्न व संतुष्ट होगी तभी वहां की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता हो सकती है तथा निश्चित रूप से वहां शासन कर रहे नेताओं को सुरक्षा का अनुभव होगा।

सातवें दशक के मध्य व अंतिम वर्षों में हिन्द-चीन में हुए परिवर्तनों ने आसियान-चीन संबंधों पर विशेष प्रभाव डाला। सन् 1978-81 में तो हिन्द-चीन की कम्पूचियाई समस्या ने आसियान देशों व चीन के बीच घनिष्ठ संबंधों को काफी उत्प्रेरित कर बढ़ा दिया है।

जब सन् 1975 में साम्यवाद ने समूचे हिन्द-चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तब गैर साम्यवादी आसियान सदस्यों ने "डोमिनो सिद्धांत" को ध्यान में रखते हुए अपनी कमजोर व शिथिल संगठन के उत्थान व सक्रियता के लिए तीव्र कदम उठाए थे। इसके साथ-साथ आसियान देशों ने साम्यवादी देशों के साथ, अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर, संबंध बनाना प्रारंभ किया व हिन्द-चीन के तीनों देशों को मान्यता देने तथा राजनैतिक संबंध बनाने की पहल की।

यद्यपि आसियान सन् 1967 में बनाया गया था परन्तु 1975 के हिन्द-चीन में परिवर्तन के बाद इसमें गतिशीलता आयी तथा इसके सक्रिय होने का मुख्य कारण तथाकथित "डोमिनो सिद्धान्त" से उत्पन्न भय था। इसके प्रारंभिक व वास्तविक उद्देश्य चाहे कुछ भी रहे हों परफरवरी, 1976 को बाली में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के बाद इसकी दिशा ही परिवर्तित हो गयी।

आसियान का चीन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन व चीन का आसियान के प्रति उदार व पक्षपाती दृष्टिकोण का संबंध निश्चित रूप से साम्यवादी देशों के अन्दर हुए विवाद से है। आसियान देश चीन के आसियान का समर्थन करने का कारण अच्छी तरह समझते हैं। चीन अपने साम्यवादी दुश्मन सोवियत संघ से घिरने के कारण शक्ति संतुलन के लिए आसियान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। आसियान देश भी समझते हैं कि कम्पूचियाई समस्या चीन के लिए सोवियत संघ के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मत को अपने पक्ष में प्राप्त करने व समस्त शक्तियों को आन्दोलित करने के प्रयासों के पीछे किस्से का एक छोटा भाग है। इसके बावजूद आसियान देश वियतनाम के विस्तारवादी मानसिकता के विरुद्ध शक्ति संतुलन के लिए चीन की मदद को समझते हैं तथा यह बात थाईलैण्ड के संदर्भ में विशेष अर्थ रखती है।

वर्ष 1978-79 में आसियान-चीन समीकरण में आए नए उत्पादित परिवर्तन का मुख्य कारण, 25 दिसम्बर, 1978 को वियतनाम का पोलपोट के

चीनी समर्थित जनवादी कम्पूचियाई सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए सैनिक हस्तक्षेप करना तथा 7 जनवरी 1979 को सोवियत व वियतनाम समर्थित हेंग सामरिन सरकार को कम्पूचिया में स्थापित होना ही था। निश्चित रूप से कम्पूचिया में घटित इस नए राजनीतिक परिवर्तन से आसियान देशों की समक्ष में उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। इस कम्पूचियाई समस्या के परिणामस्वरूप आसियान-व हिन्द-चीन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के नियंत्रित व प्रभाव क्षेत्र बनाने हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़ गई।

वियतनाम के कम्पूचिया पर सैनिक हस्तक्षेप के कारण लाखों शरणार्थी समुद्र व भूमि दोनों रास्तों से आसियान देशों की ओर आने लगे तथा इन शरणार्थियों के कारण इन देशों की जातीय संतुलन व सामाजिक स्थिरता को खतरा होने लगा।

कम्पूचियाई समस्या से उत्पन्न कठिन व जटिल राजनीतिक समस्याओं से आसियान काफी परेशान हो गया कि वह चीन-वियतनाम व चीन-सोवियत विवादों में अपनी काफी ऐसे संतुलित व सटस्थ रखे पर वियतनाम के थाई सीमा पर आक्रमण करने तथा सीमा नियमों के उल्लंघन करने के फलस्वरूप आसियान को उसमें सक्रिय रूप से आना ही पड़ा। इन समस्त गतिविधियों से दोनों पक्षों-हिन्द-चीन व आसियान को विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सैनिक व मानसिक आदि सहायता व समर्थन के प्राप्त होने के कारण यह पहले अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बना हुआ है।

चीन ने आसियान देशों के साथ एक काफी सक्रिय कूटनीतिक अभियान छेड़ रखा है तथा इस चीनी कूटनीतिक अभियान में चीन को सोवियत संघ का अफगानिस्तान व सोवियत समर्थित वियतनाम का कम्पूचिया पर आक्रमण से काफी धनात्मक लाभ प्राप्त हुआ है।

आसियान देश व चीन आज के अन्तर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण में सोवियत आधिपत्यवाद व प्रभुत्ववाद को विश्व शान्ति के लिए

सबसे बड़ा खतरा समझते हैं । चीन यह नहीं मानता कि दोनों महाशक्तियाँ, अमेरिका व सोवियत संघ, युद्ध के लिए समान रूप से इच्छुक हैं । चीन के विचार में इस समय सोवियत संघ ने हमलावर रुख अख्तियार किया है और वह अपने विस्तार के लिए युद्ध पर उतारू है जबकि अमेरिका चाहता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है वह बना रहे । सोवियत संघ द्वारा शस्त्रीकरण, हर तरह के समुद्री क्षेत्रों में युद्ध के काम आने योग्य नौ सैनिक बेड़ों का निर्माण, विभिन्न अप्रत्यक्ष सैनिक अड्डों से आक्रमण करने की तैयारी, व अफगानिस्तान जैसे छोटे निर्गुट देश में सैनिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी इच्छुक सरकार बनाने जैसी बातों ने आसियान देशों व चीन के लिए एक समान डर पैदा कर दिया है ।

आसियान देश प्रारंभ से ही बुनियादी तौर पर कम्युनिस्ट विरोधी और पूंजीवाद व पश्चिम समर्थक रहे हैं । चीन आसियान देशों में साम्यवादी विद्रोहियों की सहायता में काफी कमी करता जा रहा है । चीन पश्चिमी दुनिया तथा जापान से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बना रहा है । यहां तक कि अमेरिका, जापान, पश्चिमी यौरोप तथा तीसरी दुनिया के देशों के साथ मिलकर चीन सोवियत प्रभुत्ववाद के विरोध में एक संयुक्त मोर्चा भी बनाना चाहता है ।

सोवियत संघ व वियतनाम के दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आसियान देश चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर अग्रसित हुए जिसमें इंडोनेशिया एक अपवाद आसियान सदस्य देश है ।

कम्पूचिया की समस्या आसियान व हिन्द-चीन संबंधों में तनाव व आसियान -चीन संबंधों में घनिष्ठता का मुख्य कारण बनी हुई है । आसियान देशों के कारण कम्पूचियाई समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गई है तथा हेंग सामरिन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वैधता को प्राप्त करने में असफल रही ।

22 अक्तूबर, 1980 के संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित आसियान प्रस्ताव व 17-18 जून, 1981 में पारित आसियान के मनीला प्रस्ताव से

वर्तमान कम्पूचिया समस्या का समाधान संभव हो सकता था अगर वियतनाम अपना विस्तारवादी मानसिकता का त्याग कर देता ।

आसियान देश कम्पूचिया से वियतनामी सैनिकों की वापसी की बात इसलिए नहीं करते कि वे चीन का समर्थन करते हैं बल्कि यह उनके अपने सुरक्षा हित में है। यह मुद्दा आसियान सदस्य देशों में थाईलैण्ड के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।

कम्पूचिया समस्या को आसियान अपनी क्षेत्रीय रुचि की दृष्टिकोण से देखता है जबकि चीन इसे क्षेत्रीय व विश्वव्यापी समस्या के रूप में देखता है ।

वियतनाम-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा चीन-रूस प्रतिस्पर्धा का अंग होगा इससे इस क्षेत्र में स्थिरता अधिक समय तक नहीं रह सकती ।

चीन अपने स्वार्थ के लिए आसियान देशों को हिन्द-चीन की समस्या से उत्पन्न मामलों को भयानक रूप देकर डराना चाहता है व "डोमिनो सिद्धान्त" को पुनर्जीवित कर रहा है । इस "डोमिनो सिद्धान्त" को 1954 में अमेरिका ने साम्यवादी खतरे से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए दिया था और उस समय इस खतरे का कारण चीन को बताया गया था ।

चीन का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में मुख्यतः राष्ट्रीय हित व राजनीतिक-वैचारिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है, इसमें उसकी मान्यता, प्रभाव, मित्रता, संबंध गुटता, सुरक्षा, व्यापार आदि सम्मिलित हैं ।

अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों तथा वर्तमान संदर्भ के अनुसार चीन आसियान को अत्याधिक शक्तिशाली संगठन के रूप में देखना चाहता है तथा वह यह भी चाहता है कि आसियान की विदेश नीति अधिक से अधिक सोवियत व वियतनाम विरोधी हो । क्योंकि चीन नहीं चाहता कि हिन्द-चीन में मजबूत व शक्तिशाली वियतनाम का प्रभुत्व बना रहे तथा इस गतिविधि में वह अकेला ही प्रयत्न करे ।

यह आसियान के साथ सामूहिक सहयोग के साथ वियतनाम का विरोध करना चाहता है। चीन हिन्द-चीन में स्थाई तौर पर सोवियत उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

चीन की हिन्द-चीन में रुचि का कारण निम्न हैं :

- वियतनाम की एशियाई इच्छा का एक कारण इसी से रोकना तथा सोवियत प्रभाव से इसे व अन्य हिन्द-चीन के देशों को दूर रखना।
- कम्पूचिया व लाओस को वियतनाम से दूर रखना।
- दक्षिणी चीन सागर पर नियंत्रण करना व सम्पूर्ण क्षेत्र (दक्षिण-पूर्व एशिया) में प्रभावशाली भूमिका निभाना।
- आसियान देशों का कम्पूचिया समस्या पर चिंतित होने के निम्न

कारण हैं :

- कम्पूचिया से वियतनामी सैनिकों की वापसी के बाद वियतनाम व आसियान के बीच कम्पूचिया को मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) के रूप में बनाए रखना तथा हिन्द-चीन को चीन व आसियान के बीच मध्यस्थ राज्य को भी बनाए रखना।
- सोवियत समर्थित वियतनाम के खतरे का भय व्याप्त होना।
- कम्पूचिया समस्या से आसियान देशों की सुरक्षा व स्थिरता को खतरा पैदा होना।
- हिन्द-चीन से आसियान देशों में, लाखों की संख्या में शरणार्थियों का आगमन व उनसे उत्पन्न अनेकों सामाजार्थिक समस्याएं।

उपरोक्त आसियान व चीन के कम्पूचिया प्रश्न पर दृष्टिकोण में सोवियत समर्थित वियतनामी खतरे की बात एक देती है तथा यही वह मुख्य कारण है जिससे इस विषय पर अन्य मतभेदों के बावजूद आसियान-चीन कम्पूचिया प्रश्न पर सहमत लगते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सर्वमान्य मानक सिद्धान्त "पंचशील" की नीति, "एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना", के आधार पर वियतनाम का कम्पूचिया पर प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। स्पष्ट है कि "पंचशील" की नीतियों के निर्माण में विभिन्न देशों के शासक ही थे और वे निश्चित रूप से अपने देश व सरकार में स्थिरता चाहेंगे क्योंकि वे शासक हैं। यद्यपि "पंचशील" का यह दर्शन राज्यों के तथाकथित आदिम राज्य-सीमा मानसिकता पर आधारित है जो मानवता व समूची मानव समुदाय की दुश्मन है। कम्पूचिया में पोलपोट शासन काल के समय हुए अदम्य हिंसात्मक गतिविधियों को तीन वर्षों से अधिक समय तक इसी तथाकथित "पंचशील" सिद्धांत के कारण रोका नहीं जा सका था और वियतनाम ने इसे रोक कर या हस्तक्षेप कर तथाकथित सिद्धान्तों के लिए चाहे गलती किया हो पर मानव जाति के लिए उचित कार्य किया। और इसका चीन व अन्य देशों द्वारा विरोध करना उनके व्यक्तिगत स्वार्थों का प्रतीक है।

उग्रवादी कम्पूचियाएँ कम्युनिस्ट चीन के तथाकथित चौकड़ी (गैंग ऑफ फोर) जैसे उग्रवादी वामपंथी नीतियों के अनुयायी थे। आज की मौजूदा चीनी सरकार ने इस चौकड़ी की तथा उनके द्वारा चीनी समाज में थोपी नीतियों की भरपूर भर्त्सना की है। उग्रवादी कम्पूचिया में चलाए जा रहे साम्यवादी प्रयोग पर चीन में हुए तथाकथित "महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति" का प्रभाव था। वर्तमान चीनी सरकार इस सांस्कृतिक क्रांति की भर्त्सना करते हुए इसे सौ प्रतिशत गलत बताती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के बावजूद चीन पोलपोट के अत्याचारी सरकार का समर्थन करता है, इसका मुख्य कारण - शक्ति प्राप्ति के लिए चीनी राजनीति है।

पेइचिंग आसियान देशों में सोवियत विरोधी भावनाओं का पूरा लाभ उठा रहा है, तथा वह आसियान देशों में अपनी राजनीतिक प्रभाव को मजबूत बना रहा है। पेइचिंग मास्को-हनोई के संयुक्त दुःसाहस के विरुद्ध आसियान की

राजनीतिक वार्ताओं का भरपूर समर्थन करता है, और इसके परिणामस्वरूप आसियान देशों में चीन की छवि तुलनात्मक रूप से अच्छी हुई है। रूस के अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के बाद रूस के बढ़ते खतरे के कारण आसियान देशों के बीच चीन की छवि का विकास हुआ है।

चीन वियतनाम को दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखता है। चीन वियतनाम के सोवियत संघ के साथ घनिष्ठता से भी परेशान है। उसे डर है कि वियतनाम इस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी प्रभाव को प्रतिघात न कर बैठे। वियतनाम के कामरान्ह खाड़ी में स्थित सोवियत सैनिक अड्डा, जो चीन का दक्षिणी सीमा क्षेत्र है, इस प्रकार की सोवियत मौजूदगी को चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।

चीन की वैदेशिक व आर्थिक नीतियों की परिवर्तनशील दिशा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विकासशील राजनीतिक संबंधों की संभावनाएं व बढ़ते व्यापार संबंधों की क्षमता से आसियान-चीन संबंधों के भविष्य का पुनर्निर्धारण होगा। इससे अतीत की अपेक्षा अधिक फलोत्पादक संबंधों की संभावना है। पर इस प्रकार की पुनर्निर्धारण की सफलता तभी संभव हो सकती है जब यह उचित समय पर बिना किसी दबाव के हो।

कम्पूचिया विवाद आसियान व चीन के बीच अस्थाई बातचीत का अवसर प्रदान करता है, परन्तु साथ ही साथ इसने दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय संरचना के विस्तृत समस्या को भी पैदा किया है। चाहे कुछ भी हो, आसियान-चीन संबंधों का भविष्य, कम्पूचिया समस्या के हल, जो सबको स्वीकार हो, पर निर्भर करता है।

आसियान देश अमेरिका व चीन के बीच संबंधों की सामान्यीकरण चीन-जापान मित्रता व शान्ति संधि को दक्षिण-पूर्व एशिया व विश्व के लिए काफी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। आसियान एशिया में चीन को एक संतुलनकारक के रूप में मानता है इसलिए वह उसे दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में सामान्य स्थिरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण समझता है।

आसियान को चीन के साथ घनिष्ठ संबंध रखना आसियान देशों के लिए काफी संवेदनशील तनाव है। आसियान देश अच्छी तरह जानते हैं कि केवल चीन ही वियतनाम को सबक सिखा सकता है फिर भी आसियान देश पूर्ण रूपेण सार्वजनिक रूप से चीन का पूर्ण समर्थन व सोवियत समर्थित वियतनाम की भर्त्सना नहीं कर सके। वह किसी तरह इन शक्तियों के बीच अपने को संतुलित करने का प्रयास करता रहता है। आसियान देश मास्को-हनोई संधि को और और कम्पूचिया के वर्तमान सोवियत-वियतनाम समर्थित हेंग सामरिन की सरकार को मान्यता देते हुए शान्तिपूर्ण व संतुष्टपूर्ण नीति का अनुसरण भी नहीं कर सकते।

आसियान छः संप्रभुता संपन्न राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें अलग-अलग राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपने विभिन्न हितों के साथ समाहित हैं। इसमें किसी की उपेक्षा नहीं किया जा सकता।

सिंगापुर व थाईलैण्ड वियतनाम से वर्तमान व भविष्य में दक्षिण-पूर्व एशिया की शान्ति व सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। वियतनाम रूस के विषय में थाई व चीन दोनों की दृष्टि एक जैसी ही है। थाईलैण्ड समझता है कि हिन्द-चीन के भाग्य निर्माण में चीन की निर्णयकारी भूमिका है। जबकि मलेशिया व इंडोनेशिया दूरगामी दृष्टिकोण से चीन को बुनियादी खतरे के रूप में देखते हैं। यद्यपि फिलीपींस साम्यवाद विरोधी है फिर भी वह उभयभावी है। चीन व हिन्द-चीन की मुख्य धरती से दूर होने के कारण फिलीपींस को कोई विशेष डर अथवा खतरे की संभावना नहीं है। सिंगापुर तथा थाईलैण्ड का विचार है कि चीन सोवियत समर्थित वियतनाम के विरोध में प्रतिरोधक के रूप में काम कर सकता है। मलेशिया व इंडोनेशिया का यह विश्वास है कि वियतनाम का किसी महाशक्ति से घनिष्ठ संबंध नहीं है तथा वियतनाम अपने राष्ट्रीय उत्थान में लगा हुआ है जिससे समस्त दक्षिण-पूर्व एशियाई देश सुपरिचित हैं। इन विरोधाभासी दृष्टिकोण के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में आसियान देश कम्पूचिया के प्रश्न पर सामूहिक हल ढूंढने में एक जुट रहे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कम्पूचिया प्रश्न को आसियान ने "विश्व-व्यापी" बना दिया। आसियान ने कम्पूचिया पर वियतनामी आक्रमण के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक क्षेत्र में नैतिक विजय की प्राप्ति की, तथा वियतनाम की कम्पूचिया से बाहर चले जाने के पक्ष में विश्व जनमत प्राप्त किया। आसियान के इन समस्त गतिविधियों में चीन सदैव आसियान का समर्थन करता रहा।

यद्यपि चीन ने आसियान के तीन सदस्य देशों मलेशिया, फिलीपींस व थाईलैण्ड के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना 1974-75 में कर ली थी और चीन के सिंगापुर के साथ राजनयिक संबंधों के अतिरिक्त अन्य संबंध काफी अच्छे रहे। फिर भी दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के दूरगामी उद्देश्यों को भांपना काफी सन्देहपूर्ण व कठिन कार्य है।

पिछले वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया एक ऐसा क्षेत्र रहा है, जिसमें न सिर्फ साम्यवादी चीन की रुचि रही है, बल्कि यह महाशक्तियों को आकर्षित करने वाला एक केन्द्र रहा है। यह क्षेत्र यहाँ के देशों के मध्य होने वाली खींचातानी के कारण भी विश्व व्यापी संघर्ष को नया स्वरूप प्रदान करता रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया प्रशांत व हिन्द महासागर के बीच स्थित अपनी प्राकृतिक संपदा के कारण काफी संपन्न है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए चीन, अमेरिका व सोवियत संघ के विश्व व्यापी रणनीति का केन्द्र बना हुआ है। अध्ययन अवधि में इस क्षेत्र में सोवियत आक्रामक तथा चीन व अमेरिका रक्षात्मक स्थिति में हैं।

चीन के नए राजनीतिक व कूटनीतिक मानसिकता के कारण अगर सोवियत-चीन के बीच तनाव शैथिल्यता हुआ या काफी अच्छे संबंध हो गए तथा अमेरिका-चीन संबंध में कोई विशेष क्रांति न भी हुई तो भी इसका प्रभाव आसियान -चीन संबंधों पर नहीं पड़ने वाला। इसका कारण चीन की राष्ट्रवादी मानसिकता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच रणनीतिक संबंध पड़ते हैं तो

आसियान देश बड़ी शक्तियों की भूमिका के बारे में दूरगामी निर्णय लेंगे।

आसियान व चीन समझते हैं कि वे सोवियत संघ के सैनिक घेरे में दिन-प्रतिदिन आते जा रहे हैं। इसलिए वे चीन के साथ अपने संबंधों को दक्षिण-पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन, शान्ति व स्थिरता के लिए काफी महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

नए परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में चीन जो न केवल राजनीतिक व सैनिक रूप से सशक्त है अपितु एक उभरता हुआ आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश भी है, के साथ आसियान का कैसा रवैया होना चाहिए यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। — आसियान देशों में चीन के बारे में कुछ संदेह हैं तथा उनके विचारों में भिन्नताएं हैं -- क्या चीन का आधुनिकीकरण मानसिकता अपनी वैचारिक व राजनीतिक प्राथमिकताओं को त्याग देगा या वह इन उद्देश्यों को और अधिक मजबूत बनाएगा ? क्या आसियान को चीन का पक्ष लेने पर विवश किया जाएगा या चीन आसियान के "ज़ोपफान" प्रस्ताव को अनदेखा कर देगा और व्यापार व आर्थिक सहयोग पर अधिक बल देगा ? इन सबका उत्तर न केवल चीन पर निर्भर करता है बल्कि आसियान पर भी निर्भर करता है।

आसियान देशों के बीच परस्पर निर्भरता हिन्द-चीन समस्या से अधिक प्रेरित हुई है। आसियान देशों को सहयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने चाहिए जो उनकी मजबूती, परस्पर निर्भरता व घनिष्ठ संबंधों में योगदान दे सके।

कम्पूचियाई समस्या के उचित समाधान हेतु दो दृष्टिकोण हैं - शीघ्र व अल्प समय समाधान तथा लम्बी अवधि समाधान। शीघ्र समाधान के लिए हिन्द-चीन देशों को आसियान देशों के संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव को मान लेना चाहिए इससे सभी वर्गों को संतुष्टि मिल सकती है, अन्यथा लम्बी अवधि समाधान, जिसमें चीन की विशेष रुचि लग रही है, इस विवाद के

सम्बन्धित सभी वर्गों को तनाव की स्थिति में रखते हुए इस पूरे क्षेत्र की सैनिक गतिविधियों व प्रतिस्पर्धाओं के कुचक्रावर्त में फंसा सकता है। कम्पूचियाई समस्या जितना ही अधिक समय तक चलता रहेगा उतना ही अतिसंवेदनशील आसियान देशों के घरेलू राजनीति पर असरदार प्रभाव पड़ता जायेगा। आसियान व वियतनाम कम्पूचियाई प्रश्न पर अपनी-अपनी विचारों से चिपके हुए हैं पर यह तो स्पष्ट है कि अगर कम्पूचियाई समस्या का समाधान करना है तो निश्चित रूप से आसियान व वियतनाम को अपनी नीतियों में नरमी लानी होगी।

चीन व वियतनाम के नेता काफी उम्र के हैं, दोनों देशों के नेताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अगर फिर से दोनों देश मित्र हो गए तो पूरी नयी स्थिति आसियान देशों के विपरीत होगी। परन्तु चीन व वियतनाम के बीच इस प्रकार के पूर्ण पुनर्संबंध की संभावना काफी कम है। दक्षिण-पूर्व एशिया में व विशेषकर हिन्द-चीन में अशांति का मुख्य कारण सोवियत- चीन विवाद व तनाव है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक विकास न केवल दक्षिण-पूर्व एशियाई लोगों के लिए अपितु पूरे विश्व के स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। दक्षिण-पूर्व एशिया समकालीन विश्व राजनीति में महान विशेषता का क्षेत्र है। अगर कम्पूचियाई समस्या का उचित समाधान नहीं हुआ तो यह क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय तनाव का स्रोत बना रहेगा।

---oo00000ooo---

स न्द र्भि का

PRIMARY SOURCES:

ASEAN DOCUMENTS, ASEAN National secretariat Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 1979.

ASEAN, Jakarta : Department of Foreign Affairs, ASEAN National Secretariat of Indonesia, August 1975.

Asian Recorder (New Delhi).

Kampuchea in the seventies, Report of a Finish Inquiry commission, Helsinki, 1982.

Keesing's Contemporary Archives (Longman, London).

New War in South east Asia, Documents on Democratic Kampuchea and the current struggle for National Independence, Produced by Kampuchean Support Committee, New York.

10 Years ASEAN, Jakarta : ASEAN Secretariat, April, 1978.

SECONDARY SOURCES:

=BOOKS

Alison Broinowski (Ed.) Understanding ASEAN, (The Macmillan Press Ltd., Hongkong 1982.)

Allen Richard, A Short Introduction to the History and Politics of Southeast Asia, (Oxford University Press, London, 1970)

Anand, R.P. (Ed.) ASEAN Identity, Development and culture, (University of the Philippines law Centre And East-West centre culture Learning Institute, 1981).

Andreyev, N.A., Overseas Chinese Bourgeoisie-A Peking Tool in South East Asia, (Progress Publishers, Moscow, 1974).

Arnfinn Jorgensen- Dahl, Regional Organization and Order in Southeast Asia (The Macmillan , Hongkong, 1982.) pp.

Attarchand, Southeast Asia and the Pacific- A selected Bibliography 1967-77, (sterling publications, New Delhi).

Bastin, John and Harry, J. Benda, A History of Modern South-East Asia (New York : Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1968).

Bernhard Dahm, Werner Draguhn (eds), Politics, Society and Economy in the ASEAN States (Hamburg, 1975).

Brian Harrison, South-East Asia : A short History, (Macmillan, London, 1963),

Bruce Grant, The Security of South - East Asia, (The International Institute for Strategic Studies London, 1978).

Brugger, B. China: Radicalism to Revisionism, 1962-79, (London,1981)

Burchett, Wilfred, The China, Cambodia, Vietnam Triangle, (London: Vanguard Books, Chicago and Zed Press, 1981).

Butwell, Richard A, Southeast Asia- A political Introduction (Praeger Publishers, New York, USA, 1975).

Butwell, Richard, Southeast Asia Today and Tomorrow, Problems of Political Development (London: Pall Mall Press, 1969)

Cady, John F., Southeast Asia, Its Historical Development (New York: McGraw-Hill Book Company, 1964).

Cady, John F., The History of Post war Southeast Asia, (Ohio, Athens, 1974).

Chawla, Gurtov and Marsot, (ed.), South-east Asia under the New Balance of Power, (New York; Praeger Publ., 1974).

Choudhury, G.W., China in World Affairs: The Foreign Policy of the PRC Since 1970 (Colorado: West view Press, 1982).

Chun-tu Hsueh, (ed.) China's Foreign Relations, (Praeger Special studies, USA, 1982)

Clark, Gregory, In Fear of China, (Barrie and Rockliff, The Cresset Press, London, 1967)

Daljit Sen Mal, China And Her Neighbours. A Review of Chinese Foreign Policy, (New Delhi, 1984)

Davidson, J. Indo-China: Signposts in the Storm (Berhard: Longman, 1979)

Devillers, Philippe, The Present and Future of the Socialist Bloc in Indo-China (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1980)

Dick wilson, neutralization of Southeast Asia, (New York: praeger, 1975).

Dobby, E.H.G., South east Asia, (University of London Press Ltd., London, 1950)

Elliott, David, W.P. (ed.), The Third Indo-China Conflict. (Colorado: Westvies Press, 1981).

Estrella D. Solidum, Towards A southeast Asian Community, (University of the Philippines Press, Quezoncity, 1974).

Fifield, Russell H., National and Regional interests in ASEAN Competition and Co-operation in internationa politics. occasional paper No.57, (Institute of South East Asian Studies, Singapore, 1979

Fitzgerald C.P., China and Southeast Asia Since 1945, (Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Delhi- 1975).

Fitzgerald, C.P., The Third China. The Chinese Communities in Southeast Asia, (London, 1965).

G, Coedes, The Making of South East Asia, (London 1966)

Greg O'Leary, The Shaping of Chinese Foreign policy, (Croom Helm London 1980)

Gurtov, Melvin, China and Southeast Asia (Oxford University Press London, 1969).

Hans H. Indorf, ASEAN: Problems and Prospects, (Institute of Southeast Asian Studies, occasionnl paper No.38, December, 1975, Singapore)

Harold C. Hinton, Communist China in World Politics (Boston: Houghton Mifflin, 1966)

Harold C. Hinton, Peking-Washington: Chinese Foreign Policy and the United States (London 1976)

Harold C. Hinton, Three and A Half Powers: The New Balance in Asia, (London, 1975).

Hsin Shi - ching, Chinese- Philippine Diplomatic Relations-1946-1975 (Bookman Printing House Quezon City, 1975).

J.A.C. Mackie, (Ed.) The Chinese in Indonesia (The University Press of Hawaii, Honolulu, 1976)

Jain, R.K., China and Malaysia, 1949-1983, (Radiant Publishers, New Delhi, 1985)

Jain R.K., China and Thailand, 1949-1983, (Radiant Publishers, New Delhi, 1984).

Jay Taylor, China and Southeast Asia Peking's Relations with Revolutionary movements (USA-1976).

Jha, Gangnath, Foreign Policy of Thailand (Radiant Publishers, 1979, New Delhi.)

Joo Kyu Park, Melvin Gurtov (Ed.), South east in Transition: Regional and International politics (The Institute For Eastern studies, Seoul, Korea. 1977)

Jorgensen-Dahl, Arnfinn, Regional Organization and order in Southeast Asia. (The Macmillan Press Ltd, London 1982)

Jurgen Domes (Ed.), Chinese Politics After Mao (University College cardiff Press, Great Britain-1979)

Kahin, George M. (Ed.), Government and politics of South East Asia (New York: Cornell University Press, 1959)

Khaw Guat Hoon, *An Analysis of China's Attitudes Towards ASEAN, 1967-76* (ISAS, Singapore, Occasional Paper No.48, Sept.77)

Lea E. Williams, *Southeast Asia: A History*, (Oxford University Press, New York 1976)

Lyman M. Tondel, Jr. (Ed.) *The Southeast Asia Crisis*, (The Association of the Bar of the City of New York - 1966)

Malaviya H.D., *Peking Leadership, Treachery and Betrayal*, (New Literature Delhi, 1979)

Martin , Edwin W., *Southeast Asia And China : The End of Containment*, (West view Press, Boulder, Colorado, 1977)

Michael Leifer, *Indonesia's Foreign Policy* (The Royal Institute of International Affairs by George Allen and Unwin 1983)

Michael Yahuda, *Towards the End of Isolationism: China's Foreign Policy After Mao* (The Macmillan Press Ltd. HongKong, 1983)

Mukerjee, Dilip, *Kampuchea: ASEAN RESPONSE TO GREAT Power Rivalries*, (Programme forstrategic And International Security Studies Occasional papers, No.3, Switzerland, 1983.

Osborne, George K. *Balance of Power in South-East Asia*, (Institute of South-East Asian Studies: occasional paper No.53 (1978

Osborne, Milton, *Before Kampuchea: Preludes to Tragedy* (North Sydney: George Allen and Unwin, 1979)

Pandey, B.N., *South and South-East Asia, 1945-79 , Problems and Policies*, (New Delhi, 1980)

Peter S.J. Chen (Ed.), *Singapore Development Policies and Trends*, (The Institute of Asian Affairs in Hamburg, Oxford University Press Oxford, 1983)

Progress Publishers, *Peking Reached out: A study of Chinese Expansionism*, (Moscow 1979)

Purcell, Victor, The Chinese in Malaya, (London, 1948)

Purcell, Victor, The Chinese in Southeast Asia, (2nd Edn. London, 1965)

Ray, Hemen, China's Vietnam war, (Radiant Publishers, New Delhi 1983)

Robert G. Sutten, Chinese Foreign Policy after the cultural Revolution, 1966-1977, (West view Press, Boulder, Colorado 1978)

Robert O'Neill (Ed.), Security in East Asia, Adelphi Library 9 (The International Institute For Strategic Studies, Great Britain, 1984)

Roger M. Smith (Ed.), South East Asia (Documents of Political Development and Change), (Cornell University, London, 1974)

Ross Terrill, The Future of China After Mao, (New York, 1978)

R.S. Chavan, Chinese Foreign Policy (Sterling Publishers Pvt.Ltd. New Delhi, 1979).

Sardesai (D.R.), Indian Foreign Policy in Cambodia, Laos, and Vietnam(1947-1964) (Berkeley, California 1968)

Sardesai, D.R., South East Asia : Past and Present, (Vikas Publ. House Pvt. Ltd. New Delhi. 1981)

Simon Sheldon W., ASIAN NEUTRALISM AND US.POLICY.(American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C., 1975, Aug.)

Simon, Sheldon W., The ASEAN STATES AND Regional Security, (Hoover Press, California, 1982)

Simon, Sheldon W., The Broken Triangle: Peking, Djakarta, and the PKI (Washington, 1969)

Simonov, Vladeimir, Kampuchea: Crimes of Maoists and their Rout (Moscow Novosti Press Agency Publishing House, 1979).

Singh, Lalita Prasad, Power Politics and Southeast Asia, (Radiant Publishers, New Delhi, 1979)

'Social Sciences Today' Editorial Board USSR Academy of Sciences, South-East Asia: History and the Present Day (Oriental Studies in the USSR, 1984)

[illegible]

Speed, F.W., The South-East Asian Peninsula Today, (Allgus and Robertson, London, 1970)

Sudershan Chawla and D.R. Sardesai (Ed.) Changing Patterns of Security and Stability in Asia (Praeger, New York 1980)

Justus M. Vander Kroef, Communism in South east Asia (Berkeley University of California Press, 1981)

Williams, L., The Future of the overseas Chinese in Southeast Asia (N.Y., 1965).

Zasloff, Joseph, J. and Mc. Alister Brown(Ed.) Communism in Indo-China (Massachusetts: D.C. Heath and Co., 1975)

ARTICLES IN PERIODICALS:

"A Bridge to China" Asiaweek,(Hong Kong),14 Apr. 1979, pp.26-32.

"A friend in deed", Far Eastern Economic Review (FEER), (Hong Kong) 22 Feb.80, pp.8-9.

Adam Malik,"Indochina and the Domino Theory" Summary of World Broadcasts, Second Series FE/4880,17 Apr. 1975. A3/1

Adam Malik,"On Peaceful Coexistence Between ASEAN and Indo-China" Asian Pacific Community (Tokyo), Summer, 1978, p.4.

Ahmad, Zakaria H. "The Pacific Basin and ASEAN: Problems and Prospects." Contemporary Southeast Asia (Singapore)2(4) March 1981, pp.332-41.

Alejandro Melchor, Jr, "Assessing ASEAN's viability in a changing world", Asian Survey (Berkeley ,Cal) Apr. 1978, p.422

Arfinn Jorgensen- Dahl, "ASEAN 1967-1976: Development or stagnation", Pacific Community, (Tokyo) July 1976, pp.519-535.

Arora, B.D., "Indo-China, ASEAN and Great Powers", Mainstream (New Delhi) Vol.xxii No.28, March 10, 1984, pp.29-31

"ASEAN and China: Marching together, out of step." Economist (London) 22 March'80 , p.42.

ASEAN'82 Focus, FEER, 13 Aug. 1982.
"ASEAN: Seeking a Zone of peace and Neutrality", Beijing Review, 12 Aug. 1977, pp.45-46.

"ASEAN Tycoons in China", Asia Week, (HONGKONG) 15 Aug. 1980, pp.40-pp.40-41.

Bedeski, Robert E," ASEAN in the wake of Vietnam: The Road to Bali and Beyond", International Prospective (Ottawa) Nov.-Dec. 1976, pp.12-18.

Berindranath, Dewan Zhao visits ASEAN Democratic World (New Delhi) 10(34), Aug.23, 1981, pp.5-6, 18.

Bhattacharya, S.S.,"ASEAN AND INDO-CHINA", News Bulletin on Japan, Southeast Asia and Australasia, Institute of Defence Studies and Analyses, (IDSA) New Delhi, April, 1976, pp.320-323.

Bhattacharya, S.S.,"ASEAN and Kampuchean Issue", Strategic Analysis (IDSA, New Delhi) 4(8); Nov. 1980, pp.365-72.

-- "The impact of vietnam on ASEAN", News Bulletin on Japan, Southeast Asia and Australia, (IDSA, New Delhi) June, 1975, p.459.

Cane, Barry,"China Looks South" Newsweek, (New York),27 March 1978, 18.

Chanda, Nayan," A curious parallel over the cork in the bottle" FEER, 7 March 80, pp.42-43.

Chanda, Nayan," A subtle approach from Hanoi". FEER, 8 Feb.1980, p pp.17-18.

Chanda Nayan, "Hanoi's Bid to woo ASEAN; No Headway" Times of India (TOI), New Delhi, 11 Feb. 1980.

Chanda, Nayan," Putting the Heat on ASEAN", FEER, 13 Jan.1980,p.14

Chanda Nayan,"The China-Kampuchea-Vietnam Triangle" FEER, 18 Apr. 1980, pp.8-20.

Chandola, Harish," ASEAN: After Bali", Economic and Political Weekly (Bombay), p.529.

Chang,C.Y., ASEAN'S Proposed Neutrality: China's Response" Contemporary Southeast Asia (ISEAS) Singapore 1(3),Dec.1979, pp.249-67.

Chang Pao-min,"Beijing versus Hanoi: The Diplomacy over Kampuchea" Asian Survey,(Berkley) V.23 No.5, May 1983, pp.598-618.

Chang Ya-Chun, " Chao Tze Yang's Visits to Three ASEAN Countries". Issues and Studies (Taipei) 17(9):Sept.1981, pp.9-12.

"China: A Diplomatic Blitz" Newsweek (New York), 6 Feb.1978, pp.7-8.

"China Looks South" Newsweek, 27 March 1978, p.18

"China'77 Focus, FEER, 98(40), 7 Oct.1977.

"Chinese and Thai Ministers Discuss Kampuchea" The Times, (London), 30 July 1980

Choudhury, G.W.," ASEAN and the Communist world" Asia Pacific Community (Tokoyo), (13), Sept.1981; pp.34-49.

Das.K., " Peking Sends out a hawk", FEER, 28 March 1980, pp.15-16.

Das, K. "Searching for signs of a thaw" FEER, 25 Jan.1980, pp.28-30.

दास, परिमल कुमार, " रशिया का हवलदार ", दिनमान (नयी दिल्ली), 11 मार्च, 1979, पृष्ठ- 33-35 ।

Das, Parimal Kumar, "Philippines: Mao Ka Ghat Ka ASAR", Dinman, 26 Feb., 4 March 1978.

David Jenkins, " China's secreta wooing of Jakarta," FEER. Feb.15, 1980, p.16-17.

David, S.G. Goodman," China after Chou" The world Today (London) June 1976, pp.203-213.

David S.G. Goodman," China: The Politics of Succession", The world Today April, 1977, pp.131-140.

Dennis Duncanson," China's Vietnam war . new and old Strategic imperatives," The world Today, June 1979, pp.241-248.

Denzil Peiris," Sympathy from the Hanoi Communists", FEER, (Hong Kong), Aug.26, 1977 p.40.

"Despite Anxieties, Bright Prospects" Asia Week (Hong Kong) 18 Apr. 1980, 42-44.

Dick Wilson, " ASEAN and Indo-China: Future Relations", Asian Pacific Community (Tokeyo) Summer, 1978, p.16-33.

"Diplomatic BLUES in Peking" Times (New York) 6 Feb. 1978, p.10

Eads, Brian."Why Thais Support Peking" Observer (London) 6 May 1979.

Editorial, " Colombo to Havana", Patiot (New Delhi), 12 June 1979.

Eiland, Michael," Rivalry for Cambodia - an old affair", FEER, V.122, No.45, 10 November, 1983, pp.50-52.

Millthorpe, H. "ASEAN fears about Peking-Hanoi Flare-up", Indian Express,(New Delhi), Jan.19, 1979.

Millthorpe, H."Chinese dilemma in S.E. Asia", Indian Express, 24 May, 1979.

Millthorpe,H. "Russia-China Rivalry Threat to Asian Peace", Indian Express, Jan. 2, 1979.

Engaging Talk" Asia Week (HongKong) 1 July 1977, p.16.

Fifield, Russell H. "ASEAN: Image and Reality," Asian Survey, 21(12) Dec. 1979, pp.1199-1208.

Fifield Russell H." ASEAN, KAMPUCHEA AND THE UNITED NATIONS" Asia Pacific Community (Tokyo), No.2, Summer 1982, pp.74-88.

Fifield, Russell H.," ASEAN: The Perils of viability". Contemporary Southeast Asia, 2(3), Dec. 1980, pp.199-211.

Fish, Peter, " Children the Key to Thai Integration" FEER, 100(24) 16June 1978, p.23.

Frost, Frank, "The Origins and Evolution of ASEAN" World Review (Queensland) August, 1980.

"Fruitful ASEAN Foreign Minister Meeting", Beijing Review(Beijing) 23(27), July7, 1980.

Funnell, Victor C,"China and ASEAN: The changing face of South East Asia", The World Today, 31(7): July 1975, pp.299-306.

Funnell, Victor C, " China and South east Asia: The new phase", The world Today, 28(8); Aug. 1972, pp.334-341.

Funnell, Victor C,"Development of relations between China and the ASEAN Countries", Spectrum, 3(4); July 1975, pp.20-27.

Galbraith, Francis J.,"ASEAN Today: feeling the heat", Asian Affairs (London) 8(1), Sep. -Oct. 1980, pp.31-40.

Getting it straight" Asia week, 14 March 1980, p.15.

Ghosh, S.K., "Rivalry in the South China Sea," China Report(New Delhi) 13(2), Apr. 1977, pp.3-8.

"Giving Wing to ASEAN", Asia Week, March 10, 1978, pp.45-47.

Glom, John," ASEAN and the United States: Partners for progress and security". Indonesian Quarterly (Jakarta) 8(4),Oct.1980,pp.21-27.

Gong, G.W., "Propblems and Prospects in Cultural and Regional Interactions:The case of ASSAN" Contemporary Southeast Asia, 2(1), June 1980, pp.41-49.

Gordon, Bernard K., "Southeast Asia View of China", Current History, (Philadelphia) 55(325), Sep. 1968, pp.165-169.

Heaton, William R. "China and Southeast Asian Communist movements: The decline of dual track diplomacy" Asian survey 22(8), Aug.1982, pp.779-800.

Howarth, H.M.F.,"ASEAN Perceptions of vietnam", International Defence Review (Geneva), 16(7), 1983, pp.925-926.

How Moscow Lost its Lead," Asia Week, 21 March 1980, pp.22-23.

"Huang Draws Blank with ASEAN" Patriot (New Delhi),1st Apr. 1980.

Hyman, Gerald Franklin "Southeast Asia: ASEAN and its Communist neighbours", Worldview 26(1), Jan.1983, pp.15-17.

Jenking, David,"Indonesia: Too many Congs and Lees" FEER , 100(24), 16 June 1978, pp.22-23.

Jerry Mark Silverman,"The Domino Theory: Alternatives to A self-Fulfilling prophecy", Asian Survey, Nov. 1975, pp.915-939.

J.L.S. Girling,"Southeast Asia in 1978: A Political Overview", Southeast Asian Affairs 1979(ISEAS, Singapore, 1979).

Joint Communique Conference of the Foreign Minister of Vietnam, Laos and Kampuchea, Vietnam Courier (Hanoi),2/1981 Vol.17, pp.1-3.

Joint Statement (Extract) after the meeting of Sihanouk, Son Sann and Khieu Samphan in effort to establish a coalition Gov. for Kampuchea, Singapore, 4 Sept. 1981, Asia Week 18 Sept.1981, pp.13-14.

Jorgen Sen-Dahl, Arnfinn,"The Significance of ASEAN", World Review Vol.19, No.3 (Queensland) August 1980, pp.55-59.

Judge, Paul Quinn, "ASEAN Seeks Moderates for Kampuchea", The Guardian (London), 28 Jan. 1981.

"Kampuchea"Enough! " Asia Week, 28 Nov. 1980, pp.35-38.

Karki Hussain, T.,"Duel ASEAN Stand on Kampuchea", TOI, 3 March,1983.

Kaul, T.N." Lang Son, The Waterloo of Chinese Hegemony," Patriot(New Delhi), 3 June 1979.

Kausik, B.M., Bali Summit, China Report, March-Apr. 1976, pp.16-20.

Khaw Guat Hoon," Recent Developments in China- ASEAN Relations", Southeast Asian Affairs, 1979, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, pp.61-71.

"Khmer Rouge Offensive" Asia Week, 21 March,1980, pp.10-12.

Lau Teik Soon,"ASEAN And Bali", Pacific Community, July 1976, pp.536-50.

Lau Teik Soon,"ASEAN and the Kampodian Problem", Asian-survey, Vol.22,(6), June 1982, p.548-560.

Lau Teik Soon, " South east Asia in the New Power Situation", Pacific Community, Oct(Tokyo), Oct.1975.

Lee Kuan Yu, "ASEAN; Greater capacity for Cohesiveness" Mirror, (Singapore), 12(10), March8, 1976, pp.1-3.

Lee Kuan Yew, Interview, Spoke on meeting of Kampuchean factions on formation of a united front against Vietnam, Singapore, FEER, 23 Oct. 1981, pp.19-20.

Leighton, Marian, "Vietnam and Sino-Soviet rivalry", Asian Affairs (London), 6(1), Oct. 1978, pp.1-30.

Leo Suryadinata, "ASEAN and China: Security, expediency, or both?" FEER, 120(22), 2 June, 1983, pp.40-1.

Leo Suryadinata, " Indonesia, A year of continuing Challenge", Southeast Asian Affairs 1979, Singapore, 1979, pp.105-18.

Leo Suryadinata, " The Chinese Minority and Sino-Indonesian-Diplomatic Normalization", Journal of Southeast Asian Studies, Vol.XII, (1), March 1981.

Mc Beth, John. "Peking prepares to dump pol.Pot" FEER, 6Feb.1981, pp.8-11.

M.Ghazali bin Shafie, "On the Domino Theory", Pacific Community, Oct. 1975, pp.55-64.

Michael B. Yahuda, " Chinese Foreign Policy after Mao", The World Today, (London) April, 1977, pp.141-43.

Michael B. Yahuda, "Chinese Foreign Policy after the victories in Indochina", The world Today, (London) July 1975, Vol.31(7), pp.291-98.

Michael B. Yahuda, "Modernization and Foreign Policy in China", The world Today Nov.1980, pp.445-51.

Michael Leifer, " China and Southeast Asia", Pacific Community, Oct. 1977, pp.84-95.

--- "Post mortem on the Third Indochina war", The World Today, June 1979, pp.249-58.

--- "The Security of Southeast Asia", Pacific Community V.7, Oct. 1975, pp.14-27.

Morello, Ted,"A Question of Principle" FEER, 17 Oct. 1980, pp.13-14.

Mukerjee, Dilip,"Real Threat to S.E. Asia from Russia:Leo" TOI, 26 Aug. 1980.

---; "Rift in ASEAN over Kampuchea", TOI, 12 Dec. 1979.

---; "Singapore's Deal with China" , TOI, 11 Feb.1980.

---; "Thiland Sides with China", TOI, 12 May 1979.

Nagorski, Andrew," East VS. East, News Week, Jan.1, 1979, pp.30-31.

Nations, Richard,"Removing a block on the road to Hanoi," FEER, 4 Apr. 1980.

Nations, Richard and K.Das,"The Season of Goodwill", FEER, 98(51), 23 Dec. 1977, pp.10-12.

Norodom Sihanouk "A Letter to the U.N.O. on International Conference on Kampuchea and his peace plans, Paris" Indian Express, 30 July 1981.

"Peking Boils the Pot" Asia Week, 7 March 1980, pp.8-9.

Ping, H. Kwon,"Singapore Takes up Peking's Challeng", FEER, 14 Sept. 1979, pp.38-42.

Ping, Ho Kwon and Hye Cheah Cheng " Five Fingers on the tringger" FEER, 110(44) Oct.24, 1980, pp.32-7.

Rajagopal, D.R., " South-East Asia: The Chinese Shadow" Link(New Delhi) 26(1) Aug.15, 1983, pp.141-147.

Ramachandran, K.N.," Beijing, Hanoi, and Sotheast Asia", Strategic Analysis, (IDSA, New Delhi) 3(10), Jan.1980,pp.363-66.

Raul A. Manglapus," ASEAN, The Natural Community", Asia Pacific Community, No.2, Fall 1978, pp.43-55.

• [illegible], " Correct Approach for Solving Sino-Vietnamese Dispute", Beijing Review, 22(4), 4 May 1979, pp.18-20.

Rithauddin, Tengku Ahmad, " The Kampuchean Problem and the Non-Aligned Movement." Contemporary Southeast Asia (ISEAS) 1(3), Dec. 1979, pp.205-10.

Robert L. Rau," Normalization with PRC with Emphasis on ASEAN States", Pacific Community Vol.7(2) January 1976, pp.230-247.

Roesnadi, O. Sutomo," ASEAN and the great powers," India Quarterly (New Delhi) July, 1973.

Romulo, Carlos,"Big Power Currents will Test ASEAN", Asia Week, 25 Jan. 1980, pp.37-38.

Sambandan,V.T.,"Hanoi for Non-aggression Pact with ASEAN." The Hindu (Madras), 4 Apr. 1980.

Sanittanont, Sura,"China's Modernisation Programme and its Impact on ASEAN". Asia Pacific Community, 6, Fall 1979,pp.56-71.

Sacerdoti, Guy,"Asean's Common Stand," FEER, 28 May 1982,pp.62-63.

Shee Poon-Kim, " A Decade of ASEAN, 1967-77", Asian Survey 17(8); Aug.1977, pp.753-770.

Shears, Benjamin, "ASEAN responds to New Challenges", Mirror 12(6), Feb.9, 1976, p.1.

Shih-fu,Lo,"Peiping's current Strategy Toward Cambodia" Issues and Studies (Taipei) 17(5) May 1981, pp.57-69.

———; "Peiping's new Scheme for ASEAN Nations", Issues and Studies, 11(3), March, 1975, pp.43-57.

Shinde, B.E.," Outline of History of Kampuchean Communism", China Report, Jan. 1982.

----; "Sino-Vietnamese Relations 1950-78" China Report, 17(3), May-June 1981, pp.13-32.

Sin, Yon Soon," China's Relations with South East Asia. A Review" Asian Profile, Apr. 1977, pp-103-110.

Simon, Sheldon W.,"China, Vietnam, and ASEAN : The Politics of Polarization". Asian Survey, 21(12), Dec.79, pp.1971-88.

Simbayon, Holly," Manila flies the flag of unity" FEER, 100(24), 16 June, 1978, pp.23-24.

Singh, Vishal," China and Southeast Asia", China Report, Vol.4,No.3, June 1968, pp.18-20, 28.

----; "Southeast Asia: The threat from China", World Focus 3(6); June 1982; pp.19-21.

Sir Robert Thompson," Southeast Asia after Vietnam", Pacific Community Vol.7, (1-4) Oct.1975, pp.1-13.

"Social- Imperialist Strategy in Asia." Beijing Review, No.3, 19 Jan. 1979, pp.13-16.

Soon, Lau Teik," ASEAN and the Cambodian Problem", Asian Survey 22(6), June 1982, pp.548-60.

Stockwin, Harvey," China's Efforts to woo ASEAN" I,II and III, TOI, 27,28,29 Aug. 1981.

Stuart Drummond," ASEAN: the growth of an economic dimension", The World Today, Jun.1979, pp.31-38.

Suryanarayan,V." China and Insurgency in Malaysia," IDSA Journal, Apr.- June 1978, pp.368-91.

Tocker, Rodney," A game of friends and neighbours, FEER, 100(26), 30 June 1978, pp.18-21.

---; "Buttressing the ASEAN buffer", FEER, 99(12), 24 March 1978, p.13.

---; "Indochina, Hugs but no Kisses", FEER, V.123, No.6, 9 February, 1984, p.14.

---; "Quest for peaceful co-existence Vietnam's troubles fuel hopes of a Kampuchea Settlement", FEER Vo.107, No.9; Feb.29, 1980, pp.8-11.

---; "Stopping any Shade of red" FEER, 24 Aug.1979,pp.24-28.

"The Day China came Courting", Asia Week, 28 March 1980, pp.12-13.

Tunku Abdul Rahman," The Communist Threat in Malyasia and Southeast Asia", Pacific Community vol.8(4), July 1977, pp.561-574.

"U.N. Security Council Discusses Vietnam's Invasion of Kampuchea" Beijing Review, No.3, 19 Jan. 1979, pp.10-12.

Vander Kroef Justus,M;"ASEAN Hanoi, and the Kampuchean Conflict: Between," Kuantan" and a Third Alternative," Asian Survey, May 1981, pp.515-35.

---; "ASEAN in the 1980's" World Review, 19(3), Aug. 1980, pp.60-70.

---; "ASEAN: The view from Hanoi, Moscow and Peking", Contemporary Asia Review 1, No.1 (1977).

V ---; "Hanoi and ASEAN: A New Confrontation in Southeast Asia." Asia Quarterly (Brussels), (4) 1976, pp.245-69.

---; "Hanoi and ASEAN: Is Co-existence Possible?" Contemporary Southeast Asia," (ISEAS), 1(2), Sept.1979, pp.164-78.

---; "S.E. Asia after the Vietnam War: Security Problems and Strategies", Pacific Community , April,1976, pp.377-405.

---; "Kampuchea: The Diplomatic Labyrinth", Asian Survey, Vol. XXII(10), Oct., 1982, pp.1009-1030.

---; "The Kampuchean Problem: Diplomatic Deadlock and Initiative", Contemporary South East Asia, Vol.5, Nov.3, Dec. 1983, pp.263-292.

---; "The United States and the Cambodian Problem: Political Realities and Policy Options", Asian Affairs (London) (Nov.-Dec. 1981), pp.69-84.

Victor C. Funnell, "CHINA and ASEAN: The changing face of Southeast Asia", The world Today (London) July, 1975, Vol.31 No.7, pp.299-305.

Wanandi, Yusuf," An Indonesian view" (Kampuchea and ASEAN's Option) FEER, 28 March 1980, p.16.

---; "ASEAN's New Era", Newsweek, 17 Oct. 1977, p.9.

Watts David," ASEAN fears support for Pol Pot regime May crumble at UN." The Times (London), 16 Sept. 1980.

Werner Draguhn," The Indochina Conflict and the Positions of the Countries Involved," Contemporary Southeast Asia, Vol.5(1), June, 1983, pp.95-116.

"What's in it for ASEAN" Asia Week, 19 Sept. 1980, pp.18-19.

Yu, Chun, Chang," Communist China and South East Asia" Issues and Studies, (TaiPei) 18(3), March 1982, pp.60-77.

Yee, Herbert S." Asia Policy Options in the 1980s". Asia Pacific Community, Spring 1981, pp.101-24.

Yeh Po- Tang, "Communist China's Foreign policy Toward ASEAN," Issues and Studies, 16(11), Nov. 1980, pp.20-35.

Yoon, Suthichai," A Lesson for Moscow", Asia Week, 17 Aug. 1979.

NEWS PAPERS:

Bangkok Post

China Daily (Beijing)

Indian Express (New Delhi)

Indonesia Times (Jakarta)

Mainichi Daily (Tokyo)

Malaysia Daily (Kuala Lumpur)

Patriot (New Delhi)

Renminribao (Beijing)

The Hindu (Madras)

The Hindustan Times (New Delhi)

The New Straits Times (Kuala Lumpur)

The New York Times

The Statesman (New Delhi)

The Straits Times (Singapore)

The Times of India (New Delhi)

The Tribune (Chandigarh)